टाइप सेट : क्विक प्रिंटस, सी-111/1, फेस-1, नारायणा, नई दिल्ली-110028
मुद्रक : चार दिशाएं प्रिंटर्स प्रा॰लि॰, नौएडा, दूरभाष: 0120-4041800 से 822

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

परिणाम बजट
2011-2012

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

परिणाम बजट
2011–2012

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

विषय-सूची

कार्यकारी सारांश

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड 1
बाल फिल्म समिति, भारत 2
क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय 2
विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय 3
फिल्म समारोह निदेशालय 3
फिल्म प्रभाग 4
भारत और विदेशों में आयोजित फिल्म बाजारों में भागीदारी 5
भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे 5
सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता 6
भारतीय जन संचार संस्थान 6
भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय 7
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड 7
पत्र सूचना कार्यालय 8
भारतीय प्रेस परिषद 9
फोटो प्रभाग 10
प्रकाशन विभाग 10
एम्पलॉइमेंट न्यूज/रोजगार समाचार 11
भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक का कार्यालय 11
गवेषणा संदर्भ एवं प्रशिक्षण प्रभाग 12
गीत एवं नाटक प्रभाग 12
एफएम रेडियो (निजी) 12
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानीटरिंग केंद्र (ईएमएमसी) 13
अन्तरराष्ट्रीय चैनल 13
सामुदायिक रेडियो 14
सूचना भवन का निर्माण 14
विकास संबंधी पहलों का आर्थिक विश्लेषण (नई योजना) 14
मानव संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षण 15
प्रसार भारती 15
ऐनीमेशन, गेमिंग और विशेष प्रभावों के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना 18

अध्याय - I

उद्देश्य एवं लक्ष्य, नीति निर्धारण एवं नीतिगत ब्यौरा

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड 19
बाल फिल्म समिति, भारत (सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्तशासी निकाय 20
क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय 21
विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय 22
फिल्म समारोह निदेशालय 22
फिल्म प्रभाग 23
भारत और विदेशों में आयोजित फिल्म बाजार में भाग लेना 23
भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे 24
सत्यजीत राय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता 26
भारतीय जन संचार संस्थान 29
भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय 31
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड 32
पत्र सूचना कार्यालय 33
भारतीय प्रेस परिषद 35
फोटो प्रभाग 36
प्रकाशन विभाग 36
एम्पलॉयमेंट न्यूज/रोजगार समाचार 42
भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक का कार्यालय 42
गवेषणा संदर्भ एवं प्रशिक्षण प्रभाग 43
गीत एवं नाटक प्रभाग 44
एफएम रेडियो (निजी) 45
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानीटरिंग केंद्र (ईएमएमसी) 45
अन्तरराष्ट्रीय चैनल 46
सामुदायिक रेडियो 46
सूचना भवन का निर्माण 46
विकास संबंधी पहलों का आर्थिक विश्लेषण (नई योजना) 47
मानव संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षण 47
प्रसार भारती 47
ऐनीमेशन, गेमिंग और विशेष प्रभावों के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना 53

अध्याय - II

वित्तीय परिव्यय, अनुमानित वास्तविक परिणाम एवं अनुमानित परिणाम

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड 54
बाल फिल्म समिति, भारत (सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्तशासी निकाय 57
क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय 59
विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय 61
फिल्म समारोह निदेशालय 63
फिल्म प्रभाग 66
भारत और विदेशों में आयोजित फिल्म बाजार में भाग लेना 70
भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे 72
सत्यजीत राय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता 77
भारतीय जन संचार संस्थान 83
भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय 85
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड 86
पत्र सूचना कार्यालय 87
भारतीय प्रेस परिषद 92
फोटो प्रभाग 93
प्रकाशन विभाग 100
एम्पलॉयमेंट न्यूज/रोजगार समाचार 103
भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक का कार्यालय 105
गवेषणा संदर्भ एवं प्रशिक्षण प्रभाग 107
गीत एवं नाटक प्रभाग 112
एफएम रेडियो (निजी) 121
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानीटरिंग केंद्र (ईएमएमसी) 122
अन्तरराष्ट्रीय चैनल 123
सामुदायिक रेडियो 124
सूचना भवन का निर्माण 125
विकास संबंधी पहलों का आर्थिक विश्लेषण (नई योजना) 126
मानव संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षण 127
प्रसार भारती 129

अध्याय - III

सुधार के लिए उठाए गए कदम और नीतिगत पहल

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड 155
बाल फिल्म समिति, भारत (सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्तशासी निकाय) 155

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय 155
विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय 156
फिल्म समारोह निदेशालय 156
फिल्म प्रभाग 157
भारत और विदेशों में आयोजित फिल्म बाजार में भाग लेना 157
भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे 157
सत्यजीत राय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता 158
भारतीय जन संचार संस्थान 158
भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय 158
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड 160
पत्र सूचना कार्यालय 161
भारतीय प्रेस परिषद 161
फोटो प्रभाग 162
प्रकाशन विभाग 162
एम्पलॉयमेंट न्यूज/रोजगार समाचार 163
भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक का कार्यालय 164
गवेषणा संदर्भ एवं प्रशिक्षण प्रभाग 164
गीत एवं नाटक प्रभाग 165
एफएम रेडियो (निजी) 165
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानीटरिंग केंद्र (ईएमएमसी) 166
अन्तररष्ट्रीय चैनल 166
सामुदायिक रेडियो 166
सूचना भवन का निर्माण चरण-V 167
विकास संबंधी पहलों का आर्थिक विश्लेषण (नई योजना) 167
मानव संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षण 168
प्रसार भारती 168
ऐनीमेशन, गेमिंग और विशेष प्रभावों के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना 170

अध्याय - IV

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड 171
बाल फिल्म समिति, भारत 172
क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय 173
विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय 177
फिल्म समारोह निदेशालय 181

फिल्म प्रभाग 183
भारत और विदेशों में आयोजित फिल्म बाजार में भागीदारी 186
भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे 187
सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता 193
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड 197
पत्र सूचना कार्यालय 198
भारतीय प्रेस परिषद 201
फोटो प्रभाग 203
प्रकाशन विभाग 204
एम्पलॉयमेंट न्यूज/रोजगार समाचार 209
भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक का कार्यालय 210
गवेषणा संदर्भ एवं प्रशिक्षण प्रभाग 213
गीत एवं नाटक प्रभाग 217
एफएम रेडियो (निजी) 219
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानीटरिंग केंद्र (ईएमएमसी) 220
अन्तरराष्ट्रीय चैनल 221
सामुदायिक रेडियो 222
सूचना भवन का निर्माण 223
विकास संबंधी पहलों का आर्थिक विश्लेषण (नई योजना) 224
प्रसार भारती 225

अध्याय - V 268
अध्याय - VI
केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड 288
बाल फिल्म समिति, भारत (सूचना और प्रसारण मंत्रालय का स्वायतशासी निकाय) 289
सत्यजीत राय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता पर समीक्षा 291
भारतीय जनसंचार संस्थान 294
भारतीय प्रेस परिषद 295
एफएम रेडियो (निजी) 296
सामुदायिक रेडियो 297
प्रसार भारती 298

कार्यकारी सारांश

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय अपने जनसंचार माध्यमों जैसे रेडियो, टेलीविजन, फिल्मों, प्रकाशन संस्थानों, विज्ञापनों और नृत्य एवं नाटक जैसे परंपरागत माध्यमों के ज़रिये लोगों तक सूचना पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मंत्रालय राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण सुरक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, निरक्षरता उन्मूलन, महिलाओं बच्चों और समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित मामलों के प्रति ध्यान दिलाने के लिये विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की बौद्धिक जरूरतों और मनोरंजन करने का कार्य करता है। मंत्रालय को तीन घटकों में बांटा गया है – सूचना स्कंध, प्रसारण स्कंध और फिल्म स्कंध।

मंत्रालय के कार्य विभाजन नियम के अनुसार इस प्रकार है:

– देश में विभिन्न जन माध्यमों के स्वस्थ विकास के लिये नीतिगत ढांचा तैयार करने और उसके लिये समुचित वातावरण तैयार करना।

– जन माध्यमों के जरिये सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में लोगों को जानकारी देना।

– सरकार की विभिन्न विकासात्मक गतिविधियां और कार्यक्रमों में ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल करना।

– सूचना और प्रसार के क्षेत्र में राज्य सरकारों और उसके संगठनों के बीच सामंजस्य स्थापित करना।

– सरकार और मीडिया के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करना और केन्द्र सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों से संबंधित प्रमाणिक आंकड़े और अधिकारिक सूचनाएं पहुंचाना।

मंत्रालय मीडिया इकाइयों द्वारा दिये जा रहे समाचारों और विचारों के प्रभावी प्रचार के लिये नीतिगत दिशा–निर्देश तैयार करने के लिये जिम्मेदार है। हालांकि मीडिया इकाइयों को स्वायत्त रूप से कार्य करने की स्वतंत्रता है। मंत्रालय इन इकाइयों के बीच समन्वय, सहायता, निगरानी और नियंत्रण रखता है ताकि इन इकाइयों का काम सुचारू रूप से चलता रहे। विभिन्न मीडिया इकाइयां लोगों की आवश्यकता लक्ष्य को ध्यान में रखकर कई तरह के कार्यक्रम तैयार करती हैं।

मंत्रालय अपने अधीन 14 कार्यालयों और छह स्वायत्त संगठनों और दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सहायता से कार्य करता है।

मंत्रालय के अधीन कार्यालयों, स्वायत्त संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थिति और विभिन्न योजनाएं एवं कार्यक्रम इस प्रकार हैं:

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड विभिन्न क्षेत्रीय केंद्रों के जरिए फिल्मों को सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रमाणित करता है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को ध्यान में रखते हुए इस कार्यालय ने सभी संबद्ध आंकड़े वेबसाइट www.cbfcindia.gov.in के जरिए इंटरनेट पर उपलब्ध कराए हैं। इनमें बजट आबंटन, सीबीएफसी के प्रत्येक कर्मचारी द्वारा आहरित मूल वेतन सहित कुल आहरित वेतन संबंधी आंकड़े भी शामिल हैं। राजभाषा अधिनियम, 1963 के मद्देनजर इसे द्विभाषी बनाया गया है। भौतिक और वित्तीय प्रगति पर निरंतर निगरानी रखी जाती है। ऐसा करते समय क्षेत्रीय प्रमुखों से भी सलाह–मशवरा किया जाता है। उन्हें धन आबंटित करने से पहले भी उनका परामर्श लिया जाता है।

बाल फिल्म समिति, भारत

बाल फिल्म समिति, भारत की स्थापना 1860 के सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत मई, 1955 में हुई थी। यह भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में स्वायत्तशासी निकाय के तौर पर कार्य करती है और इसे अपनी योजना और गैर योजना गतिविधियों के लिए सरकार से अनुदान प्राप्त होता है। बाल फिल्म समिति, भारत (सीएफएसआई) बच्चों को मूल्यपरक मनोरंजन प्रदान करने के साथ ही फिल्मों के माध्यम से उनकी मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक आवश्यकताओं को भी पूरा करती है।

इसका अध्यक्ष, सिनेमा के क्षेत्र की किसी प्रतिष्ठित हस्ती को बनाया जाता है। अध्यक्ष कार्यकारी परिषद तथा आम सभा का भी प्रमुख होता है जिसके सदस्य भारत सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। सभी विभागों के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी के तहत कार्य करते हैं। कार्यकारी अधिकारी प्रशासन, निर्माण, विपणन और लेखा विभाग की दैनिक गतिविधियों का संचालन करता है। समिति का मुख्यालय मुंबई में तथा शाखा कार्यालय नई दिल्ली और चेन्नई में हैं।

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय का मुख्य उद्देश्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में आमलोगों को जानकारी देना और लक्षित समूहों में विशेषकर दूर दराज के लोगों में स्वास्थ्य, राष्ट्रीय एकता और अन्य सामाजिक मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करना है।

सूचना को और तीव्र गति से तथा प्रभावी ढंग से पहुंचाने के उद्देश्य से क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय मल्टीमीडिया प्रोजेक्टरों, डीवीडी प्लेयरों और वायरलेस पब्लिक ऐड्रेस प्रणालियों आदि के माध्यमों, फिल्म प्रदर्शनों तथा अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों आदि का उपयोग करता है। प्रचार के लिए यह विभिन्न भाषाओं में अनेक विषयों पर अलग-अलग माध्यमों-फिल्म प्रभाग, एनएफडीसी, सीएफपी, आदि के माध्यम से फिल्मों और कैसेटों की खरीद भी करता है। क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय देश भर की सभी 207 क्षेत्रीय प्रचार इकाईयों तथा 22 क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए उपकरणों, नवीनतम कम्प्यूटरों के साथ-साथ अन्य सहायक उपकरणों का भी खरीद करता है और उन्हें इंटरनेट की सुविधा भी उपलब्ध कराता है जिससे वे एक-दूसरे के साथ अच्छी तरह से संपर्क कायम रखें और जब भी आवश्यकता पड़े, तत्काल सूचना उपलब्ध करा सकें।

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के काम-काज की निगरानी नियमित रूप से की जाती है। सरकार के कार्यक्रमों और नीतियों के बारे में लोगों के विचार जानने के लिए देश भर से प्रतिक्रियाएं प्राप्त की जाती हैं। व्यय की स्थिति की जानकारी हासिल करने के लिए क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय से समय-समय पर व्यय विवरणों और तिमाही कार्य निष्पादन रिपोर्टें भी मंगाई जाती हैं। किसी महीने के कार्यक्रम के विभिन्न स्वरूपों का इस्तेमाल करके चलाए गए कार्यक्रमों की संख्या के बारे में क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय से भी इसी प्रकार की रिपोर्टें मंगाई जाती हैं और किसी अवधि के लिए निर्धारित लक्ष्यों के सम्बन्ध में उनकी जांच परख भी की जाती है।

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय की वेबसाइट को समय-समय पर अद्यतन किया जाता है और ऐसी सभी तर्कसंगत सूचनाओं को साइट में सम्मिलित कर लिया जाता है ताकि आमलोग आसानी से उन तक पहुंच सकें।

विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय

डीएवीपी की भूमिका : विज्ञापन और प्रचार निदेशालय भारत सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों को प्रचारित करने वाली नोडल मल्टी मीडिया एजेंसी है। यह प्रेस विज्ञापनों, टीवी स्पॉट तथा केबल और सेटेलाइट नेटवर्क चैनलों, रेडियो/टेलीविजन पर प्रायोजित कार्यक्रमों, स्पॉट/जिंगल्स, डिजीटल सिनेमा, प्रदर्शनियों, मुद्रित प्रचार सामग्रियों और बाहरी प्रचार माध्यमों की सहायता से केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए प्रचार अभियान चलाती है। सेकटोरियल प्रचार प्रस्तावित करने वाले मंत्रालयों/विभागों से फंड प्राप्त किए जाते हैं इसलिए डीएवीपी अपने योजना/गैर योजना से अलग लागू करता है।

योजना स्कीमों के लिए बेहतर कोश : केन्द्र सरकार प्रचार कार्यक्रमों को मजबूत बनाने और अपनी सेवाओं को प्रभावी रूप से चलाने के लिए दो नियोजित योजनाएं, 1. विकास प्रचार कार्यक्रम : अवधारणा एवं प्रसार (जारी योजना) और 2. डीएवीपी का आधुनिकीकरण (नई योजना) को मंजूरी प्रदान की गई है। पंचवर्षीय योजना 2007-12 के पिछले दो वर्षों के लिए व्यय वित्त समिति ने कोश बढ़ाने की मंजूरी दे दी है।

प्रचार सरल बनाना : सरकार में प्रचार और विज्ञापनों के विभिन्न पहलुओं को सुव्यवस्थित करने और इस काम में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने मुद्रित माध्यम के लिए नई विज्ञापन नीति लागू की है। इसी प्रकार की नीति आडियो-विजुअल माध्यम में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए विज्ञापन/प्रचार करने के लिए बनाई गई है। समाचार पत्रों का नया पैनल बनाया गया जबकि दृश्य-श्रव्य मीडिया के लिए दरें तय करना प्रक्रियाधीन है।

इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली : डीएवीपी ने भुगतान की गति तेज करने तथा पारदर्शीता लाने के लिए सभी भुगतान नेशनल इलेकट्रानिक फाइल ट्रांसफर सिस्टम के जरिए शुरु किया है। डीएवीपी वेबसाइट www:davp.nic.in पर बिलों की स्थिति देखी जा सकती है।

शिकायत निवारण तथा आरटीआई को सरल बनाना : प्रत्येक विंग के निदेशक को पीआईसी बनाकर आरटीआई ढांचे का विकेंद्रीकरण किया गया है। सिटिजन चार्टर को संशोधित किया गया है और इसे सेवोत्तम के अनुरूप बनाया गया है।

व्यय की निगरानी : वार्षिक योजना के दौरान निर्धारित लक्ष्यों के साथ-साथ वितीय तथा भौतिक उपलङ्गधयों के विश्लेषण द्वारा डीएवीपी को योजना स्कीमों/गैर योजना व्यय की नियमित निगरानी की जाती है।

डीएवीपी के ढांचे तथा सेवाओं का आधुनिकीकरण : आधुनिकीकरण तथा इसकी सेवाओं को आधुनिक बनाने के लिए एक डीपीआर स्वतंत्र परामर्श से तैयार कराई जा रही हैं। रिपोर्ट दाखिल होते ही इसकी सिफारिशों को लागू किया जाएगा।

फिल्म समारोह निदेशालय

फिल्म समारोह निदेशालय (डीएफएफ) के माध्यम से तीन योजना स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं :

(1) भारत और विदेशों में आयोजित फिल्म समारोहों के माध्यम से निर्यात संवर्धन

(2) सीरीफोर्ट सांस्कृतिक परिसर में संयोजन और बदलाव

(3) प्रिंट यूनिट का उन्नयन

स्कीमों के लक्ष्य और उद्देश्य इस प्रकार हैं :

- देश के अंदर अच्छे भारतीय सिनेमा को बढ़ावा देना तथा उत्कृष्ट भारतीय फिल्मों को विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाना।
- समारोहों में उत्कृष्ट अंतर्राष्ट्रीय निर्देशकों की फिल्मों का प्रदर्शन।

फिल्म समारोह निदेशालय की स्थापना देश में अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय फिल्म समारोह आयोजित करने के लिए की गई थी। डीएफएफ विदेशी समारोहों में भारत की भागीदारी में मदद करता है। भारत में विदेशी फिल्मों तथा विदेश में भारतीय फिल्मों के कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कार्यक्रम आयोजित करता है।

सांस्कृतिक आदान-प्रदान के साधन के रूप में, डीएफएफ अंतर्राष्ट्रीय मित्रता को बढ़ावा देता है, विश्व सिनेमा में नए आयामों तक पहुंच मुहैया कराता है, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा करता है और इस प्रक्रिया में, भारतीय फिल्मों का स्तर सुधारने में मदद करता है।

डीएफएफ निम्नलिखित प्रमुख आयोजन करता है :

(1) भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह

(2) भारतीय पैनोरमा का चयन

(3) राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार

(4) विदेशी फिल्म समारोहों में भागीदारी

(5) सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम

इन प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में जनता को सूचना देने के लिए निम्नलिखित माध्यम अपनाए जाते हैं:

- पीआईबी के जरिए नियमित प्रेस रिलीज
- डीएवीपी के जरिये समाचार पत्रों में नियमित विज्ञापन और बैनर तथा पोस्टरों का प्रदर्शन
- कार्यक्रमों के दौरान समारोह प्रकाशन जारी किए जाते हैं, देश और विदेश में मिशनों के जरिये सूचना प्रसार तथा
- बेव साइटों के-www.dff.nic.in, www.iffi.nic.in, जरिये सूचना प्रसार

फिल्म प्रभाग

फिल्म प्रभाग की स्थापना वृत्तचित्र, एनीमेशन, छोटी एवं कार्टून फिल्में बनाने के लिये की गई थीं जिन्हें जन सूचना, शिक्षा, प्रोत्साहन और सांस्कृतिक उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा उपयोग किया जाता है। फिल्म प्रभाग सिनेमा प्रायोजकों को सांविधिक तौर पर सिनेमेटोग्राफी अधिनियम, 1952 और अनेक राज्य नियमों के अंतर्गत 'पारित फिल्मों' के प्रदर्शन में सहायता देता है। फिल्म प्रभाग भारत में वृत्तचित्र निर्माण को भी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सवों में हिस्सा लेने वाले स्वतंत्र निर्माताओं के जरिये प्रोत्साहन देता है, साथ ही यह वृत्तचित्रों, छोटी एवं एनीमेशन फिल्मों का मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (एमआईएफएफ) भी आयोजित करता है। फिल्म प्रभाग के अभिलेखागार में 8000 से अधिक फिल्में हैं जो सिनेमा प्रेमियों और सभी के लिए संदर्भ सामग्री के तौर पर उपलब्ध हैं। प्रभाग ने अपनी इन दुर्लभ फिल्मों को बड़े पर्दे से वीडियो में बदलने की शुरुआत कर दी है।

अपने मुंबई स्थित मुख्यालय और बंगलुरु, कोलकाता और नई दिल्ली स्थिति क्षेत्रीय निर्माण केंद्रों में फिल्म प्रभाग के पास प्रोडक्शन पूर्व एवं बाद की अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, देश भर में फैली इसकी 10 शाखाएं फिल्म-प्रेमियों की जरूरतों को पूर्ण करने के साथ-साथ 12,000 सिनेमा घरों को सिनेमेटोग्राफी अधिनियम-1952 के अंतर्गत 'पारित' फिल्में सप्लाई करती हैं।

फिल्म प्रभाग का मुखिया महानिदेशक होता है।

भारत और विदेशों में आयोजित फिल्म बाजारों में भागीदारी

फिल्मों के निर्यात और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मौजूदगी के लिए फिल्म उद्योग का तब तक हाथ थामने के उद्देश्य से, जब तक कि उद्योग अपनी स्वंय की निर्यात उन्नयन परिषद नहीं बना लेता तथा साथ ही पाइरेसी समाप्त करने और फिल्म समारोह आंदोलन को देश के विभिन्न भागों में फैलाने के लिए मंत्रालय ने अपनी मुख्य सचिवालय स्कीम यथा विदेशी समारोहों/बाजारों में भागीदारी के जरिए 11वीं पंचवर्षीय योजन दौरान 1100 लाख रुपये प्राप्त किए थे।

2010-11 की योजना स्कीम 'भारत तथा विदेश में फिल्म समारोहों/बाजारों में भागीदारी' के लिए 220 लाख रुपये निर्धारित किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, 2010 (आईएफएफआई) गोआ के साथ-साथ मंत्रालय ने केन्स फिल्म समारोह, 2010 तथा फिल्म बाजार में भाग लिया। इस स्कीम का उद्देश्य फिल्म निर्माताओं को विदेशी बाजारों में विपणन के लिए प्लेटफार्म उपलब्ध कराना तथा भारत को एक निवेश तथा फिल्म शूटिंग केंद्र के रूप में बढ़ावा देना है।

फिल्मों के निर्यात को बढ़ावा देने तथा वैश्विक बाजारों में भारतीय फिल्मों को बढ़ावा देने के मद्दे नजर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक स्वतंत्र एजेंसी यथा-आईआईपीए को इसमें शामिल किया है जो स्कीम का मूल्यांकन करेगी तथा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नीति संबंधी पहलों को सुझाव देगी। अध्ययन से निम्नलिखित प्रेक्षण प्राप्त हुए हैं :-

- 2007 से फिल्मों के निर्यात में बढ़ोतरी के संकेत मिले हैं।
- 2004-05 से स्कीम के अनुमोदित परिव्यय के उपयोग में सुधार हुआ है।
- यद्यपि विगत वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत दो या तीन प्रमुख फिल्म समारोहों में बाजार आयोजित हुआ जिसमें भारतीय पवेलियन विदेशी प्रतिनिधि मण्डलों को आकर्षित करने में सफल रहा फिर भी इन समारोहों को और व्यवसायिक तथा एकाग्र रूप से आयोदित करने की आवश्यकता है।
- विगत वर्षों के दौरान एनएफडीसी द्वारा आयोजित फिल्म बाजारों में भागीदारों की संख्या तथा गतिविधियों में सुधार हुआ है।

योजना स्कीमों की सीमितताओं के मद्दे नजर आईआईपीए ने एनएफडीसी को स्कीम के प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपने की सिफारिश की है। तद्नुसार वित्त वर्ष 2011-12 से भारत और विदेशी अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म बाजारों में भागीदारी का कार्य सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एनएफडीसी को सौंप दिया है। एनएफडीसी अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में उपलब्ध परिणामों की रिपोर्ट मंत्रालय को देगा। एनएफडीसी की भागीदारी और उपलब्धियों को प्रेस विज्ञप्तियों के रूप में तथा मंत्रालय की वेब साइट पर उपलब्ध कराया जाएगा।

भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे

भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान फिल्म निर्माण और टेलीविजन प्रशिक्षण में प्रशिक्षण प्रदान करने का उत्तरदायित्व निभाने वाला प्रमुख संस्थान है। एफटीआईआई विभिन्न विषयों में फिल्म एवं टेलीविजन में तीन वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा भी कराता है जो निर्देशन, सिनेमेटोग्राफी, ऑडियोग्राफी और संपादन के क्षेत्र में कराया जाता है। संस्थान अभिनय

और कला निर्देशन तथा प्रोडक्शन में दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम, एनीमेशन एवं कम्प्यूटर ग्राफिक्स में डेढ़ वर्षीय प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम, निर्देशन, इलैक्ट्रॉनिक सिनेमैट्रोग्राफी, वीडियो संपादन, ऑडियोग्राफी और टेलीविजन इंजीनियरिंग के क्षेत्र में टेलीविजन में एक वर्ष का स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम तथा फीचर फिल्म पटकथा लेखन में एक वर्षीय स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम चलाता है। एफटीआईआई कामकाजी पेशेवरों और संबंधित क्षेत्र में दिलचस्पी रखने वालों के लिए विविध अल्पकालिक पाठ्यक्रम भी चलाता है।

संस्थान के कार्य की निगरानी समय-समय पर अनुदान सहायता की किश्त जारी करते समय और शासकीय परिषद, स्थायी वित्त समिति जिसमें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सरकारी प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं इत्यादि की बैठकों के दौरान सरकार द्वारा की जाती है।

सत्यजित रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता

सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (एसआरएफटीआई) का मुख्य उद्देश्य फिल्म एवं टेलीविजन उद्योग के लिए प्रशिक्षित और सृजनशील पेशेवर प्रदान करना है।

संस्थान निर्देशन एवं पटकथा लेखन,चलचित्र फोटोग्राफी, एडीटिंग एवं साउंड रिकार्डिंग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करता है। मुख्य धारा के पाठ्यक्रमों के अलावा संस्थान स्व-वित्त पोषित आधार पर लघु अवधि पाठ्यक्रम संचालित/प्रस्तावित करता है। फिल्म एवं टेलीविजन की समाजिक, संस्कृति तथा प्रौद्योगिकी में अनुसंधान तथा खोजी अध्ययन एसआरएफटीआई में फोकस का एक और क्षेत्र है।

संस्थान के कार्य की निगरानी सरकार द्वारा समय-समय पर की जाती है। अनुदान सहायता जारी करने और शासी परिषद, स्थाई वित्त समिति इत्यादि की बैठकों के दौरान सूचना और प्रसारण मंत्रालय प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखा का ऑडिट किया हुआ विवरण से इसका निष्पादन संतोषजनक पाया गया है।

भारतीय जन संचार संस्थान

भारत सरकार ने वर्ष 1965 में भारतीय जन संचार की स्थापना की थी। यह संस्थान 18.8.1966 को सोसायटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम (XXI), 1860 के अंतर्गत एक सोसायटी के रूप में दर्ज किया गया था।

भारतीय जन संचार संस्थान के मुख्य लक्ष्य हैं देश के सामाजिक-आर्थिक विकास की आवश्यकताओं के विशेष संदर्भ में जन संचार के मीडिया के प्रयोग एवं विकास में शिक्षण, प्रशिक्षण और शोध का आयोजन करना।

सूचना व प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार कुल वार्षिक मदद अनुदान के रूप में इस संस्थान को वित्त प्रदान करती है।

भारतीय जन संचार संस्थान के पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स आम लोगों के लिए खुले हैं और लिखित परीक्षा/साक्षात्कार के माध्यम से उम्मीदवारों का चयन किया जाता है।

यह संस्थान विदेश मंत्रालय के सहयोग से विकासशील देशों के कार्यरत पत्रकारों और सूचना अधिकारियों के लिए प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के दौरान विकास पत्रकारिता में दो कोर्सों का आयोजन करता है।

यह संस्थान भारतीय सूचना सेवा (आई आई एस) के ग्रुप ए और ग्रुप बी के अधिकारियों के लिए बुनियादी पाठ्यक्रमों का भी आयोजन करता है। भारत सरकार के विभिन्न विभागों/संगठनों के अधिकारियों के लिए और आम लोगों के लिए भी कई अन्य अल्पकालीन पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। सरकार की ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान यह संस्थान जन माध्यम से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अनुसंधान परियोजनाएं भी चलाता है। इनमें से ज्यादातर अध्ययन प्रायोजकों द्वारा प्रायोजित होते हैं और उनकी वित्तीय सहायता से किये जाते हैं। यह संस्थान दो शोध पत्र–कम्युनिकेटर (अंग्रेजी में) और संचार माध्यम (हिन्दी में) प्रकाशित करता है। यह संस्थान समय–समय पर पत्रकारिता/जन संचार पर पुस्तकें एवं अन्य प्रकाशन भी प्रकाशित करता है।

आईआईएमसी की वेबसाइट (www.iimc.gov.in) सार्वजनिक है जिसको आम जनता देख सकती है।

भारत का राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय

11वीं योजना (2007–2012) के दौरान भारत के राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय के पास 30 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ निम्नलिखित अनुमोदित योजना स्कीमें हैं :–

'अभिलेख फिल्मों की प्राप्ति और प्रदर्शन'

वर्ष 2010–11 से *राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन* नामक एक नई स्कीम शुरु की गई तथा वर्ष 2011–12 के लिए स्कीम पर 5.00 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रस्ताव है।

एनएफएआई की योजना स्कीमों की प्रगति की निगरानी मासिक/त्रैमासिक/अर्द्धवार्षिक वास्तविक और वित्तीय प्रगति विवरणों के माध्यम से की जाती है जो नियमित रूप से मंत्रालय को भेजे जाते हैं। विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के तहत एनएफएआई द्वारा चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों में हुई प्रगति की सूचना एनएफएआई की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। स्कीम के कार्यनिष्पादन पर नियंत्रण संस्तुत योजना आवंटन के दायरे में ही रखा जाता है।

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम इस मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो निम्नलिखित गतिविधियों में संलग्न है।

1. निर्देशक की पहली फीचर फिल्म के निर्माण की शत–प्रतिशत जिम्मेदारी उठाकर नयी प्रतिभा को बढ़ावा देना,
2. नई फिल्म पटकथा के विकास में सहायता प्रदान करना
3. भारतीय और विदेशी फिल्म निर्माताओं के साथ व्यावसायिक तौर पर बेहतरीन गुणवत्ता वाली फिल्मों का सहनिर्माण करना,
4. विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के प्रचार अभियान चलाना।
5. फिल्मों का जीर्णोद्धार
6. गोवा में हर वर्ष फिल्म बाजार आयोजित करना

निगम को क्षेत्रीय फिल्म निर्माण में सक्षम बनाने के उद्देश्य से ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में क्षेत्रीय फिल्मों के निर्माण के लिए 46 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है। इसके लिए राज्य सरकार से राज्य विकास निधियों की जरूरत होगी ताकि उन्हें जो मदद चाहिए वह दी जा सके। वर्ष 2008-09 के दौरान ''विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्म निर्माण'' की योजना के तहत 6.50 करोड़ रुपये का परिव्यय आबंटन था जिससे एनएफडीसी ने 7 फिल्में निर्मित की हैं। वर्ष 2009-2010 के लिए 7.84 करोड़ रुपये का संशोधित अनुमान आबंटित किया गया है। 5.00 करोड़ रुपये निगम को क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्म निर्माण के लिए तथा 5.00 करोड़ रुपये फिल्मों के जीर्णोद्धार के लिए जारी कर दिए गए हैं। चूंकि ये फिल्में जिस लागत में बनती हैं उस हिसाब से उनका उतना बाजार मूल्य नहीं होता है और इसलिए ऐसी फिल्मों पर निवेश के एक हिस्से की पूर्ति निगम के सहयोग से होती है इसलिए ऐसी क्षेत्रीय फिल्मों का विकास पूरी तरह से मुनाफे की दृष्टि को ध्यान में रखकर नहीं बल्कि विकासवादी लक्ष्यों के लिए होना चाहिये।

पत्र सूचना कार्यालय

लोगो को सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और गतिविधियों के संबंध में जानकारी देने के लिए पत्र सूचना कार्यालय भारत सरकार की अग्रणी संस्था है। मीडिया (इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट) के साथ संवाद के प्रमुख सरकारी चैनेल के रूप में पत्र सूचना कार्यालय इस मूल विचार के साथ कार्य करता है कि लोकतंत्र में सरकार को यह सुनिश्चित करना होता है कि उसकी नीतियां और कार्यक्रम प्रेस और अन्य मीडिया के जरिए सही और उपयुक्त तरीके से उन लोगों तक पहुंचें जिनके समर्थन और विश्वास पर वह सत्ता में है।

पत्र सूचना कार्यालय (मुख्यालय) के अधिकारी मीडिया को सूचना प्रदान करने और फीड बैक उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से संबद्ध किए जाते हैं। वे मीडिया परामर्शदाता के रूप में काम करते हैं और प्रचार कार्य का समन्वयन करते हैं।

इसके क्षेत्रीय/शाखा कार्यालय कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए जुड़े हैं। कार्यालय का इंटरनेट पर एक होमपेज भी है जिसे www.pib.nic.in पर देखा जा सकता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उपयोग के लिए प्रचार सामग्री इस होमपेज पर डाली जाती है। पीआईबी की प्रेस विज्ञप्तियां अब कम्पयूटर के जरिए स्थानीय समाचार पत्रों, महत्वपूर्ण बाहरी समाचार पत्रों के स्थानीय संवाददाताओं और इसके क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों को भेजी जाती हैं। विशेष लेख और ग्राफिक्स आदि भी इंटरनेट के साथ-साथ पीआईबी नेटवर्क के जरिए जारी किये जाते हैं।

यह कार्यालय मीडिया प्रतिनिधियों को पेशागत सुविधाएं उपलब्ध करता है। इसके लिए यह भारतीय और विदेशी मीडिया प्रतिनिधियों, न्यूज कैमरामैनों और तकनीशियनों को प्रत्यायन उपलब्ध कराता है। दिसंबर 2010 तक 1375 संवाददाता, 401 कैमरामैन, 112 तकनीशियन और 159 सम्पादक/मीडिया समीक्षक इसके मुख्यालय से प्रत्यायित थे। भारतीय और विदेशी संवाददाताओं की आवश्कताओं को पूरा करने के लिए पीआईबी का नई दिल्ली में आधुनिक संचार सुविधाओं वाला एक राष्ट्रीय प्रेस केंद्र कार्यरत है।

मीडिया को जानकारी प्रदान करने के लिए यह कार्यालय विभिन्न तरीके अपनाता है — प्रेस विज्ञप्तियों और विशेष लेख, प्रेस ब्रीफिंग्स, संवाददाता सम्मेलन और प्रेस दौरे।

प्रेस विज्ञप्तियों, संवाददाता सम्मेलनों, विशेष लेखों आदि के संदर्भ में पीआईबी के कार्य निष्पादन की निगरानी तत्काल की जाती है और यह समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों की संख्या से परिलक्षित होती है। पीआईबी के कार्य की देख-रेख सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत अन्य मीडिया इकाइयों की ही भांति की जाती है।

समग्र निष्पादन

वार्षिक योजना 2010-11 के दौरान स्वीकृत प्रावधान 4650 लाख रुपये का है। वर्ष के दौरान योजना के अंतर्गत 2608.20 लाख रु. व्यय किये गये। वर्ष 2010-11 के दौरान (दिसंबर 2010 तक) वित्तीय संदर्भ में पत्र सूचना कार्यालय का प्रदर्शन इस प्रकार रहा :

(लाख रुपये में)

क्र.सं.		योजना	गैर-योजना	कुल
1.	बजट अनुमान 2010-11	4650.00	3688.00	8338.00
2.	संशोधित अनुमान 2010-11	4600.00	3817.00	8417.00
3.	दिसंबर 2010 तक वास्तविक खर्च	2608.00	2824.60	5432.80
4.	बजट अनुमान 2011-12	3825.00	4123.00	7648.00

भारतीय प्रेस परिषद

भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना संसद द्वारा की गई थी। यह एक अर्ध न्यायिक प्राधिकार है। समाचारपत्र तथा न्यूज एजेंसियों के मानक स्तर की निगरानी रखना इसका मुख्य कार्य है। प्रेस परिषद संसद के उस विश्वास को सुदृढ़ करनेवाली संस्था है जो प्रेस के स्तर तथा उसकी स्वतंत्रता की रक्षा का वचन देती है। इस अर्ध न्यायिक संस्था के परामर्शदात्री तथा नियामक उत्तरदायित्व भी है। विगत 45 वर्षों से यह संस्था अपने दायित्वों का निर्वाह करती आ रही है। मौजूदा दौर में जिस तरह प्रेस की जिम्मेदारी बढ़ी है, उसी तरह उस पर निगरानी रखना भी जरूरी है। आज के दौर की सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया को अपनी गलतियां मानने से गुरेज नहीं है। स्वस्थ वाद-विवाद, चर्चा-परिचर्चा आदि के माध्यम से मीडिया की कार्यप्रणाली पर चर्चा उसके अच्छे भविष्य की तरफ अग्रसर करती है।

वर्ष 2010-11 के दौरान जांच के द्वारा सामान्य न्यायिक प्रक्रिया के तहत 225 मामलों का निर्णय किया गया तथा 801 मामलों का निपटारा मौखिक जांच के बिना किया गया। मामलों के निपटान के समय मीडिया की स्वतंत्रता के साथ ही उसके मानकों का भी ध्यान रखा जाता है क्योंकि मीडिया की स्वतंत्रता जरूरी है लेकिन इसके साथ ही इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि मीडिया को निरंकुश भी नहीं होना चाहिए। मीडिया को हमेशा मानकों के दायरे में रहना चाहिए। ऐसा करके ही मीडिया अपने दायित्वों का निर्वाह कर सकता है। पेड न्यूज की समस्या मीडिया में बढ़ती जा रही है। प्रेस परिषद ने पेड न्यूज को गंभीरता से लिया है।पेड न्यूज की प्रवृत्ति को रोकने के लिए परिषद ने कुछ सिफारिशें की है क्योंकि पेड न्यूज का दुष्प्रभाव चुनाव प्रक्रिया पर भी पड़ रहा है और इससे कहीं-न-कहीं से हमारी व्यवस्था प्रभावित होगी। परिषद ने पेड न्यूज को लेकर संसदीय समिति को भी अपनी सिफारिशें भेजी हैं। पेड न्यूज के मामले में चुनाव आयोग भी गंभीर है। पेड न्यूज की प्रवृत्ति को रोकने का प्रयास जारी है।

भारतीय प्रेस परिषद डब्ल्यूएपीए के माध्यम से अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर भी सक्रिय है ताकि मीडिया के स्व-नियंत्रित तौर-तरीकों को अपनाया जाए। उल्लेखनीय है कि प्रेस की स्वतंत्रता के लिए यह बहुत जरूरी है। इस क्रम में इंडोनेशिया के प्रेस परिषद के साथ भारतीय प्रेस परिषद ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते में अशांत क्षेत्रों में रिपोर्टिंग तथा पत्रकारिता में शांतिपूर्ण सहयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है।

यहां इस बात का उल्लेख जरूरी है कि भारतीय प्रेस परिषद को हिंदी भाषा को बढ़ावा देने तथा एड्स रिपोर्टिंग के लिए गाइड लाइन बनाने के लिए पुरस्कार मिल चुका है।

परिषद ने अपना कार्य दक्षतापूर्वक करते हुए मीडिया और आम लोगों का विश्वास प्राप्त किया है। अन्तरराष्ट्रीय मंच पर भी इसने अपनी क्षमता और कार्य प्रणाली के प्रति सम्मान हासिल किया है। साथ ही, वित्तीय दृष्टि से लगभग पूरी तरह सरकार पर आश्रित होने के बावजूद यह सरकारी हस्तक्षेप से पूरी तरह मुक्त करने में सफल रही है। परिषद अपने दायित्वों का निर्वाह बाखूबी करती है। परिषद के प्रेस से संबंधित फैसले इसकी वेबसाइट पर भी देखे जा सकते हैं। वर्ष 2011–12 के दौरान परिषद के उद्देश्य इस प्रकार हैं –

1. प्रेस परिषद अधिनियम में संशोधन करके प्रेस परिषद का सुदृढ़ीकरण।

2. मीडिया और प्राधिकार के लिए आचार संहिता के लिए गाइड लाइन तैयार करना।

2 परिषद की विशेष आर्काइव रिपोर्टों को ई–फारमेट में बदलना।

4. इंडोनेशिया प्रेस परिषद के साथ हुए समझौते का कार्यान्वयन।

आम आदमी तथा मीडिया के वैचारिक संबंधों को लेकर परिषद हमेशा जागरुक रहती है। परिषद इस बात पर बल देती है कि आम आदमी के हितों के साथ ही मीडिया की स्वतंत्रता भी न प्रभावित हो। आम आदमी द्वारा मीडिया के खिलाफ की गई शिकायतों को परिषद गंभीरता से लेती है।

फोटो प्रभाग

फोटो प्रभाग भारत सरकार की एक मीडिया इकाई है जो आंतरिक और बाह्य प्रचार के लिए फोटोग्राफ्स तैयार करने और दृश्य प्रलेखन के लिए उत्तरदायी है। फोटो प्रभाग देश के विकास के विभिन्न पहलुओं और ऐतिहासिक घटनाओं का रिकार्ड रखता है तथा देश को एक समग्र फोटोग्राफिक दस्तावेज उपलब्ध कराता है। यह फोटो प्रतियोगिताओं और कार्यशालाओं के माध्यम से युवाओं को प्रोत्साहित करता है। प्रभाग की एक मूल्य योजना भी है जिसके अंतर्गत आम जनता को भुगतान करने पर फोटोग्राफ उपलब्ध कराये जाते हैं। फोटोग्राफिक उद्योग की बदलती प्रवृत्तियों के मद्देनजर, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय फोटोग्राफी केंद्र नामक एक प्लान योजना कार्यान्वित की गई है जिससे प्रयोक्ताओं और ग्राहकों को बेहतर सेवा और गुणवत्ता दी जा सके और उनकी वर्तमान भागों को पूरा किया जा सके। पूर्वोत्तर, जम्मू और कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के लिए विशेष अभियान नाम से एक अन्य प्लान योजना भी शुरू की है। इस योजना में इन क्षेत्रों के विकास पर विशेष बल दिया गया है।

प्रकाशन विभाग

प्रकाशन विभाग देश के सबसे बड़े प्रकाशन भवनों में से एक है। हिंदी, अंग्रेजी और अन्य प्रमुख भारतीय भाषाओं में प्रकाशन विभाग द्वारा निकलने वाली पुस्तकों और पत्रिकाओं को इस प्रकार तैयार किया जाता है कि उनके माध्यम से इस देश के लोगों की समझ का विकास हो सके।

प्रकाशन विभाग का कार्य है लोकप्रिय पुस्तकों और पत्रिकाओं का उत्पादन, बिक्री और वितरण करना। अपने कार्य के द्वारा यह विभाग निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है :

(i) राष्ट्रीय महत्व के उन विषयों पर पुस्तकों को प्रकाशित करना जिन विषयों पर अन्य प्रकाशकों ने ध्यान नहीं दिया हो और ऐसी पुस्तकों को कम कीमत पर आम जनता के लिए उपलब्ध बनाना।

(ii) विविधता में एकता, सांप्रदायिक सद्भाव, राष्ट्रीय अखंडता इत्यादि की विचारधारा और आत्मा को मजबूत करना और बढ़ावा देना।

(iii) वर्ष 2011–2012 के दौरान प्रकाशन विभाग ने 20 पत्रिकाएं और 90 पुस्तकें प्रकाशित करने का लक्ष्य बनाया है। प्रकाशन विभाग देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित बिक्री केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से अपनी पुस्तकों और पत्रिकाओं को बेच रहा है। समय के साथ चलने के लिए प्रकाशन विभाग ने चरणबद्ध तरीके से अपने बिक्री केंद्रों को आधुनिक बनाने का प्रस्ताव किया है क्योंकि ये बिक्री केंद्र व्यवस्थित स्थिति में नहीं हैं और जीर्ण–शीर्ण अवस्था को दर्शाते हैं जबकि इसकी तुलना में इसके प्रतिद्वंद्वी प्रमुख इलाकों में स्थित सुव्यवस्थित शोरुमों के माध्यम से अपनी किताबें बेच रहे हैं।

(iv) प्रकाशन विभाग के बिक्री केंद्र नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, चेन्नई, पटना और तिरुअनंतपुरम में स्थित हैं। बिक्री के आउटलेट बंगलुरु, गुवाहाटी और अहमदाबाद में स्थित हैं।

(v) वर्ष 2011–2012 के लिए बजट आकलन गैर योजना में 2223.00 लाख रुपये और योजना में 20.00 लाख रुपये है।

एम्प्लाइमेंट न्यूज/रोजगार समाचार

साप्ताहिक रोजगार समाचार अंग्रेजी, हिंदी तथा उर्दू में प्रकाशित होता है। यह प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार का प्रमुख प्रकाशन है। इस साप्ताहिक पत्र में केंद्रीय एवं राज्य सरकारें, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, स्वायत्त निकायों, विश्वविद्यालयों, विदेशी संस्थानों जैसे फोर्ड फाउंडेशन, ब्रिटिश काउंसिल आदि में नौकरियों के विज्ञापन, व्यावसायिक पाठयक्रमों के लिए प्रवेश अधिसूचनाएं, भारतीय संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग जैसे संगठनों तथा अन्य सामान्य भर्ती निकायों की परीक्षा अधिसूचनाएं और उनके परिणामों तथा मध्य–स्तरीय रोजगार उन्नयन के अवसरों (प्रतिनियुक्तियों) की सूचनाएं प्रकाशित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त एक सम्पादकीय हिस्सा भी है जो कैरियर से सम्बन्धित दो मुख्य लेख प्रकाशित करता है।

रोजगार समाचार प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का प्रमुख प्रकाशन है। इस साप्ताहिक पत्र का मूल लक्ष्य समूह सिविल सेवा के अभ्यार्थियों, प्रतियोगी परीक्षाओं और साक्षात्कारों में बैठने वाले तथा रोजगार अवसरों की खोज में जुटे युवा लोग हैं।

इस साप्ताहिक पत्र का उद्देश्य इसको पढ़ने वाले लोगों को जानकारी उपलब्ध कराना है ताकि वे अपने लिए सर्वोत्तम उपलब्ध कैरियर चुन सकें।

रोजगार समाचार की रोजगार उन्मुख वेबसाइट www.employmentnews.gov.in है। वेबसाइट अभूतपूर्व सफल है और नौजवानों के बीच काफी लोकप्रिय है। इस वेबसाइट को रोज करीब तीन लाख लोग सर्च करते हैं।

भारत के समाचारपत्र के पंजीयक का कार्यालय

भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का कार्यालय (आरएनआई) प्रेस तथा पुस्तक पंजीकरण कानून, 1867 के अन्तर्गत देश में प्रकाशित होने वाले समाचारपत्रों/पत्रिकाओं का अद्यतन रिकार्ड तथा आंकड़े संभाल कर रखता है, नये प्रकाशनों के लिए शीर्षक उपलब्ध कराता है, पंजीकरण के प्रमाणपत्र जारी करता है, प्रकाशकों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक प्रसार दावों की समीक्षा करता है तथा 'भारत के समाचारपत्र' नामक शीर्षक से प्रिंट मीडिया के हालात पर वार्षिक रिपोर्ट तैयार करता है। आरएनआई समाचारपत्रों के प्रसार

के दावों पर भी नियन्त्रण रखता है। अपने वैधानिक कार्यों के अलावा, यह कार्यालय अखबारी कागज के आयात के लिए समाचारपत्रों को पात्रता प्रमाणपत्र जारी करता है। इसके अलावा, आरएनआई समाचारपत्रों द्वारा अपेक्षित प्रिंटिंग मशीनरी तथा सम्बद्ध सामग्री के आयात के लिए अनिवार्यता प्रमाणपत्र जारी करता है।

गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग

गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन कार्यालय है। इस प्रभाग की भूमिका मीडिया इकाइयों को शोध के संबंध में एकत्रित, संकलित और तैयार सामग्री के प्रकाशन कार्य आदि में सहायता करना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मीडिया इकाइयों के उपयोग के लिए महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी का सारांश निर्मित करना और सामयिक एवं अन्य विषयों पर मार्गदर्शन एवं पृष्ठभूमि नोट तैयार करना भी इस प्रभाग का दायित्व है।

यह प्रभाग प्रत्यक्ष रूप से आम जनता को कोई सेवा प्रदान नहीं करता है। वास्तविक लक्ष्यों को सामान्यत: वार्षिक बजट योजना के रूप में बनाया जाता है और इनकी इस प्रभाग द्वारा निगरानी की जाती है। मंत्रालय का प्रशासनिक खंड इसकी गतिविधियों की निगरानी करता है।

सार्वजनिक सूचना प्रणाली के संबंध में प्रभाग की वेबसाइट www.rrtd.gov.in जन अधिकार के क्षेत्र में आती है और आम जनता इसे देख सकती है।

गीत एवं नाटक प्रभाग

गीत एवं नाटक प्रभाग की स्थापना 1954 में आकाशवाणी की एक इकाई के रूप में की गई थी और 1956 में इसे विकासात्मक संचार की अनिवार्यता के साथ ही स्वतंत्र मीडिया इकाई का दर्जा दे दिया गया। इस विभाग की स्थापना के उद्देश्य इस प्रकार हैं :

- देश की प्रगति में सहायक सामाजिक, आर्थिक और लोकतांत्रिक विचारों और आदर्शों को लोगों के बीच पहुंचाने और जागरूकता जगाने के लिए।
- सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच रक्षात्मक भावना और देश के अन्य भागों के लोगों के साथ उनके सांस्कृतिक जुड़ाव के लिए।
- लोक कलाओं और शहरी कलाओं दोनों के माध्यम से दूरदराज के कठिन इलाकों में तैनात सेना के जवानों में साहस का संचार करने के लिए।

गीत एवं नाटक प्रभाव प्रदर्शन कलाओं को संचार माध्यम के साथ इस्तेमाल करने वाला देश का सबसे बड़ा संगठन है। प्रभाग नाटक, नृत्य नाटिका, गीत नाट्य, लोक कलाओं, पारंपरिक गीतों, कठपुतली कला जैसी कलाओं का प्रदर्शन करता है। प्रभाग सांप्रदायिक सदभाव, राष्ट्रीय एकता, धर्मनिरपेक्षता, सांस्कृतिक धरोहर को प्रोत्साहित करने के लिये, पर्यावरण, स्वास्थ्य और शिक्शखा जैसे विषयों को लोगों तक पहुंचाने के लिए गीत एवं नाट्य कार्यक्रम आयोजित करता है।

एफ एम रेडियो

सरकार ने 1999 में निजी एजेंसियों के जरिये एफएम रेडियो प्रसारण की एक नीति की शुरुआत की और इसे 2005 में दूसरे चरण के तहत विस्तारित किया। इस नीति में यह अनिवार्य है कि जहां प्रसार भारती के टावर हैं वहां निजी प्रसारकों की प्रसारण सुविधाओं को उन्हीं टावरों से जोड़ा जाये और जिन स्थानों पर प्रसार भारती के टावर नहीं हैं वहां निजी प्रसारकों के लिए मेसर्स बेसिल के जरिये नए टावर बनाये जाए। दूसरे चरण के तहत पहचाने गये 91 शहरों में से 84 शहरों में प्रसार भारती के टावर हैं तथा शेष सात शहरों – दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु और जयपुर में नए टावर प्रस्तावित हैं।

2. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने निजी एफ एम रेडियो नाम की योजना के तहत सात शहरों में नए टावर लगाने का प्रस्ताव किया है। ये टावर मेसर्स बेसिल द्वारा 18.18 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने हैं और इसके लिए योजना आयोग ने 2006 में मंजूरी दे दी थी। इन टावरों के निर्माण के खर्च प्रतिपूर्ति निजी एफ एम प्रसारकों से वार्षिक किराये के रूप में की जाएगी। प्रसार भारती का टावर होने पर किराया राशि की वसूली प्रसार भारती द्वारा की जाएगी। प्रसार भारती टावर दो शहरों – मुंबई और बेंगलुरु में उपलब्ध हो चुके हैं। इस बीच सरकार ने देहरादून में भी एक नया टावर बनाने का फैसला किया है क्योंकि वहां प्रसार भारती का कोई टावर नहीं है। इस तरह अब छह शहरों – दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, जयपुर, हैदराबाद और देहरादून में नए टावर बनाने की जरूरत है। इस योजना को 10वीं योजना के तहत 2005–2006 और 2006–07 में दो वर्षों के लिये मंजूरी मिली थी। चूंकि योजना आयोग से जनवरी 2006 में सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई थी और मार्च 2006 में अग्रिम राशि जारी की गई थी, इसलिए वास्तविक काम अप्रैल 2006 से शुरू हो गया। यही नहीं बेसिल को जगह के हस्तांतरण में देरी होने आदि कारणों से यह परियोजना तय कार्यक्रम के अनुसार मार्च 2007 तक पूरी नहीं हो पाई। पांच शहरों – जयपुर, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली और देहरादून में टावरों का निर्माण पूरा हो चुका है। चूंकि दो शहरों में टावरों के निर्माण के काम को छोड़ दिया गया है और देहरादून में टावर के निर्माण के कार्य को बाद में शामिल किया गया, छह शहरों में टावरों के निर्माण की परियोजना की कुल अनुमानित लागत 1311.24 लाख रुपये बैठती है। इस समय तक बेसिल को 10.81 करोड़ रुपये (लगभग) जारी किये जा चुके हैं। (कुल 1311.24 लाख रुपये के कुल परिव्यय के मुकाबले 2005–06 में 8.00 करोड़ रुपये, 2006–07 में 63 लाख रुपये, 2007–08 में एक करोड़ रुपये, 2008–09 में दस लाख रुपये और 2009–10 में 108 लाख रुपये जारी हो चुके हैं।

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानिटरिंग केंद्र (ईएमएमसी)

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानीटरिंग केन्द्र (ईएमएमसी)की स्थापना निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए की गई है – (i) केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम 1995 तथा उसके अंतर्गत बने नियमों में निहित कार्यक्रम और विज्ञापन की मानीटरिंग, एवं (ii) निजी एफ एम रेडियो आदि के लिए अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) शर्तों की निगरानी तथा (iii) ऐसे अन्य कार्य जो प्रसारण क्षेत्र की विषयवस्तु की निगरानी से संबंधित जिन्हें सरकार द्वारा समय-समय पर सौंपा गया हो। यह 100 टी वी चैनलों की मानीटरिंग सुविधा के साथ 09 जून 2008 से अस्तित्व में आया। वर्ष 2008–09 के दौरान यह सुविधा बढ़कर 150 चैनल कर दी गई। और 05 जनवरी, 2011 से यह सुविधा बढ़ाकर 300 टीवी चैनलों की कर दी गई। यह योजना पूर्ण रूप से सरकार द्वारा वित्तपोषित है।

अंतर्राष्ट्रीय चैनल

भारत के वैश्विक शक्ति के रूप में उभर कर आने से यह अनिवार्य हो गया है कि संवेदनशील मामलों पर भारत की स्थिति और उसके दृष्टिकोण को यथाशीघ्र अधिक से अधिक देशों में मुखर किया जाए। मुख्य उद्देश्य हैं : भारत की स्थिति का संपूर्ण विश्व में उसी प्रकार प्रचार करना जिस तरह से अल-जज़ीरा, बीबीसी, सीएनएन, सीसीटीवी इत्यादि चैनल करते हैं। इसके लिए डीडी इंडिया, जिसे बहुत से देशों में देखा जाता है, पर प्रसारण के साथ-साथ वर्तमान डीडी न्यूज़ चैनल के ज़रिए अंतर्राष्ट्रीय समाचारों और कार्यक्रमों की शुरुआत करनी होगी।

सामुदायिक रेडियो के लिए आईईसी गतिविधियां

सामुदायिक रेडियो बेजुबानों को आवाज देने का एक असाधारण एवं अदृश्य माध्यम है। यह समुदाय को उनके जीवन से जुड़े मुद्दों के बारे में बोलने का अवसर प्रदान करता है। यह ग्रामीण विकास, कृषि, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, पंचायती राज जैसे मुद्दों के बारे में सूचनाओं का प्रसार-प्रचार करके यह विकास को भी बढ़ावा देता है।

दुनिया भर में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों ने जागरूकता कायम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है तथा इसने लोगों के विकास में योगदान दिया है। सामुदायिक रेडियो स्टेशनों ने सुनामी, बाढ़, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं एवं हादसों के दौरान भी समुदायों की मदद की है। भारत के विशाल परिदृश्य, अनेक भाषाओं, विभिन्न तरह की संस्कृतियों एवं विभिन्नतापूर्ण सामाजिक ढांचे को देखते हुए यहां बड़ी संख्या में रेडियो स्टेशनों की भारी संभावना है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय देश में सामुदायिक रेडियो आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय कदम उठा रहा है। सरकार को अब तक शैक्षणिक संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों, कृषि विश्व विद्यालयों, कृषि विज्ञान केन्द्रों आदि की ओर से 825 आवेदन पत्र प्राप्त हो चुके हैं। अब तक स्वीकृति संबंधी 263 पत्र जारी किये जा चुके हैं और अनुमति के 126 अनुदान पत्रों पर हस्ताक्षर हो चुके हैं।

4. इस समय देश के विभिन्न भागों में 103 सामुदायिक रेडियो स्टेशन कार्य कर रहे हैं। इन 103 स्टेशनों में 71 स्टेशन शैक्षणिक संस्थानों की ओर से, 24 स्टेशन समुदाय आधारित संगठनों की ओर से और आठ स्टेशन कृषि विज्ञान केन्द्रों/राज्य कृषि संस्थाओ की ओर से चलाए जा रहे हैं।

5. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की स्थापना एवं उनके संचालन के लिए देश के विभिन्न भागों में अनेक कार्यशालाओं और सेमिनारों का आयोजन करके इस नीति के बारे में लोगों में जागरूकता कायम करने का प्रस्ताव किया है।

सूचना भवन का निर्माण चरण-V

सूचना भवन का निर्माण सूचना और प्रसारण मंत्रालय की एक प्रमुख परियोजना है। मंत्रालय की विभिन्न मीडिया इकाइयों को यथोचित स्थान उपलब्ध कराने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया कि विभिन्न स्थलों पर बिखरे मीडिया इकाइयों के कार्यालयों (आकाशवाणी महानिदेशालय और दूरदर्शन महानिदेशालय के अतिरिक्त) को एक स्थान पर लाने के लिए मंत्रालय को स्वयं का एक भवन निर्मित करना चाहिए। योजना आयोग ने इस योजना को मंजूर किया और इसे पांचवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया। तद्नुसार, 1981 में मंत्रालय को एन्वेलप सं.-8 पर 8364.3 वर्गमीटर आकार का भूमि का टुकड़ा आवंटित किया गया हालांकि इस पर निर्माण कार्य 1985 में शुरू हो पाया। वित्तीय बाधाओं के चलते निर्माण कार्य चरणों में किया जा रहा है। इस भवन का निर्माण कार्य आकाशवाणी के सिविल कंस्ट्रक्शन विंग द्वारा किया जा रहा है। अब तक I, II, III और IV चरण पूरे हो चुके हैं। इन चार चरणों के तहत, केवल 38 प्रतिशत क्षेत्र (27,259 वर्गमीटर) का निर्माण कार्य हुआ है। सूचना भवन के निर्माण के चरण (अंतिम चरण के लिए कार्य प्रगति पर है, जिसके अंतर्गत बचे हुए 62 प्रतिशत क्षेत्र (45,500 वर्गमीटर) पर निर्माण कार्य किया जाएगा।

विकास संबंधी पहलों का आर्थिक विश्लेषण (नई योजना)

अर्थव्यवस्था के तहत मनोरंजन और मीडिया क्षेत्र में 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) के दौरान उच्च वृद्धि की उम्मीद है। विकास की इस गति से लाभ उठाने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा फिल्म, सूचना और प्रसारण क्षेत्र संबंधी विभिन्न स्कीम/कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि निर्धाारित लक्ष्यों/उद्देश्यों

को हासिल किया जा सके। 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) में यह स्कीम लागू की जा रही है।

इस स्कीम के उद्देश्य इस प्रकार हैं :

- फिल्म, सूचना और प्रसारण क्षेत्र में प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) को विकसित करना।
- फिल्म, सूचना और प्रसारण क्षेत्रों से संबंधित नियामक और विकास नीतियों के प्रभाव का अध्ययन और मूल्यांकन करना।

मानव संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षण

सूचना और प्रसारण मंत्रालय की 11वीं योजना में एक नई स्कीम ''भारतीय सूचना सेवा अधिकारियों के लिए विदेश स्थित संस्थानों में मानव संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षण'' हेतु सेवा के दौरान प्रशिक्षण का प्रस्ताव शामिल है जिसमें वर्ष 2011-2012 के लिए 150.00 लाख रुपये आबंटित किए गए हैं।

प्रसार भारती

प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) देश की एक सार्वजनिक प्रसारक सेवा है और उसके दो संघटक हैं, आकाशवाणी और दूरदर्शन। यह 23 नवंबर 1997 से अस्तित्व में आया। इस सेवा का उद्देश्य सार्वजनिक प्रसारण सेवा के रूप में सर्वसाधारण को जानकारी देना, उन्हें शिक्षित करना और उनका मनोरंजन करना एवं देश में प्रसारण के संतुलित विकास को सुनिश्चित करना है।

संगठनात्मक ढांचा

निगम के मामलों का सामान्य निरीक्षण, निर्देशन और प्रबंधन प्रसार भारतीय बोर्ड करता है। बोर्ड समय-समय पर बैठकें करता है और महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों पर विचार विमर्श करता है एवं नीतियों के कार्यान्वयन के लिए अधिकारियों को निर्देश देता है। कार्यकारी सदस्य निगम मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ)के रूप में कार्य करते हैं और बोर्ड का नियंत्रण और निरीक्षण करते हैं। सीईओ बोर्ड में इस तरह अपने अधिकारों का प्रयोग करेगा और अपने सभी कार्य इस प्रकार करेगा जिस प्रकार अधिनियम के तहत निगम द्वारा किए जाते हैं।

महानिदेशक आकाशवाणी और दूरदर्शन के प्रमुख के तौर पर कार्य करते हैं। बोर्ड के नीति निर्देश और आकाशवाणी एवं दूरदर्शन की दैनंदिन मामलों के प्रबंधन के लिए वे सदस्य(वित्त), सदस्य (कार्मिक) और सीईओ के निकट सहयोग से कार्य करते हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन में, विभिन्न गतिविधियों, जैसे प्रोग्राम, इंजीनियरिंग, प्रशासन, वित्त और समाचार के लिए व्यापक स्तर पर चार भिन्न खंड हैं।

आकाशवाणी

आकाशवाणी (एआईआर)प्रसार भारती अधिनियम, 1990 में दिए गए प्रावधान के तहत कार्य करता है। 500 डब्ल्यू मीडियम वेव ट्रांसमीटर से शुरुआत करते हुए आकाशवाणी आज प्रमुख प्रसारक संगठन बन गया है। 275 रेडियो ट्रांसमीटर के सात यह 91.82 प्रतिशत क्षेत्र और 99.16 प्रतिशत आबादी के दायरे में फैला हुआ है। आकाशवाणी विभिन्न स्टेशनों पर अपने कार्यक्रम प्रसारणों के माध्यम से सर्वसाधारण को जानकारी देता है, उन्हें शिक्षित करता है और उनका मनोरंजन करता है।

ध्वनि प्रसारण के माध्यम से यह देश के सभी लोगों को सरकारी नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों और उपलब्धियों की जानकारी देता है। इसके कार्यक्रम संस्कृति, शिक्षा, विज्ञान, स्वास्थ्य, स्वच्छता, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, महत्वपूर्ण समाचार और प्रासंगिक रुचि की समसामयिक घटनाओं पर आधारित होते हैं। यह राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करने के लिए अपने प्रसारण के माध्यम से विभिन्न विचारों को प्रस्तुत करता है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्यक्रम संतुलित और निष्पक्ष हैं(अध्याय-1)।

वार्षिक योजना 2011-12 के लिए आकाशवाणी का प्रस्तावित परिव्यय 632.46 करोड़ रुपए है जिसमें 584.30 करोड़ रुपये पूंजी घटक के अंतर्गत एफएम सेवा के विस्तार, उत्तर पूर्व के विशेष पैकेज के तहत एफएम सेवा के विस्तार, आकाशवाणी नेटवर्क के डिजिटलीकरण के लिए और 48.16 करोड़ रुपये सीमांत क्षेत्रों में आकाशवाणी/दूरदर्शन के दायरे को मजबूत करने और राजस्व फुटकर व राजस्व सॉफ्टवेयर के लिए सुनिश्चित हैं। पूंजी योजना परियोजनाएं सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण द्वारा वित्त पोषित होती हैं जबकि राजस्व योजना परियोजनाएं अनुदान के रूप में प्रदान की जाती हैं (अध्याय-2)।

सार्वजनिक प्रसारक के रूप में संगठन के अधिक विकास से संबंधित नीतिगत फैसलों के आधार पर आकाशवाणी द्वारा विभिन्न पहल की गई हैं। इन्हें आम जनता की जरूरतों और विशेष लक्षित समूहों, जैसे अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति के कल्याण, महिला सशक्तीकरण और उत्तर पूर्व क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखकर लागू किया जाता है (अध्याय-3)।

वार्षिक योजना 2009-10 और 2010-11 (नवंबर 2010 तक) के दौरान भौतिक एवं वित्तीय प्रदर्शन का योजनागत विवरण अध्याय 4 में दिया गया है। वार्षिक योजना 2009-10 की स्वीकृत लागत 261.00 करोड़ रुपए थी और खर्चा 33.67 करोड़ रुपये था। इसी प्रकार वार्षिक योजना 2010-11 की कुल लागत 183.48 करोड़ रुपये थी।

वित्तीय वर्ष 2008-09 के बजट अनुमान का योजनागत विवरण और संशोधित अनुमान तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010-11 (30 नवंबर 2010 तक) की जानकारी अध्याय-5 में दी गई है। वित्तीय वर्ष 2008-09 तक जारी किए गए अनुदान के संदर्भ में आवश्यक उपयोग सर्टिफिकेट (यूसी) प्रासंगिक नियमों के अनुसार प्रसार भारती (आकाशवाणी) द्वारा जुटाए गए हैं और कोई लंबित यूसी नहीं है।

निरीक्षण प्रणाली

विभिन्न स्तरों पर समीक्षा और प्रसार भारती को जारी अनुदान के समय ही मासिक व्यय विवरण के माध्यम से आकाशवाणी की सभी योजना परियोजनाओं के प्रदर्शन का नियमित निरीक्षण किया जाता है। लागत के विकास और मंत्रालय द्वारा रखी गई अन्य शर्तों को पूरा करने के आधार पर अनुदान को जारी किया जाता है। इसके अतिरिक्त, योजना आयोग द्वारा प्रस्तुत फॉरमेट में अर्द्ध वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट (एचपीआर)को तैयार किया जाता है जो समग्र रूप से सभी योजनाओं के विकास की समीक्षा करती है।

प्रसार भारती के सीईओ द्वारा आकाशवाणी के वित्तीय प्रदर्शन के योजनागत विवरण का नियमित निरीक्षण किया जाता है। इसके अतिरिक्त योजना समन्वय इकाई मासिक वक्तव्य के आधार पर भी इसका निरीक्षण करती है। सीईओ, पीबी और सचिव(सूचना और प्रसारण)के स्तर की समीक्षा बैठकों में उनके वित्तीय एवं भौतिक प्रचालनों के विकास की समीक्षा की जाती है।

दूरदर्शन

भारत में दूरदर्शन की शुरुआत, दिल्ली में एक प्रायोगिक प्रसारण के माध्यम से सितंबर 1958 में की गई जिसे बाद में 1965 में एक स्थायी सेवा के तौर पर जारी किया गया। 1976 तक दूरदर्शन आकाशवाणी का ही हिस्सा रहा, तत्पश्चात इसे अलग किया गया और महानिदेशक की अध्यक्षता में इसे अलग विभाग बना दिया

गया। रंगीन टीवी और राष्ट्रीय प्रसार की शुरुआत 1982 में की गई। तब से दूरदर्शन विश्व के प्रमुख सार्वजनिक प्रसारक के रूप में निरंतर प्रगति कर रहा है। निशुल्क डीटीएच सेवा के साथ, दूरदर्शन 31 चैनलों का संचालन करता है। दूरदर्शन का 66 स्टूडियो का क्षेत्रीय नेटवर्क है और देश के भू-भागीय रूप को देखते हुए दूरदर्शन ने देशभर में 1416 ट्रांसमीटर लगाए हैं। इसके 31 चैनल इस प्रकार हैं :

डीडी 1- राष्ट्रीय चैनल

डीडी न्यूज- समाचार चैनल

डीडी भारती- समृद्धि चैनल

डीडी स्पोर्ट्स- खेल चैनल

डीडी राज्य सभा- संसद चैनल

डीडी उर्दू- उर्दू भाषा चैनल

क्षेत्रीय भाषाओं के चैनल- कुल 11

मलयालम, (केरलम), तमिल (पोदिगई), उड़िया, तेलुगू, (सप्तगिरी), बंगाली (बांग्ला), कन्नड़ (चंदना), मराठी (सहयाद्रि), गुजराती, कश्मीरी (कशीर), उत्तर पूर्व, पंजाबी

राज्य नेटवर्क- 12

राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय

डीडी भारत - अंतरराष्ट्रीय चैनल

ज्ञान दर्शन- शैक्षिक चैनल

क्षेत्रीय नेटवर्क के माध्यम से दूरदर्शन देश की 92 प्रतिशत आबादी को अपने दायरे में लेता है।

आकाशवाणी और दूरदर्शन के अधिदेश, लक्ष्य और उद्देश्यों, नीतिगत ढांचे से संबंधित जानकारी अध्याय- 1 में दी गई है।

वर्ष 2011-12 के लिए दूरदर्शन के संदर्भ में वित्तीय लागत, प्रस्तावित उत्पादन और प्रस्तावित परिणाम की जानकारी अध्याय-2 में दी गई है, जो जम्मू-कश्मीर, निरंतर योजनाओं के उत्तर पूर्व विशेष पैकेज और कुछ नई योजनाओं के तहत दिए गए हैं। वार्षिक योजना 2011-12 के दौरान प्रत्यक्ष बजटीय सहयोग 697.39 करोड़ रुपये है जिसमें 483.39 करोड़ रुपए पूंजी घटक के तहत ट्रांसमीटरों, स्टूडियो के डिजिटलीकरण और एचडीटीवी के लिए है और 214.00 करोड़ रुपये जम्मू-कश्मीर के लिए विशेष योजना, उत्तर पूर्व के लिए विशेष पैकेज और सॉफ्टवेयर अधिग्रहण के लिए राजस्व योजना के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों के लिए कोई प्रोजेक्शन नहीं किया जाएगा। पूंजी योजना परियोजनाएं सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण द्वारा वित्त पोषित होती हैं जबकि राजस्व योजना परियोजनाएं अनुदान के रूप में प्रदान की जाती हैं (अध्याय-2)।

सार्वजनिक प्रसारक के रूप में संगठन के अधिक विकास से संबंधित नीतिगत फैसलों के आधार पर दूरदर्शन द्वारा विभिन्न पहल की गई हैं। इन्हें आम जनता की जरूरतों और विशेष लक्षित समूहों, जैसे अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति के कल्याण, महिला सशक्तीकरण और उत्तर पूर्व क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखकर लागू किया जाता है (अध्याय-3)।

वार्षिक योजना 2009-10 और 2010-11 (नवंबर 2010 तक) के दौरान भौतिक एवं वित्तीय प्रदर्शन की योजनागत विवरण अध्याय 4 में दिया गया है। वार्षिक योजना 2009-10 की स्वीकृत लागत 251.00 करोड़ रुपये थी और खर्चा 125.53 करोड़ रुपये था। इसी प्रकार वार्षिक योजना 2010-11 की कुल परिव्यय 157.00 करोड़ रुपये थी। वित्तीय वर्ष 2008-09 तक जारी किए गए अनुदान के संदर्भ में आवश्यक उपयोग सर्टिफिकेट (यूसी) प्रासंगिक नियमों के अनुसार प्रसार भारती (आकाशवाणी) द्वारा जुटाए गए हैं और कोई लंबित यूसी नहीं है।

गैर योजना के संदर्भ में प्रत्यक्ष बजटीय सहयोग के रूप में 1412.35 करोड़ रुपए का प्रावधान है और प्रसार भारती के लिए अनुवर्ती अतिरिक्त बजटीय संसाधनों/आईबीईआर के रूप में 1000 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। वर्ष 2010-11 का कुल व्यय 3162 करोड़ रुपये है जिसके परिणामस्वरूप 650 करोड़ रुपये का बजट अंतराल अपरिहार्य होता है।

वैधानिक और स्वायत्त निकाय के रूप में प्रसार भारती के प्रदर्शन की समीक्षा अध्याय- 4 में की गई है।

निरीक्षण प्रणाली

दूरदर्शन की परियोजनाओं की योजना, उनका प्रतिपादन और प्रणाली तैयार करने का काम दूरदर्शन निदेशालय का है। योजनाओं को दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई स्थिति जोनल कार्यालयों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में लागू किया जाता है। असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नगालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम राज्यों में गतिविधियों पर नजर रखने के लिए उत्तर पूर्व के लिए अलग जोन बनाया गया है जिसका मुख्यालय गुवाहाटी में है। लोक सेवा से संबंधित परियोजनाओं को आकाशवाणी और दूरदर्शन के लोक निर्माण खंड द्वारा लागू किया जाता है। परियोजनाओं से संबंधित प्रमुख गतिविधियों का निरीक्षण निदेशालय स्तर पर किया जाता है। जोनल चीफ इंजीनियर और चीफ इंजीनियर, सीसीडब्ल्यू परियोजनाओं की विभिन्न गतिविधियों का निरीक्षण करते हैं जो उनके क्षेत्र में आते हैं।

प्रत्येक वर्ष दूरदर्शन की सभी प्रमुख परियोजनाओं के संदर्भ में लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं जिनका निरीक्षण जोनल कार्यालयों और निदेशालय द्वारा किया जाता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि निश्चित लागत के साथ परियोजनाएं पूरी हो जाएं। लोक सेवा के विकास की समीक्षा के लिए जोनल चीफ इंजीनियर सीसीडब्ल्यू अधिकारियों के साथ नियमित बैठकें करते हैं। ई-इनसी स्तर पर नियमित रूप से निदेशालय के अधिकारियों, जोनल अधिकारियों और सीसीडब्ल्यू अधिकारियों के साथ परियोजना समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। दूरदर्शन के महानिदेशक और प्रसार भारती के सीईओ के स्तर की सावधि समीक्षा भी की जाती है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय दूरदर्शन की परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर नजर रखने के लिए समय-समय पर समीक्षा बैठकें भी आयोजित करता है।

ऐनीमेशन, गेमिंग और विशेष प्रभावों के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना

योजना स्कीम एनीमेशन, गेमिंग और विशेष प्रभावों के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए मानव संसाधन अध्ययन किया गया। अध्ययन के बाद उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की सिफारिश की गई। स्कीम की सैद्धान्तिक स्वीकृति के लिए मंत्रालय ने योजना आयोग से संपर्क किया था। योजना आयोग ने मंत्रालय से एक रिपोर्ट (एफआर) तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत करने का अनुरोध किया था। इस मंत्रालय प्रयोजनार्थ द्वारा नियुक्त सलाहकार ने एफआर/डी पी आर प्रस्तुत कर दी है जिस पर मंत्रालय में चर्चा चल रही है।

अध्याय-1

अधिदेश, लक्ष्य, उद्देश्य, नीतिगत ढांचा तथा नीति वक्तव्य

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की स्थापना फिल्मों को सार्वजनिक प्रदर्शन का प्रमाणपत्र देने के उद्देश्य से सिनेमेटोग्राफी अधिनियम, 1952 (1852 का 37) के तहत की गई थी। बोर्ड का मुख्यालय मुंबई में है तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बंगलुरु, तिरुअनंतपुरम, हैदराबाद, नई दिल्ली, कटक तथा गुवाहाटी में हैं। बोर्ड के कार्य इस प्रकार हैं :

(i) गैर प्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्म को प्रमाणपत्र देना (यू प्रमाणपत्र)

(ii) वयस्कों (जो 18 वर्ष के हो चुके हैं) के लिए फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रमाणपत्र देना (ए प्रमाणपत्र)

(iii) गैर-प्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए इस चेतावनी के साथ प्रमाणपत्र जारी करना कि 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे माता-पिता के साथ ही फिल्म देखने आएंगे (यूए प्रमाणपत्र)

(iv) किसी व्यवसाय विशेष के सदस्यों के लिए सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रमाणपत्र देना (एस प्रमाणपत्र)

इसके अलावा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड फिल्म को प्रमाणपत्र देने से पहले कुछ अंशों को हटाने का आदेश दे सकता है और बोर्ड प्रमाणपत्र देने से इंकार भी कर सकता है।

सीबीएफसी की वार्षिक योजना 2011-12 की स्कीमें निम्नलिखित हैं :

1. कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली की स्थापना तथा ढांचागत उन्नयन

स्कीम में एनआईसी की सहायता से सीबीएफसी के सभी कार्यों का कंप्यूटरीकरण करने का विचार है। ढांचागत उन्नयन के साथ तकनीकी उपकरण प्रदान करना भी है। 2011-12 के लिए स्वीकृत परिव्यय 100.00 लाख रुपये है।

2. नई दिल्ली, कटक तथा गुवाहाटी में क्षेत्रीय कार्यालय खोलना

नई दिल्ली, कटक तथा गुवाहाटी में इन क्षेत्रों में निर्मित फिल्मों के प्रमाणन के लिए सीबीएफसी कार्यालय खोलने की आवश्कता है। इन क्षेत्रों में बनाई गई फिल्मों के प्रमाणन के लिए इन कार्यालयों की स्थापना की गई है। बुनियादी सुविधाएं एवं मानवशक्ति प्रदान की जा रही हैं। नई दिल्ली, कटक और गुवाहाटी के क्षेत्रीय कार्यालयों में कर्मचारी और बुनियादी सुविधायें दिये गए हैं। 2011-12 के लिए स्वीकृत परिव्यय 50 लाख रुपये है।

3. प्रमाणन प्रक्रिया की निगरानी और आधुनिकीकरण

इस स्कीम के तहत प्रमाणन प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में बोर्ड बैठकों/कार्यशालाओं/बोर्ड और पैनल सदस्यों के लिए सम्मेलन आयोजित किया जाता है। प्रमाणन प्रक्रिया के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए और नये नियुक्त सदस्यों को इन चीजों की जानकारी देने के लिए कार्यशालाओं, सम्मेलनों और बोर्ड बैठकों का आयोजन किया जाता है। 2011-12 के लिए स्वीकृत परिव्यय 70 लाख रुपये है।

बाल फिल्म समिति, भारत

सीएफएसआई की विभिन्न गतिविधियां निम्नलिखित हैं :

1. निर्माण और खरीद : सीएफएसआई बच्चों तथा युवाओं के लिए फिल्म तथा वीडियो फॉरमेट में फीचर फिल्म, लघु फीचर फिल्म, एनीमेशन, लघु फिल्म, पपेट फिल्म तथा टीवी सीरियल बनाता है। संगठन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में लोकप्रिय रही कुछ फिल्मों के प्रदर्शन अधिकार भी खरीदता है। इन फिल्मों तथा समिति द्वारा निर्मित फिल्मों की विभिन्न भारतीय भाषाओं में डबिंग कराई जाती है।

2. फिल्म समारोह

क. अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह : सीएफएसआई हर दूसरे साल प्रतियोगी बाल फिल्म समारोह का आयोजन करता है। अंतर्राष्ट्रीय बाल एवं युवा फिल्म केंद्र जो कि दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों को नियंत्रित करने वाली यूनेस्को से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, ने इसे 'ए' श्रेणी में रखा है।

ख. अंतर्राष्ट्रीय बाल समारोहों में भागीदारी : सीएफएसआई की फिल्में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में प्रदर्शित हुई हैं, इससे विदेशों में बच्चों की फिल्मों को बढ़ावा देने में मदद मिली है। हर दूसरे साल होने वाले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में राष्ट्रीय डिजिटल फिल्म समारोह आयोजित करने का भी प्रस्ताव है।

3. आधुनिकीकरण तथा संवर्धन : सीएफएसआई ने अपने कार्यालय का कंप्यूटरीकरण किया है तथा मौजूदा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का उन्नयन किया जा रहा है।

4. एनिमेशन तथा फिल्म निर्माण पर कार्यशालाएं : सीएफएसआई बच्चों को फिल्म निर्माण के विभिन्न पहलुओं की जानकारी देने के लिए फिल्म निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया तथा एनीमेशन पर कार्यशालाएं आयोजित करती है। इनमें एनिमेशन कार्यशाला, पटकथा लेखन कार्यशाला, फिल्म समालोचना कार्यशाला तथा फिल्म निर्माण कार्यशालाएं शामिल हैं।

5. सीएफएसआई फिल्मों का डिजिटल रूपांतरण तथा वेबकास्टिंग : सीएफएसआई द्वारा (निर्मित, डब की हुई तथा उपशीर्षक सहित) सभी फिल्मों को अभिलेखन के उद्देश्य से डिजिटल रूप में रूपांतरित करना तथा उन्हें इंटरनेट/वेब पर उपलब्ध कराना

6. फिल्मों का प्रदर्शन और वितरण

क. निजी प्रदर्शन

कई स्कूल और व्यक्ति, स्कूलों या सिनेमाहॉल में 35 मिमी, 16 मिमी प्रोजेक्टरों के जरिए गैर व्यावसायिक प्रदर्शनों के लिए नियत शुल्क देकर इन फिल्मों को किराए पर लेते हैं।

ख. जिला और राज्य स्तर के समारोह

यह गतिविधि जिला प्रशासनों के साथ मिलकर की जाती है। विभिन्न राज्यों के कुछ जिलों को चिन्हित कर वहां मामूली प्रवेश शुल्क पर फिल्में दिखाई जाती हैं। सरकारी निगम, स्कूलों या जिला परिषद के स्कूलों में जाने वाले बच्चों को ये फिल्में देखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2007-08 से यह निर्णय लिया गया है कि सीएफएसआई फिल्मों के प्रदर्शन के लिए बच्चों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

ग. सिनेमाहॉल के बाहर मुफ्त प्रदर्शन

ग्रामीण और मनोरंजन के दूसरे साधनों से वंचित बच्चों तक पहुंचने के लिए सीएफएसआई ने सरकारी स्कूलों के बच्चों और आदिवासी बच्चों को मुफ्त फिल्में दिखाने की एक नई योजना शुरू की है। नेहरू युवा केंद्र संगठन जैसे गैर सरकारी संगठनों की इसमें मदद ली जा सकती है। मुफ्त प्रदर्शनों पर होने वाला खर्च सीएफएसआई, इस मद में सरकार से मिलने वाले सहायक अनुदान से पूरा करती है। इस योजना में सुधार गृहों, अनाथालयों आदि में रहने वाले बच्चों को भी फिल्में दिखाने का मौका दिया जाता है।

घ. वितरकों के जरिए प्रदर्शन

सीएफएसआई, स्कूल और सिनेमाहॉलों में फिल्मों के प्रदर्शन के लिए वितरकों/आयोजकों से भी सहयोग लेती है। यह एक तय मासिक शुल्क लेकर फिल्में ले लेते हैं और आवंटित क्षेत्र में उनका प्रदर्शन करते हैं।

च. टेलीविजन पर फिल्मों का प्रदर्शन

समिति की फिल्में दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क और क्षेत्रीय चैनलों के अलावा निजी चैनलों पर दिखाई जाती हैं।

छ. पूर्वोत्तर क्षेत्र और जम्मू-कश्मीर में गतिविधियां

समिति पूर्वोत्तर राज्यों सहित क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्मों के निर्माण पर कार्यशालाओं के आयोजन और प्रदर्शन के जरिए उन्हें प्रोत्साहन देती है।

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय में 207 क्षेत्रीय प्रचार इकाइयां कार्यरत हैं और देश भर में 22 क्षेत्रीय कार्यालयों के नियंत्रण में ये कार्यरत हैं। केन्द्र सरकार की इन नीतियों, कार्यक्रमों तथा योजनाओं पर उनका लक्ष्य और उद्देश्य केन्द्रित है जिनमें लोगों के उत्थान पर अधिक जोर दिया गया है। इस प्रकार इनके कार्यकाल देश के ग्रामीण, पिछड़े, सीमावर्ती तथा जनजातीय क्षेत्रों तक केन्द्रित हैं। बहुमाध्यम अभियानों, फिल्म प्रदर्शनों, फोटो प्रदर्शनियों, संगोष्ठियों, ग्रुप विचार-विमर्शों तथा विशेष वार्ता कार्यक्रमों जिनमें गोष्ठी, संगोष्ठी, रैलियां तथा ग्रामीण खेल आदि शामिल हैं, के माध्यम से संदेशों का प्रचार-प्रसार किया जाता है। निदेशालय के लक्ष्य और उद्देश्य मोटे तौर पर इस प्रकार हैं—

(1) लोगों और सामग्री को एक दूसरे के निकट लाकर सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को प्रस्तुत करना और उनके लाभ के लिए कार्यक्रमों और नीतियों के बारे में जानकारी देना।

(2) लोगों को लोकतंत्र, समाजवाद और धर्म निरपेक्षता के बुनियादी राष्ट्रीय मूल्यों की जानकारी देना तथा लगातार व्यक्तिगत संपर्कों के माध्यम से ऐसे मूल्यों में उनकी आस्था को दृढ़ बनाना।

(3) विकासात्मक गतिविधियों में सक्रिय, सहभागिता के लिए सबसे निचले स्तर के लोगों के साथ संपर्क स्थापित करना और कल्याण तथा विकास कार्यों पर अमल करने के संबंध में जनमत को भी सक्रिय करना।

(4) सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों तथा उनके कार्यान्वयन के बारे में लोगों की प्रतिक्रिया हासिल करना। इस प्रकार निदेशालय सरकार और जनता के बीच संचार के दो तरफा चैनल की तरह कार्य करता है।

विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय

विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) भारत सरकार की प्रमुख मल्टी मीडिया विज्ञापन एजेंसी है। यह विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की नीतियों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों को विभिन्न प्रचार माध्यमों के जरिए जनता तक पहुंचाने का काम करती है। डीएवीपी अनेक स्वायत्त संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रचार आवश्यकताओं को भी पूरा करती है। समाज से जुड़े संदेशों का आम आदमी तक पहुंचाने के लिए यह निम्नलिखित माध्यमों का सहारा लेती है-

(क) समाचारपत्रों में विज्ञापन

(ख) इलेकट्रनिक मीडिया श्रव्य/दृश्य स्पॉट, जिंगल्स इत्यादि,

(ग) मुद्रित प्रचार साहित्य, पुस्तिकाएं, ब्रोशर, पोस्टर इत्यादि,

(घ) बाह्य प्रचार माध्यमों - होर्डिंग्स, मेट्रो रेल पैनल, बस पैनल, कियोस्क, सार्वजनिक सुविधाएं इत्यादि।

(ङ) ग्रामीण तथा कस्बाई क्षेत्रों में भीड़भाड़ वाले इलाके जैसे कि मेले इत्यादि में फोटो प्रदर्शिनी

साफ्टवेयर, आफिस के बुनियादी ढांचे और कम्प्यूटर प्रशिक्षण इत्यादि।

कुल मिलाकर डीएवीपी कई वर्षों से सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन और विकास के क्षेत्र में उत्प्रेरक की भूमिका निभा रहा है और यह जनता के बीच जागरूकता निभाने, विकासात्मक गतिविधियों में जनता की भागीदारी प्राप्त करने और गरीबी तथा अन्य सामाजिक बुराइयों को खत्म करने में बेहद अहम भूमिका निभा रहा है। मुद्रित माध्यम प्रचार तथा श्रव्य-दृश्य प्रचार को भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी क्रमश: विज्ञापन नीति और दृश्य-श्रव्य प्रचार नीति के तहत किया जाता है। वेबसाइट www.davp.nic.in पर उपलब्ध चार्टर अपने ग्राहकों, नागरिकों आदि को मात्रातमक तरीके से सेवाएं देने का एक प्रयास है। डीएवीपी वर्तमान में अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच बार-बार गुणवता बोध के साथ ग्राहक समर्पित संगठन बनने के लिए तैयार कर रहा है। इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी, सेवाओं का व्यावसायीकरण तथा कार्य प्रक्रियाओं और ढांचे का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। आगे, मीडिया आउटलेट के लिए मंत्रालयों/विभागों की आवश्यकताओं के लिए मात्र डाक जर होने के स्थान पर डीएवीपी ऐसी सामग्री/विषयवस्तु को तैयार करने का लक्ष्य बना रहा है जोकि सरकारी सूचना और संचारी टूलों के लिए एकीकृत भूमिका निभा सके।

फिल्म समारोह निदेशालय

फिल्म समारोह निदेशालय को अच्छे सिनेमा को बढ़ावा देने तथा भारत में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों (आईएफएफआई) का आयोजन करने, देश और विदेश में भारतीय फिल्मों को बढ़ावा देने, फिल्म सप्ताहों का आयोजन तथा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

निदेशालय भारत में और विदेशों में सर्वश्रेष्ठ भारतीय सिनेमा को प्रदर्शित करने के प्रयास भी करता है। निदेशालय द्वारा आयोजित फिल्म समारोह भारत और विदेश के एक जैसी सोच वाले पेशेवरों के लिए विचार विनिमय और अपने दृष्टिकोण और अवधारणाओं को एक-दूसरे के साथ बांटने के एक मंच के रूप में कार्य करते हैं।

निदेशालय की गतिविधियां 'भारत और विदेशों में फिल्म समारोह के जरिए निर्यात संवर्धन' योजना के माध्यम से चलाई जाती हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

(क) भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह

(ख) भारत और विदेशों में आयोजित फिल्म समारोहों में भारतीय पैनोरमा फिल्मों की भागीदारी

(ग) भारतीय पैनोरमा फिल्मों का चयन

फिल्म समारोहों के जरिए निर्यात संवर्धन की योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के दृष्टिकोण से निदेशालय को एक तकनीकी रूप से सुसज्जित प्रिंट यूनिट, जो प्रिंटों की लम्बी अवधि तक भंडारण में मदद करेगी, प्रदान करने के लिए एक नई योजना का भी 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रावधान है।

इसके अलावा, सीरीफोर्ट फिल्म समारोह परिसर के रख-रखाव तथा देखभाल की जिम्मेदारी भी निदेशालय की है। परिसर में सुविधाएं/सुधार का कार्य 'फिल्म समारोह परिसर - संयोजन और बदलाव' योजना स्कीम के माध्यम से हाथ में लिया गया है।

फिल्म प्रभाग

भारत सरकार की जरुरतों के अनुसार वृत्तचित्र, एनिमेशन तथा लघु फिल्म बनाने तथा उनके वितरण की जिम्मेदारी फिल्म प्रभाग की है। इन वृत्तचित्रों, एनिमेशन तथा लघु फिल्मों का प्रयोग जनता तक सूचना पहुंचाने, उन्हें जानकारी देने, शिक्षित करने, प्रोत्साहित करने तथा सांस्कृतिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। फिल्म प्रभाग का मुख्यालय मुंबई में है। प्रभाग की एक उप इकाई दिल्ली में भी स्थित है जो समाज कल्याण मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय तथा अन्य सरकारी उपक्रमों द्वारा प्रायोजित विषयों पर फिल्म/वृत्तचित्र बनाता है। इसके अलावा प्रभाग के दो क्षेत्रीय कार्यालय एक बंगलुरु तथा दूसरा कोलकाता में हैं जो ग्रामीण विषयों पर मंनोरंजक तत्त्वों से युक्त फीचर/वीडियो फिल्में बनाते हैं। चौदह मुख्य कैमरामैन तथा दो सहायक कैमरामैन राज्यों की राजधानियों में तैनात किए गए हैं जो राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं, विशेष अवसरों तथा सांस्कृतिक विरासत की विस्तृत कवरेज करते हैं। फिल्मों का वितरण दस शाखा कार्यालयों के नेटवर्क द्वारा किया जाता है।

महाराष्ट्र सरकार तथा अन्य फिल्म इकाइयों के सहयोग से फिल्म प्रभाग अर्ध-वार्षिक अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह आयोजित करता रहता है। पिछला समारोह 3 से 9 फरवरी, 2010 तक आयोजित हुआ था। 12 वाँ मुंबई अन्तरारष्ट्रीय फिल्म समारोह 3 से 9 फरवरी. 2012 तक आयोजित होगा।

देश में डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के प्रोत्साहन तथा निर्माण के मद्दे नजर, फिल्म प्रभाग ने एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) पीएसबीटी से एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किए हैं। इसके माध्यम से बाहरी निर्माताओं को डॉक्यूमेंट्री बनाने का अवसर मिलता है। बाहरी निर्माताओं को 115 डॉक्यूमेंट्री फिल्मों को बनाने का कार्य सौंपा गया है तथा बाहरी निर्माताओं से प्राप्त 122 फिल्म प्रस्तावों में से 7 निर्माताओं को फिल्म बनाने का कार्य सौंपा जाएगा। फिल्म प्रभाग ने हाल ही में एक विज्ञापन के जरिए बाहरी निर्माताओं से फिल्म बनाने का प्रस्ताव आमंत्रित किया गया था जिसके फलस्वरूप अब तक 750 प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं।

भारत और विदेशों में आयोजित फिल्म बाजारों में भागीदारी

11वीं पंचवर्षीय योजना में मुख्य सचिवालय फिल्म स्कंध "फिल्मों का निर्यात और विपणन" का स्कीम के उप-घटक के रूप में "भारत और विदेशों में फिल्म बाजारों में भागीदारी" का कार्यान्वयन कर रहा हैं। "भारत और विदेशों में फिल्म बाजार में भागीदारी" घटक का कार्यान्वयन मंत्रालय के मुख्य सचिवालय द्वारा तथा "भारत और विदेशों में फिल्म समारोहों द्वारा निर्यात संवर्हन" का कार्यान्वयन फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा किया जा रहा है।

वित्त वर्ष 2011-12 से भारत और विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म बाजारों मं भागीदारी का कार्य राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) को सौंपा गया है। ऐसे योजनाबद्ध ढंग से स्कीम का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। चूंकि एनएफडीसी ही ऐसी राष्ट्रीय निकाय है जिसे विदेशों में फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने का अनुभव है, अतः इसे इस कार्य के लिए चुना गया है।

भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे

इस संस्थान की स्थापना 1960 में फिल्म निर्माण कला और तकनीक में प्रशिक्षण के लिए की गई थी। 1974 से इसने दूरदर्शन कर्मचारियों को फिल्म निर्माण में प्रशिक्षित करने का काम शुरू किया और इसका नाम भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कर दिया गया। यह अपने ढंग का अग्रणी संस्थान है और फिल्म निर्माण एवं टेलीविजन प्रशिक्षण की पूरी जिम्मेदारी संभाले हुए है।

क्र.सं.	पाठ्यक्रम	वर्तमान में छात्रों की संख्या
(क).	फिल्म एवं टेलीविजन में तीन वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम	
1.	निर्देशन	50
2.	सिनेमेटोग्राफी (फिल्म एवं टेलीविजन)	50
3.	संपादन (फिल्म एवं टेलीविजन)	47
4.	ऑडियोग्राफी (फिल्म एवं टेलीविजन)	36
(ख).	दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम	
1.	अभिनय	40
2.	कला निर्देशन तथा निर्माण डिजाइन	24
(ग).	एमीमेशन एवं कंप्यूटर ग्राफिक्स में डेढ़ वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	24
(घ).	टेलीविजन में एक वर्षीय प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	
1.	निर्देशन	11
2.	इलेक्ट्रॉनिक सिनेमेटोग्राफी	11
3.	वीडियो संपादन	11
4.	ऑडियोग्राफी एवं टेलीविजन इंजीनियरिंग	09
(ई).	फीचर फिल्म पटकथा लेखन में एक वर्षीय स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	13
	कुल	**326**

लघु पाठ्यक्रम

एफटीआईआई कार्यरत पेशेवरों और संबंधित क्षेत्र में दिलचस्पी रखने वालों के लिए विभिन्न लघु पाठ्यक्रम चलाता है।

योजना स्कीमें

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित दो स्कीमों को प्रस्तावित किया गया है :

(क) जारी स्कीम

I. एफटीआईआई, पुणे को अनुदान सहायता

II. मशीनरी और उपकरण

III. एफटीआईआई, पुणे का कंपयूटरीकरण औक आधुनिकीकरण

IV. सामुदायिक रेडियो की स्थापना

V. केप्टिव टीवी चैनल की स्थापना

VI. विद्यार्थियों के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ छात्रवृत्ति और आदान-प्रदान कार्यक्रमों सहित एचआरडी आयाम।

(ख) नई स्कीम

ग्लोबल फिल्म स्कूल (नई)

(क) जारी स्कीम

एफटीआईआई, पुणे को अनुदान सहायता : स्कीम का उद्देश्य ढांचागत कमी से उबरना और उद्योग में बेहतर वातावरण के साथ उपलब्ध प्रशिक्षण सुविधाओं को बढ़ाना है। इस स्कीम के लाभार्थी सीधे तौर पर विद्यार्थी और प्रशिक्षु हैं।

मानव संसाधन विकास से संबंधित योजना में संस्थान के छात्रों तथा संकाय सदस्यों के लिए लाभ बढ़ाने के संबंध में परिणाम के साथ कुछ प्राथमिक प्रयास किए गए हैं। हालांकि इस मौजूदा योजना के कुछ तत्वों को अधिकतम लाभ की दिशा में पुनर्आकार देने की आवश्कता हो सकती है, इसको जारी रखने की आवश्यकता है।

(ख) नई स्कीम

ग्लोबल फिल्म स्कूल (नई): ग्लोबल फिल्म स्कूल का विचार और प्रस्ताव अंर्तराष्ट्रीय छात्रों को आकर्षित करने की दिशा में ढांचा उन्नयन तथा एफटीआईआई को अंतर्राष्ट्रीय परिसर में विकसित करने के लिए संस्थान के पाठ्यक्रम को अद्यतन करता है। उद्देश्य विश्वभर के छात्रों को एफटीआईआई पुणे तक आकर्षित करना तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त फिल्म स्कूल के साथ छात्र आदान-प्रदान की अनुमति प्रदान करना है। जिसके लिए एफटीआईआई द्वारा दिए गए श्रेय को मान्यता की आवश्कता होगी।

एफटीटीआई को वैश्विक मानकों के अनुरूप उन्नत बनाने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है तथा शीघ ही इसे अनुमति के लिए मंत्रालय में पेश किया जाएगा।

सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता

फिल्म तथा टेलीविजन कार्यक्रमों की विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षित मानवशक्ति उपलब्ध कराने के मकसद से भारत सरकार ने एक स्वायत्त शैक्षणिक संस्थान के रूप में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन कोलकाता के सत्यजीत राय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान की स्थापना की थी और यह प्रसारण और सूचना मंत्रालय एवं पश्चिम बंगाल सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1961 के तहत पंजीकृत है। कोलकाता में संस्थान की स्थापना का विशेष उद्देश्य पूर्वी तथा उत्तरपूर्वी भारत के लिए फिल्म एवं टेलीविजन निर्माण में शिक्षा प्रदान करना है। संस्थान का प्राथमिक मूल उद्देश्य छात्रों के लिए फिल्म और टेलीविजन पर विभिन्न पाठ्यक्रम चलाना है। प्रति वर्ष यहां से लगभग 40 छात्र निकलते हैं। टेलीविजन उद्योग के लिए और फिल्म उद्योग के लिए प्रशिक्षित मानव शक्ति प्रदान करना मुख्य उद्देश्य है।

भारत सरकार द्वारा स्थापित संस्थान, निर्देशन और पटकथा लेखन, चलचित्र छायाकंन, संपादन और ध्वन्यांकन में तीन साल का स्नातकोत्तर डिप्लोमा कोर्स कराता है। फिल्म तथा टेलीविजन से जुड़े अन्य क्षेत्रों में बुनियादी डिप्लोमा कोर्सों के अतिरिक्त समाजशास्त्र, संस्कृति और फिल्म तथा टेलीविजन टेक्नोलाजी के बारे में अनुसंधान और खोजी अध्ययनों पर भी यह संस्थान ध्यान देता है। कक्षा की पढ़ाई के अतिरिक्त, प्रसिद्ध फिल्मी हस्तियों द्वारा विभिन्न कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं।

विभाग-वार वर्तमान छात्र संख्या निम्नलिखित तालिका में दर्शाई गई है :

बैच	**07-10**	**08-11**	**09-13**	**कुल**
निर्देशन	9	10	9	28
सिनेमेटोग्राफी (एमपीपी)	10	10	10	30
संपादन	10	10	10	30
ऑडियोग्राफी (साउंड)	8	9	7	24
कुल	**37**	**39**	**36**	**112**

बुनियादी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के अलावा संस्थान, विभिन्न संगठनों और फिल्म उद्योग की मांग पर विभिन्न अल्पावधि पाठ्यक्रम और विभिन्न परियोजनाएं हाथ में लेता है।

योजना स्कीम

प्रारंभ में आधारभूत ढ़ाचा के कारण संस्था में मात्र एक ही बैच चलाना पड़ता है। आगामी बैचो को आगे पढ़ाया जायेगा लेकिन बुनियादी सुविधाएं नहीं बढ़ने के कारण संस्थान में जबरदस्त सुविधाओं और लोगों के अभाव में तीन बैच चलाना मुश्किल हो रहा है। पर्याप्त सुविधाएं एवं लोगों के ने होने पर शैक्षिक सत्र में देरी के कारण छात्रों में अंसतोष फैल रहा था। चालू वर्ष के प्लान योजना में मुख्य लक्ष्य पर्याप्त बुनियादी सुविधा का सृजन करना है।

एसआरएफटीआई, कोलकाता की अनुदान सहायता की योजना स्कीम

संस्थान ने 10वीं योजना के दौरान शुरू की गई उन विभिन्न स्कीमों को 11वीं पंचवर्षीय योजना में संस्थान के एकल सहायता अनुदान में मिला दिया है जो अभी चल रही हैं। इनमें से प्रत्येक स्कीम का संक्षिप्त परिणाम नीचे दिया गया है :

11वीं पंचवर्षीय योजना में सहायता अनुदान स्कीम में निम्नलिखित भाग हैं :

क्र.सं.	स्कीम/परियोजना का नाम
(क)	**जारी स्कीम**
1.	सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना
2.	केप्टिव टीवी सॉफ्टवेयर निर्माण केंद्र की स्थापना
3.	प्रशिक्षण और कौशल विकास डब्ल्यु.आर.टी सामाजिक सुसंगत फिल्म निर्माण
4.	छात्रवृत्ति, छात्र/संकाय आदान प्रदान कार्यक्रम
5.	मानवशक्ति सहित ढांचागत प्रावधानों के साथ कंप्यूटरीकरण, आधुनिकीकरण
(ख)	**नई स्कीम**
1.	एनीमेशन तथा इलेक्ट्रानिक इमेजिंग विभाग
2.	फिल्म एवं टेलीविजन में निर्माण प्रबंधन विभाग

जारी स्कीम

सामुदायिक रेडियो स्टेशन

सामुदायिक रेडियो स्टेशन (सीआरएस) की स्थापना संस्थान में एफएम आधारित रेडियो स्टेशन के रूप में इस विचार से की गई कि छात्रों को ऑन-लाइन प्रसारण में प्रशिक्षण दिया जा सके। एफ एम चैनलों की बढ़ती लोकप्रियता जन शिक्षा और मनोरंजन, स्थानीय रुचियों और स्टाइल के मनमाफिक तैयार कार्यक्रमों के लिए एक प्रभावी मीडिया के रूप में स्थानीय प्रसारण प्रणालियों के संचालन की उर्वर भूमि की मौजूदगी दर्शाती है। अपने मौजूदा तैयार ढांचे तथा युवा, ओजस्वी छात्र संसाधन के साथ एसआरएफटीआई सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना तथा सफलतापूर्वक इसे चलाने के लिए उपयुक्त स्थान है। परियोजना को ताकत निम्नलिखित से मिलती है :

- संपूर्ण प्रसारण प्रणाली का कार्य बिना किसी व्यक्ति की मौजूदगी में, स्वत: किया जाता है।
- समाज की अत्यावश्यक विषयों को प्रायोगिक प्रशिक्षण द्वारा प्रभावी प्रचार द्वारा सूचित करना।
- छात्रों के खाली समय में एक अन्य तरह की गतिविधियों का निर्माण करना।
- बुनियादी सुविधा, उपकरणों एवं उपलब्ध साधनों को सकारात्मक उपयोग करना।

स्कीम का उद्देश्य संस्थान में दिए जा रहे प्रशिक्षण की गुणवत्ता में मूल्य वर्धन के साथ इस क्षेत्र में भविष्य के रोजगार तथा उत्कृष्टता के विस्तार को अनिवार्य रुप से बढ़ाना है। यद्यपि, एक बार परियोजना शुरू हो गई तब प्रायोजक मिलने की संभावना है जिससे पूरी अथवा आंशिक निर्माण लागत निकल आएगी जो सरकारी विभाग एवं अंतरराष्ट्रीय संस्था करती है।

केप्टिव टीवी सॉफ्टवेयर केंद्र की स्थापना

प्रस्तावित केप्टिव टी वी सॉफ्टवेयर निर्माण केंद्र में प्रारंभिक विकसित केप्टिव टेलीविजन (सूक्ष्म कास्टिंग) का विकास दूरदर्शन द्वारा विशेष दर्शकों के लिए प्रसारण हौगा। परियोजना का उल्लेखनीय उद्देश्य ऑन-लाइन टेलीकास्ट की कला और तकनीक की शुरुआत करना है और छात्रों को दिए जा रहे प्रशिक्षण में गुणवत्ता बढ़ाना है। इसमें अनिवार्य रूप से कम शक्ति/उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों (एलपीटी/एचपीटी) के जरिए प्राप्त किए गए दैनिक/साप्ताहिक स्लॉट में प्रसारण के लिए छात्रों और शिक्षकों द्वारा टीवी सॉफ्टवेयरों का निर्माण शामिल है। कार्यक्रम मुख्य रूप से स्थानीय रुचियों के हिसाब से परिवार कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा मनोरंजन के सामाजिक मुद्दों से संबंधित होते हैं।

डब्ल्यु.आर.टी. सामाजिक संदर्भ वाले फिल्म निर्माण का प्रशिक्षण और कौशल विकास

संस्थान राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से चुने गए 120 प्रतियोगी युवाओं के लिए फिल्म एवं टेलीविजन में तीन वर्षीय पीजी डिप्लोमा कार्यक्रम संचालित करता है। परियोजना का उद्देश्य इस क्षेत्र में प्रशिक्षण पा रहे युवा छात्रों के लिए प्रशिक्षण में अति वांछित मूल्य जोड़ना है। इस स्कीम के तहत संस्थान की मौजूदा प्रशिक्षण गतिविधियों में प्रस्तावित तत्वों से छात्रों को इस उद्योग की कठिनाइयों से सामना करने में सहायता मिलेगी।

छात्रवृत्ति छात्र/संकाय आदान प्रदान कार्यक्रम

स्कीम का उद्देश्य संस्थान के छात्रों के लिए एक सहयोगी आधार तैयार करना है जहां विदेशी प्रतिष्ठित फिल्म स्कूलों के साथ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सवों/फोरमों तथा छात्र आदान प्रदान कार्यक्रमों के जरिए फिल्म निर्माण की उभरती प्रौद्योगिकी तथा तकनीकों से परिचित कराना है। प्रस्तावित योजना के तहत संस्थान में प्रशिक्षण गतिविधियों द्वारा युवा छात्रों को विभिन्न चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करता है। फिल्म एवं टीवी उद्योग में प्रशिक्षण मनोरंजन उद्योग में हालिया प्रौद्योगिकीय बदलावों को समझने में यह स्कीम शिक्षकों की भी मदद करेगी। स्कीम में प्रतिभाशाली छात्रों के लिए छात्रवृत्ति तथा विदेशी उद्योगों और फिल्म उद्योगों के साथ आदान-प्रदान कार्यक्रम शामिल हैं।

मानव शक्ति सहित ढांचे के कंप्युटरीकरण, आधुनिकीकरण का प्रावधान

संस्थान का मुख्य उद्देश्य फिल्म और टेलीविजन मीडिया के लिए प्रशिक्षित मानव शक्ति प्रदान करने के लिए फिल्म और टीवी पर विभिन्न पाठयक्रमों में प्रशिक्षण देना है। इसमें सभी कुछ कम्प्यूटर द्वारा किया जाता है लेकिन लोगों की कमी दर्ज की गई है।

नई स्कीम

ऐनीमेशन और इलेक्ट्रॅनिक इमेजिंग विभाग

पिछले कुछ सालों में दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के निर्माण की दुनिया में जबरदस्त परिवर्तन आया है। एक प्रमुख क्षेत्र जिसमें उल्लेखनीय विकास हुआ है, वह ऐनीमेशन और मल्टी-मीडिया प्रयोगों का है। एनीमेशन की लोकप्रियता और संभावनाओं के बारे में हर कोई जानता है और इस बारे में अलग से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। वेब से जुड़े प्रयोगों और एनीमेशन फिल्मों के साथ-साथ मल्टी मीडिया सीडी-रोम्स/गेम्स का एक विशाल गतिशील और संभावनाओं से भरा बाजार मौजूद है। अगले कुछ सालों में भारत एनीमेशन से जुड़े काम के लिए एक प्रमुख केंद्र बन जाएगा। इन गतिविधियो में मदद करने वाले प्रशिक्षित मानव संसाधन की भारी मांग है।

भारत सरकार के नियमानुसार संस्थान में 'एनीमेशन और इलेक्ट्रानिक इमेजिंग' में दो साल का एक स्नातकोत्तर डिप्लोमा कोर्स प्रारंभ करने का प्रस्ताव किया है जिसमें प्रत्येक बैच में 10-10 छात्रों का लेने का प्रस्ताव है। अनुमानत: 11 वीं पंचवर्षीय योजना में अंतिम वर्षो में वांछित सुविधाएं और लोगों की भर्ती होगी। नई बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है जहां नए विभाग की स्थापना की जाएगी।

फिल्म तथा टेलीविजन कार्यक्रम प्रबंध विभाग

एक सफल कार्यक्रम के निर्माण के लिए सभी विविधताओं को एक व्यविस्थित और किफायती एकजुटता में उसमें कुशल और पेशेवर प्ररबंधन को लाने के लिए मीडिया के कार्यकलापों के बारे में व्यावहारिक ज्ञान रखने वाले योग्यता प्राप्त प्रबंधकों का होना अनिवार्य है। ये प्रबंधक व्यापार से जुड़ा अनुशासन और पारदर्शिता लाने में कामयाब हो सकेंगे जिससे कार्यक्रम निर्माण आर्थिक दृष्टि से व्यावहारिक हो सकेगा। चूंकि आज विशेषज्ञता का युग है, इसलिए उद्योग की जरूरतों के अनसार मानव संसाधनों को प्रशिक्षित और प्रयोग करना जरूरी हो गया है। ढांचा और व्यक्तियों की भर्ती के बाद प्रत्येक बैच में 10–10 छात्र लिए जाएंगे। 11वीं पंचवर्षीय योजना के 5वें वर्ष में बिल्डिंग का कार्य जोरों से चल रहा है। संस्थान में 2011 से फिल्म और टीवी में निर्माण प्रबंधन का नया पाठ्यक्रम शुरू करने का इरादा है।

गैर योजना

संस्थान का मुख्य उद्देश्य फिल्म एवं टीवी उद्योग के लिए प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध कराना है। संस्थान निर्देशन और पटकथा लेखन, साउंड रिकार्डिंग, मोशन पिक्चर फोटोग्राफी, एडीटिंग एवं साउंड रिकार्डिंग में प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। तीन बैचों में कुल 120 छात्र हैं। नियमित गतिविधियों में निरंतरता, लघु फिल्म, वृत्तचित्र, पार्श्वगायन तथा डिप्लोमा फिल्में बनाने जैसी परियोजनाएं हैं। कक्षा में फिल्मी हस्तियों द्वारा कार्यशालाएं आयोजित कराई जाती हैं। 37 छात्र अपनी फिल्म परियोजनाएं पूरी करने वाले हैं। परियोजना अवधि में 30 मिनट की 10 लघु फिल्में बनाई जानी हैं। पहले वर्ष के बैच की पढ़ाई और प्रोजेक्ट का कार्य आरंभ हो गया है। इस अवधि में 2011 के लिए नए प्रवेश किए जाएंगे। गैर–योजना खर्च के तहत संस्थान का बुनियादी ढांचा बनाए रखने की जरूरत है ताकि संस्थान के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके।

भारतीय जन संचार संस्थान

आईआईएमसी 17 अगस्त, 1965 को अस्तित्व में आया। इस संस्थान का उद्घाटन भारत की पूर्व प्रधानमंत्री और तत्कालीन सूचना व प्रसारण मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। इस संस्थान की स्थापना जन संचार के क्षेत्र में शिक्षण, प्रशिक्षण और शोध कार्य के उद्देश्य से की गई थी। यूनेस्को के दो परामर्शदाताओं समेत कुछ कर्मचारियों के साथ शुरू किया गया था जिसमें मुख्य तौर पर केन्द्रीय सूचना सेवा अधिकारियों के लिए पाठ्यक्रम और छोटे स्तर पर शोध अध्ययन का आयोजन होता था लेकिन पिछले लगभग 45 वर्षों में यह संस्थान आधुनिक समय में तेजी से बढ़ते हुए और बदलते हुए मीडिया एवं संचार उद्योग की विविध और बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई कोर्स आयोजित करने वाला संस्थान बन गया।

हाल के समय में जन संचार में काफी बदलाव आया है और यह निर्णय लेने की प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाली गतिविधि के एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में उभरा है। सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति ने मास मीडिया के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान किया है। इसने इस विधा के छात्रों, शिक्षकों और प्रयोगकर्ताओं के लिए बड़ी चुनौतियां भी खड़ी की हैं। तेजी से बदलती हुई प्रौद्योगिकी इस विद्या के पूरे रंग को एक ऐसे रूप में बदल रही है जिसके बारे में शैक्षणिक गतिविधि के किसी अन्य क्षेत्र में कोई जानकारी नहीं है। निस्संदेह समय की मांग है मीडिया और संचार के निर्वाह और प्रभाव क्षमता को बढ़ाने के लिए आने वाली चुनौतियों का कारगर ढंग से जवाब देना।

यह संस्थान एक ऐसे सूचना ढांचे के निर्माण और उसकी मजबूती में योगदान करता है जो न केवल भारत बल्कि अन्य विकासशील देशों की आवश्यकताओं के लिए भी अनुकूल होता है। यह संस्थान देश के और विदेश के अन्य संस्थानों/निकायों को अपनी विशेषज्ञ और परामर्श सेवाएं प्रदान करता है। भारतीय जनसंचार संस्थान केन्द्रीय/राज सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों, विश्वविद्यायों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों से प्राप्त किए गए अनुरोध के जवाब में प्रशिक्षण, शोध और परामर्श सेवा प्रदान करता है।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियों की बढ़ती लोकप्रियता और क्षेत्रीय आकांक्षा को पूरा करने के लिए इस संस्थान ने पूर्वी क्षेत्र की मांगों को पूरा करने के लिए 1993 में उड़ीसा के ढेंकनाल में एक शाखा खोली। वर्तमान में इस शाखा में दो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पत्रकारिता (अंग्रेजी) और पत्रकारिता (ओड़िया) का आयोजन किया जाता है।

भारत सरकार सूचना व प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से भारतीय जन संचार संस्थान को वित्तीय सहयोग प्रदान कर रहा है। इस संस्थान की गतिविधियों का मार्ग निर्देशन इसकी कार्यकारी परिषद द्वारा किया जाता है। सूचना व प्रसारण मंत्रालय के सचिव इस कार्यकारी के अध्यक्ष होते हैं और इस संस्थान (सोसायटी) के भी अध्यक्ष होते हैं। इस परिषद के अन्य सदस्यों में अन्य लोगों के साथ-साथ दुनिया की विख्यात हस्तियां शामिल हैं।

शैक्षणिक कार्यक्रम

संस्थान की गतिविधियां तीन क्षेत्रों – शिक्षण, प्रशिक्षण और शोध पर केंद्रित है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संस्थान में निम्नलिखित पाठ्यक्रमों कासंचालन किया जाता है।

1. भारतीय सूचना सेवा (ग्रुप ए और बी) के अधिकारियों के लिए पाठ्यक्रम

2. नई दिल्ली और ढेंकनाल में पत्रकारिता (अंग्रेजी) का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

3 पत्रकारिता (हिन्दी) का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम,

4 विज्ञापन और जनसंपर्क में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

5. रेडियो और टेलीविजन पत्रकारिता का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

6. पत्रकारिता (ओड़िया) का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, और

7. विकास पत्रकारिता में डिप्लोमा पाठ्यक्रम

क्रम संख्या-7 का पाठ्यक्रम विकासशील देशों के कार्यरत पत्रकारों और सूचना अधिकारियों के लिए है। अफ्रीका, एशिया और लातिन अमरीका के मध्य स्तर पर कार्यरत पत्रकार इस पाठ्यक्रम में शामिल होने के बेहद इच्छुक रहते हैं। प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रत्येक वर्ष औसतन 20-25 लोगों को दाखिला दिया जाता है। वर्तमान में प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में दो पाठ्यक्रमों का संचालन होता है।

ये पाठ्यक्रम आईटीसी/एससीएएपी योजना के तहत विदेश मंत्रालय के वित्तीय सहयोग से संचालित होते हैं।

संस्थान ने भारतीय नागरिकों के लिये प्रदान किये जाने वाले डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) संबंधी आरक्षण के अंतिम चरण को लागू कर दिया है।

भारतीय सूचना सेवा के लिए बुनियादी पाठ्यक्रम

आई आई एम सी, भारतीय सूचना सेवा (आई आई एस) के अधिकारियों के प्रशिक्षण का प्रमुख केंद्र है। यह संस्थान इस सेवा के अधिकारियों को संचार तकनीकों को सीखने का अवसर देता हैं तथा उन्हें जन सूचना प्रणाली के प्रति अभिमुख करता है। पाठ्यक्रम में सूचना नीतियों और रणनीतियों पर विशेष फोकस है।

अल्पकालीन पाठ्यक्रम, कार्यशाला, संगोष्ठी और सम्मेलन

भारतीय जन संचार संस्थान द्वारा भारत और विकासशील देशों के परिप्रेक्ष्य में जन संचार के मुद्दों की बेहतर समझ के प्रति सहयोग की दृष्टि से संचार के विभिन्न विषयों पर संगोष्ठी और सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। संस्थान, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न मीडिया इकाइयों के कार्मिकों के लिए नियमित और लघु-अवधि के पाठ्यक्रमों को चलाता है। रक्षा अधिकारियों और केंद्र/राज्य और निजी क्षेत्र के विभिन्न मीडिया/सूचना संगठनों में कार्य कर रहे कर्मिकों के लिए एक सप्ताह से तीन माह तक की अवधि वाले कई अल्पकालिक पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

शोध व प्रकाशन

भारतीय जन संचार संस्थान जन संचार शोध का एक शीर्ष केन्द्र रहा है। इन वर्षों में संस्थान ने कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों, सरकार और गैर सरकारी निकायों के लिए प्रमुख शोध अध्ययनों का आयोजन किया है। संस्थान ने पहले 165 से भी अधिक शोध व मूल्यांकन अध्ययन आयोजित किए हैं और इसके अलावा यहां अनेक शोध-निर्बंध तैयार किए गए हैं। इसके द्वारा आयोजित किए जाने वाले अधिकांश शोध अध्ययनों को प्रायोजकों द्वारा वित्त प्रदान किया जाता है। यह संस्थान अपनी वार्षिक योजनाओं के हिस्से के रूप में मास मीडिया से संबंधित मुद्दों के विविध पहलुओं पर भी शोध अध्ययन आयोजित करता है।

संस्थान अंग्रेजी में कम्यूनिकेटर और हिन्दी में संचार माध्यम अर्द्धवार्षिक पत्रिकाओं को प्रकाशित करता है। यह लेबोरेटरी पत्रिकाओं (विभिन्न डिप्लोमा कोर्सों के छात्रों द्वारा) जैसी अन्य पत्रिकाओं को अपनी गतिविधियों पर एक वार्षिक रिपोर्ट और पत्रकारिता/जनसंचार पर पुस्तकों को प्रकाशित करता है।

योजनाएं

1. चार राज्यों - जम्मू एवं कश्मीर, मिजोरम, महाराष्ट्र (विदर्भ) और केरल में आईआईएमसी की चार शाखाओं की स्थापना

2. आईआईएमसी को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार उन्नत बनाना

3. अकादमी वर्ष 2011-12 से आईआईएमसी के पी जी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को दो साल की अवधि वाले पाठ्यक्रमों में बदलने का प्रस्ताव है ताकि इन पाठ्यक्रमों को मास्टर डिग्रियों के समतुल्य बनाया जा सके।

शोध अध्ययन

संस्थान ने वर्ष 2009-10 के दौरान 4 जारी अध्ययनों को पूरा कर लिया है। इन अध्ययनों को पूरा करने के अलावा संस्थान ने सूचना व प्रसारण मंत्रालय के अनुरोध पर नीति के मुद्दों और भारत में विदेशी समाचार एजेंसियों के न्यूज ऑपरेशन नामक एक नया प्रायोजित अध्ययन भी शुरू किया है।

कुछ और अध्ययन मौजूदा वित्त वर्ष की शेष अवधि के दौरान किये जाने का प्रस्ताव है।

भारत का राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय

विश्व भर में कलाकृतियों और ऐतिहासिक दस्तावेजों के रूप में फिल्मों को संरक्षित करने की आवश्यकता महसूस की गई है। सिनेमा को उसकी सभी विविधतापूर्ण अभिव्यक्तियों और स्वरूपों के साथ संरक्षित करने का दायित्व किसी ऐसे राष्ट्रीय संगठन को दिया जाता है जिसके पास पर्याप्त संसाधन, एक स्थाई व्यवस्था और फिल्म उद्योग का आत्मविश्वास जोकि फरवरी 1964 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वतंत्र मीडिया इकाई के रूप में स्थापना हुई थी। इसके लिए, एनएफएआई की एक योजना स्कीम है। स्कीम के अंतर्गत एनएफएआई अपने अभिलेखागार में फिल्मों का डिजिटाइजेशन और जीर्णोद्धार भी कर रही है। 'द रीस्टोरेशन ऑफ मास्टर्स' कार्य को प्राथमिकता के रूप में लिया गया है।

भारत के राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय के लक्ष्य और उद्देश्य :

(क) राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय की विरासत का पता लगाना, अर्जित करना और संरक्षित करना तथा विश्व सिनेमा का प्रतिनिधित्व संग्रह बनाना (ख) फिल्म संबंधी डाटा को वर्गीकृत और प्रायोजित करना, सिनेमा पर शोध करना और प्रोत्साहित करना एवं प्रकाशित करना तथा उसे वितरित करना (ग) देश में फिल्म संस्कृति के प्रसार के केंद्र तथा विदेशों में भारतीय सिनेमा की सांस्कृतिक उपस्थिति सुनिश्चित करने के केंद्र के रूप में कार्य करना।

क्रियान्वयन के अंतर्गत स्कीमों/कार्यक्रमों के नाम:

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं. स्कीम/कार्यक्रम का नाम	स्वीकृत 11वां योजना परिव्यय 2007-2012	एस.बी.जी. 2009-10	आर.ई. 2009-10	अंतिम अनुदान 2009-10	2009-10 के दौरान वास्तविक व्यय
जारी स्कीम					
अभिलेख फिल्मों की प्राप्ति और प्रदर्शन	30.00	4.00	7.00	7.00	6.99
कुल	**30.00**	**4.00**	**7.00**	**7.00**	**6.99**

वास्तविक उपलब्धियां

वर्ष 2009-10 के दौरान, एनएफएआई ने 505 फिल्में, 434 डीवीडी, 366 पुस्तकें, 3420 स्टिल्स, 1541 वाल पोस्टर, 192 गीत पुस्तिकाएं, 247 पेंफलेट्स/फिल्म फोल्डर, 25 डिस्क रिकार्ड, 148 डिजिटाइजड फिल्में, 48 रिस्टार्ड फिल्में तथा 2,08,5392 अनुषंगी सामग्री प्राप्त की।

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड

1. भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय एजेंसी राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड (एनएफडीसी) की स्थापना भारतीय फिल्म उद्योग की वृद्धि को प्रोत्साहित करने और सिनेमा में श्रेष्ठता को प्रोत्साहित करने के लिए की गयी है।

2. एनएफडीसी द्वारा वित्त पोषित/निर्मित फिल्मों और उनके निर्माण से संबंधित कलाकारों ने पूर्व में अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किये हैं। एनएफडीसी (पूर्ववर्ती फिल्म वित्त निगम सहित), ने अब तक करीब 300 ऐसी फिल्मों का निर्माण/सहनिर्माण/वित्तपोषण किया है। भारतीय फिल्म उद्योग ने विभिन्न भारतीय भाषाओं में सिनेमा को समाविष्ट किया है और 17 से अधिक फिल्मों का अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ सह-निर्माण करने वाला निगम एक मात्र निर्माता है।

3. एनएफडीसी का लक्ष्य उत्कृष्ट फिल्मों को बढ़ावा देना और विभिन्न भारतीय भाषाओं में बनी फिल्मों द्वारा भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना है।

4. नई गतिविधियों के माध्यम से भारत के सिनेमा को बढ़ावा देने की अपनी वचनबद्धता को नया रूप देने का प्रस्ताव है। अपने मौजूदा कार्य के अतिरिक्त, 11वीं योजना अवधि में फिल्म निर्माण के लिए 36 करोड़ रुपये सरकार ने स्वीकृत किए हैं। निगम की 77 फिल्मों के जीर्णोद्धार के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया है।

पत्र सूचना कार्यालय

पत्र सूचना कार्यालय भारत सरकार की उन प्रमुख एजेंसियों में से एक है जिनका कार्य नीतियों, कार्यक्रमों और विभिन्न क्षेत्रों में सरकार की उपलब्धियों के बारे में सूचनाएं उपलब्ध कराना है। वर्तमान में इसके आठ क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, भोपाल, चंडीगढ़, गुवाहाटी, लखनऊ और हैदराबाद में स्थित हैं। इसके 27 शाखा कार्यालय, 5 कार्यालय-सह-सूचना केंद्र और दो सूचना केंद्र हैं जो देश भर में फैले हुए हैं। इन स्थानों से अनेक पत्र-पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं और नित्य प्रति बड़ी संख्या में पत्रकार वहां आते हैं। कभी-कभी अति विशिष्ट व्यक्तियों/मंत्रियों/सचिवों एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भारत सरकार की नीतियों की जानकारी देने के लिए प्रेस कांफ्रेस/प्रेस ब्रीफिंग आयोजित करनी होती है।

पिछले कुछ वर्षों के दौरान समाचार जगत में दो बड़े घटनाक्रम हुए हैं, - प्रथम, इंटरनेट का बहुत बड़े पैमाने पर विस्तार और दूसरे-चौबीसों घंटे चलने वाले न्यूज चैनलों का अभ्युदय। इन दोनों के कारण संचार की गति बहुत तेज हो गई है, राष्ट्रों की सीमाएं महत्वहीन हो रही हैं और समाचार संग्रह तथा वितरण में बहुत तेजी और त्वरित महत्व आ गया है। इन हालात में जहां परंपरागत मीडिया-खासतौर से प्रिंट मीडिया का महत्व बना हुआ है, वहीं अब पत्र सूचना कार्यालय को नए माध्यमों की जरूरतें पूरी करने के लिए भी काम करना है। नए उभरते साधनों का इस्तेमाल करते हुए अब उसे पूरी जनसंख्या तक पहुंचना है।

चूंकि आजकल इंटरनेट के जरिए सूचनाएं जल्दी मिल जाती हैं और उनमें पारदर्शिता रहती है अत: इस कार्यालय के पुराने साधनों को आधुनिक और आज के मीडिया की जरूरतों के अनुकूल बनाने की आवश्यकता है। इसलिए पत्र सूचना कार्यालय को आज के ग्राहकों को तुरन्त और रोचक तरीके से सूचना पेश करने के लिए नई गतिविधियां शुरू करनी होंगी।

पत्र सूचना कार्यालय अखबारों और अन्य मीडिया से मिलने वाली प्रतिक्रिया विभिन्न सरकारी विभागों को उपलब्ध कराता है ताकि वे उसके अनुकूल कदम उठा सकें और अपने प्रयासों को नई दिशा दे सकें।

इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वर्ष 2011-12 के दौरान निम्नलिखित गतिविधियों/स्कीमों/परियोजनाओं को चलाने का प्रस्ताव है :

1. नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रेस केंद्र की स्थापना

राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को कान्फ्रेंस हाल, प्रेस लांज, ब्रीफिंग/कान्फ्रेंस रूम, लाइब्रेरी तथा अन्य आधुनिक उपकरणों सहित अति आधुनिक सुविधा एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए ब्यूरो का नई दिल्ली में अलग इमारत में एक राष्ट्रीय प्रेस केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

परियोजना के आकार और लागत में वृद्धि के कारण इस परियोजना की लागत 35 करोड़ रुपये बढ़कर 60 करोड़ रुपये हो चुकी है। जिसे ईएफसी ने 15 सितम्बर 2009 को अनुमोदित कर दिया है। एनबीसीसी के साथ पुराने के स्थान पर नए समझौते पर 22 मार्च 2010 को हस्ताक्षर किए गए। मार्च 2006 तथा मार्च 2010 में एनबीसीसी को क्रमश 7 करोड़ तथा 4 करोड़ रुपये अदा किए गए। 2010-11 के बजट अनुमान में 10 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। यद्धपि, कार्य पिछड़ रहा है फिर भी अगस्त 2012 तक पूर्ण हो जाएगा। 31 दिसंबर 2010 तक निचले बेसमेंट तक एसीसी स्लैब पहुंच चुका है। अगले वित्तीय वर्ष के लिए 35 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है जिनमें से बजट अनुमान 2011-12 के लिए 20.50 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं।

2. मीडिया आउटरीच कार्यक्रम

इस स्कीम का उद्देश्य जन सूचना अभियानों, मीडिया से बातचीत, सफलता की कहानियों तथा प्रेस दौरे आयोजित कर सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में सूचना देना है। 11वीं योजना के दौरान 49.00 करोड़ रुपये का प्रशासनिक अनुमोदन 16.11.2007 को प्राप्त हुआ था। 2010-11 की अवधि में पीआईसी, 100 से 150 सफलता की कहनियों के लिए 14.50 करोड़ रुपये आबंटित किए गए। दिसंबर 2010 तक 79 पीआईसी, 79 सफलता की कहानियों पर 6.14 करोड़ रुपये व्यय किए गए। वित्त वर्ष के अंत तक बाकी बची राशि भी खर्च कर ली जाएगी। आगे इस परियोजना में प्रबंधन इकाई, क्षेत्रीय मीडिया आउटरीच और 24 घंटे नियंत्रण कक्ष को मजबूत करने जैसी

परियोजनाएं शामिल करने का प्रस्ताव है। 11 वीं परियोजना की कुल आवश्यकता 49 करोड़ के स्थान पर 60.59 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। इसलिए, अगले वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए 21.37 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए। जबकि वर्ष 20011-12 के दौरान इस स्कीम के लिए 14.50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

3. विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रचार

इस स्कीम के तीन हिस्से हैं जो इस प्रकार हैं :

क. भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह

फिल्म समारोह स्थल पर मीडिया केंद्र की स्थापना तथा पत्रकारों को विशेष मान्यता, स्वागत व्यवस्थाएं, प्रेस कान्फ्रेंस, कंप्यूटर, इंटरनेट, टेलीफोन, समाचारपत्र, स्टेशनरी, फोटो कॉपियर इत्यादि सुविधाओं वाले प्रेस विज्ञप्ति वर्क रूम जैसी सुविधाओं का विस्तार। वर्ष 2010-11 के लिए इस कार्यालय को गोवा में फिल्म समारोह हेतु 8.00 लाख रुपये आवंटित हुए। यह समारोह नवंबर-दिसंबर 2010 में आयोजित हुआ। आईएफएफआई के लिए वार्षिक योजना 2011-12 के लिए प्रशासनिक अनुमोदन के अनुसार 8 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं।

ख. प्रवासी भारतीय दिवस समारोह

पत्र सूचना कार्यालय प्रवासी भारतीय दिवस समारोह के दौरान मीडिया की सुविधा के लिए अपने अधिकारी नियुक्त करता है जो मौके पर ही पत्रकारों की सुविधा और मीडिया केंद्र में कंप्यूटर उपलब्ध कराते हैं। वर्ष 2010-11 के दौरान 1.25 लाख रुपये आवंटित किए गए थे। 2011-12 के दौरान, जनवरी 2012 में आयोजित होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस के लिए 1.25 लाख रुपये आवंटित किए गए।

ग. मीडिया आदान-प्रदान कार्यक्रम

इस स्कीम का प्रमुख लक्ष्य विभिन्न देशों के बीच बेहतर समझ विकसित करने और मीडियाकर्मियों के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान के जरिए क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना है। साथ ही इस बात पर भी जोर देना है कि लोकतांत्रिक मूल्यों और विभिन्न समाजों में सहनशीलता को बढ़ावा देने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में सूचनाओं के आदान-प्रदान के जरिए देशों के बीच मित्रतापूर्ण संबंध सुदृढ़ बनाए जाते हैं और सूचना तथा मास मीडिया के क्षेत्र में निकट संबंध विकसित करने के लिए लोगों में समान इच्छाओं की प्रेरणा प्रदान की जाती है।

इस स्कीम के प्रमुख घटक इस प्रकार हैं :

- सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम (सीईपी)
- संयुक्त कार्यदल
- सूचना क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता।

बजट अनुमान 2010-11 में 15.75 लाख रुपये इस स्कीम के लिए आबंटित किए गए हैं। सीईपी और संयुक्त कार्य दल का क्रियान्वयन मुख्य रूप से बाहरी कारकों जैसे आदान-प्रदान के लिए दूसरे देशों की इच्छा, लागू करने की के लिए प्रतिक्रिया देने की गति, संबंधित देशों में स्थित भारतीय दूतावासों की प्रतिक्रिया आदि पर निर्भर करता है। अन्य देशों से कोई प्रतिक्रिया न प्राप्त होने के चलते इस मद में कोई खर्च नहीं हुआ।

वर्ष 2011-12 के लिए सीईपी के लिए 15.75 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं।

4. पुणे में राष्ट्रमंडल युवा खेल, 2008 तथा दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के लिए मुख्य प्रेस केंद्र और अन्य मीडिया केंद्र

11वीं पंचवर्षीय योजना के एक भाग के रूप में लागू की जाने वाली यह एक नई स्कीम है। इसके लिए 3.11.2008 को 20.00 करोड़ रुपये अनुमोदित लागत के रूप में स्वीकृत हुए हैं जो 2008-09 से 2010-11 के बीच तीन वर्षों में वितरित हैं। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य प्रिंट, रेडियो और टेलीविजन जैसे विभिन्न मीडिया में दिलचस्पी पैदा करना है।

इस स्कीम के लिए बजट अनुमान में 2010-11 में कुल बजट आबंटन 21.75 करोड़ रुपये है। दिसंबर 2010 तक 19.87 करोड़ रुपये उपयोग में लाए जा चुके हैं। जिन्हें बेसिल को अदा किया गया है। आर ई के संबंध में, एसबीजी 21.98 करोड़ बढ़ा दी गई है। आर ई में 23 लाख की बढ़ोतरी के संबंध में उल्लेखनीय है कि 2009-10 के दौरान 10 करोड़ में से 9.77 करोड़ रुपये खर्च कर लिए गए थे। चूंकि स्कीम वार्षिक योजना 2010-11 में पूरी कर ली गई है, अत: बीई 2011-12 में किसी फंड की आवश्यकता नहीं होगी।

भारतीय प्रेस परिषद

प्रेस परिषद की स्थापना और कार्यों पर संक्षिप्त टिप्पणी

भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना प्रथम प्रेस आयोग की अनुशंसा पर वर्ष 1966 में की गयी थी। प्रेस की आजादी को बनाये रखने और उसके स्तर में सुधार लाने के अपने दोहरे उत्तरदायित्व की पूर्ति की दिशा में परिषद बहुमुखी भूमिका अदा करती है। एक ओर यह सिविल न्यायालय की शक्तियों सहित न्यायिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करती है, वहीं परामर्शदायी भूमिका में यह प्रेस और सरकारी अधिकारियों को प्रेस की आजादी और उसके संरक्षण से जुड़े मसलों पर मार्गनिर्देश भी देती है।

प्रेस परिषद का मुखिया चेयरमैन कहलाता है जो परंपरा से सर्वोच्च न्यायालय का वर्तमान/सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। इसके 28 अन्य सदस्यों में 20 प्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं और 5 संसद से आते हैं और 3 सदस्य सांस्कृतिक, साहित्यिक और विधि के क्षेत्र से होते हैं जिन्हें क्रमश: साहित्य अकादमी, विश्व विद्यालय अनुदान आयोग और भारतीय बार काउंसिल द्वारा नामित किया जाता है।

परिषद का वित्त पोषण मुख्यत: भारत सरकार से प्राप्त अनुदान सहायता द्वारा होता है। पंजीकृत समाचार पत्रों पर उनकी प्रसार संख्या के अनुसार शुल्क भी वसूला जाता है, धनराशि की कमी केन्द्र सरकार के अनुदान से पूरी की जाती है हालांकि काफी हद तक परिषद वित्तीय रूप से सरकार पर आश्रित है, फिर भी अपने काम में इसने कभी भी किसी बाहरी प्रभाव को हावी नहीं होने दिया है।

परिषद के अर्ध न्यायिक कार्य प्रेस परिषद अधिनियम की धारा 14 और 15 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों और प्रक्रियाओं के अनुसार किये जाते हैं और परामर्शदायी एवं मार्ग निर्देशन कार्य धारा 13 के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत किये जाते हैं। परिषद स्त्री-पुरुष समानता पर भी बल देती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए परिषद ने 'प्रेस दिवस 2008' को 'महिलाएं और मीडिया' के रूप में मनाया।

फोटो प्रभाग

देश भर में सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकासात्मक कार्यक्रमों तथा सामाजिक परिवर्तन के फोटोग्राफ्स का दस्तावेजीकरण फोटो प्रभाग का मुख्य कार्य है। यह प्रभाग प्रचार के लिए आंतरिक तथा बाह्य तौर पर फोटोग्राफ्स की आपूर्ति करता है। इसके अलावा फोटो प्रभाव पी आई बी (प्रेस इनफोर्मेशन ब्यूरो) को फोटो ग्राफ्स देता है ताकि उसे समाचार पत्रों को वितरित किया जा सके। प्रदर्शन के लिए डीएवीपी तथा विदेश में प्रचार के किए प्रभाग एक्स पी डिवीजन को भी फोटोग्राफ्स की आपूर्ति करता है।

इसके अतिरिक्त प्रभाग केंद्र/राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, पब्लिक सेक्टर उपक्रम तथा 'मूल्य स्कीम' के तहत अन्य लोगों को भी फोटोग्राफ की आपूर्ति करता है। इन फोटो इकाइयों का मुख्य कार्य है – महत्त्वपूर्ण घटनाओं की फोटो लेना, उसे प्रचार सामग्री के रूप में मुहैया करना आर्काइव में फोटोग्राफ्स को सुरक्षित रखना।

मौजूदा दौर में तकनीकी विकास के मद्देनजर, फोटो प्रभाग सक्षम प्राधिकरण से सलाह ले रहा है ताकि योजना स्कीम अद्यन विकास के अनुसार कार्यान्वित किया जा सके।

प्रकाशन विभाग

प्रकाशन विभाग देश के सबसे बड़े प्रकाशन भवनों में से एक है। हिंदी, अंग्रेजी और अन्य प्रमुख भारतीय भाषाओं में प्रकाशन विभाग द्वारा निकलने वाली पुस्तकों और पत्रिकाओं को इस प्रकार तैयार किया जाता है कि उनके माध्यम से इस देश के लोगों की समझ का विकास हो सके। इन प्रकाशनों का लक्ष्य है इस देश के जीवन और संस्कृति के रंग-बिरंगे रुपों पर तथा पंचवर्षीय योजनाओं समेत राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में दर्ज की गई प्रगति पर सूचना को सम्प्रेषित करना। इस विभाग के महत्वपूर्ण प्रकाशनों में महात्मा गांधी के कार्यों के संग्रह पर गौरवशाली शृंखलाएं, राष्ट्रीय नेताओं के भाषण, राष्ट्रीय महत्व के विषयों तथा बाल साहित्य पर शिक्षाप्रद और जानकारी देने वाली किताबें और रोजगार समाचार शामिल हैं।

प्रकाशन विभाग का कार्य है देश और विदेश में आम लोगों को भारत के बारे में अद्यतन और सही जानकारी देने के लिए आंतरिक और बाहरी प्रचार के लिए राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर लोकप्रिय पुस्तकों, पत्रिकाओं का उत्पादन, उनकी बिक्री और उनका वितरण करना। ऐसा करते हुए प्रकाशन विभाग निम्ननिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य बनाना है :-

(i) राष्ट्रीय महत्व के उन विषयों पर पुस्तकों को प्रकाशित करना जिन विषयों पर अन्य प्रकाशकों ने ध्यान नहीं दिया हो और ऐसी पुस्तकों को कम कीमत पर आम जनता के लिए उपलब्ध बनाना।

(ii) विविधता में एकता, सांप्रदायिक सद्भाव, राष्ट्रीय अखंडता इत्यादि की विचारधारा और आत्मा को मजबूत करना और बढ़ावा देना।

वर्ष 2009-10 और 2010-11 के दौरान प्रकाशित पुस्तकों की सूची अनुलग्नक-I में दी गई है –

अनुलग्नक I

अप्रैल 2009 से मार्च 2010 तक प्रकाशित पुस्तकों की सूची :

भाषा : हिंदी

क्र.सं.	पुस्तक का नाम
1.	विवरणिका - 2009 (द्विभाषी)
2.	नेताजी संपूर्ण वाङ्मय (खंड-10)
3.	दलित देवो भवः (भाग-2)-डीलक्स
4.	अष्टछाप के कवि - चतुर्भुजदास
5.	दश कुमार चरित
6.	तिरुक्कुरल
7.	पूर्वोत्तर के स्वतंत्रता सेनानी
8.	परिणाम बजट-2009-10 (सू. और प्र.मं)
9.	वार्षिक रिपोर्ट 2008-09 (सू और प्र मं)
10.	हाथी दादा की चौपाल
11.	प्रेरणा दीप (पुनर्मुद्रण)
12.	1857 की जन क्रांति : विविध आयाम
13.	भारतीय रेल
14.	गुरु नानक (पुन.)
15.	रोजगार की नई दिशाएं
16.	लालू का मोबाइल
17.	गुरु नानक से गुरु ग्रंथ साहब तक (पुन.)
18.	डा. के.बी. हेडगेवार (बीएमआई)
19.	वैज्ञानिकों की जीवन कथाएं
20.	नेताजी वाङ्मय (खंड-1) (पुन.)
21.	थार की ढाणी
22.	चोटी-छोटी चुभन
23.	सलेक्टेड स्पीचेज आफ पीएम (IV) (डीलक्स)
24.	भारत 2010

25. अहिल्याबाई होलकर (पुन.)
26. कला और साहित्य
27. टिन्नू मियां का कुर्ता
28. वार्षिक रिपोर्ट 2009–2010 (सू और प्र मं)
29. अनुवाद और तत्काल भाषांतरण
30. भारत के गुरुद्वारे
31. निर्भय निर्गुण
32. खेल है गणित
33. परिणाम बजट 2010–11 (सू और प्र मं)
34. और पेड़ गूंगे हो गए (पुन.)
35. तराजू का करिश्मा (पुन.)
36. रानी लक्ष्मीबाई (पुन.)
37. उन्नीसवीं शताब्दी के अन्वेषक
38. काशी नगरी एक रूप अनेक (डीलक्स)
39. भारत (पुन.) 2010
40. विश्व कवि विद्यापति (पुन.)
41. भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार 2007–08
42. अनकही शौर्य कथाएं (पुन.)
43. दो सिर वाला दैत्य
44. भारतीय पुष्प
45. 1857 का इतिहास संस्कृति
46. सन सत्तावन के भूले बिसरे शहीद
47. मस्ती की पाठशाला
48. मेरे अधिकारों की पहली किताब
49. आयुर्वेद के ज्वलंत प्रश्न
50. संयुक्त राष्ट्र बच्चों के लिए
51. प्रेस इन इंडिया
52. वैदिक काल की कहानियां
53. संत ज्ञानेश्वर

अंग्रेजी

क्र.सं.	पुस्तक का नाम
1.	एनुअल रिपोर्ट 2008-09 (सू और प्र मं)
2.	आउटकम बजट 2009-10 (सू और प्र मं)
3.	स्टेम सैल्स, हाइप एंड होप
4.	ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया (पुन.)
5.	चिल्ड्रेन इन इंडिया - ए लीगल पर्सपेक्टिव
6.	बदरुद्दीन तैयबजी (बीएमआई) पुन.)
7.	ग्रेट लाइव्स, ग्रेट बर्ड्स (पुन.)
8.	सर छोटू राम
9.	प्रेस इन इंडिया - 2010
10.	गजेटीयर आफ इंडिया (डीलक्स)
11.	एनुअल रिपोर्ट-2009-10 (सू और प्र मं)
12.	आउटकम बजट 2010-11 (सू और प्र मं)
13.	इंडियन फोक टेल्स (पुन)
14.	लोस्ट माइथोलॉजिकल सिटीज आफ इंडिया
15.	इंडिया रिफ्रेंस (एनुअल-2010 पुन.)
16.	चिल्ड्रेंस महाभारत (पुन.)
17.	ढोंडो केशव कर्वे (बीएमआई)
18.	अबुल कलाम आजाद (बीएमआई)
19.	सुभाष चंद्र बोस (बीएमआई)
20.	जगदीश चंद्र बोस (बीएमआई)

क्षेत्रीय भाषाएं

क्र.सं.	पुस्तक का नाम
1.	जवाहरलाल नेहरू (तमिल)
2.	बेताल कथा (उड़िया)
3.	साहस वनिता दुर्गाबाई देशमुख (तेलुगु)

4. एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन म्यूजिक (तमिल)
5. इंडियन कॉस्ट्यूम (बांग्ला)
6. जवाहरलाल नेहरू - ए पिक्टोरियल बायोग्राफी (मलयालम)
7. सरदार वल्लभ भाई पटेल (बीएमआई) (बांग्ला)
8. जहान-ए-रूमी (उर्दू)
9. भगतसिंह - अमर विरोधी (पंजाबी)
10. अकबर (उर्दू)
11. वार्ता नामनु नगर (गुजराती)

अप्रैल 2010 से दिसंबर 2010 के दौरान प्रकाशित पुस्तकों की सूची

हिंदी

क्र.सं.	पुस्तक का नाम
1.	लोकजीवन के सदाबहार पत्र
2.	पहेलियां
3.	हमारा भारत
4.	संयुक्त राष्ट्र बच्चों के लिए
5.	मेरे अधिकारों की पहली किताब
6.	सूचना भारती
7.	उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और उपभोक्ता के अधिकार (पुन.)
8.	चार्ल्स डार्विन
9.	भारतीय हाकी तथा राष्ट्रमंडल खेल
10.	सलेक्टेड स्पीचेज आफ पी एम मनमोहन सिंह
11.	भारतीय भोजन की परंपरा और विविधता
12.	एक महात्मा का अभ्युदय
13.	ठक्कर बप्पा (बीएमाई) (पुन
14.	प्रकाश भारती खंड XIII

अंग्रेजी

क्र.सं.	पुस्तक का नाम
1.	बाबू जगजीवन राम (बीएमआई)
2.	जमशेदजी टाटा (बीएमआई)
3.	राजेंद्र प्रसाद
4.	चिल्ड्रेंस रामायणा (पुन.)
5.	इंडिया-2010 (पुन)
6.	सी.एन. अन्नादुरई (बीएमआई)
7.	प्राइम मिनिस्टर डा. मनमोहन सिंह सलेक्टेड स्पीचेज (वॉल्यूम-)
8.	भूलाभाई देसाई (बीएमआई)
9.	के. कामराज (बीएमआई) (पुन.)
10.	मोहम्मद कुली कुतुब शाह - द फाउंडर आफ हैदराबाद (पुन)
11.	लाजपत राय- लाइफ एंड वर्क्स (बीएमआई) (पुन)
12.	प्रेसीडेंट-एपीजे अब्दुल कलाम सलेक्टेड स्पीचेज (वॉल्यूम-2) डीलक्स
13.	मास मीडिया इन इंडिया-2009
14.	मौलाना जलालुद्दीन रूमी
15.	इंडिया इन द स्पेस एज (पुन)
16.	गीतगोविंद (पुन) डीलक्स

भाषा : क्षेत्रीय भाषाएं

क्र.सं.	पुस्तक का नाम
1.	आल आर इक्वल इन द आईज आफ गॉड (उर्दू)
2.	जातक कथाएं (तमिल)
3.	सी. राजगोपालाचारी (बीएमआई) (पुन) तमिल
4.	नेशनल पार्क आफ इंडिया (पुन) तमिल
5.	डा. एस. राधाकृष्णन (पुन) तमिल
6.	अवर नेशनल फ्लेग (पुन) तमिल
7.	विष्णुपुरेर टेराकोटा मंदिर (बांग्ला)
8.	साइंस : नेचर्स कापीकेट (तेलुगु)

एम्प्लाइमेंट न्यूज/रोजगार समाचार

साप्ताहिक रोजगार समाचार अंग्रेजी, हिंदी तथा उर्दू में प्रकाशित होता है। यह प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार का प्रमुख प्रकाशन है। इस साप्ताहिक पत्र में केंद्रीय एवं राज्य सरकारें, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, स्वायत्त निकायों, विश्वविद्यालयों, विदेशी संस्थानों जैसे फोर्ड फाउंडेशन, ब्रिटिश काउंसिल आदि में नौकरियों के विज्ञापन, व्यावसायिक पाठयक्रमों के लिए प्रवेश अधिसूचनाएं, भारतीय संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग जैसे संगठनों तथा अन्य सामान्य भर्ती निकायों की परीक्षा अधिसूचनाएं और उनके परिणामों तथा मध्य-स्तरीय रोजगार उन्नयन के अवसरों (प्रतिनियुक्तियों) की सूचनाएं प्रकाशित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त एक सम्पादकीय हिस्सा भी है जो कैरियर से सम्बन्धित दो मुख्य लेख प्रकाशित करता है।

इस साप्ताहिक पत्र का मूल लक्ष्य सिविल सेवा के अभ्यार्थियों, प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं तथा साक्षात्कार में बैठने वाले उम्मीदवारों, अपने कैरियर तथा पेशे को चुनने के लिए तैयार युवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करना है।

यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि अपनी सामाजिक जिम्मेवारी, जिसके लिए इस पत्र को शुरू किया गया था, निभाने के साथ-साथ एम्प्लाइमेंट न्यूज/रोजगार समाचार नियमित रूप से पर्याप्त लाभ कमा रहा है। यह पत्र, जिसे सबसे अधिक प्रसारित साप्ताहिक पत्रों में शामिल होने का गौरव प्राप्त है, हर शनिवार को देश के कोने-कोने में उपलब्ध होता है।

सरकार के इस इंटरेक्टिव कैरियर साप्ताहिक ने अपनी कैरियर वेबसाइट www.employmentnews.gov.in खोलकर अपने खाते में एक और उपलब्धि दर्ज की है। यह वेबसाइट बहुत अधिक सफल रही है तथा युवाओं में बहुत लोकप्रिय हो रही है। हर रोज 3 लाख से अधिक लोग इस वेबसाइट को खोलते हैं। सरकारी क्षेत्र में यह सबसे अधिक हिट पेज है। वेबसाइट के जरिये पेश की जा रही ऑनलाइन सेवाओं में कैरियर परामर्श, सरकारी क्षेत्र में रिक्तियों के बारे में अग्रिम जानकारी उपलब्ध कराना शामिल है।

भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक

भारत के समाचार पत्र पंजीयक का कार्यालय की स्थापना पहली जुलाई 1956 को प्रेस और पुस्तक पंजीयन अधिनियम 1867 में संशोधन करके की गई थी। यह कार्यालय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अन्तर्गत कार्य करता है। अधिनियम के अन्तर्गत कुछ विधि विहित कार्य इस प्रकार हैं :

(1) देश भर में प्रकाशित समाचार पत्रों/पत्रिकाओं का एक रजिस्टर तैयार काना उसका रख-रखाव करना तथा उसमें समाचार पत्रों/पत्रिकाओं का विवरण संकलित करना।

(2) संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की गई सिफारिश के बाद समाचार पत्रों/पत्रिकाओं के शीर्षक की उपलब्धता की जांच के बाद पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करना।

(3) समाचार पत्रों के प्रकाशकों द्वारा प्रेस एवं पुस्त्क पंजीयन अधिनियम के अन्तर्गत समाचार पत्रों/पत्रिकाओं के प्रकाशन की जानकारी सुनिश्चित करना।

(4) प्रकाशकों द्वारा समाचार पत्रों की प्रसार संख्या के दावों की जांच करना।

(5) भारत में प्रेस के बारे में उपलब्ध समस्त सूचनाओं, आंकड़ों और विशेष तौर पर विभिन्न श्रेणियों के समाचार पत्रों पत्रिकाओं के आए बदलावों पर वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।

इसके अतिरिक्त कार्यालय के सामान्य कार्य इस प्रकार हैं :

(क) अखबारी कागज आंबटन के लिए समाचार पत्रों को योग्यता प्रमाणपत्र जारी करना ताकि वह अखबारी कागज का आयात कर सकें।

(ख) समाचार प्रतिष्ठानों की प्रिंटिंग मशीनें (मुद्रण) और अन्य संबंधित सामग्री आयात करने की आवश्यक जरूरतों का मूल्यांकन ओर प्रमाणपत्र जारी करना।

गवेषणा, संदर्भ एवं प्रशिक्षण प्रभाग

गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मीडिया इकाइयों को शोध के संबंध में एकत्रित, संकलित और तैयार सामग्री के प्रकाशन कार्य आदि में सहायता करता है। मीडिया इकाइयों के उपयोग के लिए महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी का सारांश निर्मित करना और सामयिक एवं अन्य विषयों पर मार्गदर्शन एवं पृष्ठभूमि नोट तैयार करना भी इस प्रभाग का दायित्व है। 1945 में स्थापित किया गया यह विभाग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय एवं इसकी अनेक मीडिया इकाइयों के लिए सूचना प्रदान करने वाली एक इकाई के रूप में काम करता है। यह प्रभाग जनसंचार क्षेत्र की प्रवृत्तियों का अध्ययन करते हुए जनसंचार की संदर्भ एवं प्रलेखन सेवा को कायम रखता है। प्रभाग मंत्रालय, इसकी मीडिया इकाइयों तथा जनसंचार से संबद्ध अन्य इकाइयों को पृष्ठभूमि, संदर्भ तथा शोध सामग्री उपलब्ध कराता है।

यह प्रभाग वर्ष के दौरान दो वार्षिक संदर्भ ग्रंथ तैयार करता है, *इंडिया* - संदर्भ वार्षिकी, यह केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य/संघ-शासित क्षेत्रों तथा पीएसयू/स्वायत्त निकायों द्वारा किए गए विकास और उन्नति का संकलन है। भारत में मास मीडिया *(मास मीडिया इन इंडिया)* यह भारत के जनसंचार पर एक विस्तृत प्रकाशन है। साथ ही इंडिया को हिंदी में *भारत* शीर्षक से प्रकाशित किया जाता है।

यह प्रभाग नियमित रूप से हर पखवाड़े 'डायरी ऑफ इवेंट्स' निकालता है जो अभिलेख और संदर्भ के लिए महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर केंद्रित होता है। यह प्रभाग विषय विशेष पर आधारित पत्रिकाओं की मासिक रिपोर्ट भी तैयार करता है। इन पत्रिकाओं में एफडीआई की हिस्सेदारी होती है और ये विषय विशेष से संबंधित होती हैं जिसके लिए इन्हें भारत में प्रकाशित करने की अनुमति दी जाती है। इन पत्रिकाओं का अनुवीक्षण यह देखने के लिए किया जाता है कि ये सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन कर रही हैं अथवा नहीं।

संदर्भ पुस्तकालय

इस प्रभाग का पुस्तकालय विभिन्न विषयों पर दस्तावेजों के बड़े संग्रह, चुनी हुई पत्रिकाओं के सजिल्द ग्रंथों तथा मंत्रालय की विभिन्न रिपोर्टों से सुसज्जित है। इसके संग्रह में पत्रकारिता, जनसंपर्क, विज्ञापन एवं दृश्य-श्रव्य प्रचार माध्यम, प्रमुख विश्वकोष, सम-सामयिक लेख और वार्षिकी शामिल हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के अतिरिक्त पुस्तकालय की सुविधाएं मान्यता प्राप्त भारतीय एवं विदेशी पत्रकारों के लिए भी उपलब्ध हैं। जगह की कमी के चलते वर्ष 2010-2011 के दौरान (दिसंबर 2010 तक) केवल 19 नई किताबें ही शामिल की जा सकीं।

राष्ट्रीय जनसंचार प्रलेखन केन्द्र

राष्ट्रीय जनसंचार प्रलेखन केन्द्र (एनडीसीएमसी) का गठन 1976 में मंत्रालय की ओर से गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया। इसकी सावधिक सेवाओं के माध्यम से जन संचार माध्यम की प्रवृत्तियों और उनसे जुड़ी घटनाओं की जानकारी एकत्र कर उनकी व्याख्या करना इसका मुख्य दायित्व है। एनडीसीएमसी जनसंपर्क/संचार पर उपलब्ध बड़े समाचारों, लेखों तथा सूचनाओं का प्रलेखन करता है। यह पूरे देश में जनसंचार के विकास के लिए ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रवाह में शामिल होने के लिए सूचना के संग्रहण और प्रलेखन से लेकर इसके प्रचार-प्रसार तक समसामयिक गतिविधियों का केंद्रीय क्षेत्र है।

एकत्रित सूचना को विभिन्न सेवाओं के द्वारा अनुरक्षित एवं प्रचारित किया जाता है जैसे - समसामयिक जागरूकता सेवा - केंद्र द्वारा खरीदे जा रहे समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में मास मीडिया पर चुनिंदा लेखों की प्रकाशित सूची, *संदर्भ ग्रंथ सेवा* - केंद्र द्वारा खरीदे जा रहे समाचारपत्रों और पत्रिकाओं में पिछले एक वर्ष के दौरान प्रकाशित मास मीडिया पर लेखों की विषय सूची, *फिल्म बुलेटिन* - भारत के फिल्म उद्योग के विकास का एक सारांश, *संदर्भ सूचना सेवा* - मास मीडिया क्षेत्र के प्रासंगिक हितों के विषयों पर पृष्ठभूमि दस्तावेज, - *हूज हू इन मास मीडिया*-लोक प्रसिद्ध विभिन्न मीडिया व्यक्तियों की जीवनियां, जनसंचार में कौन क्या है, *जनसंचारकों को दिए गए पुरस्कार* - वर्ष के दौरान जनसंचारकों को दिए गए पुरस्कारों के साथ-साथ घोषित राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की झलकियां और *मीडिया अपडेट* - यह प्रलेख और संदर्भ के लिए बड़ी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को केंद्रित करती है।

राष्ट्रीय जनसंचार प्रलेखन केंद्र **मास मीडिया इन इंडिया** नामक एक संदर्भ पुस्तक का संकलन एवं संपादन भी करता है। इस वार्षिकी में केंद्र सरकार, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मीडिया संगठनों की स्थिति पर सूचना और मास मीडिया के कई पहलुओं पर लेखों को शामिल किया जाता है। इसमें प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आम सूचना को भी शामिल किया जाता है। गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग के अधीन राष्ट्रीय जनसंचार प्रलेखन केंद्र ने वर्ष 2010-11 के दौरान (दिसंबर 2010 तक) मास मीडिया के विविध पहलुओं पर 42 सेवाएं जारी कीं।

वर्ष 2010-11 की झलकियां

- इंडिया-2011 का 55 वां संस्करण सफलतापूर्वक निकाला।

- गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग की एक इकाई राष्ट्रीय जनसंचार प्रलेखन केंद्र ने वर्ष 2010-11 के दौरान (दिसंबर 2010 तक) मास मीडिया के विभिन्न पहलुओं पर 42 सेवाएं जारी कीं।

गीत एवं नाटक प्रभाग

परिचय

प्रभाग की स्थापना 1954 में संचार माध्यम के रूप में पारंपरिक कलाओं और विलुप्त हो चुकी लोक कलाओं को फिर से पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से एक छोटी प्रयोगात्मक इकाई के रूप में की गई थी। प्रभाग ने कलाओं के माध्यम से समकालिक विचारों, मुद्दों और तरीकों को अपनाकर लोगों के साथ तात्कालिक तादात्म्य स्थापित किया जिससे लोगों के बीच में एक जीवन्त माध्यम के रूप में लोकप्रियता हासिल की है। प्रभाग ने दुर्गम पहाड़ी इलाकों, रेगिस्तान और सीमावर्ती क्षेत्रों में निचले स्तर पर लोगों के साथ प्रभावी ढंग से सम्पर्क स्थापित करके अपनी पहुंच और प्रभाव के क्षेत्र में बहुत विस्तार किया है।

उद्देश्य

प्रभाग के कार्यों के बारे में इसकी वेबसाइट में विस्तार से बताया गया है। इसके मुख्य कार्यों में देश की प्रगति के अनुकूल सामाजिक, आर्थिक और लोकतांत्रिक विचारों को आम जनता में जागरूकता और भावनात्मक स्वीकार्यता पैदा करना है। यह सरहदी इलाकों में रहने वाले लोगों के मन में रक्षा की तैयारियों और देश के बाकी हिस्सों से सांस्कृतिक एकजुटता को लेकर विश्वास पैदा करने के लिए काम करता है। इसके कामकाज में सीमा के अलग थलग इलाकों में तैनात सैनिकों के मनोबल को बनाए रखना भी शामिल है। यह अपना काम मनोरंजन के जीवंत साधनों के जरिए करता है जिनमें देश के सभी क्षेत्रों की शहरी नाटय विधाएं और लोक विधाएं भी शामिल हैं।

अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रभाग नाटक, नृत्य नाटिका, ओपेरा, वाचन और कठपुतली जैसी विभिन्न लोक और पारंपरिक विधाओं का सहारा लेता है। यह प्राचीन परंपरा वाले सैकड़ों जादुगरों की सेवाएं भी लेता है। इसके अलावा यह ध्वनि और प्रकाश की आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए साम्प्रदायिक सदभाव, राष्ट्रीय एकता, धर्मनिरपेक्षता, सांस्कृतिक विरासत, स्वास्थ्य, पर्यावरण और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर कार्यक्रम करता है जिनमें सैकड़ों कलाकारों की सेवाएं ली जाती हैं।

इस तरह प्रभाग देश के विभिन्न हिस्सों की अनगिनत लोक और पारंपिक विधाओं को पुनर्जीवित करने और उनहें बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। साथ ही वह हजारों कलाकारों की कलाओं का सोद्देश्य संवाद के लिए उनकी भाषाओं, मुहावरों और बोलियों में इस्तेमाल कर उन्हें आजीविका भी मुहैया करता है।

(i) प्रभाग का मुख्यालय दिल्ली में है और इसका प्रमुख एक निदेशक होता है। (ii) इसके 10 क्षेत्रीय केन्द्र बंगलूरू, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, कोलकाता, लखनऊ, पुणे और रांची में हैं। (iii) दरभंगा, गुवाहाटी, जम्मू, जोधपुर, इंफाल, नैनीताल और शिमला में इसके सात सीमा केन्द्र हैं जिनका अधयक्ष सहायक निदेशक होता है। प्रभाग के छह विभागीय नाटय दल भुवनेश्वर, दिल्ली, हैदराबाद, पटना, पुणे और श्रीनगर में हैं।

प्रभाग की विभिन्न फील्ड यूनिट प्रचार केंद्रित कार्यक्रम तैयार करने, प्रस्तुत करने और उनकी निगरानी के लिए जिम्मेदार हैं। इसके अलावा सशस्त्र बल मनोरंजन शाखा योजना के तहत कलाकारों के नौ दल (आठ दल दिल्ली में और एक चेन्नई में) हैं। इन नौ दलों की जिम्मेदारी सीमा के सुदूर और अलग-थलग इलाकों में सशस्त्र बलों का मनोरंजन करना है।

एफएम रेडियो

सूचना और प्रसारण मंत्रालय रेडियो, टेलीविजन, फिल्म, प्रेस प्रकाशन, विज्ञापन, नृत्य और नाटक जैसे परम्परागत माध्यमों से मिलकर बने जनसंचार माध्यम के जरिये लोगों को निर्बाध सूचनाओं को हासिल करने में मदद करने में कारगर भूमिका निभाता है। मंत्रालय चार प्रभागों - सूचना प्रभाग, प्रसारण प्रभाग, फिल्म प्रभाग एवं समन्वित वित्त प्रभाग की मदद से राष्ट्रीय अखंडता, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य आदि मुद्दों पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने तथा विभिन्न आयु समूहों की बौद्धिक एवं मनोरंजन संबंधी जरूरतों की पूर्ति के काम में संलग्न है। निजी एफएम रेडियो की योजना का उद्देश्य निजी एफ एम प्रसारकों को वैसी संरचना प्रदान करना है जिसकी मदद से वे स्पेक्ट्रम के कारगर उपयोग के लिए अपनी प्रसारण सुविधाओं को एक समान जगह पर स्थापित कर सकें।

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानीटरिंग केंद्र (ईएमएमसी)

(i) केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम 1995 तथा उसके अंतर्गत बने नियमों में निहित कार्यक्रम और विज्ञापन की मानीटरिंग, एवं (ii) निजी एफ एम रेडियो आदि के लिए अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) शर्तों की निगरानी तथा (iii) ऐसे अन्य कार्य जो प्रसारण क्षेत्र की विषयवस्तु की निगरानी से संबंधित जिन्हें सरकार द्वारा समय-समय पर सौंपा

गया हो। वार्षिक योजना 2010-11 के अन्तर्गत ईएमएमसी परियोजना के लिए रु. 2.18 करोड़ का आवंटन किया गया है। ईएमएमसी का गैर-योजना बजट वर्ष 2010-11 के बजट अनुमान के अन्तर्गत रु. 4.10 करोड़ का आवंटन था, जिसे संशोधित बजट के द्वारा बढ़ाकर रु. 4.36 करोड़ कर दिया गया। वर्ष 2011-12 के लिए अनुमानित परिव्यय रु. 2.18 करोड़ (योजना) एवं रु. 450 करोड़ (गैर योजना है।

अंतर्राष्ट्रीय चैनल

भारत के वैश्विक शक्ति के रूप में उभर कर आने से यह अनिवार्य हो गया है कि संवेदनशील मामलों पर भारत की स्थिति और उसके दृष्टिकोण को यथाशीघ्र अधिक से अधिक देशों में मुखर किया जाए। मुख्य उद्देश्य है : भारत की स्थिति का संपूर्ण विश्व में उसी प्रकार प्रचार करना जिस तरह से अल-जजीरा, बीबीसी, सीएनएन इत्यादि चैनल करते हैं। इसके लिए डीडी इंडिया, जिसे बहुत से देशों में देखा जाता है, पर प्रसारण के साथ-साथ वर्तमान डीडी न्यूज चैनल के जरिए अंतर्राष्ट्रीय समाचारों और कार्यक्रमों की शुरुआत करनी होगी।

सामुदायिक रेडियो के लिए आईईसी गतिविधियां

भारत सरकार ने वर्ष 2002 में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों (सीआरएस) की स्थापना के लिए लाइसेंस देने के लिए नीति संबंधी दिशानिर्देशों को मंजूरी दी। वर्ष 2006 में इन दिशानिर्देशों में काफी बदलाव किए गए और सरकार ने सामुदायिक रेडियो के लिए नए दिशा निर्देश जारी किये। इससे पहले के दिशानिर्देशों के तहत केवल शैक्षणिक संस्थाओं को ही सामुदायिक रेडियो स्टेशन चलाने की अनुमति दी जाती थी। नए दिशानिर्देशों में योग्यता की शर्तों को अधिक व्यापक बना दिया गया है और नागरिक समाजों और स्वैच्छिक संगठनों सहित समुदाय आधारित संगठनों, राज्य कृषि विश्व विद्यालयों, आईसीएआर संस्थानों, कृषि विज्ञान केन्द्रों, सोसायटीज एक्ट के तहत पंजीकृत संगठनों/स्वायत्त निकायों/लोक न्यासों को भी सामुदायिक रेडियो स्टेशन चलाने की अनुमति दी जाती है, बशर्ते वे योग्यता संबंधी शर्तों को पूरा करते हों।

सूचना भवन का निर्माण

सूचना भवन के निर्माण पर होने वाला व्यय योजना आयोग की मंजूरी के पश्चात इस मंत्रालय को उपलब्ध कराए गये योजना बजट से पूरा किया जाता है। अब तक उपलब्ध निर्मित स्थान विभिन्न मीडिया इकाइयों को आवंटित किया गया है, जैसे सिविल कंस्ट्रक्शन विंग, गीत एवं नाटक प्रभाग, फोटो प्रभाग, प्रकाशन विभाग, गवेषणा संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग, भारतीय प्रेस परिषद, विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (अंशत:) और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम। सूचना भवन के चरण V के पूरा होने पर उपलब्ध निर्मित स्थल का आवंटन बाकी मीडिया इकाइयों को किया जाएगा और यदि फिर भी स्थल बचता है तो उसे अन्य विभागों को किराए पर उपलब्ध कराया जाएगा।

विकास संबंधी पहलों का आर्थिक विश्लेषण (नई योजना)

अर्थव्यवस्था के तहत मनोरंजन और मीडिया क्षेत्र में 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–2012) के दौरान उच्च वृद्धि की उम्मीद है। विकास की इस गति से लाभ उठाने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा फिल्म, सूचना और प्रसारण क्षेत्रों संबंधी विभिन्न स्कीम/कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि निर्धारित लक्ष्यों/उद्देश्यों को हासिल किया जा सके। प्रत्येक स्कीम/कार्यक्रम से संबंधित कार्ययोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा तैयार की जाएगी जिसमें भौतिक और वित्तीय दोनों तरह से लक्ष्यों और उपलब्धियों को दर्शाया जाएगा। कार्यान्वयन प्रगति की मंत्रालय स्तर पर भी निगरानी की जाएगी। इन स्कीमों/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा छमाही आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी तथा रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाएगा।

मानव संसाधन विकास के लिये प्रशिक्षण

प्रस्ताव है कि भारतीय सूचना सेवा, केंद्रीय सचिवालय सेवा तथा अन्य विभिन्न सेवाओं के अधिकारी जो केंद्रीय स्टाफिंग स्कीम अथवा अन्य स्कीमों के अंतर्गत विभिन्न माध्यम एककों की आवश्यकता के अनुसार विदेश स्थित उत्कृष्ट संस्थानों/विश्वविद्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर मंत्रालय आते हैं, को प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। इस स्कीम में निहित व्यय केवल राजस्व व्यय है। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम विवेकपूर्ण रूप से मिला–जुला होगा, जो मंत्रालय की आवश्यकताओं की तुलना में पाठ्यक्रम की उपयुक्तता के आधार पर अल्पकानीन अथवा दीर्घकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा। प्रतिष्ठित संगठनों/विश्वविद्यालयों में चुनिंदा पाठ्यक्रमों के लिए अधिकारियों को मंत्रालय द्वारा भी नामांकित किया जाएगा।

इसका उद्देश्य अधिकारियों को बदलते राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी वातावरण से अवगत कराना। जिनमें उन्हें जनसंचार में मुख्य भूमिका निभाने के लिए कहा जाता है तथा इसके साथ ही किसी संगठन के विकास की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए आवश्यक मानव संसाधन विकास के लिए उन्हें सुग्राही बनाना भी इसका उद्देश्य है।

प्रसार भारती

अधिदेश

अधिदेश प्रसार भारती नाम से भारतीय प्रसारण निगम की स्थापना के प्रावधान बनाए गए। प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 को 15 सितंबर 1997 से लागू किया गया। इस अधिनियम में प्रावधान है कि निगम सर्वसाधारण को जानकारी देने, शिक्षित करने और मनोरंजन के लिए सार्वजनिक सेवा प्रसारण का कार्य करेगा। यानी जो कार्य पहले आकाशवाणी और दूरदर्शन करते थे, वह कार्य अब यह निगम करेगा। निगम के सामान्य पर्यवेक्षण निर्देशन और प्रबंध के कार्य प्रसार भारती बोर्ड को सौंपे जाएंगे। यह बोर्ड अपने ऐसे सभी अधिकारों का इस्तेमाल और अपने ऐसे सभी कार्य उसी प्रकार करेगा जिस प्रकार इस अधिनियम के तहत निगम द्वारा किए जाते हैं।

निगम अपने कार्य सुचारू रूप से कर सके, इसके लिए अधिनियम में प्रावधान है कि संसद द्वारा कानूनी तौर पर इस बारे में विधिवत विनियोजन किए जाने के बाद केंद्र सरकार आवश्यकतानुसार निगम को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इक्विटी सहायता अनुदान या ऋण के रूप में धनराशि प्रदान कर सकती है। निगम का अपना कोष होगा और निगम की सारी प्राप्तियां इसी कोष में जमा की जाएंगी और निगम सभी भुगतान इसी कोष से करेगा।

1. इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निगम का प्राथमिक दायित्व सर्वसाधारण को जानकारी देने, शिक्षित करने और मनोरंजन के लिए सार्वजनिक प्रसारण सेवा को संचालन करना तथा रेडियो और टेलीविजन पर प्रसारण का संतुलित विकास सुनिश्चित करना होगा। स्पष्टीकरण—शंका दूर करने के लिए एतद् द्वारा यह घोषणा की जाती है

कि इस खंड के प्रावधान भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के प्रावधानों के अलावा होंगे, न कि अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध होंगे।

2. निगम अपने कार्यों के निर्वहन में निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखेगा :

(क) देश की एकता और अखण्डता तथा संविधान में निहित मूल्यों का संरक्षण।

(ख) सार्वजनिक हित, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मामलों के बारे में मुक्त, सच्ची तथा निष्पक्ष सूचना प्राप्त करने के नागरिक के अधिकार का संरक्षण तथा अपनी विचारधारा या किसी राय को जोड़े बिना विविध दृष्टिकोणों सहित सूचना की निष्पक्ष तथा संतुलित प्रस्तुति।

(ग) शिक्षा के क्षेत्र में एवं साक्षरता, कृषि, ग्रामीण विकास, पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और विज्ञान एवं तकनीक पर विशेष ध्यान देना।

(घ) उपयुक्त कार्यक्रमों के प्रसारण द्वारा देश के विविध क्षेत्रों की सांस्कृतिक विविधता एवं भाषाओं को पर्याप्त कवरेज प्रदान करना।

(ङ) क्रीड़ा एवं खेल को पर्याप्त कवरेज प्रदान करना जिससे कि स्वस्थ प्रतियोगिता एवं खेल भावना को बढ़ावा मिले।

(च) युवाओं की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त कार्यक्रम प्रदान करना।

(छ) महिलाओं की स्थिति एवं समस्याओं के संबंध में राष्ट्रीय चेतना बढ़ाना तथा महिला उत्थान पर विशेष ध्यान देना।

(ज) शोषण, असमानता को दूर करने, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने एवं छुआ-छूत जैसी बुराई को दूर करने तथा समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए काम करना।

(झ) कामगारों के अधिकारों की रक्षा करना एवं उनके कल्याण को बढ़ावा देना।

(ञ) कमजोर एवं ग्रामीण वर्ग तथा सीमावर्ती क्षेत्र, पिछड़े एवं सुदूर क्षेत्रों के लोगों की भलाई के लिए कार्य करना।

(ट) अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय समुदायों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त कार्यक्रम प्रदान करना।

(ठ) बच्चों, नेत्रहीनों, बूढ़ों, अपंगों एवं जनता के अन्य कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा के लिए विशेष कदम उठाना।

(ड) राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के लिए, ऐसे प्रसारण करना जो भारत में विभिन्न भाषाओं के जरिए संवाद को बढ़ाते हों और हर राज्य में वहां की भाषा में क्षेत्रीय प्रसारण को बढ़ावा देना।

(ढ) उपयुक्त तकनीक द्वारा समग्र प्रसारण कवरेज प्रदान कराना तथा प्रसारण फ्रीक्वेंसी का सर्वोत्तम उपयोग एवं उच्च-स्तरीय उपलब्धियां सुनिश्चित करना।

(ण) रेडियो एवं टेलीविजन प्रसारण के निरंतर विकास के क्रम में शोध एवं विकास कार्य को आगे बढ़ाना।

(त) विभिन्न स्तरों पर प्रसारण के विभिन्न चैनलों की स्थापना द्वारा प्रसारण सुविधाओं का विस्तार।

3. विशेष रूप से एवं बिना पूर्वाग्रह के सामान्य रूप से, वर्तमान प्रावधानों के अनुरूप, निगम कुछ कदम उठा सकता है :

(क) कार्यक्रमों के निर्माण एवं उपलब्धता को लोकसेवा के रूप में संचालित करने के लिए प्रसारण को सुनिश्चित करना।

(ख) रेडियो एवं टेलीविजन के लिए समाचार एकत्र करने के लिए एक व्यवस्था की स्थापना।

(ग) खेल प्रतियोगिताओं, अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं, फिल्मों, सीरियलों, समारोहों, बैठकों तथा जनहित की अन्य घटनाओं के कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए खरीद

अथवा प्राप्ति के लिए बातचीत करना और ऐसे कार्यों की प्रक्रिया निर्धारित करना।

(घ) रेडियो, टेलीविजन या अन्य सामग्री के लिए लाइब्रेरी की स्थापना एवं देखभाल।

(ङ) समय-समय पर कार्यक्रम, दर्शक शोध, बाजार या तकनीकी सेवाओं को संचालित या प्रारंभ करना, जो उपयुक्त व्यक्तियों को उपयुक्त तरीकों और नियमों एवं शर्तों के अनुसार कार्य किए जा सके।

(च) नियमों द्वारा विर्निदिष्ट हो सकने वाली अन्य सेवाओं को प्रदान करना।

4. उपखंड (2) और (3) निगम की कोई बात निगम को, ऐसे नियमों एवं शर्तों के अनुसार जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट हों, विदेशी सेवाओं के प्रसारण और ऐसे विदेशी प्रसारण की निगरानी से नहीं रोक सकती जिनके प्रसारण के लिए केंद्र सरकार से भुगतान किया जाना हो।

5. इस खंड में स्थापित उद्देश्यों को बढ़ाने के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध कराया गया है, इनकी सुनिश्चितता के उद्देश्य के लिए विज्ञापन के संबंध में केंद्र सरकार को प्रसारण समय की अधिकतम सीमा के निर्धारण की शक्ति होगी।

6. निगम की मात्र इस आधार पर कोई भी सिविल जवाबदेही नहीं होगी कि वह इस खंड के किसी भी प्रावधान को पूरा करने में असफल रहा है।

7. निगम को विज्ञापन या ऐसे कार्यक्रम, जो नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट हो, के संबंध में फीस या अन्य सेवा शुल्क निर्धारित करने का अधिकार होगा।

इस खंड के अधीन इकट्ठा की गई फीस या अन्य सेवा शुल्क समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित वैसी सीमाओं से बाहर नहीं हो।

लक्ष्य तथा उद्देश्य

आकाशवाणी (ऑल इंडिया रेडियो), प्रसार भारती का एक अभिन्न भाग है, जो उपरोक्त दिए गए आदेशों को निरंतर पूरा कर रहा है। आकाशवाणी अपने विभिन्न स्टेशनों से प्रसारित कार्यक्रमों द्वारा लोगों को सूचना देता है, शिक्षित करता है और उनका मनोरंजन करता है। यह पूरे देश की जनता को सरकारी नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों और उपलब्धियों की सूचना श्रव्य-प्रसारण के माध्यम से देता है और संस्कृति, शिक्षा, विज्ञान, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों पर विभिन्न कार्यक्रम प्रसारित करता है। यह पूरे देश की जनता को महत्वपूर्ण समाचार तथा सम-सामयिक घटनाओं की जानकारी देता है। यह विचारों के विभिन्न बिंदुओं को प्रस्तुत करता है ताकि इसके द्वारा प्रसारित कार्यक्रम संतुलित एवं निष्पक्ष हों। यह शिक्षा एवं राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है। यह प्राकृतिक आपदाओं के दौरान अपने तीव्र प्रसार के द्वारा जनता एवं सरकारी विभागों को समय पर सूचना प्रदान करता है। यह एक व्यवसायिक सेवा (विविध भारती) भी संचालित करता है जो कि वस्तुओं एवं सेवाओं की बिक्री के विज्ञापन भी देता है। इसका विदेश सेवा प्रभाग विदेशी श्रोताओं के लिए कार्यक्रम प्रसारित करता है। इसका समाचार सेवा प्रभाग 24 घंटे ताजा समाचार उपलब्ध कराता है। इसके अलावा आकाशवाणी का एफएम और डीटीएच चैनल दिन-रात संगीत, गाने आदि के जरिये लोगों का मनोरंजन करते हैं।

नीति वक्तव्य

सार्वजनिक सेवा प्रसारक के रूप में प्रसार भारती के उद्देश्य हैं

- गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रम बनाना और
- महिलाओं, बच्चों, सुविधाविहीन, विशिष्ट भाषाई समूहों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर केंद्रित कार्यक्रमों के माध्यम से सूचना प्रदान करने, शिक्षा देने और मनोरंजन करने के प्रयोजन को पूरा करना।

प्रसार भारती के अंतर्गत आकाशवाणी, प्रसार भारती के अधिदेश को आगे बढ़ाने के लक्ष्यों और उद्देश्यों को हासिल करने का प्रयत्न करता है। अनेक प्रकार की नई पहल की जा रही है, जैसे 86 चुने हुए आकाशवाणी स्टेशनों से खेत और घर से जुड़े कार्यक्रम– किसान वाणी कार्यक्रम, पर्यावरण, परिवार कल्याण, ग्रामीण बच्चों और छोटे बच्चों को केंद्र में रखकर बनए गए विशेष कार्यक्रम, महिला कार्यक्रम, शैक्षिक प्रसारण (इग्नू/एसीईआरटी/सीआईईटी) दिखाए जा रहे हैं। एचआईवी/एड्स पर जागरूकता बढ़ाने के कार्यक्रम और दूसरे स्वास्थ्य कार्यक्रमों, इग्नू के सहयोग के साथ कार्यक्रम, राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका (विज्ञान भारती), सीसेम स्ट्रीट कार्यक्रमों को आकाशवाणी पर प्रसारित किया गया है, साथ ही संगीत और नाटक से संबंधित कार्यक्रमों का प्रसारण भी किया जाता है। पहल के इंजीनियरिंग पक्ष की ओर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्व और द्वीपीय क्षेत्रों के लिए विशेष पैकेज कार्यक्रम चलाए गए हैं और एफएम सेवाओं का विस्तार, प्रोडक्शन कार्यक्रमों और ट्रांसमिशन सुविधाओं का डिजिटलीकरण एवं नई तकनीक को प्रस्तावित किया गया है। समाचार सेवा प्रभाग और अनुसंधान एवं विकास से संबंधित गतिविधियों को भी संचालित किया गया है।

सभी प्रकार की पहल के उचित एवं समयाबद्ध कार्यान्वयन को परिणाम के रूप में प्रदर्शित करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है।

भारतीय क्लासिक योजना का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता के कार्यक्रम का निर्माण और देश की समृद्ध संस्कृति तथा साहित्यिक विरासत को संरक्षित रखना है। योजना के अंतर्गत सभी कार्यक्रम सभी भारतीय भाषाओं में बनाए गए हैं और इन साहित्यिक रचनाओं को अन्य भाषाओं में डब किया गया है जिससे देश के सभी दर्शकों को लाभ प्राप्त हो।

दूरदर्शन में, महाराणा रंजीत सिंह की ऐतिहासिक गाथा पर 52 एपीसोड की श्रृंखला निर्माणाधीन है। फोर्ट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी, कॉमन वरशिप सेंटर्स जैसे चुनींदा विषयों पर विशेष कार्यक्रम निर्माणाधीन हैं।

दूरदर्शन सार्वजनिक सेवा प्रसारण कोष के सहयोग से व्यापक स्तर के विषयों पर वृत्तचित्रों का निर्माण कर रहा है। इसके अंतर्गत हर वर्ष चार वृत्तचित्रों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते हैं।

डीडी उर्दू

पांच करोड़ 20 लाख उर्दू भाषी आबादी की जरूरतों को देखते हुए और उर्दू की साहित्यिक व सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने के लिए 15 अगस्त 2006 को डीडी उर्दू अस्तित्व में आया। प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम का उद्देश्य इस चैनल पर अच्छे विषय और लक्षित दर्शकों के कल्याण के लि अनेक कार्यक्रमों को प्रसारित करना है। इसके लिए डीडी की अधिग्रहण परियोजना के माध्यम से सॉफ्टवेयर खरीदा गया है और डीडी में इसे तैयार भी किया गया है।

डीडी न्यूज

डीडी न्यूज पहला और एकमात्र क्षेत्रीय न्यूज चैनल है जो देश की लगभग आधी आबादी तक पहुंचता है। इस चैनल की शुरुआत नवंबर 2003 में हुई थी। डीडी न्यूज बिना सनसनी के, संतुलित समाचारों के प्रसारण को सुनिश्चित करते हुए सत्य, सर्वत्र, संपूर्ण (पूरा सच हमेशा) का आदर्श वाक्य देता है।

आज के मीडिया परिदृश्य में, जहां 24 घंटे के अनेक निजी समाचार चैनल मौजूद हैं, डीडी न्यूज जैसे 24 घंटे के क्षेत्रीय सेटेलाइट राष्ट्रीय समाचार चैनल की मजबूत उपस्थिति की जरूरत है। सरकारी दृष्टिकोण, विशेष रूप से विकास नीतियों और कार्यक्रमों को प्रदर्शित करने के लिए यह अनिवार्य है। डीडी न्यूज एकमात्र भारतीय न्यूज चैनल है जो देश के 50 प्रतिशत लोगों तक पहुंचता है, विशेष रूप से समाज के सुविधाविहीन और अभावग्रस्त तबकों तक जो केबल सेटेलाइट के जरिए देश से जुड़े हुए नहीं हैं। राष्ट्रीय आपदा, विनाश आदि की स्थिति में, सार्वजनिक प्रसारक की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है।

श्रोता अनुसंधान खंड

श्रोता अनुसंधान खंड अनुसंधान और आंकड़ा एकत्रीकरण के विभिन्न तरीकों के माध्यम से चैनलों पर कार्यक्रमों की योजना बनाने और उनकी गुणवत्ता सुधारने में महत्पूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्रोता अनुसंधान डीटीएच पेनेट्रेशन और कृषि कार्यक्रमों की नेरोकास्टिंग की मदद से देश भर में सर्वेक्षण करता है। श्रोता अनुसंधान खंड देश के विभिन्न हिस्सों

में स्थित अपनी 18 इकाइयों के सहयोग से शहरी और ग्रामीण इलाकों में डार्ट सर्वेक्षण भी करता है। वर्तमान वर्ष में भारत सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रमों के प्रभाव पर सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज द्वारा किया गया है।

इन हाउस सर्वेक्षणों के अतिरिक्त दूरदर्शन ने टैम मीडिया रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड से रेटिंग डेटा और एमआरयूसी से बेसलाइन डेटा प्राप्त करेगा और उन्हें देश के विभिन्न हिस्सों में चैनल प्रबंधकों एवं मार्केटिंग विभाग को प्रदान करेगा।

डीडी भारती

डीडी भारती एक सांस्कृतिक विरासत को प्रोत्साहित करने वाला चैनल है जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रस्तावित, प्रोत्साहित और संरक्षित रखने में निर्णायक भूमिका निभाता है। चैनल संगीत, नृत्य, विरासत, स्वास्थ्य, बच्चों पर केंद्रित है और भारतीय जीवन शैली, दर्शन, कला और संस्कृति पर बल देता है। चैनल संगीत और नृत्य, पर्व, विशेष घटनाओं, मुशायरा, कवि सम्मेलन आदि के लाइव कवरेज को भी प्रसारित करता है। फिक्स प्वाइंट चार्ट्स में परिवर्तन के साथ, दर्शकों की संख्या बढ़ाने के लिए चैनल ने नए कार्यक्रमों को भी प्रस्तावित किया है। कार्यक्रमों में वैविध्य तथा उनकी गुणवत्ता में सुधार के लिए नए कार्यक्रम भी खरीदे गए हैं। कार्यक्रमों, विशेष रूप से सांस्कृतिक विरासत से संबंधित कार्यक्रमों में सुधार के लिए फिर कमीशनिंग प्रस्तावित है।

क्षेत्रीय प्रसारण

देश की सामाजिक सांस्कृतिक और भाषाई विभिन्नता के मद्देनजर दूरदर्शन देश के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों, विशेष रूप से प्रमुख क्षेत्रीय भाषाएं –तमिल, तेलुगू, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, बांग्ला, असमी, पंजाबी, गुजराती, मराठी और कश्मीरी – बोलने वाले लोगों के हित के लिए क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों में भी कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। मुख्य भाषा के कार्यक्रमों के अतिरिक्त, क्षेत्रीय भाषाओं के 11 सेटेलाइट चैनल भी उर्दू, सिंधी, संस्कृत, टुलु, कोंकणी, डोगरी, हिमाचली, हरियाणवी, नेपाली और उत्तर पूर्व की सबी भाषाओं और बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण करते हैं।

क्षेत्रीय भाषाओं के कार्यक्रम राज्य में विभिन्न एचपीटी और एलपीटी के क्षेत्रीय सहयोग के साथ सेटेलाइट पर, जमीनी ट्रांसमीटरों के माध्यम से डीडी 1 की क्षेत्रीय विंडो के रूप में दोपहर तीन बजे से शाम आठ बजे तक उपलब्ध रहते हैं। तमिलनाडु में यह क्षेत्रीय सहयोग रात 11 बजे तक रहता है।

इन क्षेत्रीय भाषाओं के चैनलों पर राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में निर्मित विभिन्न कार्यक्रम और फॉरमेट उपलब्ध कराए जाते हैं और इन्हें संबंधित राज्य के राजधानी केंद्र से फीड और प्रसारित किया जाता है। इन चैनलों पर फीचर फिल्में, फिल्मी गाने, धारावाहिक, शास्त्रीय–सुगम–लोक संगीत, नृत्य, समाचार और समसामयिक कार्यक्रम, कृषि और ग्रामीण विकास कार्यक्रम आदि प्रसारित किए जाते हैं जोकि श्रोता विशेष की रुचि के कार्यक्रमों के साथ समाज के सभी तबकों, महिलाओं, बच्चों और युवाओं का रंजन करते हैं।

राज्य नेटवर्क

दूरदर्शन के क्षेत्रीय सेवा प्रसारण भी हैं जिन्हें राज्य नेटवर्क कहा जाता है। ये नेटवर्क उत्तर भारत के दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में रहने वाले लोगों के लिए है। एचपीटी और एलपीटी के इन सभी राज्य नेटवर्कों के माध्यम से डीडीके, दिल्ली से सोमवार से शनिवार को दोपहर तीन से चार बजे तक एक घंटे के लिए उत्तरी नेटवर्क धारावाहिक आधारित मनोरंजन कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं और रविवार को हिंदी फीचर फिल्म प्रसारित की जाती है। इसलिए संबंधित राज्य की राजधानी से दोपहर चार से शाम आठ बजे के बीच कार्यक्रम बीम किए जाते हैं और उस राज्य के जमीनी ट्रांसमीटर से रिले किए जाते हैं जिससे क्षेत्र की प्रमुख स्थानीय बोली में आयोजित होने वाली गतिविधियों को कनेक्ट किया जा सके।

शिक्षा, सूचना और मनोरंजन के अतिरिक्त वर्ष भर सबसे ज्यादा बल फ्लैगशिप कार्यक्रमों को दिया जाता है। अपनी क्षमता का ध्यान न करते हुए क्षेत्रीय केंद्रों ने फ्लैगशिप कार्यक्रमों और लोक सेवा कार्यक्रमों को प्रमुखता देने में बड़ी उपलब्धि हासिल की है।

डीडी अभिलेखागार

डीडी अभिलेखागार 40 वर्षों से सृजित मीडिया कन्टेंट का परिरक्षक है। किसी भी मीडिया संगठन का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि वह अपनी परिसंपत्ति को कैसे प्रबंधित करता है। ब्रॉडकास्टिंग चैनल के रूप में वह मौजूदा घटनाओं की प्रासंगिकता के अधिक से अधिक फाइल फुटेज पर निर्भर रहता है। इसके अतिरिक्त डीडी अभिलेखागार का सांस्कृतिक कन्टेंट बहुत मूल्यवान है, चूंकि डीडी अभिलेखागार ऐसा एकमात्र माध्यम है जो विभिन्न सांस्कृतिक प्रवृत्तियों, जिसमें शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, लोक संगीत और लोक नृत्य, आदिवासी संगीत और नृत्य शैलियां, परंपरागत और आधुनिक रंगमंच आदि शामिल है, के संरक्षण के उत्तरदायित्व को मान्यता देता है। यह बहुमूल्य कन्टेंट उस देश के स्पंदमान सांस्कृतिक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है जो पूरे विश्व में अपनी सांस्कृतिक बपौती के लिए जाना जाता है। डीडी अभिलेखागार ने अपने कन्टेंट को संरक्षण का अभियान चलाया है जो भविष्य और देश की समृद्धि के लिए अतीत और वर्तमान का प्रतिनिधित्व करता है। अगले चार वर्षों में डीडी अभिलेखागर विश्व के सर्वश्रेष्ठ ब्रॉडकास्टिंग अभिलेखागारों में से एक हो जाएगा।

स्व वित्त कमीशनिंग (एसएफसी)

दूरदर्शन ने देश के प्रतिष्ठित निर्माताओं से अपने फ्लैगशिप चैनल डीडी 1 के लिए गुणवत्तापूर्ण मनोरंजक कन्टेंट आउटसोर्स करने के लिए स्व वित्त कमीशनिंग की नई योजना प्रतिपादित की है। इस योजना के तहत वरिष्ठ फिल्मकारों और टेलीविजन निर्माताओं द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर को दूरदर्शन की ओर से वितरित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन के स्वामित्व वाले कन्टेंट को दूसरे चैनलों द्वारा प्रसारित किया जा सकता है। यह योजना दूरदर्शन के प्राइम टाइम के दौरान अच्छा राजस्व अर्जित कर रही है।

डीडी एसएफसी कार्यक्रमों द्वारा सभी प्राइम टाइम और मिड प्राइम स्लॉट्स को अधिग्रहित करने को प्रतिबद्ध है। प्राइम टाइम और मिड प्राइम स्लॉट्स के अतिरिक्त एसएफसी कार्यक्रमों के लिए नॉन प्राइम टाइम स्लॉट्स को लेने की रणनीति पर विचार किया जा रहा है। यहां यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि हर वर्ष निर्माण की लागत बढ़ रही है और गुणवत्ता के लिहाज से दूसरे सेटेलाइट चैनलों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए हमें एपीसोड के मूल्य को बढ़ाना चाहिए।

इस योजना के तहत निर्मित कार्यक्रम केवल दूरदर्शन की संपत्ति हैं। डीडी इस संपत्ति को बिना किसी अतिरिक्त मूल्य के, दूरदर्शन के किसी दूसरे चैनल पर जब चाहे प्रयोग कर सकता है। एक समय निवेश और बहुउपयोग का यह अधिकार, बिना किसी आवर्ती व्यय के, दूरदर्शन को प्रायोजित कार्यक्रमों के साथ नहीं मिलता। राजस्व में बढ़ोतरी के अतिरिक्त, डीडी मार्केटिंग एजेंसियों/प्रायोजकों के देय की समस्या से भी निजात पा लेता है क्योंकि डीडी सीधा ग्राहकों के संपर्क में होता है। अदालती मामलों/पंचाट से भी छुटकारा मिलता है। वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान, प्राइम टाइम पर दैनिक धारावाहिक को प्रस्तावित करने का प्रयोग भी किया गया जो दर्शक संख्या बढ़ाने के साथ-साथ दूरदर्शन का राजस्व भी बढ़ाएगा।

वर्ष 2011-12 के लक्ष्य इस प्रकार हैं:

- उर्दू उपन्यासों पर देश के प्रख्यात फिल्मकारों से बहु शृंखला वाले धारावाहिकों का निर्माण
- भारत के प्रख्यात रंगकर्मियों द्वारा किए गए उर्दू नाटकों का पुनर्निर्माण
- दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों, यूरोप और अमेरिका के कलाकारों के अंतरराष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम
- उर्दू भाषा और साहित्यिक पृष्ठभूमि वाले फिल्मकारों द्वारा उर्दू भाषा की कहानियों पर उर्दू फीचर फिल्मों का निर्माण

सॉफ्टवेयर की कमीशनिंग

- हैदराबाद, लखनऊ, मुंबई, पटना, जयपुर, श्रीनगर, जम्मू स्थित केंद्रों के माध्यम से इन हाउस प्रोडक्शन गतिविधियों का संचालन
- इस वर्ष के दौरान घोषित कमीशंड योजनाओं पर काम चल रहा है, जो कि चैनल के लिए वर्ष 2011-12 में गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रम प्रदान करेंगी।

ऐनीमेशन, गेमिंग और विशेष प्रभावों के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना

तीव्र प्रौद्योगिकी विकास ने एनीमेशन, गेमिंग और विशेष दृश्य प्रभावों के क्षेत्र में विकास को बढ़ावा दिया है। एनीमेशन सॉफ्टवेयर कार्यक्रमों का इस्तेमाल कंटेंट विकसित करने के लिए 2 डी सैल एनीमेशन तथा 3 डी एनीमेशन तकनीकों का इस्तेमाल होता है। 3 डी मोशन केप्चर एनीमेशन तकनीकों का इस्तेमाल लो रिजोल्युशन गेम, इंटरनेट करेक्टर्स, विशेष प्रभाव इत्यादि में होता है। इसी तरह, गेमिंग उद्योग गेम डिजाइन, प्लेटफार्म डिजाइन तथा प्ले करेक्टरिस्टिक सिस्टम के लिए आधुनिक गेमिंग सॉफ्टवेयर पर निर्भर है। भारतीय गेमिंग उद्योग मोबाइल तथा ऑन लाइन गेमिंग क्षेत्रों में अवसरों का इस्तेमाल करना चाहता है। ऐनीमेशन, गेमिंग तथा दृश्य प्रभाव उद्योग प्रौद्योगिकी तथा तकनीकी/व्यवसायिक दोनों मानवशक्ति की मांग वाला क्षत्र है। भारतीय उद्योग पहले से ही विरोध का सामना कर रहा है। ऐसे में जब इन उद्योगों में भारत का एक छोटा हिस्सा है, वैश्विक मांग और भारत में आईटी व्यावसायिकों का विशाल पूल होने के नाते इसमें अत्यधिक संभावनाएं हैं।

दृश्य प्रभाव एक अत्यंत कौशलपूर्ण गतिविधि है जो लगातार श्रव्य दृश्य उद्योग को व्यक्त करता है। इस संबंध में फिल्में जैसे मिशन इम्पॉसिबिल तथा हालीवुड की 'मैटिक्रस' और 'धूम-2' एवं 'डॉन' स्मरण में आती है। यह कौशल विकास का एनीमेशन तथा गेमिंग के अनुरूप है जिसमें राजस्व की संभावनाएं अधिक हैं।

तथापि लगातार बढ़ती हुई एनिमेशन, गेमिंग एवं दृश्य प्रभाव उद्योग में प्रशिक्षित व्यवसायिकों का अभाव है। विभिन्न रिपोर्टों में अनुमानों के अनुसार लगभग 10,000 एनिमेशन व्यवसायिकों की आवश्यकता है जबकि वर्तमान में केवल 3000 ही उपलब्ध है। इसी प्रकार गेमिंग उद्योग में 6000 व्यवसायिक हैं जबकि मांग अधिक की है। उद्योग के विकास के बाद कुशल व्यवसायिकों की मांग और अधिक बढ़ सकती है। अत: एनीमेशन, गेमिंग और दृश्य प्रभाव सैक्टर में प्रशिक्षित व्यवसायिकों की मांग भारत में और बढ़ना अवश्यम्भावी है। लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इस क्षेत्र हेतु मानव संसाधन योजना की आवश्यकता है जिससे प्रशिक्षित कार्मिकों की संख्या बढ़ सके। अत: उच्च शिक्षा में स्कूल पाठयक्रमों तथा एनीमेशन प्रशिक्षण में लक्ष्य के मद्देनजर एनीमेशन, गेमिंग तथा दृश्य प्रभाव सैक्टर के लिए एक विशेष प्रशिक्षण एवं सलाहकार संस्थान की स्थापना सरकारी/निजी भागीदारी में लिए जाने की परिकल्पना की गई है।

संस्थान इस क्षेत्र में अनुसंधान के अवसर भी उपलब्ध कराएगा। इससे और अधिक तकनीकी पहलों एवं सॉफ्टवेयर का विकास होगा। दूरगामी दृष्टिकोण से अनुसंधान से न केवल बौद्धिकता को बढ़ावा मिलेगा बल्कि राजस्व अर्जित करने में भी सहायक होगा तथा संबंधित सैक्टर का नेतृत्व भी हो सकेगा।

प्रधानमंत्री कार्यालय/योजना आयोग की सलाह पर मंत्रालय ने इन सैक्टरों में कौशल अन्तराल का मूल्यांकन मैसर्स पी डब्ल्यू सी से कराया। मैसर्स पीडब्ल्यूसी ने एनिमेशन, गेमिंग और दृश्य प्रभावों के लिए राष्ट्रीय केन्द्र स्थापित करने की सिफारिश की है।

जब मंत्रालय योजना स्कीमों की सैद्धान्तिक स्वीकृति के लिए योजना आयोग के पास गया तो योजना आयोग ने उक्त योजना स्कीम की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आग्रह किया।

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य मैसर्स प्राइसवाटरहाउस कोआपर्स को दिया गया। पी डब्ल्यु सी ने जून, 2010 में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट संबंधी कार्य पूरा कर लिया। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का अंतिम मसौदा 27.1.2011 को प्रस्तुत किया गया। जिसमें कुछ संशोधन सुझाए गये।

अध्याय-2

परिव्यय और परिणाम/लक्ष्य (2011-12) का विवरण

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

योजना

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य/परिणाम	परिव्यय 2011-12			परिमाणनीय/ वितरण योग्य/ भौतिक नतीजे	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम घटक
1	2	3	4			5	6	7	8
			4 (i)	4 (ii)	4 (iii)				
			गैर-योजना बजट	योजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
1.	कम्प्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली की स्थापना और सीबीएफसी में बुनियादी सुविधाओं का उन्नयन (पूंजी)	क्षेत्रीय कार्यालयों व सीबीएफसी मुख्यालयों और मंत्रालय के बीच डाटा के तीव्र ट्रांसमिशन के लिए लीज्ड लाइन संपर्क स्थापित किया गया है।	-	100.00	—	सीबीएफसी के क्षेत्रीय कार्यालयों और मुख्यालयों एवं मंत्रालय को लीज्ड लाइन संपर्क द्वारा जोड़ा जाएगा। (इंट्रानेट) लोगों को दिखाने के लिए आरटीआई अधिनियम के संदर्भ में जानकारी देने के लिए प्रमाणित फिल्मों और कटों की विस्तृत जानकारी को वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है।	देश के सभी क्षेत्र में प्रमाणन में समरूपता लाने के लिए ऑडियो व वीडियो डाटा का तीव्र प्रसार।	वार्षिक आधार	विभिन्न हितधारकों द्वारा काम का क्रियान्वयन करवाना

2.	नई दिल्ली, कटक और गुवाहाटी में बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों का प्रारम्भ। (राजस्व)	पूर्वोत्तर क्षेत्रों में बनने वाली फिल्मों के प्रमाणन की व्यवस्था करना	—	50.00	—	इन क्षेत्रों में बनाई गई फिल्मों के प्रमाणन के लिए इन कार्यालयों की स्थापना की गई है। बुनियादी सुविधायें और मानवशक्ति दी जा रही है।	पूर्वोत्तर क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश व दिल्ली एवं चंडीगढ़ के केंद्रशासित प्रदेशों में बनी फिल्मों को बढ़ावा देना।	वार्षिक आधार	योजना निधि को आत्मसात करने की सीबीएफसी की क्षमता
3.	प्रमाणन प्रक्रिया की निगरानी (राजस्व)	प्रमाणन प्रक्रिया में सुधार आने के लिए	—	70.00	—	सीबीएफसी व परामर्शदाता पैनल के सदस्यों के लिए कार्यशालाओं, सम्मेलनों और बोर्ड बैठकों का आयोजन किया जाएगा।	प्रमाणन दिशा-निर्देशों की बेहतर समझ के लिए प्रमाणन प्रक्रिया में सुधार।	वार्षिक आधार	वार्षिक बजट आबंटन का उपयोग करना
	कुल			**220.00**					

गैर योजना

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य/परिणाम	परिव्यय 2011-12			परिमाणनीय/ वितरण योग्य/ भौतिक नतीजे	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम घटक
1	2	3	4			5	6	7	8
			4 (i)	4 (ii)	4 (iii)				
			गैर-योजना बजट	**योजना बजट**	**पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन**				
1.	वेतन	एन.ए.	400.00	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
2.	ओ.टी.ओ	एन.ए.	0.10	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	वार्षिक आधार	वार्षिक बजट आबंटन का उपयोग करना
3.	चिकित्सा	एन.ए.	4.00	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	वार्षिक आधार	वार्षिक बजट आबंटन का उपयोग करना
4.	टीई	एन.ए.	25.00	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	वार्षिक आधार	वार्षिक बजट आबंटन का उपयोग करना
5.	ओ.ई.	एन.ए.	70.00	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	वार्षिक आधार	वार्षिक बजट आबंटन का उपयोग करना
6.	पी.पी.एस.एस	एन.ए.	150.00	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	वार्षिक आधार	वार्षिक बजट आबंटन का उपयोग करना
7.	मदद अनुदान	एन.ए.	0.10	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	वार्षिक आधार	वार्षिक बजट आबंटन का उपयोग करना
8.	लघु कार्य	एन.ए.	10.00	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	वार्षिक आधार	वार्षिक बजट आबंटन का उपयोग करना
9.	विदेश यात्रा		5.00						
	कुल		**664.20**						

बाल फिल्म समिति, भारत

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम (चालू योजनाएं)	ग्यारहवीं योजना के लिए उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2010-11			वास्तविक प्रतिफल/ मात्रात्मक परिणाम (2010-11)	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/जोखिम संबंधी घटक
	1	2	3			4	5		6 7
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर-योजना बजट	योजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजट स्रोत				
1	सीएफएसआई को सरकार से अनुदान	1. लक्ष्य : फिल्मों के माध्यम से शिक्षा तथा संस्कृति को बेहतर बनाना और स्वस्थ मनोरंजन के लिए बच्चों में फिल्म समालोचना को प्रोत्साहन देना। 2. परिव्यय निर्माण 12 फीचर फिल्म स्टैन्ड दो लघु/एनिमिशन फिल्म और डब 134 शीर्षक भारत के प्रमुख भाषाओं में।		5.15	शून्य	3 फीचर फिल्में, 2 लघु फिल्में, 14 डबिंग, 6 उपशीर्षक, 20 फिल्में खरीदी जाएंगी।	राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मानकों की बाल फिल्में उपलब्ध कराई जाएंगी।	31.03. 2012	बच्चों के फिल्मीं कला को बढ़ावा देना और अधिक से अधिक दर्शक तक पहुंचने के लिए विभिन्न भाषाओं में 55 बिग सबटाइटिल करना।
		1. लक्ष्य : अभिलेख के उद्देश्य से डिजिटल रूप में सीएफएसआई की फिल्मों का रूपांतरण 2. (170 घंटे की फिल्मों का डिजटिलीकरण किया जाएगा)	1.55			सीएफएसआई की सभी फिल्में अभिलेख हेतु डिजिटल फॉरमेट में रूपांतरित की जाएंगी।		31.03. 2012	बाल फिल्म निर्माताओं के लिए तकनीकी स्रोत का विस्तार
		1. लक्ष्य : सीएफएसआर फिल्म (निर्माण, डब, और उपशीर्षक के लिए) डिजिटल लाइब्रेरी में बनाया जा रहा है। 2. परिव्यय बाल फिल्मों को ऑनलाइन उपलब्ध कराना				लाइब्रेरी के रूप में सीएफएसआई की सभी फिल्मों की वेबकास्टिंग तथा सीएफएसआई की फिल्मों की इंटरनेट पर उपलब्धता।	सीएफएसआई की सभी फिल्मों की वेबकास्टिंग तथा सीएफएसआई की वेबसाइट पर उनका प्रदर्शन।	31.03. 2012	फंड पर निर्भर
		1. लक्ष्य : राज्य और जिला प्रशासन, नेहरू युवा केंद्रों तथा गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से देश के सभी बच्चों तक पहुंचना। 2. परिव्यय लगभग 30 हजार शो का आयोजन				25 लाख दर्शकों को लाभांवित करने के लिए 5000 प्रदर्शनों का आयोजन।	देश के दूर-दराज के क्षेत्रों के ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचना।	31.03. 2012	फंड पर निर्भर

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम (चालू योजनाएं)	ग्यारहवीं योजना के लिए उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2010-11			वास्तविक प्रतिफल/ मात्रात्मक परिणाम (2010-11)	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/जोखिम संबंधी घटक
	1	2	3			4	5	6	7
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर-योजना बजट	योजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजट स्त्रोत				
	बच्चों की फिल्मों की नगर निगम के स्कूलों में प्रदर्शनी	1. लक्ष्य : राज्य और जिला स्तर के प्रशासन की मदद से पूरे देश में पहुंचते हैं। इसके लिए नेहरू युवा केन्द्र एनजीओ स्कूल एवं अन्य स्थलों पर प्रदर्शित करती है। परिव्यय 30,000 शो का आयोजन		0.65	शून्य	5000 शो से 25 लाख बच्चे के लिए आयोजन	दूर-दराज क्षेत्र में पहुंचने की कोशिश	31.03. 2012	फंड पर निर्भर
	महोत्सव			1.00		विश्व के फिल्मों की प्रदर्शनी ताकि भारतीय बच्चों को लाभ हो।			
	सीएफएस आईसीएफएफ संगठन	भारतीय और अंतरराष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं के विचार विनिमय के लिए मंच तैयार करना।							
	आईसीएफएफ में भागीदारी	सीएफएसआई फिल्मों को विभिन्न अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भागीदारी और मार्केटिंग के आयाम ढूढ़ने का प्रयास।							
	नई योजना								
	बाल चित्र समिति का प्रांगण								

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय
बजट परिव्यय 2011-12 की तालिका

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2011-12			मात्रात्मक लाभ/उत्पादन वास्तविक भौतिक	प्रदर्शित परिणाम	प्रक्रिया/ समयबद्धता	टिप्पणी
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर योजना बजट	योजना बजट (अनुमोदित)	पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन				
I.	**राजस्व** **(नई स्कीम)** आपूर्ति एवं सामग्री (i) आयोजित यात्रा/दक्षता उन्नयन	स्कीम का उद्देश्य नेताओं/ संसाधन व्यक्तियों की राय से परिचित कराना जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों से युवा सम्मिलित हैं जो देश के विभिन्न राज्यों में हो रहे विकास कार्यों से सम्बद्ध हैं। इस ग्रुप में सामाजिक कार्यकर्ता, गैर-सरकारी संगठन, किसान, दस्तकार, स्कूलों के अध्यापक और छात्र आदि शामिल हैं।	—	55.00	—	वर्ष 2010-11 के दौरान क्षेत्रीय कार्यलयों द्वारा 11 (ग्यारह) यात्राएं आयोजित की जाएंगी।	आयोजित यात्रा में सम्मिलित सदस्य केन्द्रीय सरकार की नीतियों और योजनाओं के संदेश वाहक हो जाते हैं। आयोजित यात्रा के सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों में संचालन में विभिन्न कल्याण स्कीमों के बारे में स्थानीय लोगों को भरोसा दिलाने में सहायक सिद्ध होते हैं।	सक्षम अधिकारी की स्वीकृति मिलने पर क्षेत्रों के साथ विचार-विमर्श के यात्रा कार्यक्रमों को अंतिम रूप देने के बाद वर्ष के दौरान यात्रा पूरी हो जाएंगी।	

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2011-12			मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम वास्तविक प्रतिफल	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i)	4(ii)	4(ii)				
			गैर-योजना बजट	योजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन				
II.	**पूंजी (नई स्कीम)**								
	(ii)आधुनिकीकरण तथा उन्नयन (अ) क्षेत्रीय कार्यालयों/ इकाइयों का कम्प्यूटरीकरण/ सॉफ्टवेयर	हाल ही में लागू सूचना का अधिकार के तहत देश में प्रत्येक नागरिक सरकार की विभिन्न योजनाओं और नीतियों की जानकारी पा सकता है। यह सूचना देशभर में फैले 22 क्षेत्रीय कार्यालयों और 207 क्षेत्रीय प्रचार इकाइयों के माध्यम से प्रदान की जाएगी तथा लोगों को लाभान्वित किया जाएगा।		321.00	-	फिल्म प्रभाग से 31 मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, 10 डी.वी.डी. प्लेयर तथा 08 डिजिटल वीडियो कैमरे, 15 वायरलैस पीए सिस्टम से अधिक से अधिक फिल्में प्राप्त करना। यथासंभव 1 प्रोग्रामर, 1 सहायक प्रोग्रामर तथा 100 डी.ई.ओ., 25 डिजिटल कैमरे, 26 वाहनों को कार्य में लगाए रखना।	उपकरणों का इस्तेमाल लोगों के बीच सूचना संप्रेषण तथा सामाजिक मुद्दों पर शिक्षित करने में होगा।	टेंडर प्रक्रिया पूरी करना आपूर्ति आर्डर देना और बिल भुगतान शर्तें पूरी होने पर वर्ष के दौरान पूर्ण हो जाएंगे।	
		कुल		**376.00**					

विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय

(लाख रुपये में)

क्र. स.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य परिणाम	परिव्यय 2011-12			परिमाणनीय/ हस्तांतरणीय/ वास्तविक प्रतिफल	परिमाणनीय/ हस्तांतरणीय वास्तविक प्रतिफल	प्रक्रिया/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम घटक
1	2	3	4			5	6	7	8
			4 (i)	4 (ii)	4 (iii)				
	प्लान योजना का नाम		गैर-योजना बजट	योजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
1	विकासात्मक प्रचार कार्यक्रम अवधारणा और प्रसार	1. स्थापना 2. प्रदर्शनी 3. डिस्प्ले वर्गीकृत 4. रेडियो स्पॉट 5. मुद्रित प्रचार वितरण 6. बाह्य प्रचार	2766.00 185.00 3242.00 200.00 240.00 - 100.00	— 200.00 1550.00 2500.00 400.00 - 850.00	— — — — — — —	— 500 15000 4800 189 — 250	सांप्रदायिक सद्भाव, राष्ट्रीय एकता, सामाजिक आर्थिक उत्थान के बारे में विभिन्न माध्यमों-बाह्य प्रचार, रेडियो, दूरदर्शन, समाचारपत्र और पोस्टर/ पुस्तिकाओं के जरिए प्रचार करने से जन समुदाय में जागरूकता पैदा होगी और विकास में उनकी भागीदारी को प्रेरित किया जा सकेगा।	आवश्यकता अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य किए जाएंगे।	
		कुल (1)	**6733.00**	**5500.00**					
2	डीएवीपी का आधुनिकीकरण	1.कम्प्यूटरीकरण और डिजिटलीकरण 2.कार्यालय ढांचा 3.मानव संसाधन विकास		— 100.00 —	— — —	— — —	कंप्यूटरीकरण और डिजिटलीकरण, कार्यालय ढांचा और मानव संसाधन विकास		
		कुल (2)		**100.00**					
		कुल (1 और 2)	**6733.00**	**5600.00**					

वित्तीय आवश्यकताएं

क्रं. सं.	गतिविधि–वार वर्गीकरण	वास्तविक 2009–10			बजट अनुदान 2010-2011			संशोधित अनुमान 2010-2011			बजट अनुदान 2011-2012		
		योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
न	प्रदर्शनी	30.00	105.81	135.81	174.00	185.00	359.00	174.00	185.00	359.00	200.00	185.00	385.00
1	डिस्प्ले तथा वर्गीकृत विज्ञापन	900.00	3530.93	4430.93	1305.00	3242.00	4547.00	1305.00	3242.00	4547.00	1550.00	3242.00	4792.00
2	रेडियो/टीवी कमर्शियल	1940.00	166.57	2106.57	2175.00	200.00	2375.00	2175.00	200.00	2375.00	2500.00	200.00	2700.00
3	वितरण सहित मुद्रित प्रकाशन	35.00	223.11	258.11	348.00	240.00	588.00	348.00	24000	558.00	400.00	240.00	640.00
4	बाह्य प्रचार	603.00	100.00	703.00	348.00	100.00	448.00	348.00	100.00	448.00	850.00	100.00	950.00
5	निदेर्श तथा सा.मा.प्रशासन	180.00	2610.53	2790.53	100.00	2261.00	2361.00	100.00	2470.00	2570.00	100.00	2766.00	2866.00
	कुल	3688.00	6736.95	10424.95	4450.00	6228.00	10678.00	4450.00	6437.00	10887.00	5600.00	6733.00	12333.00

फिल्म समारोह निदेशालय

गैर-योजना

(लाख रुपये में)

क्र. स.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य परिणाम	प्रस्तावित परिव्यय 2011-12			परिमाणनीय/ हस्तांतरणीय/ वास्तविक प्रतिफल	परिमाणनीय/ हस्तांतरणीय वास्तविक प्रतिफल	प्रक्रिया/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम घटक
1	2	3	4			5	6	7	8
			4 (i) गैर-योजना बजट	4 (ii) योजना बजट	4 (iii) पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
1	प्रतिस्थापना संबंधी खर्चे	वेतन भत्ते, ओई, डीटीई आदि	245.00		शून्य			-	
2	लघु कार्य	सीरीफोर्ट सांस्कृतिक परिसर का रख-रखाव	400.00		शून्य	कला संस्कृति तथा सिनेमा के क्षेत्र में प्रदर्शन के लिए सभागार सुज्जित करना तथा किराए पर देना	किराए से उच्च आय की उम्मीद	एक वर्ष	
3	सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के तहत फिल्म समारोह	विश्वभर में समृद्ध और विविध संस्कृति को फैलाना और विदेशों की उपस्थिति बढ़ाना	25.00		शून्य	सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के तहत भारत और विदेशों में 12 फिल्म समारोहों का आयोजन।	भारतीय सिनेमा को प्रोत्साहन तथा सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के तहत देशों के साथ संबधों को मजबूत बनाना।	सीईपी का वर्ष भर आयोजन	
4	राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार	भारत में निर्मित फिल्मों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार स्थापित कर अच्छे सिनेमा को बढ़ावा देना	250.00		शून्य	वर्ष 2010 के 58वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करना।	भारतीय कला और संस्कृति के क्षेत्र में सुधार लाना तथा बेहतर प्रतिभाओं को मान्यता प्रदान करना ताकि भारतीय सिनेमा को बेहतर बनाया जा सके।	एक वर्ष	
		कुल	920.00						

फिल्म समारोह निदेशालय

योजना

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	योजना का नाम	उद्देश्य/परिणाम	प्रस्तावित परिव्यय 2011-12			मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता
1	2	3	4			5	6	7
			गैर-योजना	योजना	*पूरक अति.ब.सं.*			
1.	भारत और विदेशों में फिल्म समारोहों के जरिए निर्यात प्रोत्साहन (योजना राजस्व) **क.** भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह **ख.** विदेशी फिल्म समारोहों में भाग लेना **ग.** भारतीय पैनोरमा फिल्मों का चयन।	इस योजना को 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया ताकि फिल्म समारोहों में भाग लेकर और निर्यात को प्रोत्साहन देकर भारतीय सिनेमा को बढ़ावा दिया जा सके।		740.00	शून्य	क. भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2011 का आयोजन। 50 देशों की समारोह में भागीदारी और चरणबद्ध तरीके से विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें लागू करना **ख.** विभिन्न देशों में आयोजित 50 विदेशी फिल्म समारोहों में भारतीय फिल्मों की भागीदारी। **ग.** 26 फीचर और 21 गैर-फीचर फिल्मों का चयन।	फिल्म समारोहों में निर्यात को प्रोत्साहन देकर बेहतर भारतीय सिनेमा को बढ़ावा देना। इससे पूरे विश्व में भारत की समृद्ध और विविध संस्कृति को सिनेमा के माध्यम से फैलाने में मदद मिलेगी। फिल्म निर्यात से भारत की 'सॉफ्ट पावर' को प्रोत्साहन मिलेगा और आर्थिक लाभ के साथ-साथ भारत में अच्छा विदेशी सिनेमा आ सकेगा	वित्तीय वर्ष 2011-12 में कार्यान्वित होगा।
2.	फिल्म समारोह परिसर-फेरबदल और अतिरिक्त निर्माण-प्रमुख कार्य (योजना पूंजी)	सीरीफोर्ट परिसर का नवीनीकरण और सुविधाओं में सुधार ताकि इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के परिसर की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।		128.00	शून्य	अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नवीनीकृत ऑडिटोरियम बनाना और कला, संस्कृति तथा सिनेमा के क्षेत्र में आडिटोरियम/ परिसर को अन्य पार्टियों को किराए पर देकर अधिक राजस्व अर्जित करना।	बेहतर सुविदाएं प्रदान कर आशा की जाती है कि किराए से हो रही आमदनी बढ़ेगी	वित्तीय वर्ष 2011-12 में कार्यान्वित होगा।

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	योजना का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2011-12			मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता
1	2	3		4		5	6	7
3.	डीएफएफ में प्रिंट यूनिट का उन्नयन (पूंजी अनुभाग)	इस नई योजना के अंतर्गत फिल्म समारोह निदेशालय को एक तकनीकी रूप से सुसज्जित प्रिंट यूनिट प्रदान की जाएगी जिससे प्रिंटों के लम्बे समय तक भंडारण में मदद मिलेगी। यह फिल्म समारोहों के जरिए भारत तथा विदेश में निर्यात संवर्धन की योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के मंतव्य से है।		100.00	शून्य	भारतीय पेनोरमा फिल्मों का डिजिटली-करण तथा एलटी-04 जैसे प्लेयर को खरीदना।	आदर्श ताप और आद्रता पर फिल्म प्रिंटों के उचित परिरक्षण के साथ साथ डिजिटलीकरण। भारतीय तथा विदेशी फिल्म समारोहों में भारतीय फिल्मों की भागीदारी के जरिए अच्छे भारतीय सिनेमा के निर्यात को बढ़ावा देना जिससे समृद्ध भारतीय संस्कृति को बढ़ावा मिल सके।	वर्ष 2011-12 में कार्यान्वित होगा।
		कुल		968	शून्य			

फिल्म प्रभाग

योजना

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/उपलब्धियां	वित्तीय परिव्यय (यो.ब.) 2011-12	वास्तविक/मात्रात्मक उपलब्धियां	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/अवधि	टिप्पणी/ जोखिम के घटक
1	अन्तर्राष्ट्रीय वृत्तचित्र, लघु और एनिमेशन फिल्म समारोह	मुंबई में दो-वर्षीय अंतर्राष्ट्रीय वृत्तचित्र, लघु एवं एनीमेशन फिल्म समारोह आयोजित करना। 11वीं योजना अवधि में 3 फिल्म समारोह	250.00	12वां एमआईएफएम (मिफ्फ) आयोजित करना (उसे 9 फरवरी 2010 तक चलेगा)। देश में वृत्तचित्र अभियान को प्रोत्साहन; वैश्विक स्तर पर भारत की सकारात्मक छवि का प्रदर्शन। 11वें एमआईएफ (मिफ्फ) 2012 की तैयारी शुरू जो 3-9 फरवरी 2012 को आयोजित होगा।	यह डाक्यूमेंट्री निर्माणताओं को डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा।	द्विवार्षिक मिफ्फ समारोह में विश्व भर से फिल्मकारों द्वारा आवेदन पत्र/प्रविष्टियां आमंत्रित की जाती हैं और प्रतिष्ठित ज्यूरी की सिफारिश पर भागीदारों को 28.50 लाख राशि के पुरस्कार। इस दौरान डाक्यूमेंटरी और लघु फिल्मों के क्षेत्र में लाइफटाइम अचीवमेंट के लिए डा. वी शांताराम पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है।	विशिष्ट जोखिम नहीं
2	प्रभाग की फिल्मों का डिजीटलीकरण तथा वेबकास्टिंग	इंटरनेट के माध्यम से फिल्म प्रभाग की डॉक्यूमेंट्री, लघु तथा एनिमेशन फिल्मों का दुनियाभर में प्रचार। इसके लिए आर्काइव की सभी 6 फिल्मों का डीवीडी में ट्रांसफर 1 हाई डेफिनिशन तकनीक का प्रयोग। फिल्म प्रमाग	200.00	फिल्म प्रभाग की फिल्मों की, वेबकास्टिंग के लिए इसे स्वातंत्र्योत्तर भारत की ऑडियो-वीजुअल इनसाइक्लोपिडिया से जोड़ना तथा प्रभाग की फिल्मों को डिजिटल फॉरमेट में हस्तांतरण। **मात्रात्मक उपाय** फिल्म कंटेंट का वेबसाइट के अनुसार अंतरण यानी डीवीडी	इससे इंटरनेट के माध्यम से लोग फिल्म प्रभाग की फिल्मों से जुड़ सकेंगे।	बाहरी एजेंसी द्वारा फिल्मों का वेबसाइट पर इनकोड किया गया है। फिल्मों का डीवीडी में हस्तांतरण के लिए टेंडर आमंत्रित किए गए हैं। वेबकास्टिंग एक सतत प्रक्रिया है। फिल्मों का डिजीटलीकरण का कार्य 11वीं योजना अवधि के दौरान पूरा कर लिया जाएगा।	कोई जोखिम नहीं।

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम	उद्देश्य/उपलब्धियां	वित्तीय परिव्यय (ब.अ.) 2010-11	वास्तविक मात्रात्मक उपलब्धियां	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/अवधि	टिप्पणी/ जोखिम के घटक
		की फिल्में वेबसाइट www.filmsdivision.org पर उपलब्ध हैं।		अंतरण। तकरीबन 7443 फिल्मों का हाईडेफिनेशन के माध्यम से डिजीटलीकरण हो चुका है। 688 फिल्मों का इस फॉरमेट में हस्तांतरण बाकी है।			
3.	डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का निर्माण	समय की जरूरत को ध्यान में रखते हुए पूर्वोत्तर तथा जम्मू-कश्मीर के फिल्म निर्माताओं तथा जनता को मुख्य धारा में लाना। उनके लिए डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना प्रस्तावित है। ये फिल्में सामाजिक मुद्दों पर होंगी तथा समाधानपरक होंगी।	700.00	इन क्षेत्रों के लोगों को डाक्यूमेंट्री फिल्मों के माध्यम से जागरुक बनाना तथा उन्हें राष्ट्र निर्माण के लिए अग्रसर करना। सरकार का ऐसा प्रयास है। **मात्रात्मक उपाय** 11वीं पंचवर्षीय योजना में यह एक नयी योजना शामिल की गई है। मंत्रालय के निर्देशानुसार फिल्म प्रभाग ने पीएसबीटी के साथ डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के निर्माण के लिए समझौता किया है।	इन क्षेत्रों के लोगों को डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के माध्यम से जागरुक बनाना तथा उन्हें राष्ट्र निर्माण के लिए अग्रसर करना सरकार का ऐसा प्रयास है।	इन क्षेत्रों के लोगों को डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के माध्यम से जागरुक बनाना तथा उन्हें राष्ट्र निर्माण के लिए ग्रसर करना सरकार का ऐसा प्रयास है।	कोई जोखिम नहीं।

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम	उद्देश्य/उपलब्धियां	वित्तीय परिव्यय (ब.अ.) 2010-11	वास्तविक मात्रात्मक उपलब्धियां	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/अवधि	टिप्पणी/ जोखिम के घटक
4.	मूविंग इमेज संग्रहालय की स्थापना। इसका वैकल्पिक नाम होगा - नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा (एनएमआईसी)	आंगुतकों/फिल्म प्रेमियों के लाभार्थ प्रख्यात निर्देशकों, निर्माताओं, संस्थानों, आदि की कृतियों का प्रदर्शन और फिल्म निर्माण से संबंधित सामग्री दर्शाने के लिए एक स्थाई संग्रहालय की स्थापना करना। इसके बाद फिल्म निर्माताओं तथा फिल्म छात्रों के लिए सेमिनार, कार्यशाला आदि आयोजित करना।	6251.00	फिल्म प्रभाग, मुम्बई में एक संग्रहालय की स्थापना करना, जिसमें दृश्य-श्रव्य माध्यम से भारतीय सिनेमा का इतिहास और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फिल्म निर्माण सामग्री दर्शाई जाएगी। **मात्रात्मक उपाय** प्रचार प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर मुंबई में एनएमआईसी संग्रहालय की स्थापना करना। योजना स्कीम के तहत मंत्रालय वास्तविक तथा वित्तीय विकास का प्रत्यक्ष निगरानी करता है। ईएफसी प्रस्ताव 116.40 रु. का स्वीकृत हुआ है तथा फिल्म प्रभाग एवं एनबीसीसी के बीच समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं। संग्रहालय निर्माण के लिए कार्य शुरू हो चुका है।	एनबीसीसी द्वारा तैयार परियोजना रिपोर्ट के आधार पर फिल्म प्रभाग, मुम्बई में एमओएमआई नामक संग्रहालय की स्थापना करना।	परियोजना 2011-12 के अन्त तक पूरी हो जाएगी।	निश्चित अवधि से अधिक समय लगने का जोखिम, क्योंकि यह प्लान स्कीम एनबीसीसी द्वारा परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और उसके द्वारा ठेके देने से सीधे संबंधित है।

फिल्म प्रभाग

गैर योजना

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/उपलब्धियां	वित्तीय परिव्यय (यो.ब.) 2011-12	वास्तविक/मात्रात्मक उपलब्धियां	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/अवधि	टिप्पणी/ जोखिम के घटक
1	उत्पादन	लोगों को सूचित करने जागरूक करने, प्रोत्साहित करने तथा सांस्कृतिक उन्नयन के मद्देनजर भारत सरकार की जरूरतों के अनुसार डॉक्यूमेंट्री, एनिमेशन तथा लघु फिल्में बनाना मुख्य उद्देश्य। देश भर के लोगों तथात संस्थाओं को उनकी जरूरत के अनुसार वीसीडी फॉरमेट में लघु फिल्मों, एनिमेशन, डाक्यूमेंट्री की बिक्री तथा वितरण सुनिश्चित करना।	1378.08	36	सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं, विकास कार्यों के बारे में लोग जानकारी पा सकेंगे इससे उन्हें जानकारी मिलेगी तथा वे प्रोत्साहित होंगे।	01.04.11 से 31.03.2012	अनुमान है कि अधिकाधिक डॉक्यूमेंट्री का निर्माण होगा। चूंकि न्यूज मैगजीन के निर्माण में कमी आई है।
2	थिएटरों में डॉक्यूमेंट्री का वितरण	दस शाखा कार्यालयों के नेटवर्क के द्वारा डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का वितरण। स्टॉक शॉट्स की बिक्री केवल मुंबई स्थित मुख्यालय से।	1952.28	किराए में 1% कमी का प्रस्ताव विचाराधीन है। इसलिए संभवत किराया न हो। हालांकि फिल्म प्रभाग की फिल्में काफी संख्या में फिल्म थिएटर वाले लेते हैं तथा उन्हें पर्दे पर दिखाते हैं।	सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं, विकास कार्यों के बारे में लोग जानकारी पा सकेंगे इससे उन्हें जानकारी मिलेगी तथा वे प्रोत्साहित होंगे।	01.04.11 से 31.03.2012	थिएटर के लिए डॉक्यूमेंट्री जारी करना।

भारत और विदेशों में आयोजित फिल्म बाजारों में भागीदारी

सूचना और प्रसारण मंत्रालय फिल्म विंग की मुख्य सचि. स्कीम

(करोड़ रुपये में)

क्रं. सं.	योजना कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2011-12			परिमाणनीय/वितरण योग्य वास्तविक आउटपुट	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	टिप्पणियां/ जोखिम घटक
1	2	3	4			5	6	7	8
			(i) नॉन बजट	(ii) प्लान	(iii) प्लान बजट				
1.	विदेशी फिल्म समारोहों/ बाजारों में भागीदारी	भारतीय फिल्मों के निर्यात को प्रोत्साहित करना और भारतीय फिल्मों के लिए बाजार का विस्तार करने के लिए फिल्मों को एक उद्योग के रूप में मजबूती प्रदान करना		4.20		अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म बाजारों और विदेशों में भागीदारी का कार्य एनएफडीसी को सौंपा गया है। भारतीय फिल्मों को विश्वस्तर पर बढावा देने के लिए एनएफडीसी ने निम्नलिखित अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में भागीदारी का प्रस्ताव किया है– (1) केंस अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह एवं बाजार, फ्रांस (मई, 2011) (2) सनी साइड ऑफ दी डॉक; फ्रांस (डॉक्यूमेंट्री मार्केट) जून, 2011 (3) एमआईपीसीओएम, फ्रांस (अक्टूबर, 2011) (4) ईएफएम, बर्लिन, जर्मनी (फरवरी, 2011) (5) हांगकांग फिल्म मार्ट (मार्च, 2012)	भारतीय फिल्मों के विश्व बाजार में अधिक से अधिक दिखाने और भारतीय फिल्मों के निर्यात को बढाना भारत को फिल्म शूटिंग केन्द्र के रूप में बढ़ावा देने से राजस्व बढ़ोतरी	अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म बाजारों और विदेशों में भागीदारी का कार्य एनएफडीसी को सौंपा गया है। (1) इस प्रयोजन के लिए ''भारत और विदेशों में फिल्म बाजारों में भागीदारी'' शीर्ष के अन्तर्गत सूचना और प्रसारण मंत्रालय को उपलब्ध कराए गए वार्षिक बजट आवंटन को एनडीएफसी के निपटान पर कर देना चाहिए। (2) अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों जैसे कि अमरीकन फिल्म मार्केट, बर्लिन, केंस, टोरोंटो आदि में जहां सूचना और प्रसारण मंत्रालय को भाग लेना है इस संबंध में प्रत्येक वर्ष समय रहते निर्णय लेने के साथ इसकी रचना एनडीएफसी को दे देनी चाहिए ताकि तदनुसार वे इसकी आवश्यक अवस्था कर सकें। (3) इन अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों के प्राप्त परिणामों की रिपोर्ट सूचना और प्रसारण मंत्रालय को एनएफडीसी द्वारा प्रस्तुत	कॉलम 5 में दिए गए वितरण योग्य परिणामों के अतिरिक्त दृश्यता बढ़ाने की अन्य पहलों के लिए व्यय हो सकता है।

2.	ऐनीमेशन, गेमिंग और विशेष प्रभाव के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना संबंधी नई योजना	उच्च प्रौद्योगिकी विषयवस्तु उद्योग में कार्मिकों की समस्या के समाधान के लिए ऐनीमेशन, गेमिंग और विशेष प्रभाव में उत्कृष्टता के लिए सरकारी–निजी भागीदारी में केंद्र की स्थापना।	–	100.00	–	(i) एम/एस पीडब्ल्युसी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और उत्कृष्टता केंद्र और बीएफएक्स की स्थापना के लिए सिफारिश की है। (ii) एम/एस पी डबल्यु सी द्वारा सौंपे गए विचारार्थ विषयों को अंतिम रूप दिया जा चुका है और डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। (iii) संपूर्ण स्कीम के लिए योजना आयोग का अनुमोदन	विस्तृत डीपीआर के आधार पर तथा नई स्कीम पर सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त करना।	परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद 'उत्कृष्टता केंद्र' की स्थापना के लिए अपेक्षित धन की व्यवस्था और स्थापना में लगने वाले समय के मुद्दे स्पष्ट होंगे।	यह योजना सरकारी–निजी भागीदारी में लागू की जानी है। इसलिए निजी पार्टियों के योगदान की पहचान करनी होगी।

योजना

भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे

मंत्रालय/विभाग : सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

वार्षिक योजना की समीक्षा (2011-12)

(करोड़ रुपये में)

परिव्ययों और परिणामों/लक्ष्यों का विवरण (2011-12) (परिणाम बजट 2011-12 के अनुसार) तथा वास्तविक उपलब्धि

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2011-12	निर्धारणीय/वितरणीय भौतिक परिव्यय	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम घटक
1	2	3	4	5	6	7	8
(अ)	चालू योजनाएँ						
(i) (i)	**संस्थान को अनुदान राशि** मशीनरी एवं उपकरण	(i) फिल्म तथा टीवी उद्योग दोनों में आधुनिक एवं तकनीकी प्रगति के अनुरूप पुराने एवं अप्रचलित उपकरणों के स्थान पर नये उपकरणों की खरीद और संसाधनों में वृद्धि। (ii) नई तकनीकों जैसे हाई डेफिनेशन टी.वी., विकसित कंप्यूटर एनिमेशन, डिजिटल फिल्म रिकार्डिंग आदि का समावेश। (iii) एफटीआईआई के स्वर्ण जयंती वर्ष समारोह के आयोजन तथा ढांचागत विकास के लिए अतिरिक्त आवश्यकता है।	4.50	सामान प्राप्त हो गया है और मंत्रालय के एसएफसी के अनुमोदन के मुताबिक कार्य संपन्न कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष शुरू होने से पहले ही त्रैमासिक भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य तय कर दिए गए हैं और उपलब्धि की विभागीय बैठकों, मासिक व्यय रिपोर्टों और मंत्रालय के अर्द्धवार्षिक निष्पादन के माध्यम से नजदीकी से निगरानी की जाती है।	विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त संख्या में अत्यधिक उन्नत प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराना। क्षेत्र में आधुनिक प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षण प्रदान करना	**प्रकियाएं :** (1) उपयोगकर्ता विभाग से इंडेंट प्राप्ति (2) जब भी आवश्यक हो समाचार पत्रों में टेंडर प्रकाशन के लिए कोटेशन मंगाना (3) विशिष्ट अवधि के बाद कोटेशनों/टेंडरों को खोलना तथा जांचना (4) वित्तीय अनुमोदन प्राप्त करना (5) आपूर्ति/खरीद/निष्पादन आदेश देना (6) उपयोगकर्ता विभाग द्वारा सामग्री/सामान का निरीक्षण (7) मात्रा/गुणवत्ता इत्यादि के लिए सामानों की जांच रिपोर्ट/ खरीद आदेश में उपकरण का प्रदर्शन और अन्य शर्तों की जांच। विभागीय बैठकों में समयबद्धता पर विचार किया जाता है और त्रैमासिक भौतिक और वित्तीय लक्ष्य सुनिश्चित करने के लिए संबंधित कार्य योजना की तिथि बताई जाती है।	उपलब्धियों निधियों की उपलब्धता और संस्थान के नियंत्रण से परे किसी अन्य कारक पर आधारित है।

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2011-12	निर्धारणीय/वितरणीय भौतिक परिव्यय	प्रक्षिप्त परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम घटक
(ii)	भवन निर्माण	छात्रों के रहने तथा कार्यक्रमों के लिए वर्तमान में स्थान की कमी है। वर्तमान योजना मंत्रालय की संस्तुति के साथ-साथ जहां कहीं व्यवहार्य हो एफटीआई की इमारतों के कुछ भागें के वर्टिकल विस्तार तथा 100 कमरों के छात्रावास निर्माण की है। एक आधुनिक संसाधन तथा ज्ञान केंद्र की याजेना भी है। जैसे पुस्तकालय, ई-पुस्तकालय, इंटरनेट, विद्यार्थी केंद्र, फैकल्टी के लिए विचार-विमर्श कक्ष तथा वीडियो कांफ्रेंसिंग केंद्र का समन्वय नई मशीनरी और उपकरणों के लिए ढाँचागत बदलाव तथा स्वर्ण जयंती वर्ष समारोह के लिए इमारतों के नवीकरण के लिए भी अतिरिक्त निधियों की जरूरत है।	2.81	100 कमरों वाले छात्रावास का निर्माण कार्य प्रगति पर है।	विद्यार्थियों की बढ़ती संख्या की पूर्ति के साथ-साथ संस्थान में उनके ठहरने को आरमदायक और उत्पादक बनाने के लिए बुनियादी ढांचे को बढ़ाना	नागरिक प्राधिकरणों को अनुमति तथा उपलब्धियां विधियों की उपलब्धता और संस्थान के नियंत्रण से परे किसी अन्य कारक पर आधारित है।	
(iii)	कम्प्यूटरीकरण तथा आधुनिकीकरण		0.15		कम्प्यूटरीकरण और आधुनिकीकरण के जरिए श्रमशक्ति सहित उपलब्ध संसाधनों का श्रेष्ठतम उपयोग		

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2011-12	निर्धारणीय/वितरणीय भौतिक परिव्यय	प्रक्षिप्त परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम घटक
(iv)	सामुदायिक रेडियो की स्थापना	विद्यार्थियों को रेडियो प्रोग्रामिंग के क्षेत्र में शोध तथा प्रशिक्षण उपलब्ध कराना	0.46	10वीं योजना की समाप्ति के साथ ही रेडियो कार्यक्रम नियमित रूप से प्रसारित किए जा रहे हैं। निर्माण रिले तथा प्रसारण प्रणाली की देख रेख के लिए प्रावधान किया गया है।	स्कीम का उद्देश्य भावी रोजगार एवं क्षेत्र में उत्कृष्टता की क्षमता बढ़ाने के लिए संस्थान में प्रशिक्षण की गुणवत्ता का मूल्य संवर्धन करना है।		
(v)	कैप्टिव टीवी चैनल की स्थापना	छात्रों को प्रोग्रामिंग तथा प्रसारण के क्षेत्र में प्रयोग तथा रचनात्मकता के अवसर उपलब्ध कराने के एकमात्र उद्देश्य वाली यह स्कीम 10वीं योजना से ही चलाई जा रही है। मुख्य विचार लक्षित श्रोताओं के साथ नजदीकी और सीधी बातचीत करना है।	0.40	कार्यक्रमों की शूटिंग हो चुकी है और अतिरिक्त शूटिंग और बाद में इसके प्रसारण की व्यवस्था की जा रही है।	.. वही ..		
(vi)	एच.आर.डी पक्ष जिसमें छात्रों के लिए छात्रवृति तथा विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ कार्यक्रमों का आदान-प्रदान शामिल है।	1. एफ.टी.आई. की गतिविधियों को और आगे बढ़ाना। छात्रों एवं संकाय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक गतिविधियों का अध्ययन एच.आर.डी. कार्यक्रम के आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाना। 2. एफटीआईआई के स्वर्णजयंती वर्ष आयोजन के अंतर्गत उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार, सम्मेलनों, कार्यशालाओं, अनुसंधान तथा फेलोशिप आयोजन के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता है।	1.00	आदान-प्रदान कार्यक्रम की गतिविधि से छात्र अपने क्षेत्र से बाहर निकलकर, फिल्म स्कूलों से मिलकर फिल्म निर्माण के नये विचार प्राप्त करेंगे ताकि अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में आधुनिक तकनीक से परिचित हों। एफटीआईआई की योजना है कि भारत के विश्वविद्यालयों एवं फिल्म स्कूलों के साथ-साथ देश में अपनी गतिविधि बढ़ाएं। संकाय/स्टाफ का	स्कीम का उद्देश्य उद्योग में उपलब्ध श्रेष्ठ प्रथाओं के अनुरूप विद्यार्थियों के कौशल को बढ़ाने के लिए मूल्य संवर्धन करना है।		

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2011-12	निर्धारणीय/वितरणीय भौतिक परिव्यय	प्रक्षिप्त परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम घटक
				प्रशिक्षण, प्रशिक्षण से संबंधित पत्रिका जैसे लेनसाईट का प्रकाशन खरीद, सेमिनार, लेक्चर, सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि का आयोजन, एचआरडी संबंधी पुस्तकों की खरीद तथा लाइब्रेरी के लिए डीवीडी की खरीद। एफटीआईआई के स्वर्णजयंती वर्ष आयोजन के तहत उच्च स्तरीय सेमिनार, सम्मेलन, कार्यशालाएं, अनुसंधान तथा फेलोशिप आयोजित करना।			
		कुल : (क)	**9.32**				

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2011-12	निर्धारणीय/वितरणीय भौतिक परिव्यय	प्रक्षिप्त परिणाम	प्रक्रिया/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम घटक
(ब)	**नयी योजना**						
	वैश्विक फिल्म स्कूल (नया)	एफटीआईआई इंटरनेट प्रौद्योगिकी, वायर के साथ साथ सेटेलाइट के जरिए लाभ उठाने की सोच रही है ताकि अपने सभी भागों को देश में और देश के बाहर जोड़ सके और इस प्रकार ग्लोबल फिल्म स्कूल का हिस्सा बन सके।	2.00	यह नई स्कीम है। अनुमानित खर्च सिनेमेटोग्राफी तथा टीवी इंजीनियरिंग विभाग के लिए मशीनरी तथा उपकरण के लिए है, मास्टर प्लान में ऑडिटोरियम, क्लास रूम थिएटर, अंदर की सड़क पार्किंग शेड, पैदल चलने वालों का क्षेत्र तथा इमारत निर्माण कार्य शामिल है जिसमें प्रशासनिक भवन, स्टूडियो फ्लोर, ऑडिटोरियम प्रिव्यू थिएटर, छात्रावास तथा स्टॉफ क्वार्टर शामिल हैं।	बुनियादी ढांचे को उन्नत बनाकर संस्थान को गुणवत्ता के मामले में विश्व के श्रेष्ठ संस्थानों के तुलनीय बनाना	वैश्विक फिल्म स्कूल की परिकल्पना ओर प्रस्ताव मौजूदा संस्थान को वैश्विक स्तर का बनाने के लिए एफटीआईआई के पाठ्यक्रम और मौजूदा बुनियादी ढांचे को उन्नत बनाना है। इसके उद्देश्यों और लक्ष्यों में वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्द्धा स्तर के लिए फिल्म और मीडिया के क्षेत्र में दक्षता बढ़ाने के लिए एफटीआईआई के विद्यार्थियों को तैयार करना तथा अन्य देशों से विद्यार्थियों को एफटीआई की तरफ आकर्षित करना और एफटीआईआई को फिल्म एवं मीडिया के क्षेत्रों में वैश्विक उत्कृष्ट केन्द्र बनाना शामिल है। एफटीआईआई के वैश्विक मानकों तक उन्नयन के लिए डीपीआर तैयार की जा रही है तथा शीघ्र ही अनुमोदन के लिए इसे मंत्रालय में पेश किया जाएगा।	
		(ब)	2.00				
		कुल : (अ + ब)	11.32				

सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता

परिणाम/लक्ष्य 2011-12 (प्लॉन) परिणाम बजट के

(करोड़ रुपये में)

क्रं. सं.	स्कीम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	2011-12 के लिए अनुमोदित परिव्यय (रुपया करोड़ में) 4i नॉन प्लान बजट		प्लान बजट	वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	टिप्पणियां/ जोखिम घटक
1.	सत्यजीत रे फिल्म एवं टीवी विजन संस्थान कोलकाता	संस्थान का मूल उद्देश्य फिल्म एवं टीवी उद्योग के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों को मुहैया कराना है, संस्थान निर्देशन तथा पटकथा लेखन, चलचित्र फोटोग्राफी, संपादन और साउंड रिकार्डिंग में प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। कुल 120 छात्रों की क्षमता संस्थान के तीन समवर्ती बैचों में फैली है।	7.00		पूरक अतिरिक्त बजट स्रोत	फिल्म उद्योग में सारी विधाओं के जानकार लोगों को वार्षिक तौर पर निकलते हैं। यह संस्था से प्रतिवर्ष छात्र फिल्म उद्योग के लिए निकलते हैं।	संस्था फिल्म एवं टेलीविजन उद्योग को उच्च दर्जे का फिल्मों का ज्ञान प्राप्त लोगों को मुहैय्या करवाता है।	**माध्यमिक/अंतिम** अंतिम वर्ष बैच (2007-10 सत्र का छठा बैच) के 37 छात्र अपनी अंतिम परियोजनाएं पूरी कर रहे होंगे। परियोजना अवधि में 30 मिनट अवधि की 10 लघु फिल्में (डिप्लोमा फिल्में) निर्मित की जाती हैं। 2008-11 सत्र का 9वां बैच तथा 2009-13 का 10वां बैच (जूनियर) परियोजना कार्य सहित निर्धारित समयसीमा के मुताबिक अपने पाठ्यक्रमों का अध्ययन कर रहा होगा। इस अवधि में 2010-14 के 10वें नए बैच के प्रवेश का कार्य शुरू किया जाएगा।	1. अनुमानित परिणाम/प्रतिफल की उपलब्धि धन की उपलब्धता पर निर्भर करती है। 2. संस्थान के नियंत्रण से बाहर का कोई कारक

(करोड़ रुपये में)

क्रं. सं.	स्कीम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	2010-11 के लिए अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	टिप्पणियां/ जोखिम घटक
1.	एस आर एफ टी आई कोलकाता में केप्टिव टीवी चैनल स्कीम	स्कीम एसआरएफटीआई, कोलकाता में ''ए फीडर टेलीविजन सॉफ्टवेयर बेस'' के विकास के विचार से शुरू की गई।	0.01	स्कीम समाज तथा सामुदायिक विकास के लक्ष्य के साथ नए उभरते स्थानीय टी वी नेटवर्क की आवश्यकताओं को पूरा करने के ऑन लाइन टीवी के क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए नए रास्ते खोलेगी।	स्कीम का उद्देश्य प्रशिक्षण की गुणवत्ता में नए मूल्य जोड़ना है जिससे छात्रों को भविष्य में रोजगार के अवसर बढ़ सकें तथा क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकें।		1. स्कीम के लक्ष्य की उपलब्धि धन की उपलब्धता पर निर्भर करती है। 2. लाइसेंस के लिए सरकारी अनुमति की प्राप्ति 3. संस्थान के नियंत्रण से बाहर का कोई कारक
2.	एस आर एफ टी आई में सामुदायिक रेडियो	स्कीम का मुख्य उद्देश्य रेडियो के क्षेत्र में छात्रों को ऑन-लाइन प्रशिक्षण देना है।	0.08	स्कीम परिवार कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्थानीय रुचि खासकर मनोरंजक कार्यक्रमों जैसी जन जागरूकता के लिए है।	स्कीम का उद्देश्य प्रशिक्षण की गुणवत्ता में नए मूल्य जोड़ना है जिससे छात्रों को भविष्य में रोजगार के अवसर बढ़ सकें तथा क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकें। एक बार परियोजना समेकित हो जाए तो सरकारी विभागों, अंतर्राष्ट्रीय निकायों से रेडियो कार्यक्रम प्रायोजित होने लगेंगे जिससे निर्माण लागत आंशिक या पूरी निकल आएगी।	बेसिल ने परियोजना चालू करने का कार्य पूरा कर लिया है और प्रसारण लाइसेंस प्राप्त कर लिया है। 24 मई 2008 को सी आर सी का प्रसारण शुरू हो चुका है। तब से कार्यक्रम नियमित प्रसारित हो रहे हैं। लाइसेंस के नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, कार्यक्रमों की विषयवस्तु को विविधता प्रदान की जाएगी, प्रसारण समय 3 घंटे (सुबह) से +2 घंटे पुनः प्रसारण कर बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे।	1. लक्ष्य उपलब्धि धन की उपलब्धता पर निर्भर करती है। 2. संचालन लाइसेंस का नवीनीकरण तथा फ्रीक्वेंसी लाइसेंस 3. संस्थान के नियंत्रण से बाहर के कारक

(करोड़ रुपये में)

क्रं. सं.	स्कीम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	2010-11 के लिए अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता माध्यमिक/अंतिम	टिप्पणियां/ जोखिम घटक
3.	एस एआर एफ टी आई में छात्रवृत्ति तथा आदान-प्रदान कार्यक्रम सहित एच आर डी पहलू	स्कीम की परिकल्पना फिल्म निर्माण में उभरते चलन तथा प्रौद्योगिकी पर ज्ञान की आपसी समझ साझा करने के उद्देश्य से प्रतिष्ठित विदेशी फिल्म स्कूलों के साथ निरंतर छात्र/ संकाय-आदान प्रदान करना है।	0.20	1. छात्र आदान प्रदान कार्यक्रम आयोजित करना 2. छात्रवृत्ति अनुदान 3. राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सवों में भागीदारी आयोजित करना	स्कीम का उद्देश्य नए मूल्यों के साथ प्रशिक्षण में गुणवत्ता बढ़ाना है जिससे भविष्य में रोजगार के अवसर बढ़ सकें।	छात्र आदान प्रदान कार्यक्रम का अगला चरण शुरू किया जाएगा, छात्रवृत्ति/इंटर्नशिप कार्यक्रम जअंतराष्ट्रीय आदान-प्रदान कार्यक्रम जारी रहेंगे।	1. लक्ष्य उपलब्धि धन की उपलब्धता पर निर्भर करती है। 2. संचालन लाइसेंस का नवीनीकरण तथा फ्रीक्वेंसी लाइसेंस 3. संस्थान के नियंत्रण से बाहर के कारक
4.	प्रशिक्षण और कौशल विकास डब्ल्यु. आर. टी. सामाजिक सुसंगत फिल्म निर्माण	परियोजना अनिवार्य रूप से संस्थान द्वारा फिल्म एवं टीवी के क्षेत्र में नौजवान छात्रों को दिए जा रहे प्रशिक्षण में वांछित मूल्य वर्धन करना है। स्कीम के तहत प्रस्तावित तत्वों से संस्थान की मौजूदा प्रशिक्षण गतिविधियों को और बढ़ाएंगी जिससे उद्योग की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो रहे छात्रों को सहायता मिल सके।	1.00	1. फिल्म और टी वी के क्षेत्र में आधुनिक प्रौद्योगिकी विकास के साथ परिचय कराने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना 2. सामाजिक रूप से सुसंगत फिल्मों का निर्माण 3. न्यूज लैटर का प्रकाशन	सिनेमा और टीवी के क्षेत्र में आधुनिक प्रौद्योगिकीय बदलावों से परिचय में स्कीम संकाय सदस्यों की मदद करेगी। स्थानीय कार्यक्रम में कलाकार प्रसिद्ध राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के साथ विचारों के आदान प्रदान में सहायता करेंगे। छात्रों को भी इस अवसर पर बातचीत का मौका मिलेगा फिल्म निर्माण के प्रावधान से निर्माण में छात्रों को सीधा अनुभव मिलेगा जो उनके कैरियर की चुनौतियों से निपटने में मददगार साबित होगा अपनी फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन	1. संकाय चक्रानुक्रम में फिल्म निर्माण और उससे संबंधित पहलुओं पर लघु पाठ्यक्रम शुरू करेगा। उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों, सेमिनारों, महोत्सवों में जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। 2. स्थानीय कार्यक्रमों में अंतराष्ट्रीय-राष्ट्रीय कलाकार होंगे जिनसे छात्र-संकाय को बातचीत का मौका मिलेगा। 3. छात्रों की भागीदारी से योजना वर्षों में संकाय पूरी फीचर फिल्म तथा वृत्त चित्र का निर्माण करेगा।	1. लक्ष्य उपलब्धि धन की उपलब्धता पर निर्भर करती है। 2. संचालन लाइसेंस का नवीनीकरण तथा फ्रीक्वेंसी लाइसेंस

(करोड़ रुपये में)

क्रं. सं.	स्कीम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	2010-11 के लिए अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता माध्यमिक/अंतिम	टिप्पणियां/ जोखिम घटक
					से उन्हें संस्थान के छात्र के रूप में अपनी प्रतिभा आकलन का अवसर मिलेगा।	4. स्कीम में छात्र फिल्मोत्सव 'क्लेप्स्टिक' तथा 'डोसेज' छात्रों तथा फिल्मकारों के बीच फिल्म जागरूकता फैलाएंगे। 5. संस्थान अपनी अकादमिक तथा अन्य गतिविधियों को प्रमुखता से द्विवार्षिक न्यूज लैटर (टेकवन) में प्रकाशित करेगा।	
5.	मानव शक्ति के प्रावधान सहित ढांचे के कंप्यूटरी-करण तथा आधुनिकी-करण का प्रावधान	फिल्म और टीवी के क्षेत्र में एक साथ तीन बैचों के छात्रों के लिए पेशेवर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए फिल्म संस्थान में अपेक्षित ढांचा (उपकरण आधार) और पर्याप्त मानव शक्ति बढ़ाने के लिए परियोजना	3.35	• नए फिल्म स्टूडियो तथा फिल्म अभिलेखागार का निर्माण • नए स्थाई/अर्द्ध स्थाई सेटों का निर्माण • उपकरण, कंप्यूटर तथा सॉफ्टवेयर की प्राप्ति, ईआरपी का क्रियावयन • आत्म विश्वास प्राप्त करने के लिए मानवशक्ति की नियुक्ति	संस्थान स्थापित करने का उद्देश्य पूरा होगा और संस्थान आत्मनिर्भर बनेगा। छात्र समुदाय लाभांवित होगी और अपने पाठ्यक्रम समय से पूरा कर सकेगी। नियमित गतिविधियों को व्यवस्थित करने पर, संस्थान का और विकास होगा और भारतीय मीडिया की गुणवत्ता में सुधार होगा।	सीसीडब्ल्यु, एआईआर द्वारा निर्माण और रूपांतरण कार्य हाथ में लिया जाएगा। विभागीय खरीद से ही उपकरण प्राप्ति होगी। इसके लिए मंत्रालय द्वारा निर्धारित नियमों के मुताबिक मानवशक्ति की नियुक्ति की जाएगी	1. लक्ष्य उपलब्धि धन की उपलब्धता पर निर्भर करती है। 2. संचालन लाइसेंस का नवीनीकरण तथा फ्रीक्वेंसी लाइसेंस 3. संस्थान के नियंत्रण से बाहर के कारक

(करोड़ रुपये में)

क्रं. सं.	स्कीम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	2010-11 के लिए अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता माध्यमिक/अंतिम	टिप्पणियां/ जोखिम घटक
6.	एनीमेशन तथा इलेक्ट्रॉनिक इमेजिंग विभाग	पिछले कुछ वर्षों में, दृश्य-श्रव्य निर्माण की दुनिया में अभूतपूर्व बदलाव आया है। इनमें सबसे बड़ा क्षेत्र एनीमेशन तथा मल्टी-मीडिया संबंधी एप्लीकेशन हैं जो तेजी से विकसित हुई हैं। एनीमेशन की प्रसिद्ध और समृद्धि जग जाहिर है जिसके बारे में विस्तार से कहने की आवश्यकता नहीं। एनीमेशन फिल्मों के अतिरिक्त वेब संबंधी एप्लीकेशन तथा मल्टी मीडिया सीडी-रोम्स/ गेम्स डेवलपमेंट का विशाल बाजार और संभावनाएं हैं। अगले पांच वर्षों में भारत एनीमेशन संबंधी कार्य के लिए प्रमुख आउटसोर्स केंद्र बन जाएगा। इसके लिए प्रशिक्षित पेशेवरों की भारी मांग है। इसलिए इस पाठ्यक्रम को शुरू करने का यही सबसे उचित समय है। बदलते परिदृश्य को देखते हुए संस्थान में इसकी नई शाखा खोलने की आवश्यकता है। इसलिए संस्थान का दो वर्षीय पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव जिसमें प्रत्येक बैच में 10 छात्र होंगे।	1.24	1. नए अकादमिक ब्लॉक का निर्माण 2. कंप्यूटर तथा सॉफ्टवेयर और एनीमेशन तथा डिजिटल इमेजिंग सॉफ्टवेयर प्राप्त करना 3. मानवशक्ति की नियुक्ति	संस्थान की स्थापना का उद्देश्य पूरा होगा छात्र समुदाय लाभांवित होगा और छात्रों को नए पाठ्यक्रम के अध्ययन का अवसर मिलेगा। उभरते क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। संस्थान भारतीय मीडिया की संपूर्ण गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अपनी गतिविधियों में विविधता लाएगी और प्रशिक्षित पेशेवर उपलब्ध कराकर उद्योग को सहयोग देगा।	सीसीडब्ल्यु, द्वारा निर्माण और रूपांतरण कार्य हाथ में लिया जाएगा। संभवतः यह कार्य 2011-12 में पूर्ण कर लिया जायेगा। विभागीय खरीद से ही उपकरण प्राप्ति होगी। इसके लिए मंत्रालय द्वारा निर्धारित नियमों के मुताबिक मानवशक्ति की नियुक्ति की जाएगी।	1. लक्ष्य उपलब्धि धन की उपलब्धता पर निर्भर करती है। 2. संचालन लाइसेंस का नवीनीकरण तथा फ्रीक्वेंसी लाइसेंस 3. संस्थान के नियंत्रण से बाहर के कारक

(करोड़ रुपये में)

क्रं. सं.	स्कीम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	2010-11 के लिए अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता माध्यमिक/अंतिम	टिप्पणियां/ जोखिम घटक
7.	फिल्म एवं टीवी में निर्माण प्रबंधन विभाग	दृश्य श्रव्य मीडिया बहुअनुशासनात्मक है जोकि काफी भिन्न भी है। एक सफल निर्माण को सभी भिन्नताओं के सरल और आर्थिक संयोजन की आवश्यकता होती है। संस्था ने दो वर्ष के पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आरंभ करने वाला है। फिल्म एवं टीवी के प्रबंधक व्यापार के लिए 10 छात्रों को प्रत्येक सत्र में लेना है। यह शैक्षिक सत्र 2011-12 में होगा।	1.07	1. नए अकादमिक ब्लॉक का निर्माण 2. कंप्यूटर तथा सॉफ्टवेयर और एनीमेशन तथा डिजिटल इमेजिंग सॉफ्टवेयर प्राप्त करना 3. मानवशक्ति की नियुक्ति	संस्थान की स्थापना का उद्देश्य पूरा होगा छात्र समुदाय लाभांवित होगा और छात्रों को नए पाठ्यक्रम के अध्ययन का अवसर मिलेगा। उभरते क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। संस्थान भारतीय मीडिया की संपूर्ण गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अपनी गतिविधियों में विविधता लाएगी और प्रशिक्षित पेशेवर उपलब्ध कराकर उद्योग को सहयोग देगा	सीसीडब्ल्यु, एआईआर द्वारा निर्माण और रूपांतरण कार्य हाथ में लिया जाएगा। विभागीय खरीद से ही उपकरण प्राप्ति होगी। इसके लिए मंत्रालय द्वारा निर्धारित नियमों के मुताबिक मानवशक्ति की नियुक्ति की जाएगी	1. लक्ष्य उपलब्धि धन की उपलब्धता पर निर्भर करती है। 2. संचालन लाइसेंस का नवीनीकरण तथा फ्रीक्वेंसी लाइसेंस 3. संस्थान के नियंत्रण से बाहर के कारक
		कुल	**7.00**				

भारतीय जनसंचार संस्थान
परिणाम बजट 2011-12

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2011-12			वितरण योग्य/ परिणाम/भौतिक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम का घटक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4(i) गैर-नियोजित बजट	4(ii) योजना बजट	4(iii) पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन				
1.	जनसंचार में प्रशिक्षण एवं अनुसंधान भारतीय जन संचार संस्थान	पत्रकारिता/जनसंचार के क्षेत्र में आईआईएमसी द्वारा आयोजित किए गए शोध अध्ययन और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम देश के सामाजिक आर्थिक विकास के साथ गति बनए रखने के लिए उपयोगी है।	1117.00	—	400.00	निम्नलिखित में पी जी डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करना : नई दिल्ली और ढेंकवाल में पत्रकारिता (अंग्रेजी); नई दिल्ली में पत्रकारिता (हिन्दी), नई दिल्ली में रेडियो व टीवी पत्रकारिता, विज्ञापन व पब्लिक रिलेशंस और ढेंकनाल में ओड़िया पत्रकारिता (325); विकास पत्रकारिता में डिप्लोमा पाठ्यक्रम (40-45); (मंत्रालय की जरूरत के अनुसार)आई आई एस के ग्रुप ए और ग्रुप बी अधिकारियों के लिए सेवाकालिन पाठ्यक्रम अल्पकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (600-700)	निम्नलिखित में पी जी डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करना : -पत्रकारिता (हिन्दी) 62 - पत्रकारिता (अंग्रेजी) 124 (62+62) -पत्रकारिता (ओड़िया) (23) -एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस (70) -रेडियो व टीवी पत्रकारिता (46) -विकास पत्रकारिता में दो डिप्लोमा कोर्स (40-45) **अल्पकालीन कार्यक्रम** -अल्पकालीन कोर्स/ कार्यशालाएं (600-700) -आई आई एस अधिकारियों के चल रहे कोर्सों को पूरा करना। -शोध अध्ययन (4 से 5 अध्ययन)। **प्रकाशन :** अंग्रेजी में कम्यूनिकेटर और हिंदी में संचार माध्यम जैसी अर्द्धवार्षिक पत्रिकाओं का, वार्षिक रिपोर्ट और छात्रों के लंब जर्नलों को प्रकाशित करना।	दो वर्ष के सभी डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश की प्रक्रियें (अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के आधार पर) जुलाई 2011 तकपूरी हो जायेगी और इसके तुरंत बाद ये पाठ्यक्रम शुरू हो जायेंगे। पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जायेगा। समय-समय पर अनुसंधान अध्ययन किए जायेंगे।	एन आर आई, शारीरिक रूप से विकलांग और अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति जैसे कुछ आरक्षित श्रेणियों में 100 प्रतिशत सीटों का नहीं भरना था अन्य संस्थानों/ विश्वविद्यालयों में प्रवेश मिलने के कारण या व्यक्तिगत कारणों से आई आई एम सी को छोड़ देने की संभावना भी रहती है।

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2011-12			मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम का घटक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4(i) गैर-नियोजित बजट	4(ii) योजना बजट	4(iii) पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन				
2.	अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार आईआईएमसी का उन्नयन	अंतर्राष्ट्रीय मानदंडो की स्थापना से जनसंचार में आधुनिक एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान किया जा सकेगा। इससे यह संस्थान मीडिया उद्योग के क्षेत्र में वैश्विक नियुक्तियों के लिए योग्य पेशेवर तैयार किए जा सकेंगे। प्रस्तावित उन्नयन में आईआईएमसी के चार नये केन्द्रों का खोला जाना भी शामिल है। आईआईएमसी उपलब्ध करायेगा: (क) सामान्य सीटों के साथ ओबीसी छात्रों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध करायेगा। (ख) भागीदारों के लिए जन माध्यम संबंधित मुद्दों में अनुसंधान एवं आधुनिक प्रशिक्षण के सुअवसर प्रदान करेगा। (ग) देश के विभिन्न क्षेत्रों में जन संचर के पाठ्यक्रमों के अध्ययन के विसंगतियों को दूर करेगा। योजना आयोग, एसएफसी और सूचना और प्रसारण मंत्रालय से 51.50 करोड़ रुपये के सरकारी अनुदान के साथ 62.00 करोड रुपये के कुल परिव्यय के लिये योजना को मंजूरी मिल गई है। यह योजना तीन वर्ष की अवधि अर्थात् मार्च 2013 तक पूरी हो जायेगी	—	22.10	—	जनसंचार के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान अध्ययन का संचालन (3-4 अध्ययन) और अर्द्धवार्षिक पत्रिका-अंग्रेजी में कम्युनिकेटर तथा हिन्दी में संचार माध्यम का प्रकाशन। दिल्ली में आईआईएमसी परिसर में मौजूदा इमारत पर अतिरिक्त मंजिल का 100 प्रतिशत निर्माण नई दिल्ली और ढेंकनाल में आईआईएमसी परिसरों में अतिरिक्त भवन में निर्माण कार्य शुरू शिक्षण सहायता उपकरणों की खरीद एडवांस्ड पी जी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश मिजोरम और महाराष्ट्र (विदर्भ) में आईआईएमसी के दो क्षेत्रीय केन्द्रों को खोला जाना।	डिप्लोमा कोर्सों में ओबीसी आरक्षण कोटा के तीसरे और अंतिम चरण को लागू किया जायेगा। ● जुलाई 2011 तक पूरा होगा। ● मार्च 2012 तक पूरा होगा। ● जुलाई 2011 तक पूरा होगा।	इमारत के निर्माण के लिए जीएफआर के प्रावधानों के अनुसार यह प्रक्रियाएं पूरी हो गई है और दिल्ली में आईआईएमएसी परिसर में अतिरिक्त मंजिल पर निर्माटा 2010-11 में पूरा होगा और जुलाई 2011 तक पूरा हो जायेगा। मार्च 2011 तक परियोजना प्रबंधन, इंजीनियरिंग, संरचनात्मक डिजाइन के लिए कंसल्टेंटों तथा कंट्रैक्टर की नियुक्ति हो जायेगी	जुलाई 2011 तक अतिरिक्त मंजिल का निर्माण होने पर, मार्च 2011 तक संबंधित दो राज्य सरकारों द्वारा कक्षाओं, अध्ययनों, कार्यालय और छात्रों के लिये छात्रावास आदि के लिए जगह मिलने पर यह निर्भर है।

नोट : कोष्ठक के अंदर दिए गए आंकड़े छात्रों की इस संख्या को दर्शाते हैं जो प्रवेश लेंगे।

भारत का राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय
परिणाम बजट 2011-12

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2011-12			मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
1	2	3	4			5	6	7	8
			4 (i)	4 (ii)	4 (iii)				
			गैर-योजना बजट	योजना बजट	पूरक बजट अतिरिक्त संसाधन				
1.	अभिलेख फिल्मों की प्राप्ति एवं प्रदर्शन।	फिल्मों की प्राप्ति एवं फिल्म संस्कृति का प्रचार-प्रसार करना	4.68	20.00	शून्य	600 फिल्में/डीवीडी/ प्राप्त करना। 400 डिजिटाइनड फिल्मों तथा पोस्टर, स्टिल्स आदि अनुषंगी सामग्री का डिजिटलीकरण	फिल्मों की प्राप्ति डिजिटलीकरण एवं फिल्म संस्कृति का प्रचार-प्रसार करना।	वार्षिक आधार	वार्षिक बजट आबंटन का प्रयोग करना
	कुल		**4.68**	**20.00**	शून्य				

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	वित्तीय परिव्यय (बी ई 2011-12)	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्मों का उत्पादन	भारतीय सिनेमा को बढ़ावा देने और फिल्म निर्माण में नई प्रतिभाओं को लाना	1583.00	8 फिल्में	यह क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्मों और भारतीय सिनेमा के दर्शक को बढ़ायेगा और इस क्षेत्र में नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करेगा	फिल्में करीब एक साल में निर्मित होंगी	फिल्म के प्रति दर्शक की प्रतिक्रिया काफी लचीली और गैर अनुमान वाली है।
2.	इक्विटी भागीदारी	एनएफडीसी का प्राधिकार तथा प्रदत्त पूंजी आधार बढ़ाना ताकि अपने अधिदेश को पाने के लिए निगम के पास फंड उपलब्ध रहे।	500.00	39 फिल्में	फिल्म निर्माण को प्रभावी बनाने के अधिदेश का पालन करने के लिए यह निगम को पर्याप्त कोष उपलब्ध करायेगा।	एनएफसीडी ने इसके रिवाइवल को मापने के लिए बी आर पी एस ई को अधिकार दिया है और इसके लिए कुछ समय लगेगा। हालांकि इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है	यह योजना अभी स्वीकृत होनी है। केबिनेट द्वारा एनएफडीसी की इक्विटी में निवेश के प्रस्ताव की मंजूरी के बाद ही फंड जारी किया जा सकता है।

पत्र सूचना कार्यालय

वार्षिक योजना (2011-12) **परिव्यय तथा परिणाम/लक्ष्य का विवरण (2010-12)**

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	कार्यक्रम योजना का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2010-11 योजना बजट	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
1	2	3	4	5	6	7
1.	नई दिल्ली में राष्ट्रीय मीडिया केंद्र की स्थापना	नई दिल्ली में पीआईबी के लिए राष्ट्रीय मीडिया केंद्र का निर्माण	20.50	मिट्टी की खुदाई का कार्य, नींव का कार्य, तहखाने भूतल, प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ तल हेतु आरसीसी का कार्य तथा सभी तलों की फिनिशिंग। एच वी ए सी शुरू। मशीन कक्ष में फर्श कार्य। बिजली, पानी, सफाई और अग्नि -शमन प्रणाली का बचा हुआ कार्य। लिफ्ट, इंटीरियर, ऑडियो विजुअल तथा अन्य कार्य बाहरी कार्य की शुरुआत।	मिट्टी की खुदाई का कार्य, नींव का कार्य, तहखाने भूतल, प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ तल हेतु आरसीसी का कार्य तथा सभी तलों की फिनिशिंग। एच वी ए सी शुरू। मशीन कक्ष में फर्श कार्य। बिजली, पानी, सफाई और अग्नि -शमन प्रणाली का बचा हुआ कार्य। लिफ्ट, इंटीरियर, ऑडियो विजुअल तथा अन्य कार्य बाहरी कार्य की शुरुआत।	
2.	मीडिया आउटरीच कार्यक्रम	सार्वजनिक सूचना अभियान (पी.आई.सी.) चला कर,प्रेस वार्ताएं आयोजित करके, सफलता की कहानियां जारी करके और प्रेस दौरे आयोजित करके केन्द्र सरकार के अग्रणी	14.50	150 जन-सूचना अभियान चलाना, 4 प्रेस वार्ताएं, 100 सफलता समाचार और 10 प्रेस दौरे आयोजित करना, पीएमयू, मीडिया	**पहली तिमाही :** 24 पीआईसी, 1 मीडिया वार्ता, 25 सफलता समाचार तथा प्रेस दौरे आयोजित करना	100 पीआईसी के स्थान पर 150 पीआईसी का लक्ष्य बढ़ाया गया है। इसमें पीएमयू, मीडिया आउटरीच तथा 24 घंटे नियंत्रण कक्ष जैसी परियोजनाएं शामिल

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	कार्यक्रम योजना का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2010-11 योजना बजट	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
1	2	3	4	5	6	7
		कार्यक्रमों की जानकारी उपलब्ध कराना		आउटरीच तथा 24 घंटे नियंत्रण कक्ष के लिए कंटेंट प्रबंधन		
					दूसरी तिमाही 36 पीआईसी, 1 प्रेस वार्ता, 25 सफलता समाचार और पत्रकारों के 3 दौरे आयोजित करना। **तीसरी तिमाही** 45 पीआईसी, 1 प्रेस वार्ता, 25 सफलता समाचार और पत्रकारों के 3 दौरे आयोजित करना **चौथी तिमाही** 45 पीआईसी, 1 प्रेस वार्ता, 25 सफलता समाचार और पत्रकारों के 3 दौरे आयोजित करना।	करने का प्रस्ताव। तदनुसार, 11वी परियोजना के लिए फंड प्रस्ताव पिछले 49.00 करोड़ के मुकाबले 60.59 करोड़ रुपये बढ़ जाएगा। उल्लेखनीय होगा कि 49 करोड़ में से 39.22 करोड़ रुपये 2010-11 तक उपयोग में लाए जा चुके हैं। अत: वार्षिक योजना 2011-12 के लिए शेष फंड 9.78 करोड़, चूंकि प्रस्तावित आवश्यकता 60.59 करोड़ रुपये की है, 11.59 करोड़ रुपये का बजट बढ़ाने के प्रस्ताव की आवश्यकता पड़ेगी। अत: अगले वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए 21.37 करोड़ रुपये धनराशि का प्रस्ताव था। जिसमें से बीई 2011-12 में 14.50 करोड़ रुपये आबंटित हो चुके हैं।

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	कार्यक्रम योजना का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2010-11 योजना बजट	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
1	2	3	4	5	6	7
3	**विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रचार** इस योजना के तीन अंग हैं:		0.25 कुल			
i	भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह	मौके पर मीडिया केंद्र की स्थापना करके पत्रकारों को विशेष प्रत्यायन, प्रेस वार्ताएं, विज्ञप्तियां, कंप्यूटर, इंटरनेट, टेलीफोन, अखबार, फोटोकापी आदि जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना।	0.08	मौके पर मीडिया केंद्र खोलना, सुविधाओं की व्यवस्था करना और पत्रकारों को विज्ञप्तियों, इंटरनेट, फोन, कंप्यूटर, फोटो कापी आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराना	**तीसरी तिमाही** कालम 5 में वर्णित सभी गतिविधियां तीसरी तिमाही में शुरू की जाएंगी। फिल्म समारोह हर साल नवंबर-दिसंबर में गोवा में आयोजित होता है।	
ii	प्रवासी भारतीय दिवस समारोह	पीआईबी विशेष प्रत्यायन हेतु अधिकारी भेजता है। वे पत्रकारों के लिए तैयार मीडिया सेंटर के लिए कंप्यूटर आदि सुविधाएं भी जुटाते हैं।	0.0125	प्रवासी दिवस समारोह में पीआईबी विशेष प्रत्यायन के लिए अधिकारी भेजता है। वे पत्रकारों के लिए तैयार मीडिया सेंटर के लिए कंप्यूटर आदि सुविधाएं भी जुटाते हैं।	**चौथी तिमाही** कालम 5 में वर्णित सभी गतिविधियां चौथी तिमाही में की जाएंगी क्योंकि प्रवासी भारतीय दिवस समारोह हर वर्ष नई दिल्ली में जनवरी में होता है।	

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	कार्यक्रम योजना का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2010-11 योजना बजट	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
1	2	3	4	5	6	7
iii	मीडिया आदान-प्रदान कार्यक्रम	सूचना एवं मास मीडिया क्षेत्रों में सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम एवं संयुक्त कार्यकारी आयोग/समझौते	05.75	सूचना एवं मास मीडिया क्षेत्र में सांस्कृतिक आदान-प्रदान के 6 कार्यक्रम और 3 कार्यकारी आयोग/ समझौते	**प्रथम तिमाही**-2 सीईपी (1 प्रतिनिधि मंडल आएगा, 1 जाएगा) **दूसरी तिमाही**-2 सीईपी (1 प्रतिनिधि मंडल आएगा 1 जाएगा), **तृतीय तिमाही**-1 सीईप्री (1 प्रतिनिधि मंडल आएगा) 1 संयुक्त कार्यकारी आयोग आएगा। **चतुर्थ तिमाही**-1 सां.अ.प्र. (जानेवाला) और 1 संयुक्त प्रतिनिधि मंडल जाएगा	
	कुल		**35.25**			

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	कार्यक्रम योजना का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2011-12 योजना बजट	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**उप-शीर्षक (गैर योजना)** वेतन, ओटीए, चिकित्या व्यय, घरेलू यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय, प्रकाशन, अन्य प्रशासनिक व्यय, विज्ञापन और प्रचार, व्यावसायिक सेवाएं आदि।	लोगों का सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और गतिविधियों के संबंध में जानकारी देने के लिए पत्र सूचना कार्यालय भारत सरकार भारत सरकार की अग्रणी संस्था है। मीडिया (इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट) के साथ संवाद के प्रमुख चैनल के रूप में पत्र सूचना कार्यालय इस मूल विचार के साथ काम करता है कि लोकतंत्र में सरकार को यह सुनिश्चित करना होता है कि उसकी नीतियां और कार्यक्रम प्रेस और अन्य मीडिया के जरिए सही और उपयुक्त तरीके से उन लोगों तक पहुंचे जिनके समर्थन और विश्वास पर वह सत्ता में है।	4123.00	वेतन पर हुआ व्यय एलटीसी लीव एनकेशमेंट, ओटीए भुगतान यात्रा भत्ते। कम्पयुटर/टाइपराइटर आदि की खरीद और मरम्मत पर हुआ खर्च। ऑफिस कोड प्रकाशन, मेनुअल तथा अन्य दस्तावेज के प्रकाशन पर खर्च। आतिथ्य/मनोरंजन पर खर्च, विधिक सेवायें, परामर्श के लिए व्यावसायिक भुगतान।	पीआईबी की गतिविधि में मानव संसाधन की जिम्मेदारी है जो सरकार की विभिन्न नीतियों और उपलब्धियों के बारे में उचित सूचना प्रदान करने मे सहायता प्रदान करती है।	तय समय के अनुसार	लागू नहीं

भारतीय प्रेस परिषद

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	योजना एवं कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2011-12			मात्रात्मक/निष्पादन प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर-योजना बजट *(लाख में)*	योजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
1.	एक अर्द्ध-न्यायिक संस्था होने के कारण परिषद कोई स्कीम नहीं चला रही है।	प्रेस की आज़ादी का संरक्षण और भारत में समाचारपत्रों और समाचार एजेन्सियों के स्तर को बनाए रखते हुए उसमें सुधार लाना	532.00	उपलब्ध नहीं क्योंकि योजना बजट के लिए प्रस्ताव नहीं आया।	परिषद पंजीकृत समाचारपत्रों, पत्रिकाओं और समाचार एजेन्सियों से प्रेस परिषद अधिनियम 1978 के अनुच्छेद 16 के अंतर्गत शुल्क वसूल करती है और जमाराशियों पर ब्याज कमाती है। वर्ष 2010-11 में परिषद का लक्ष्य लेवी और अन्य प्राप्तियों के शुल्क के रूप में 40.60 लाख रुपए इकट्ठा करके भारत सरकार से प्राप्त अनुदान सहायता को कम करना है।	चूंकि प्रेस परिषद् के कार्य अर्द्धन्यायिक प्रकृति के हैं और यह प्रेस के आचरण संबंधी स्तर का नियामन करती है, अतः इसके भौतिक प्रतिफल/परिणामों को आंकना संभव नहीं है।	परिव्यय का उपयोग परिषद के उद्देश्यों के अनुसार होगा ताकि प्रेस की स्वतंत्रता बरकरार रहे तथा समाचार पत्रों और न्यूज एजेंसियों के मानक में कमी न आने पाए।	यह वादियों द्वारा आवश्यक शर्तें पूरा करने और परिषद द्वारा जांच पूरी करने पर निर्भर करता है।	शिकायतों के निपटारे में कोई जोखिम शामिल नहीं है।

फोटो प्रभाग

11वीं पंचवर्षीय योजना के चौथे वर्ष 2010-11 के दौरान बी.ई. 253.00 लाख रु. तथा आर.ई. 2010-11 के लिए 178.00 लाख रु. के तहत व परिव्यय घटकों का विवरण :

क्र.सं.	स्कीम का नाम	बी ई 2010-11	स्कीम का नाम	आर ई 2010-11
1.	**राष्ट्रीय फोटोग्राफी केंद्र** (ए) आउटसोर्सिंग समर्थन (बी) डिजिटल प्रबंधन तथा इमेज की आउटसोर्सिंग (सी) तापमान नियंत्रण इकाई का प्रावधान (डी) अन्तरराष्ट्रीय स्तर की संदर्भ सामग्री का प्रावधान (ई) आर्काइव की महत्वपूर्ण इमेज की विशेष प्रदर्शनी (एफ) फोटोग्राफिक इमेज के डिजिटल प्रबंधन पर कार्यशाला (जी) राष्ट्रीय फोटो अवार्ड का परिचय (एच) देश के बड़े शहरों में चल प्रदर्शनी (आई) अन्य विषयों पर दो अन्य प्रदर्शनी (जे) कॉफी टेबल पुस्तकें (के) पहले और आठवें एशियाई खेलों, सार्क खेलों, राष्ट्रमंडल युवा खेलों की विशेष फोटो प्रदर्शनी (एल) क्वींस बैटन रिले राष्ट्रमंडल खेल 2010 पर कॉफी टेबल पुस्तकें (एम) सार्क स्तर की फोटो प्रतियोगिता (एन) 15 दिन के लिए 10 फोटोग्राफ की आउटसोर्सिंग, एसाइनमेंट पर सामग्री ढोने के लिए वाहन किराए पर लेना, डीवीडी की प्राप्ति, चल स्टोर, विविध सामग्री आदि	15 लाख रुपये 10 लाख रुपये 20 लाख रुपये 10 लाख रुपये 20 लाख रुपये 10 लाख रुपये 20 लाख रुपये 30 लाख रुपये 17 लाख रुपये 20 लाख रुपये 20 लाख रुपये 25 लाख रुपये 25 लाख रुपये 6 लाख रुपये	**राष्ट्रीय फोटोग्राफी केंद्र** (ए) आउटसोर्सिंग समर्थन (बी) डिजिटल प्रबंधण तथा अमेज की आउटसोर्सिंग (सी) तापमान नियंत्रण इकाई का प्रावधान (डी) अंतरराष्ट्रीय स्तर की संदर्भ सामग्री का प्रावधान (ई) आर्काइव की महत्व पूर्ण इमेज की प्रदर्शनी (एफ) राष्ट्रीय फोटो अवार्ड का परिचय (जी) फोटो का डिजिटलीकरण (एफ) बैकअप सर्वर की प्राप्ति (आई) 15 दिन के लिए 10 फोटोग्राफ की आउट सोर्सिंग, एसाइनमेंट पर सामग्री ढोने के लिए वाहन किराए पर लेना, डीवीडी की प्राप्ति, चल स्टोर, विविध सामग्री आदि	15 लाख रुपये 10 लाख रुपये 25 लाख रुपये 20 लाख रुपये 25 लाख रुपये 30 लाख रुपये 30 लाख रुपये 12 लाख रुपये 6 लाख रुपये
	कुल	**248 लाख रुपये**	**कुल**	**173 लाख रुपये**
2.	जम्मू और कश्मीर राज्यों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के लिए विशेष योजना	5 लाख रुपये	जम्मू कश्मीर राज्यों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के लिए विशेष योजना	5 लाख रुपये
		253 लाख रुपये		**178 लाख रुपये**

फोटो प्रभाग

गैर-योजना

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2011-12	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम घटक
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	प्रलेखन, प्रचार तथा अन्योन्य संदर्भ, फोटो द्वारा सरकारी विकास कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार	राजनीतिक, अर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तन का प्रचार तथा अभिलेख तैयार करना।	396.00	नियमित फोटो प्रलेखन भावी पीढ़ियों के लिए परिवर्तन की दृश्य रिपोर्ट होगा। संभवत: ये अत्यधिक मूल्यवान प्रलेख होंगे जिन्हें जब जरूरत होगी दुबारा प्रयोग किया जाएगा।	यह प्रलेखन अन्योन्य संदर्भ द्वारा देश के सही इतिहास को जानने में मदद करेगा।	—	—

योजना

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2011-12	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समय सीमा	टिप्पणी/ जोखिम घटक
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**फोटोग्राफी राष्ट्रीय केंद्र (ए).** बाह्य स्रोत से सहयोग	पुस्तकालयकर्मी, पुस्तकालय सहायक, आईटी विशेषज्ञ (प्रोग्रामर्स, डाटा इंट्री ऑपरेटर) की भागीदारी	30.00	**ए.** प्रभाग की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन प्रयोग के लिए फोटो अभिलेखागार को कारगर बनाना	**ए.** एक अच्छी फोटो लाइब्रेरी के माध्यम से प्रयोक्ता को किसी भी फोटो को सरलता से उपलब्ध कराना	—	—
	(बी). फोटो और डिजिटल प्रबंधन के लिए बाह्य स्रोत का प्रयोग	बाहर से फोटोग्राफ्स का प्रबंध और वर्तमान फोटोग्राफ्स का डिजिटल प्रबंध, किताबों और अलमारियों को हासिल करना	25.00	**बी.** राष्ट्रीय महत्व की विविध फोटोग्राफ्स के साथ अभिलेखागार को समृद्ध करना।	**बी.** जनसाधारण को गुणवत्तावान फोटो उपलब्ध कराना।		—

	(सी). स्पेस की डिजाइनिंग	डिजिटल फोटो लाइब्रेरी में एयर कंडीशनर और नमी रोकने की व्यवस्था करना और विशेष सुरक्षा स्पेस की डिजाइनिंग	30.00	**सी.** लोडिंग स्पेस तथा अनय महतवपूर्ण क्षेतों के फोटोग्राफ के लिए नया लुक देकर डिजाइनिंग करना	**सी.** प्रभावशाली वर्किंग स्पेस के लिए		—
	(डी). अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संदर्भ साम्रगी	राष्ट्रीय फोटो केन्द्र के लिए डिजिटल फोटोग्राफी पर संदर्भ पुस्तकालय को गठित करने लिए पुस्तकों और संबंधित अध्ययन साम्रगी को हासिल करना	05.00	**डी.** अभिलेखागार में साम्रग्रियों के साथ पुस्तकालय का अंतर्सम्बंध बहुत महत्वपूर्ण होता है और यह व्यावसायिक सहयोग स्वाभाविक रूप से साथ-साथ होना चाहिए तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत सामग्रियों को सहयोग देना चाहिए	**डी.** गुणवत्तावान निर्माण में मदद		—
	(ई) फोटोग्राफ्स आदि की आउटसोर्सिंग	**(ई)** देश के विभिन्न हिस्सों से पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण फोटोग्राफ की आउट सोर्सिंग ताकि उन्हें आर्काइव में रखा जा सके	20.00	**(ई)** प्रभाग के पास दिल्ली के अलावा जनशक्ति (मैन पाव) नहीं है। कई बार महत्वपूर्ण पोटो की जरूरत पड़ जाती है। इस प्रोजेक्ट के जरिए समसामयिक तथा महत्त्वपूर्ण फोटो प्राप्त की जा सकेंगी। इस कार्य में फोर्टोग्राफों को लगाना फोटो आर्काइव को समृद्ध बनाना तथा आवश्यक सामग्री प्राप्त करना।	**(ई)** बाहर के फोटोग्राफरों की मदद से प्रभाग महत्वपूर्ण तथा इमर्जेन्सी फोटो प्राप्त कर सका जो रूटीन कार्य से प्रभाग को नहीं मिल पाते		
	(एफ) फोटो की पहचान कार्य में विशेर्षज्ञों तथा शोध छात्रों को संलग्न करना	**(एफ)** गत योजना कार्यक्रम के तहत फोटो को डिजिटल बनाने के क्रम में यह पाया गया कि कई महत्त्वपूर्ण सामग्री के साथ उचित आँकड़ा नहीं है।	10.00	**(एफ)** विशेषज्ञों तथा शोध छात्रों को फोटो की पहचान के कार्य में लगाना। इससे महत्वपूर्ण फोटो सही जगह रखा जा सकेगा जिनका	**(एफ)** आर्काइव में फोटो से सम्बद्ध आंकड़ा या जानकारी मिलने पर उचित तथा सटीक कार्रवाई	—	—

		इसलिए ऐसी सामग्री को आर्काइव में उचित स्थान पर रखने में दिक्कत है। इसलिए शोधार्थियों की जरूरत है।		इस्तेमाल संदर्भ सामग्री के रूप में होता है।			
	(जी) नेशनल फोटो अवार्ड	**(जी)** पेशेवर तथा शौकिया फोटोग्राफर के लिए अतिरिक्त घटक के साथ नेशनल फोटो अवार्ड को जारी रखना।	25.00	**(जी)** आज फोटोग्राफी सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है तथा यह क्षेत्र में प्रोत्साहित करने में भूमिका निभाती है। इसलिए सरकार ने पेशेवर फोटोग्राफरों को सम्मानित करने का निर्णय लिया है। इससे उनकी प्रतिबद्धता बढ़ेगी और इस क्षेत्र का विकास होगा।	**(जी)** आज के संदर्भ में माध्यम की महत्ता को समझने के लिए आधार तैयार करना	—	—
	(एच) प्रदर्शनी	**(एच)** प्रदर्शनी नेशनल फोटो अवार्ड में पुरस्कार प्राप्त फोटो की प्रदर्शनी किसी जाने-माने संगठन के द्वारा आयोजित करना ताकि फोटोग्राफी को प्रोत्साहित किया जा सके।	15.00	**(एच)** इससे लोगों के बीच मौजूदा दौर की प्रवृत्ति की समझ बढ़ेगी तथा वे फोटोग्राफी के बारे में भी जान सकेंगे। फलस्वरूप लोगों में इस माध्यम के प्रति उत्साह पैदा होगा।	**(एच)** यह गतिविधियां इस पेशे यानी फोटो को काफी प्रोत्साहन देती हैं।		
	(आई) फोटो का डिटिलीकरण	**(आई)** विगत योजना अवधि के दौरान प्रभाग ने फोटो का पूरी तरह डिजीटलीकरण की पहल की जो जारी नहीं रह सका। इस योजना को पूरा करने के लिए प्रभाग ने योजना स्कीम का रूप बदल कर इस वर्ष पूरा करने का लक्ष्य बनाया।	35.00	**(आई)** इससे अधिकाधिक फोटो वेबसाइट पर आ जाएंगे। विश्व के किसी भी हिस्से में बैठा कोई व्यक्ति अपनी जरूरत के अनुसार फोटो देख सकेगा या डाउनलोड कर सकेगा	**(आई)** पूरे विश्व में संदर्भ सामग्री के रूप में फोटो का इस्तेमाल करना आसान हो जाएगा।		

	(जे) फोटोग्राफरों के लिए विशेष अभियान प्रबंधन	**(जे)** फोटोगराफरों के लिए अभियान प्रबंधन	10.00	विशेष प्रबंधन की भूमिका न सिर्फरख-रखाव बल्कि सुरक्षा के लिए, विशेषकर आईटी सेक्टर में, जरूरी है।	**(जे)** पूरी व्यवस्था की सुरक्षा।	—	—
2.	उत्तर-पूर्व, जम्मू-कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप के लिए विशेष अभियान	चिह्नित विकास परियोजनाओं की पहचान एवं प्रलेखन का कार्यान्वयन। उत्तर-पूर्वी राज्यों, जम्मू एवं कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में जीवन और पर्यावरण।	5.00	पूर्वोत्तर और जम्मू कश्मीर आदि में विशेष अभियान। कम से कम दो विकासात्मक कार्य कला पांच राज्यों में चलाए जाएंगे।	विकास के ऐसे क्षेत्रों पर विशेष प्रकाश डालना जिनके बारे में अभी अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है।	—	—
		कुल	**210.00**				

फोटो प्रभाग

11वीं पंचवर्षीय योजना स्कीम में पांचवें वर्ष 2011-12 के दौरान 210.00 लाख रुपये परिव्यय के घटकों का विवरण

क्र.सं.	स्कीम का नाम	बीई 2010-11
1.	**राष्ट्रीय फोटोग्राफी केंद्र**	
	(ए) आउटसोर्सिंग समर्थन	30 लाख रुपये
	(बी) पोटो की आउटसोर्सिंग तथाडिजिटल प्रबंधन	20 लाख रुपये
	(सी) स्पेस की डिजाइनिंग	30 लाख रुपये
	(डी) अन्तरराष्ट्रीय स्तर की संदर्भ सामग्री का प्रावधान	05 लाख रुपये
	(ई) देश के विभिन्न हिस्सों से पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण पोटोग्राफ की आउटसोर्सिंग ताकि उन्हें आर्काइव में रखा जा सके।	20 लाख रुपये
	(एफ) फोटो पहचान के लिए विशेर्षज्ञों तथा शोध छात्रों को लगाना	10 लाख रुपये
	(जी) नेशनल फोटो अवार्ड की निरंतरता	25 लाख रुपये
	(एच) प्रदर्शनी नेशनल फोटो अवार्ड विजेता की प्रदर्शनी ताकि फोटोग्राफी को प्रोत्साहन मिले	15 लाख रुपये
	(आई) फोटो का डिजिटलीकरण	40 लाख रुपये
	(जे) पोटोग्राफ्स की विशेष प्रबंधन योजना	10 लाख रुपये
	कुल	**205 लाख रुपये**
2.	जम्मू और कश्मीर राज्यों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के लिए विशेष योजना	**5 लाख रुपये**
	कुल	**210 लाख रुपये**

(लाख रुपये में)

उप शीर्षक का नाम	वास्तविक 2009-10			बजट अनुदान 2010-2011			संशोधित अनुमान 2010-2011			बजट अनुदान 2011-2012		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
राजस्व खण्ड												
1. वेतन		220.14	220.14		200.00	200.00		200.00	200.00		230.00	230.00
2.चिकित्सा भुगतान		5.16	5.16		3.00	3.00		3.00	3.00		6.00	6.00
3. भत्ते		0.85	0.85		2.00	2.00		2.00	2.00		2.00	2.00
4. समयोपरि भत्ता		2.21	2.21		2.50	2.50		2.500	2.50		2.50	2.50
5. घरेलू यात्रा व्यय		4.25	4.25		4.50	4.50		4.50	4.50		5.00	5.00
6. कार्यालय व्यय	209.47	90.99	300.46	253.00	58.00	313.00	178.00	58.00	236.00	210.00	60.50	240.50
7.किराया, दरें और कर		0	0		35.00	35.00		36.00	36.00	0	40.00	40.00
8. आपूर्ति और सामग्री		35.98	35.98		40.00	40.00		40.00	40.00		40.00	40.00
9. लघु कार्य		9.40	9.40		10.00	10.00		10.00	10.00		10.00	10.00
कुल (क)	**209.47**	**368.98**	**578.45**	**253.00**	**355.00**	**610.00**	**178.00**	**356.00**	**534.00**	**210.00**	**396.00**	**576.00**
(ख) पूंजी खण्ड उपकरणों की प्राप्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल (ख)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल क+ख	**209.47**	**368.98**	**578.45**	**253.00**	**355.00**	**610.00**	**178.00**	**356.00**	**534.00**	**210.00**	**396.00**	**576.00**

स्थापन व्यय	=	232.61
गैर-स्थापन व्यय	=	146.49
खरीद पर व्यय	=	199.35
		578.45

प्रकाशन विभाग

गैर योजना

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2011-12		परिमाणात्मक कार्य/ भौतिक उत्पादन	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम घटक
1	2	3	4		5	6	7	8
			4 (I)	4 (II)				
			गैर-योजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
1.	-	पत्रिकाओं व पुस्तकों को निकालना	2223.00	-	20 पत्रिकाएं और 90 से अधिक पुस्तकों को निकालना। दिल्ली में और दिल्ली के बाहर 150 पुस्तक प्रदर्शनियां/मेले आयोजित किए जाएंगे।	प्रकाशन विभाग का लक्ष्य है निम्नलिखित परिणामों को प्राप्त करना : 1. राष्ट्रीय महत्व के ऐसे विषयों पर पुस्तक छापना जिन पर अन्य प्रकाशन भवनों ने ध्यान नहीं दिया हो ऐसी पुस्तकों को कम कीमतों पर आम लोगों को उपलब्ध कराना। 2. विविधता में एकता, साम्प्रदायिक सद्भावना, राष्ट्रीय अखंडता इत्यादि की विचारधारा को मजबूत करना और बढ़ावा देना।	वार्षिक आधार पर	—

योजना

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2011-12		परिमाणात्मक कार्य/ भौतिक उत्पादन	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम घटक
1	2	3	4		5	6	7	8
			4 (I)	4 (II)				
			योजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
1.	सेल्स एंपोरियम का आधुनिकीकरण	प्रत्येक (सेल्स एंम्पोरिया) के लिए मोबाइल बुक वैन प्रदान करना।	16.00	-	एक मोबाइल वैन की खरीद	बिक्री को बढ़ावा देने के उद्देश्य से काम करना।	वार्षिक आधार	-
2.	स्टॉक, सूची तथा बिक्री प्रबंधन प्रणाली का आधुनिकीकरण	स्टॉफ की कमी से पार पाना पुस्तकों का मुद्रण/पुनमुर्दण संबंधी निर्णय लेने में प्रभावी तीव्रता एवं प्रभावी लेखा।	78.00		परियोजना से प्राप्त होने वाले लाभ वास्तविक नामों के संबंध में परिमाणात्मक नहीं हैं।	स्टॉफ की कमी से पार पाना पुस्तकों का मुद्रण/पुनमुर्द्रण संबंधी निर्णय लेने में प्रभावी तीव्रता एवं प्रभावी लेखा।		
3.	विभाग के कार्य का पेशेवर अधययन	संभावित बदलाव/ सुधार जो कि सामग्री, प्रारूप, विपणन ढांचा आदि में लाया जा सके और इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने में प्रौद्योगिकी को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है।	25.00		परियोजना से प्राप्त होने वाले लाभ वास्तविक नामों के संबंध में परिमाणात्मक नहीं हैं।	क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के समय में विकास का अंतिम परिणाम संगठन की क्षमता को मजबूत करना है।		
		कुल	**119.00**					

योजना

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 20010-11 (रुपये लाख में)			मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर योजना	योजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजट सांसाधन				
1.	रोजगार समाचार का आधुनिकीकरण, स्वचालन तथा उन्नतिकरण	सरकारी मंत्रालयों/ विभागों को उनके विज्ञापन के प्रकाशन के लिए बेहतर सेवा उपलब्ध कराने के लिए इम्पलायमेंट न्यूज के दफ्तर का कम्प्यूटरीकरण और आधुनिकीकरण अनुलग्नक 'ब' के अनुसार	-	5.00	-	(क) अनुभागों का पुनरुद्धार (ख) एयरकंडीशनर की खरीद (ग) अनियमित वेबसाइट आपरेटर/ स्टाफ प्रशिक्षण की सेवाएं	(क) एक अनुभाग का पुनरुद्धार (ख) अत्याधुनिक कार्य वातावरण का प्रावधान (ग) एंप्लॉइमेंट न्यूज की समर्पित वेबसाइट के जरिये हिंदी और अंग्रेजी में रोजगार अवसरों संबंधी सूचना का प्रसार	8-12	पुनरुद्धार/ अधिग्रहण का कार्य चालू काम को बिना बाधा पहुंचाए किया जाएगा तथा सुनिश्चित किया जाएगा कि यह पूर्णतया स्वचालित कार्य माहौल में तब्दील हो जाए।

एम्प्लाइमेंट न्यूज/रोजगार समाचार

गैर योजना (2011-12)

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2011-12		मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता संबंधी	टिप्पणी/ जोखिम घटक
1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i)	4(ii)				
			गैर-योजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
1.	एम्पलायमेंट न्यूज/रोजगार समाचार आधुनिकीकरण, स्वचलन तथा उन्नतिकरण	एम्पलायमेंट न्यूज/ रोजगार समाचार का प्रकाशन, बेरोजगार युवाओं और लोगों को रोजगार के अवसर की जानकारी देना	2729.00	शून्य	अंग्रेजी, हिन्दी तथा उर्दू में एम्पलायमेंट न्यूज/ रोजगार समाचार के 52 साप्ताहिक अंक निकालना	एम्पलायमेंट न्यूज प्रकाशित करके यह एकक निम्नलिखित लक्ष्य प्राप्ति का उद्देश्य रखता है। (i) केंद्र तथा राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों में नौकरियां, यूपीएससी, एसएससी, राष्ट्रीयकृत बैंकों, रेलवे भर्ती बोर्ड तथा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों के परिणामों तथा प्रवेश अधिसूचनाओं/परीक्षा	वार्षिक आधार पर	

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2011-12		मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i)	4(ii)				
			गैर-योजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
						अधिसूचनाओं की जानकारी देना। (ii) स्व-उद्यमिता तथा विभिन्न उभरते क्षेत्रों तथा परम्परागत क्षेत्रों में कैरियर पर लेखों की शृंखला निकालकर रोजगार के आयामों की जानकारी लोगों को देना। (iii) एम्पलायमेंट न्यूज की वेबसाइट के जरिए सरकारी क्षेत्र में रिक्तियों की जानकारी उपलब्ध की जा रही है। वेबसाइट के जरिए आधुनिकतम मूल्य-संबंधित सेवाएं जैसे ऑनलाइन कैरियर काउंसलिंग तथा पाठकों को सीधे ई-मेल पर जानकारी आदि प्रदान की जा रही हैं।		

अनुलग्नक-I

भारत के समाचारपत्र पंजीयक का कार्यालय
वित्तीय परिव्यय, वास्तविक प्रतिफल तथा अनुमानित परिणाम

गैर-योजना

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य/ उपलब्धियां	परिव्यय 2011-12		मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम घटक
			गैर योजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
1	2	3	4		5	6	7	8
1.	वेतन, ओवर टाइम, चिकित्सीय व्यय, यात्रा व्यय, कार्यालय खर्च, प्रकाशन	कार्यालय के विभिन्न कार्यों को पूरा करना जैसे—शीर्षक जारी करना, पंजीयक प्रमाणपत्र जारी करना, अखबारी कागज के आयात के लिए योग्यता प्रमाणपत्र जारी करना, रियायती शुल्क पर प्रिंटिंग मशीनरी के आयात के लिए अनिवार्यता प्रमाण पत्र जारी करना, प्रिंट मीडिया के विकास पर वार्षिक रिपोर्ट 'प्रेस इन इंडिया' का प्रकाशन इत्यादि।	4.35	शून्य	शीर्षक सत्यापन,* पंजीकरण मामले,* समाचार पत्र प्रमाणपत्र,* अखबारी कागज के आयात के लिए प्रकाशकों को पात्रता प्रमाणपत्र*, प्रिंटिंग मशीन के आयात के लिए प्रकाशकों को अनिवार्यता प्रमाणपत्र*, प्रसार के दावों की समीक्षा* प्रकाशकों से प्राप्त आवेदन पत्रो/प्रार्थनाओं पर आधारित*	इन गतिविधियों से पीआरबी अधिनियम 1867 में निर्धारित प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा। इसके अतिरिक्त मीडिया परिदृश्य के प्रभाव का आकलन किया जा सकता है। प्रसार दावों की समीक्षा के बाद आरएनआई द्वारा जारी प्रमाणपत्रों के आधार पर इन प्रकाशनों को डीएवीपी द्वारा सरकारी विज्ञापन जारी किए जाएंगे। इससे प्रिंट मीडिया द्वारा सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों का प्रचार करने में मदद मिलेगी।	सिटीजन चैप्टर में तय मानकों के अनुसार	लागू नहीं

भारत के समाचारपत्र पंजीयक का कार्यालय

योजना

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2011-12 गैर योजना बजट	परिव्यय 2011-12 पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
1	2	3	4		5	6	7	8
1.	आरएनआई का सुदृढ़ीकरण	11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) के दौरान यह निश्चय किया गया कि आरएनआई के दो नए क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र) तथा भोपाल (मध्य क्षेत्र) में खोले जाएं ताकि पीआरबी अधिनियम का सुचारू रूप से कार्यान्वयन हो सके। इसके साथ ही लोगों त्वरित, सक्षम तीाा पारदर्शी सेवा उपलब्ध हो और प्रसार संख्या की जांच कड़ाई से हो।	0.17	शून्य	आरएनआई के क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी तथा भोपाल में शुरू हुए।	शीर्षक सत्यापन, शीर्षक पंजीकरण, प्रसार दावों के सत्यापन आदि के लिए लोग आर एन आई के मुख्यालय नई दिल्ली आते थे, अब वे लोग आरएनआई के क्षेत्रीय कार्यालयों में ये कार्य करा सकते हैं।	वार्षिक आधार पर	लागू नहीं

गवेषणा, संदर्भ एवं प्रशिक्षण प्रभाग
(परिणाम बजट 2011-12)

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2011-12			मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
1	2	3		4		5	6	7	8
			4(i)	**4(ii)**	**4(iii)**				
			गैर-योजना बजट	**योजना बजट**	**पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन**				
1.	**गैर-योजना**		217.00						
	अ) मास मीडिया के विविध पहलुओं से सम्बंधित प्रलेखन सेवाओं को प्रदर्शित करना	मास मीडिया में इसकी सावधिक सेवाओं के माध्यम से इसकी घटनाओं और प्रवृत्तियों की सूचना एकत्रित, व्याख्यायित और प्रचार-प्रसारित करना	बजट में अलग से प्रावधान नहीं। व्यय सामान्य तौर पर कार्यालय खर्च से पूरा किया जाता है (0.28 लाख रुपये)	-	-	इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2011-12 के दौरान प्रभाग का लक्ष्य 56 प्रलेखन सेवाओं को लाने का है। (विस्तृत जानकारी अध्याय-1 में दी गई है)	प्रलेखन सेवाओं के प्रकाशन से मीडिया यूनिट जैसे हितधारकों को विविध प्रकार की जानकारी हासिल करने में लाभ होगा।	समयावधि के अनुसार	कोई विशेष जोखिम नहीं है।
	ब) भारत में मास मीडिया का संकलन और संपादन—एक वार्षिक प्रकाशन	मास मीडिया पत्रकारिता से संबंधित मीडिया कर्ताओं, मीडिया नीति-निर्धारकों,	- वही -	-	-	भारत में मास मीडिया-इन इंडिया का **23वां** संस्करण प्रकाशित करना।	- वही -	- वही -	- वही -

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2011-12			मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
1	2	3		4		5	6	7	8
			4(i)	**4(ii)**	**4(iii)**				
			गैर-योजना बजट	**योजना बजट**	**पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन**				
		अध्यापकों और छात्रों को सूचना का बहुमूल्य स्रोत प्रदान करता है							
	स) इंडिया एक वार्षिक संदर्भ का संकलन और संपादन	देश के विविध पहलुओं इसके भौगोलिक और जन सांख्यिकीय आकारों, राज्य व्यवस्था, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पक्षों को सूचना का बहुमूल्य स्रोत प्रदान करता है।	- वही -	-	-	इंडिया — एक वार्षिक संदर्भ - 2012 को निकालना	- वही -	- वही -	- वही -

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2010-11			मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
1	2	3		4		5	6	7	8
			4(i)	**4(ii)**	**4(iii)**				
			गैर-योजना बजट	**योजना बजट**	**पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन**				
	द) घटनाक्रमों की पाक्षिक डायरी तैयार करना	मंत्रालय और इसकी मीडिया इकाइयों को राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दैनिक महत्वपूर्ण विकास की जानकारी देना।	- वही -	-	-	इस योजना के अन्तर्गत कार्यालय ने 24 पाक्षिक 'डायरी ऑफ इवेंट्स' निकालने का लक्ष्य रखा है।	- वही -	कार्यक्रम के अनुसार	- वही -
	योजना			25					
	गवेषणा इकाई मास मीडिया में अनुसंधान	किसी विशेष मीडिया संबंधी मुद्दे पर शोध किया जाएगा और जनता की राय ली जाएगी। ताकि नई नीति बनाई जा सके, जिसे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय अपनी मीडिया यूनिटों के माध्यम से राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर लागू कर सके।	-	20.00	-	11वीं पंचवर्षीय योजना की यह योजना वर्ष 2011-12 में पांचवें वर्ष में प्रवेश कर रही है। इस वर्ष इस योजना के तहत राष्ट्रीय क्षेत्रीय और स्थानीय विषय/शीर्षक पर दो शोध पत्र निकाले जाएंगे।	प्रलेखन सेवाओं के प्रकाशन से मीडिया यूनिट जैसे हितधारकों को विविध प्रकार की जानकारी हासिल करने में लाभ होगा।	यह नयी योजना है। बहुत कुछ बाहरी संस्थानों, छात्रों और विशिष्ट व्यक्तियों पर निर्भर करेगा। इससे गहन निगरानी की आवश्यकता है।	- वही -

गैर योजना

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2011-12			मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
1	2	3		4		5	6	7	8
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर-योजना बजट	योजना बजट	मानार्थ अतिरिक्त बजट संसाधन				
2.	अ) संदर्भ यूनिट-लाइब्रेरी का आधुनिकीकरण	इस योजना के तहत प्रस्तावित राष्ट्रीय मीडिया लाइब्रेरी केंद्रीय मीडिया संदर्भ लाइब्रेरी के रूप में कार्य करेगी। इस लाइब्रेरी का उपयोग सूचना प्रसारण मंत्रालय, और उसकी मीडिया यूनिटों के अलावा पत्रकार, शोधकर्ता और विशिष्ट व्यक्ति भी कर सकेंगे। इस लाइब्रेरी को देश-विदेश की महत्वपूर्ण लाइब्रेरियों से जोड़ा जाएगा और 11वीं योजना के पांचवें और पांचवें वर्ष में इस लाइब्रेरी को वर्चुअल लाइब्रेरी में तब्दील कर दिया जाएगा।	-	5.00	-	वर्ष 2011-12 में इस प्रभाग ने 500 किताबें/ई-बुक आवर्ती पत्रिकाएं और सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों के लिए एएमसी खरीदने की कार्य योजना बनायी है।	पुस्तकालय के उन्नयन से मीडिया यूनिट, वरिष्ठ मीडिया हस्तियों, शोध विद्वानों और जानी-मानी हस्तियों इतयादि को लाभ होगा।	लागू नहीं	स्थान की कमी

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2010-11			मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
1	2	3		4		5	6	7	8
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर-योजना बजट	योजना बजट	मानार्थ अतिरिक्त बजट संसाधन				
3.	संदर्भ यूनिट राष्ट्रीय मीडिया पुरस्कार	मीडिया को सामाजिक प्रतिबद्धता स्मरण कराने के लिए, जनता की भलाई के लिए मीडिया की शक्ति का उपयोग करना। सामाजिक कल्याण के प्रति सरकार की जिम्मेदारी निभाने हेतु सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढावा देने में मीडिया की मदद लेना। उत्कृष्ट पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिस्पर्धा कराना। राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर आम सहमति बनाने के लिए कार्य करना। निजी मीडिया को प्रभावशाली भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करना और सार्वजनिक प्रसारण में से समय स्लॉट देकर उन्हें भागीदार बनाना।				इस योजना के तहत प्रभाग ने प्रिंट मीडिया की सात श्रेणियों में हिन्दी और अंग्रेजी दोनों के लिए एक-एक पुरस्कार (21 राष्ट्रीय मीडिया सम्मान) शुरू करने का प्रस्ताव किया है।	मार्ग निर्देशों में प्रस्तावित समयबद्धता के अनुरूप	- वही -	- वही -

गीत एवं नाटक प्रभाग
वार्षिक योजना 2011-12

वर्ष 2009-10 के लिए लक्ष्य और उपलब्धियां

परिव्यय और परिणामों/लक्ष्यों का विवरण (2009-10) (परिणाम बजट 2009-10 के अनुसार) तथा वास्तविक उपलब्धि (योजना और गैर योजना)

(लाख रुपये में)

वित्तीय

बजट अनुमान 2009-10			वास्तविक	व्यय	2009-10
योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
450.00	2316.50	2766.50	437.76	2284.33	2722.09

* पूवोत्तर क्षेत्र के लिए 45.00 लाख रुपये का समावेश वार्षिक योजना 2009-10 का वास्तविक कार्य निष्पादन इस प्रकार है।

गीत एवं नाटक प्रभाग

वार्षिक योजना 2011-12

योजना

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	वर्ष 2009-10 का परिव्यय	मात्रात्मक / वास्तविक परिणाम	31-3-10 को उपलब्धियां डब्ल्यू आर टी कॉल (5)	टिप्पणी/ जोखिम घटक
1	2	3	4	5	6	7
1.	ग्रामीण भारत के लिए जीवंत कला एवं संस्कृति	प्रचार कार्यक्रम	450.00	5980.00	9615.00	437.76
	घटकवार विवरण					
	अ. पर्वतीय/जनजातीय/रेगिस्तानी/ संवेदनशील और सीमा क्षेत्रों में आईसीटी गतिविधियां	- वही -	245.00	4000.00	6663.00	225.33
	ब. 76 चिन्हित जिलों में गतिविधियां	- वही -	42.00	840.00	1261.00	41.56
	स. न्यूनतम साझा कार्यक्रम का प्रचार	- वही -	37.00	570.00	879.00	36.60
	द. जम्मू-कश्मीर व पूर्वोत्तर में विशेष गतिविधियां	- वही -	46.00	520.00	774.00	55.85
	ध. राष्ट्रीय/सामाजिक मुद्दों पर रंगमंचीय कार्यक्रम	- वही -	50.00	50.00	38.00	61.24
	च. अनुसंधान/विकास एवं प्रशिक्षण		21.00	-	-	12.89
	छ. आईआईएमसी द्वारा प्रभाव मूल्यांकन		04.00	-		4.29
	ज. गीत एवं नाटक प्रभाग का आधुनिकीकरण पूंजी	- वही -	05.00	-		शून्य
	कुल		**450.00**	**5980.00**	**9615.00**	**437.76**

योजना/गैर योजना/अन्य मंत्रालय/विभाग

2009-10 के दौरान भौतिक लक्ष्य और उपलब्धियां निम्नलिखित हैं :

क्र.सं.	विवरण	लक्ष्य कार्यक्रम	कार्यक्रम उपलब्धियां	टिप्पणी
(क) सूचना और प्रसारण मंत्रालय कोष के अंतर्गत चलाए जा रहे कार्यक्रम				
1.	गैर योजना	5100.00	6265.00	
2.	योजना	5980.00	9615.00	
(ख) अन्य मंत्रालयों/विभागों के कोष से चलाए जा रहे कार्यक्रम				
3.	(i) व्यापार मेला, नई दिल्ली (ii) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	162.00	162.00	
4.	आयोडीन युक्त नमक	1700.00	786.00	
5.	नेको (राष्ट्रीय एडस नियंत्रण कार्यक्रम) रेड रिबन एक्सप्रेस सहित	3481.00	8571.00	
6.	एन एफ एस एम	2060.00	2097.00	
7.	अन्य		904.00	

(ii) वर्ष 2010-11 (सं.अ.) के लिए बजट आवंटन

योजना	गैर योजना	कुल (लाख रुपये में)
627.00	2024.00	2651.00

भौतिक कार्यनिष्पादन योजना

परिव्यय और परिणाम/लक्ष्यों का विवरण (परिणाम बजट 2010-11 के अनुसार) और वास्तविक उपलब्धि

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	वित्तीय परिव्यय (बी ई 2010-11)	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	31-12-10 को कॉलम (4) और (5) के अनुसार उपलब्धि	टिप्पणी/
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	सजीव कला और संस्कृति पर्वतीय/ जनजातीय/रेगिस्तानी/ संवेदनशील और सीमाक्षेत्रों में आईसीटी गतिविधियां तथा प्रभाव आकलन तथा एस एवं डीडी का आधुनिकीकरण	प्रचार कार्यक्रम	627.00	8685.00	2010-11	349.60	

योजना/गैर योजना/अन्य मंत्रालय/विभाग (2010-11) (दिसंबर 10 तक)
(ख)

क्र.सं.	विवरण	लक्ष्य कार्यक्रम	कार्यक्रम उपलब्धि
क. सूचना और प्रसारण कोष के अन्तर्गत चलाई जा रही गतिविधियां			
1.	गैर योजना	5100	3803
2.	योजना	5980	9459
3.	आबादी स्थिरीकरण	1993	2639
4.	आयोडाइज नमक	3015	953
5.	वत्सल्य मेला	856	18
6.	आईआईटीएफ	-	82

वित्तीय वर्ष 2010-11 का उद्देश्य

योजना	गैर योजना	कुल (लाख रुपये में)
627.00#	2124.00	2751.00

 # 150.00 लाख रुपये पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु विशेष

योजना/गैर योजना/अन्य मंत्रालय/विभाग (2010-11)

क्र.सं.	विवरण	वित्त (लाख रुपये में)
1.	गैर योजना	2194.00
2.	योजना	627.00
3.	आबादी स्थिरीकरण	122.68
4.	वत्सल्य मेला	50.00
5.	आईआईटीएफ	6.95
6.	आयोडाइज नमक	195.00

ग्रामीण भारत के लिए सजीव कला और संस्कृति। इस योजना के निम्नलिखित अवयव हैं :

1. **पर्वतीय, आदिवासी, रेगिस्तानी, संवेदनशील और सीमावर्ती इलाकों में आई सी टी गतिविधियां और मूल्यांकन :** सीमा पार से दुष्प्रचार का जवाब देने के लिए प्रभाग जम्मू-कश्मीर, पंजाब और पूर्वोत्तर क्षेत्र के संवेदनशील और अंदरूनी सीमावर्ती इलाकों में विशेष प्रचार अभियान चलाता है। इस तरह के अभियानों का उद्देश्य इन इलाकों के लोगों को राष्ट्रीय मुख्यधारा से जोड़ना भी है। सभी सीमा केन्द्र अपने क्षेत्रों में विशेष सेवा ब्यूरो, सीमा सुरक्षा बल और अन्य रक्षा एजेंसियों के सहयोग से विभागीय और पंजीकृत निजी दलों, कैजुअल कलाकारों और भाड़े के वाहन लेकर विशेष प्रचार अभियान चलाते हैं।

   प्रभाग आदिवासी, पर्वतीय और रेगिस्तानी इलाकों में वहां के लोगों को उनके कल्याण के लिए चलाई जा रही विकास गतिविधियों की जानकारी देने के लिए कार्यक्रम करता है। कार्यक्रम ऐसे बनाए जाते हैं जिन्हें वे समझा सकें। इन कार्यक्रमों का मकसद लोगों में देश के प्रति निकटता की भावना जगाना और विकास योजनाओं में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देना है। कार्यक्रमों के लिए दल स्थानीय कलाकारों के बीच से बनाए जाते हैं। वे अपने कार्यक्रमों में स्थानीय बोलियों, मुहावरों और कला स्वरूपों का इस्तेमाल करते हैं। प्रभाग की योजना 2010-11 में ऐसे 4200 कार्यक्रम करने की है। निर्धारित रकम में निगरानी, परिवहन, संपर्क, आकलन और मूल्यांकन तथा इकाई मुख्यालय और क्षेत्र में अन्य व्यवस्थाओं का खर्च शामिल है।

2. **राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों पर नाटकों का प्रदर्शन :** संगीत एवं नाटक प्रभाग ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रम सचल है जिसे प्रदर्शनों के लिए जगह-जगह से लाया जाता है। इसमें थिएटर प्रोडक्शन की विभिन्न विधाओं से संबंधित 25 से 30 तकनीशियन और भाड़े के वाहन भी शामिल होते हैं। यह माध्यम जनता और खास तौर से युवाओं को देश की सांस्कृतिक विरासत, जनजीवन, महान हस्तियों के विचारों और ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जानकारी देने के लिए बेहद असरदार है। इसका एक अहम पहलू 100 से 120 स्थानीय कलाकारों और तकनीशियनों की भागीदारी है। प्रभाग का दिल्ली और बंगलुरू में स्थित अपनी दो ध्वनि एवं प्रकाश इकाइयों के जरिए 65 ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने का विचार है।

3. **संगीत एवं नाटक प्रभाग का आधुनिकीकरण :** प्रभाग ने बंगलूरू और दिल्ली में स्थित अपनी ध्वनि एवं प्रकाश इकाइयों को 10वीं योजना में एक तार्किक समय सीमा के भीतर पूरी तरह कंप्यूटरीकृत करने की योजना बनाई थी। प्रभाग की गतिविधियों को और प्रभावी बनाने के लिए मौजूदा क्षेत्रीय इकाइयों के अलावा 11वीं योजना के दौरान खोली गई या प्रस्तावित केन्द्रों को भी अत्याधुनिक तकनीकी उपकरणों से लैस किए जाने की जरूरत है। प्रभाग ने इन उपकरणों और प्रौद्योगिकी की खरीद के लिए 5.00 लाख रुपए का प्रावधान किया है।

4. **76 चिह्नित जिलों में गतिविधियां :** योजना आयोग ने 76 चिह्नित जिलों में 880 लाइव शो आयोजित करने के लिए 42 लाख रुपए प्रदान किए हैं। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता, सांप्रदायिक सौहार्द्र, आतंकवाद का विरोध और देशभक्ति पर केन्द्रित होंगे।

5. **साझा न्यूनतम कार्यक्रम का प्रचार :** प्रभाग 2010-11 में साझा न्यूनतम कार्यक्रम के प्रचार के लिए 620 कार्यक्रम करेगा। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, शिक्षा, ग्रामीण विकास और रोजगार के मुख्य मुद्दों पर केन्द्रित होंगे। इस काम के लिए 27.00 लाख रुपए का आवंटन किया गया है।

6. **जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष गतिविधियां :** इसके तहत प्रभाग 2010-11 में 2920 कार्यक्रम आयोजित करेगा जिनके लिए 156.00 लाख रुपए का आवंटन किया गया है इसमें सरकार के निर्देश के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 150.00 लाख रुपये का कोष मुहैया कराया गया है।

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	वर्ष 2011-12 का परिव्यय (योजना)	मात्रात्मक / वास्तविक	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम घटक
1	2	3	4	5	6	7
	ग्रामीण भारत के लिए जीवंत कला एवं संस्कृति घटकवार विवरण :	प्रचार कार्यक्रम	600.00	8365	2011-12	
	(अ) पर्वतीय/जनजातीय/रेगिस्तानी/संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में आईसीटी गतिविधियां के तहत प्रचार एवं प्रभाव	-do-	277.00	4400	2011-12	
	(B) 76 चिन्हित जिलों में गतिविधियां	-do-	46.00	920	2011-12	
	(C) न्यूनतम साझा कार्यक्रम का प्रचार	-do-	43.00	670	2011-12	
	(D)जम्मू-कश्मीर व पूर्वोत्तर में विशेष गतिविधियां	-do-	115.00	2310	2011-12	
	(E) राष्ट्रीय/सामाजिक मुद्दों पर रंगमंचीय कार्यक्रम	-do-	100.00	65	2011-12	
	(F) गीत एवं नाटक प्रभाग का आधुनिकीकरण (पूंजी)	-do-	05.00			
	(G) अनुसंधान/विकास एवं प्रशिक्षण	-do-	10.00	-		
	(H) आईआईएमसी द्वारा प्रभाव मूल्यांकन	-do-	04.00			

योजना

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	वर्ष 2011-12 का परिव्यय (योजना)			मात्रात्मक / वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम घटक
1	2	3		4		5	6	7
			4(i)	4(ii)	4(iii)			
			गैर-योजना बजट	योजनागत बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन			
1.	ग्रामीण भारत के लिए जीवंत कला एवं संस्कृति	प्रचार कार्यक्रम	–	600.00	–	8365	2011-12	
	घटकवार विवरण :							
	अ. पर्वतीय/जनजातीय/रेगिस्तानी /संवेदनशील/सीमावर्ती क्षेत्रों में आईसीटी गतिविधियां के तहत प्रचार एवं प्रभाव मूल्यांकन	– वही –	–	277.00	–	4400	2011-12	
	ब. 75 चिन्हित जिलों में गतिविधियां	– वही –	–	46.00	–	920	2011-12	
	स. न्यूनतम साझा कार्यक्रम का प्रचार	– वही –	–	43.00	–	670	2011-12	
	द. जम्मू-कश्मीर व पूर्वोत्तर में विशेष गतिविधियां	– वही –	–	115.00	–	2310	2011-12	
	ध. राष्ट्रीय/सामाजिक मुद्दों पर रंगमंचीय कार्यक्रम	– वही –	–	100.00	–	65	2011-12	
	च. अनुसंधान/विकास एवं प्रशिक्षण	– वही –	–	10.00	–	–	2011-12	
	छ. आईआईएमसी द्वारा प्रभाव मूल्यांकन			04.00			2011-12	
	ज. गीत एवं नाटक प्रभाग का आधुनिकीकरण (पूंजी)			05.00			2011-12	
2.	पीएसएस (एनपी)	विभा./निजी/पैनल कलाकारों द्वारा कार्यक्रम	280.00				2011-12	
3.	एमएस (एनपी)		33.00				2011-12	
	कुल		**313.00**	**600.00**				

गीत एवं नाटक प्रभाग

वार्षिक योजना 2010–11 के अनुमानित परिणाम

अनुलग्नक

1. 63,100 व्यक्ति दिवसों के लिए रोजगार उपलब्ध कराए जायेंगे जिससे 31,55,000 व्यक्तियों तक सूचना/संदेश पहुंच सकेगा।

2. i. 42000 व्यक्ति दिवसों के लिए रोजगार सृजन होगा 21,00,000 व्यक्तियों तक सूचना/संदेश पहुंचेगा।

   ii. 8800 व्यक्ति दिवसों के लिए रोजगार सृजित होंगे, 4,40,000 व्यक्तियों तक सूचना/संदेश पहुंचेगा।

   iii. 6200 व्यक्ति दिवसों के लिए रोजगार का सृजन होगा 3,10,000 व्यक्तियों तक सूचना/संदेश पहुंचेगा।

   iv. 5,600 व्यक्ति दिवसों के लिए रोजगार का सृजन होगा 2,80,000 व्यक्तियों तक सूचना/संदेश पहुंचेगा।

   v. 10,000 व्यक्ति दिवसों के लिए रोजगार का सृजन होगा, 1,50,000 व्यक्तियों तक सूचना/संदेश पहुंच सकेगा।

   vi.&vii. कार्यक्रमों की गुणवत्ता में कई गुणा वृद्धि होगी।

एफएम रेडियो (निजी)

मेसर्स ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स लिमिटेड (बेसिल) मंत्रालय की तरफ से छह शहरों में एफ एम टावरों की स्थापना के लिए निजी एफ एम रेडियो परियोजना को क्रियान्वित कर रहा है। इस परियोजना के लिए मंत्रालय की ओर से धन उपलब्ध कराया जा रहा है।

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	योजना कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2011-12			मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर-योजना बजट	योजना बजट	अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
1.	निजी एफएम रेडियो (6 शहरों जैसे दिल्ली, चेन्नई, जयपुर, हैदराबाद, कोलकाता और देहरादून) में नए टावरों को लगाने का कार्य	निजी एफएम प्रसारकों के लिए ट्रांसमिशन उपकरणों को सह-स्थापित करने के लिए नए ट्रांसमिशन टावरों को लगाने का कार्य	—	0.01	—	दिल्ली, चेन्नई, जयपुर, हैदराबाद और देहरादून में पांच टावरों के लगाने का कार्य पूरा हो गया है। कोलकाता में टावर लगाने का काम अभी शुरू होना है क्योंकि वहां बिना बाधा वाली कोई जगह उपलब्ध नहीं है।	उपलब्ध नहीं		

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानिटरिंग केंद्र

योजना/गैर-योजना

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2011-12			मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयसीमा	टिप्पणी/ जोखिम घटक
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर-योजना बजट	योजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
1.	इलेक्ट्रानिक मीडिया अनुश्रवण केन्द्र (ई एम एम सी) की स्थापना।	निजी/विदेशी टी वी चैनलों के कार्यक्रमों की मानिटरिंग ताकि केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 में निर्धारित विज्ञापनों और कार्यक्रमों के कोड का अनुपालन निश्चित किया जा सके।	4.50	2.18	शून्य	चूंकि यह एक मानिंटरिग सुविधा है इसलिए लाभ की मात्रा निश्चित नहीं की जा सकती। वास्तविक आउटपुट 9 जून 2008 से लगभग 300 चैनलों की निगरानी की जा रही है। आवश्यक मशीनरी और उपकरण लगा दिए गए हैं।	ईएमएमसी द्वारा 9.6.2008 से 100 टीवी चैनलों की मानीटरिंग शुरु की गई थी बाद में 2008-09 के दौरान इसे बढ़ाकर 150 टीवी चैनल कर दिया गया। इसे 5.1.2011 से फिर से बढ़ाकर 300 टीवी चैनल कर दिया गया है। योजना आवंटन के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।	ईएमएमसी की मानीटरिंग क्षमता बढ़ाकर 300 चैनल कर दी गई है। निजी एफएम चैनलों की मानीटरिंग कार्यविधि के लिए प्रक्रिया चल रही है जो 31 मार्च 2012 तक पूरी हो जाने की संभावना है।	ईएमएमसी 300 टी वी चैनलों की मानीटरिंग कर रहा है। निजी एफएम चैनलों की मानीटरिंग कार्यविधि का कार्य प्रक्रियाधीन है जिसके 31 मार्च 2012 तक पूरा हो जाने की उम्मीद है बशर्ते निधि उपलबध रहे।

अंतर्राष्ट्रीय चैनल

वित्तीय परिव्यय, अनुमानित वास्तविक आउटपुट तथा अनुमानित परिणाम

चूंकि योजना आरंभिक चरण में है, इसके लिए वर्ष 2010-11 के बजट में 1.0 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2010-11			मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
			4(i) गैर-योजना बजट	4(ii) गैर-योजना बजट	कांम्पली-मेंटरी अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
1	2	3		4		5	6	7	8
1.	अंतर्राष्ट्रीय चैनल	प्रमुख उद्देश्य दुनिया भर में भारत की स्थिति को उसी प्रकार प्रस्तुत करना है, जैसा अलजज़ीरा बीबीसी, सीएनएन, सीसीटीवी, आदि पर किया जाता है।	-	1.00	-	इसके लिये डीडी इंडिया जिसे बहुत से देशों में देखा जाता है, पर प्रसारण के साथ-साथ वर्तमान डीडी न्यूज़ चैनल के जरिये अंतर्राष्ट्रीय समाचारों और कार्यक्रमों की शुरुआत करनी होगी।	संवेदनशील मसलों पर भारत की स्थिति और दृष्टिकोण को संभवत: अधिकतम देशों में यथाशीघ्र पहुंचाना।	प्रस्ताव प्रतिपादन के चरण में है।	

सामुदायिक रेडियो के लिए आईईसी गतिविधियां

सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस नीति के बारे में लोगों में जागरूकता कायम करने का प्रस्ताव करता है। इस उद्देश्य के लिए यह तय किया गया है कि देश के विभिन्न भागों में अनेक कार्यशालाओं एवं सेमिनारों का आयोजन किया जाए ताकि नागरिक समाज एवं स्वैच्छिक संगठनों को सूचना प्रदान की जा सके एवं शिक्षित किया जासके तथा उन्हें सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने एवं उन्हें चलाने के लिए उनमें आवश्यक संचार कौशल का विकास किया जा सके। इसके अलावा जिन संगठनों को अनुमति पत्र हासिल हो चुके हैं तथा जो मौजूदा सामुदायिक रेडियो स्टेशन संचालक हैं, उनकी क्षमता में बढ़ोतरी करना भी उतना ही जरूरी है। सामुदायिक रेडियो के लिए आईईसी गतिविधियां योजना का परिणाम बजट (2011-2012) अनुबंध-1 के रूप में संलग्न है।

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2010-11			परिमाणकीय/ हस्तांतरणीय वास्तविक प्रतिफल	लक्षित परिव्यय	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम घटक
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर-योजना बजट	योजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
1.	सामुदायिक रेडियो के लिए आई ई सी गतिविधियां	सामुदायिक रेडियो प्रसारण के लिए अनुदान	-	80.00	-	एनजीओ/सीएसओ के बीच नीति के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा वर्तमान में कार्य कर रहे सामुदायिक रेडियो स्टेशनों संचालकों की क्षमता निर्माण करना।	समाज और शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के प्रति जागरूकता, सांस्कृतिक एवं सामाजिक एकात्मकता के जरिए सामुदायिक विकास।	देश के विभिन्न हिस्सों में कार्यशालाएं/ परामर्श और प्रचार का आयोजन।	

सूचना भवन का निर्माण

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2011-12			मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर-योजना बजट	योजना बजट (करोड़ रुपये में)	पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
	सीजीओ कॉम्प्लैक्स लोधी रोड, नई दिल्ली में सूचना भवन फेज-V का निर्माण	सिविल एवं विद्युतीय कार्यों का निष्पादन	-	36.22 (बजट अनुमान स्तर पर)	-	1. बुनियाद के साथ-साथ ढांचागत कार्यों का निष्पादन 2. सिविल प्रगति के साथ-साथ विद्युतीय कार्य भी जारी। 3. ब्रिक कार्य, फ्लोरिंग, फिनिशिंग एवं अन्य विविध लकड़ी, स्टील, वाशबेसिन/ सिंक एवं सैनिटरी का कार्य	**विद्युतीय कार्य** 1. फायर फाइटिंग एवं फायर अलार्म 2. लिफ्ट 3. सब स्टेशन 4. विविध विद्युतीय सामग्री **सिविल कार्य** 1. शेष पाइल कैप्स तथा बेसमेंट कार्यों का निष्पादन। 2. पाकेट्स में सुपर स्ट्रक्चर कार्य 3. ब्रिक कार्य, फ्लोरिंग, लकड़ी, स्टील वाशबेसिन/ सिंक, सैनिटरी तथा फिनिशिंग सामग्री	फ्लो चार्ट के अनुसार	(क) यदि आवश्यक अनुमानित विधि की आवंटन नहीं होता है तो कार्य चालू पंचवर्षीय योजना के भीतर पूरा नहीं हो पाएगा। (ख) यदि स्वीकृत कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों को भी शामिल किया जाता है तो कार्य आगामी पंचवर्षीय योजना में चला जाएगा। (ग) सभी ढांचात्मक/ वास्तुकला की ड्राइंग/ विवरणों को समय से जारी किए जाने की आवश्यकता है।

विकास संबंधी पहलों का आर्थिक विश्लेषण (नई योजना)

योजना

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य/परिणाम	परिव्यय 2010-11 (योजना)		परिमाणनीय/ वितरण योग्य/ भौतिक नतीजे	अनुमानित परिणाम	प्रोसेस/ समयबद्धता	अभियुक्ति/ जोखिम घटक
1.	2	3	4		5	6	7	8
			4 (i) योजना बजट	4 (ii) पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
1.	विकास संबंधी पहल का आर्थिक विश्लेषण	-फिल्म, सूचना और प्रसारण क्षेत्र में प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) विकसित करना; -फिल्म, सूचना और प्रसारण क्षेत्र के बारे में नियामक और विकास नीतियों के प्रभाव का अध्ययन और मूल्यांकन	0.50		● एमआईएस विकास ● अध्ययन आयोजित किए जाने हैं	i) इससे मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र-के विकास में आने वाली रुकावटों, विकास में इसके योगदान के बारे में मौजूदा ज्ञान के आधार का विस्तार होगा। ii) इससे मंत्रालय के स्तर पर नीति निर्माण प्रक्रिया मजबूत करने में सहायता मिलेगी। iii) लोक क्षेत्र के लिए सूचना संप्रेषण		

मानव संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षण

इस स्कीम के लिए वर्ष 2011–12 हेतु अनुमानित वार्षिक योजना परिव्यय 150 लाख रुपए है। मंत्रालय के अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु विशिष्ट होने के कारण इसका (i) जेंडर बजट, (ii) अजजा बजट, और (iii) पूर्वोत्तर बजट संबंधी कोई विशिष्ट भाग नहीं है। हालांकि प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए अधिकारियों को नामित करते समय महिलाओं, अजा/अजजा अधिकारियों और पूर्वोत्तर के प्रतिनिधित्व का पूरा ध्यान रखा जाता है।

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2011–12 योजना	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आईआईएस अधिकारियों के लिये विदेश स्थित संस्थानों में मानव संसाधन विकास के लिये प्रशिक्षण	1. मानव संसाधन विकास के अंतर्गत मंत्रालय के अधिकारियों को प्रशिक्षण देना ताकि उनकी योग्यता में इजाफा हो। 2. मंत्रालय के अधिकारियों को मीडिया/प्रशासन से संबंधित कई क्षेत्रों में विदेशी संस्थानों में प्रशिक्षण देना। 3. अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण और जरूरतों को समझने के लिए विदेशों में स्थित संस्थान जैसे बीबीसी, थॉमसन फाउंडेशन, यूके, रेडियो नीदरलैंड, हार्वड यूनिवर्सिटी में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना। 4. आईआईएस अधिकारियों को विभिन्न मीडिया इकाइयों में भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए उनके कैरियर के निरंतर विकास के लिये तैयार कार्यक्रमों का प्रशिक्षण।	150.00	(क) 11वीं पंचवर्षीय योजना के पांचवें वर्ष 2011–12 में निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं : * मंत्रालय और इसकी मीडिया इकाइयों के 40–50 अधिकारियों को प्रशिक्षण देना। * कैरियर के दौरान * प्रशिक्षण के लिए सुव्यवस्थित प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना। * भारतीय सूचना सेवा के 120–140 अधिकारियों को प्रशिक्षण देना।	कौशल उन्नयन सुधार के जरिए संगठन के प्रभाव को सुधारना	विभिन्न संस्थानों / संगठनों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार इसे वर्ष भर में बांटा जाएगा।	कोई विशिष्ट जोखिम नहीं

मानव संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षण

परिणाम बजट 2010-11 में परिणाम लक्ष्य

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	स्कीम का नाम	परिव्यय	वास्तविक आउटपुट	प्रक्षेपित परिणाम	टिप्पणी/जोखिम तत्व
1.	आईआईएस अधिकारियों के लिए विदेश स्थित संस्थानों में मानव संसाधन विकास के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण	150.00	अभी तक विभिन्न प्रशिक्षणों के लिए कुल 12 अधिकारियों को नामित किया गया है।	विभिन्न मीडिया एककों के प्रभावशाली संचालन के लिए क्षमता का विकास, अधिकारियों की क्षमता तथा कौशल का उन्नयन।	कोई विशिष्ट जोखिम नहीं। मंत्रालय ने दो विदेश प्रशिक्षण कार्यक्रमों जिसमें से एक आस्ट्रेलिया में है, का परिचालन किया है जो मार्च, 2011 में आयोजित किया जाएगा तथा विभिन्न मीडिया एककों के भारतीय सूचना सेवा अधिकारियों के लिए आईआईएमसी में सेवा के दौरान प्रशिक्षण का मापदंड आईआईएमसी से प्राप्त हो गया है तथा प्रशिक्षण के लिए 20 लाख रुपये (लगभग) राशि का उपयोग किया जाएगा तथा 10 लाख रुपये (लगभग) की राशि भारतीय सूचना सेवा समूह 'क' परिवीक्षाधीन अधिकारियों के पाठ्यक्रम शुल्क के रूप में आईआईएमसी को प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त 6 विभिन्न आवासीय प्रशिक्षणों का मंत्रालय ने परिचालन किया है जो जनवरी से मार्च, 2011 के दौरान आयोजित किए जाएंगे।

आकाशवाणी - वार्षिक योजना (2011-12)

परिणाम बजट में परिणाम/लक्ष्य

करोड़ रु. में

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2011-12	मात्रात्मक लाभ/वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	टिप्पणी
1	2	3	4		5	6
1	चालू स्कीमें					
	पूंजी					
	राजस्व					
1	जम्मू कश्मीर विशेष पैकेज (चरण I और II)	जम्मू-कश्मीर में रेडियो कवरेज के विस्तार के लिए	2.50	जम्मू-कश्मीर पैकेज चरण-I पूरा हो चुका है। जम्मू-कश्मीर पैकेज चरण-II स्कीम में शामिल डीजी सेट और यूपीएस खरीदे जा चुके हैं। अल्प लंबित कार्य 2011-12 में पूरा हो जाएगा।	Q1 - लंबित संस्थापन कार्य को पूरा करना	
	पूंजी		0.50			
	राजस्व		2.00			
2	MW सेवाओं का विस्तार	प्राथमिक कवरेज क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए ट्रांसमीटरों का उन्नयन	0.40	पूरा	पूरा	
3	FM सेवाओं का विस्तार		20.52	10KW FM के 41 ट्रांसमीटरों का संस्थापन पूरा	Q1- साइट पर ट्रांसमीटरों की प्राप्ति, Q2- संस्थापन शुरू, Q3- संस्थापन पूरा, Q4- जांच और मापन	नए स्टेशनों और अतिरिक्त चैनलों को चालू करने के लिए O&M स्टाफ की जरूरत होगी।
				20 KW FM के 4 ट्रांसमीटरों की खरीद		
				3. अमृतसर में निर्माण कार्य पूरा (20 KW FM Tr.)	Q1- लोक निर्माण कार्य शुरू Q2- लोक निर्माण कार्य जारी Q3- ट्रांसमीटर भवन का निर्माण पूरा Q3- ट्रांसमीटर का संस्थापन	300 M TV टॉवर पूरा होने के बाद (जो 11 मार्च तक होने की संभावना है) अमृतसर में FM tr. शुरू होगा।
				हल्द्वानी, रायबरेली और चम्पावत में जगह का अधिग्रहण	Q1- हल्द्वानी और चम्पावत में साइट का अधिग्रहण यदि मांग नोट प्राप्त हो जाता है तो रायबरेली साइट के लिए भुगतान Q3- रायबरेली में साइट का अधिग्रहण	चम्पावत ओर हल्द्वानी साइटों के लिए डिमांड नोट की प्रक्रिया जारी है। रायबरेली में पहचानी गई साइट को अभी राज्य सरकार द्वारा आवंटित किया जाना है।
				बर्दमान, धनबाद और दार्जिलिंग में निर्माण कार्य पूरा	Q1- लोक निर्माण कार्य शुरू Q2- लोक निर्माण कार्य जारी Q3- ट्रांसमीटर भवन का निर्माण पूरा Q4- ट्रांसमीटर का संस्थापन	ट्रांसमीटर भवन के लिए अनुमान प्रक्रियाधीन है तथा 11 मार्च तक काम प्रदान किए जाने की संभावना है।
				बागेश्वर 5 KW FM Tr., करीमनगर 5 KW FM Tr., उज्जैन 5 KW FM Tr का संस्थापन पूरा	Q1- ट्रांसमीटर का संस्थापन शुरू Q2- संस्थापन का काम पूरा Q3- जांच और मापन	बागेश्वर और उज्जैन में ट्रांसमीटर के लिए आदेश दे दिए गए हैं तथा 11 मार्च तक प्राप्त हो जाने की संभावना है। पहले

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2011-12	मात्रात्मक लाभ/वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	टिप्पणी
1	2	3	4		5	6
						हैदराबाद की ओर परिवर्तित करीमनगर ट्रांसमीटर को वापस लाया गया है क्योंकि वहा 10 KW FM का Tr. संस्थापित हो गया है। स्टेशन चालू करने के लिए O&M स्टाफ की मंजूरी की जरूरत है।
				श्रीकाकुलन 1 KW FM Trs., नई टिहरी 1 KW FM Trs. ओर गैरषेण 1 KW FM Tr. का संस्थापन पूरा	Q1- ट्रांसमीटर का संस्थापन शुरू Q2- संस्थापन का काम पूरा Q3- जांच और मापन	श्रीकाकुलन 1 KW FM Tr., नई टिहरी 1 KW FM Tr. और गैरषेण 1 KW FM का ट्रांसमीटर स्थापित होने के बाद वहां से वापस लाया गया है। श्रीकाकुलम में लोक निर्माण कार्य पूरा हो चुका है तथा गैरषेण और नई टिहरी में 11 मार्च तक पूरा हो जाएगा। स्टेशनों को चालू करने के लिए O&M स्टाफ की मंजूरी की जरूरत है।
				कूचविहार ओर बलूरघाट में 10 KW FM Trs. का संस्थापन पूरा और बर्दमान, धनबाद और दार्जिलिंग में संस्थापन कार्य प्रगति पर	Q1- ट्रांसमीटरों की प्राप्ति Q2- कूचविहार और बलूरघाट में ट्रांसमीटर का संस्थापन शुरू Q3- कूचविहार और बलूरघाट में ट्रांसमीटर का संस्थापन पूरा Q4- बर्दमान, धनबाद और दार्जिलिंग में संस्थापन	ट्रांसमीटरों के लिए निविदा की प्रक्रिया जारी है तथा 11 फरवरी तक आदेश जारी होने की संभावना है। स्टेशनों को चालू करने के लिए O&M स्टाफ की मंजूरी की जरूरत है।
	प्रोडक्शन सुविधाओं का डिजिटलाइजेशन	विषय सामग्री की तकनीकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए	0.18	ट्रांसमिशन (16) और रिकार्डिंग (17) कंसोल का संस्थापन पूरा	Q1- साइटो पर कानसोल प्राप्त होने की संभावना Q2- कनसोल का संस्थापन प्रगति अधीन होने की संभावना Q3- संस्थापन कार्य पूरा होने वाला है।	
	स्टूडियो सुविधाओं और विविध स्कीमों का ऑटोमेशन		5.00	राजकोट में 1000 KW MW Trs. का संस्थापन पूरा	Q1- संस्थापन प्रगति पर Q2- संस्थापन पूरा Q3- जांच और मापन Q4- ट्रांसमीटर चालू	ट्रांसमीटर का प्रेषण पूर्व निरीक्षण पूरा हो गया है तथा 10 दिसंबर तक प्राप्त हो जाने की संभावना है।
				48 केंद्रों पर हाई एंड सर्वरों का संस्थापन पूरा	Q1- कुछ स्टेशनों पर उपकरण की प्राप्ति और SITC कार्य शुरू Q2- शेष स्टेशनों के उपकरण की प्राप्ति, उन स्टेशनों पर SITC कार्य पूरा जहां Q1- में उपकरण प्राप्त हो गए थे तथा शेष स्टेशनों में कार्य प्रगति पर Q3- SITC कार्य पूरा Q4- जांच और मापन	हाई एंड सर्जरी के लिए खरीद प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2011-12	मात्रात्मक लाभ/वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	टिप्पणी
1	2	3	4		5	6
				सिल्चर और देहरादून में कैप्टिव भू-केंद्रों का संस्थापन पूरा	Q2- उपकरण की प्राप्ति Q3- संस्थापन कार्य शुरू Q4- संस्थापन कार्य पूरा	निविदाओं का तकनीकी मूल्यांकन पर है। 11 मार्च तक अग्रिम A/T दिया जाने की संभावना है।
6	पूर्वोत्तर विशेष पैकेज	पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेडियो कवरेज बढ़ाने के लिए	45.00	अनिनी (अरूणाचल), तमेन्लोंग और उखरूल (मणिपुर) में 1 KW FM के 19 ट्रांसमीटरों के लिए 3 लंबित साइट का अधिग्रहण	साइटों को राज्य सरकारों द्वारा आवंटन मिलना है। मामले को आगे बढ़ाया जा रहा है।	अनिनी में प्रस्तावित की जा रही वैकल्पिक साइट के विवरण की राज्य सरकार से प्रतीक्षा है। तमेंगलोंग और उखरूल जोनल कार्यालय की टीम कानून व्यवस्था में सुधार होते ही साइट की विजिट करेगी। मामला आगे बढ़ाया जा रहा है।
	पूंजी		45.00	16 जगहों पर जिन्हें अंतिम रूप दे दिया गया है, लोक निर्माण काम पूरा	Q1- चंफाई, लम्डिंग, खोनसा और चांगलांग में लोक निर्माण कार्य पूरा करना। करीमगंज, चेरापूंजी, बोमडिला, फेक और दोखा में लोक निर्माण कार्य शुरू करना तथा जुनेहबोतो में लोक निर्माण कार्य सौंपना Q2- करीमगंज, चेरापूंजी, बोमडिला, फेक और दोखा में लोक निर्माण कार्य जारी रखना तता जुनेहबोतो में लोक निर्माण कार्य शुरू करना। Q3- करीमगंज, चेरापूंजी, बोमडिला, फेक और दोखा में ट्रांसमीटर निर्माण कार्य पूरा करना। जुनेहबोतो में लोक निर्माण कार्य जारी रखना। Q4- जनेहबोतो में लोक निर्माण कार्य पूरा करना।	छह स्थानों तुईपांग, नूतन बाजार, उदयपुर, ग्वालपाड़ा दापारजियो और कोलासिव में ट्रांसमीटर भवन तैयार हैं। चार स्थानों चम्फाई, लम्डिंग, खोनसा औरचांगलांग में लोक निर्माण कार्य प्रगति पर है। पांच स्थानों करीमगंज, चेरापूंजी, बोमडिला, फेक और दोखा में भवन निर्माण का अनुमान कार्य प्रगति पर है तथा 11 मार्च तक कार्य सौंपने की संभावना है। जुनेहबबोतो में साइट शीघ्र ही अधिग्रहीत होने की संभावना है। संबंधित राज्य सरकारों ने चंफाई, फेक, ग्वालपाड़ा, कोलासिब, चांगलांग, खोनसा और दारपेरिजो में आकाशवाणी की साइट के लिए संपर्क मार्ग का निर्माण कर दिया है। मामला आगे बढ़ाया जा रहा है।
	राजस्व		0.00	6 जगहों पर 1 K FM Trs. संस्थापन का काम पूरा	Q2- चम्फाई, लम्डिंग, खोनसा और चांगलांग में संस्थापन कार्य शुरू करना Q3- चम्फाई, लम्डिंग, खोनसा और चांगलांग में संस्थापन कार्य शुरू करना और करीमगंज एक चेरापूंजी, बोमडिला, फेक और दोखा में कार्य शुरू Q4- करीमगंज एवं चेरापूंजी, बोमडिला, फेक और दोखा में संस्थापन कार्य पूरा करना	O&M स्टाफ की मंजूरी के लिए स्टेशन चालू करने की जरूरत है।

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2011-12	मात्रात्मक लाभ/वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	टिप्पणी
1	2	3	4		5	6
				2. सिल्वर -5 KW FM Tr. - संस्थापन का काम पूरा	Q1- ट्रांसमीटर का संस्थापन शुरू करना Q2- संस्थापन पूरा करना Q3- परीक्षण और मापन	ट्रांसमीटर के लिए आर्डर दिया गया और 11 मार्च तक प्राप्त होने की संभावना है। O&M स्टाफ की मंजूरी के लिए अतिरिक्त चैनल चालू करने की जरूरत है।
				3. गंगतोक - 10 KW FM Tr. - संस्थापन का काम पूरा	Q1- साइट पर ट्रांसमीटरों की प्राप्ति Q2- संस्थापन शुरू करना Q3- संस्थापन शुरू करना Q4- परीक्षण और मापन	ट्रांसमीटर के लिए आर्डर दिया गया और 11 मार्च तक प्राप्त होने की संभावना है। O&M स्टाफ की मंजूरी के लिए अतिरिक्त चैनल चालू करने की जरूरत है।
				4. चिनसुरा - 1000 KW MW Tr. संस्थापन का काम पूरा	Q1- ट्रांसमीटर का संस्थापन शुरू करना Q2- संस्थापन पूरा करना Q3- परीक्षण और मापन	ट्रांसमीटर के लिए आर्डर दिया गया तथा 11 मार्च तक प्राप्त होने की संभावना है। O&M स्टाफ की मंजूरी के लिए अतिरिक्त चैनल चालू करने की जरूरत है।
				5. कावारत्ती - 10 KW MW Tr. संस्थापन का काम पूरा	Q1- ट्रांसमीटर का संस्थापन शुरू करना Q2- संस्थापन पूरा करना Q3- परीक्षण और मापन	्टांसमीटर के लिए आर्ड दिया गया तथा 11 मार्च तक प्राप्त होने कीसंभावना है।
				6. DSNG सिस्टम्स (3) - उपकरण की खरीद और तैनाती	Q1- खरीद प्रस्ताव का अनुमोदन और अग्रिम A/T का प्लेसमेंट Q2- फर्म से कार्य निष्पादन बैंक गारंटी प्राप्त करना तथा औपचारिक A/T का प्लेसमेंट Q3- उपकरण की प्राप्ति Q4- उपकरण की तैनाती	DSNG प्रणालियों (डिजिटल सैटेलाइट न्यूज गैदरिंग) के लिए निविदाओं का मूल्यांकन जारी है।
7	स्टॉफ के लिए आवास (मेट्रो स्टॉफ क्वार्टर)	प्रसार भारती कर्मचारियों के लिए मेट्रो केन्द्रों पर स्टॉफ क्वार्टर के निर्माण के लिए	1.00	दिल्ली - दिल्ली में फेज -2 (203 क्वार्टर) का काम पूरा	फेज -2 का काम पूरा	

क्र.सं. 1	योजना/कार्यक्रम का नाम 2	उद्देश्य/परिणाम 3	परिव्यय 2011-12 4	मात्रात्मक लाभ/वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य) 5	टिप्पणी 6
				मुंबई - मुंबई में 68 क्वार्टर बनाने का काम	Q1- कार्य सौंपना Q2- कार्य जारी करना Q3- कार्य जारी करना Q4- कार्य पूरा करना	सुपरस्ट्रक्चर के लिए निविदाएं प्रक्रियाधीन हैं
				चेन्नई - चेन्नई में 52 क्वार्टर बनाने का काम		CMDA के साथ योजना की अनुमति पर बात की जा रही है।
				कोलकाता - कोलकाता में 81 क्वार्टर बनाने का काम		कोलकाता मेट्रो विकास प्राधिकरण) द्वारा भूमि के एकपक्षीय वापसी के विरुद्ध याचिका दायर की गई है। अदालत ने स्थगनादेश दिया है तथा मामला विचाराधीन है।
2	नई स्कीमें					
2.1	ट्रांसमीटरों, स्टूडियो, कनेक्टिविटी और DTH चैनल का डिजिटलीकरण	डिजिटल मोड में राष्ट्रव्यापी कवरेज के लिए SW DRM Tr. एफएम विस्तार स्टूडियो डिजिटाइजेशन और कनेक्टिविटी	133.77			
	MW DRM ट्रांसमीटर					
1	मौजूदा स्टेशनों पर नए DRM MW ट्रांसमीटर लगवाकर 31 पुराने MW ट्रांसमीटर को बदलना					
	20 KW -5 संख्या, दिल्ली VB, बाड्मर & बीकानेर (राजस्थान), चेन्नई (तमिलनाडु) VB], गुवाहाटी B			1. लोक निर्माण का काम पूरा, उपकरण की खरीद, उपकरण का संस्थापन	Q1- लोक निर्माण कार्य के लिए प्रारंभिक अनुमानों की मंजूरी। Q2- लोक निर्माण सौंपना Q3- लोक निर्माण को पूरा करना। उपकरण की प्राप्ति Q4- उपकरण का संस्थापन	दस 100 KW और नौ 200 KW के लिए टीई एक 50 KW, छह 300 KW और 20KW के लिए निविदाओं का तकनीकी मूल्यांकन पूरा हो चुका है।
	*50 KW-1 [मुंबई 'C' (महाराष्ट्र)]			1. लोक निर्माण का काम पूरा, उपकरण की खरीद उपकरण का संस्थापन	Q1- लोक निर्माण कार्य के लिए प्रारंभिक अनुमानों की मंजूरी। Q2- लोक निर्माण कार्य सौंपना Q3- लोक निर्माण को पूरा करना। Q4- उपकरण का संस्थापन	दस 100 KW के लिए तकनीकी मूल्यांकन पूरा और मूल्य निविदा खोली जा चुकी है और खरीद प्रस्ताव की प्रक्रिया जारी है।

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2011-12	मात्रात्मक लाभ/वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	टिप्पणी
1	2	3	4		5	6
	100 KW-10 संख्या [विजयवाड़ा (आंप्र), पटना (बिहार, पणजी (गोवा), रांची (बिहार, मुंबई 'A' (महा), मुंबई 'B' (महा), पुणे (महा), तिरूचिरापल्ली (तमिल), वाराणसी (उ.प्र.), कोलकाता 'A' (प.बं.)]			1. लोक निर्माण का काम पूरा, उपकरण की खरीद, उपकरण का संस्थापन	Q1-लोक निर्माण कार्य के लिए प्रारंभिकअनुमानों की मंजूरी। उपकरण के लिए आर्डर प्लेसमेंट Q2- लोक निर्माण सौंपना Q3- लोक निर्माण कार्य पूरा करना। उपकरण की प्राप्ति में प्रगति लाई जाएगी। Q4- उपकरण की प्राप्ति पूरी तथा उपकरण के संस्थापन में प्रगति लाई जाएगी	दस 100 KW के लिए तकनीकी मूल्यांकन पूरा और मूल्य निविदा खोली जा चुकी है और खरीद प्रस्ताव की प्रक्रिया जारी है।
	*200 KW -9 संख्या [दिल्ली 'A', अहमदाबाद (गुजरात), बंगलुरू और धारवाड (कर्नाटक, जबलपुर (म.प्र.), अजमेर (राजस्थान), चेन्नई 'A' (तमिलनाडु), सिलीगुडी और कोलकाता 'B' (पं. बंगाल)			1. लोक निर्माण का काम पूरा, उपकरण की खरीद, उपकरण का संस्थापन	Q1- कुछ स्थानों पर लोक निर्माण कार्य के लिए प्रारंभिक अनुमान की प्राप्ति और मंजूरी। उपकरण की लिए आर्डर देना। Q2- बाकी स्थानों के लिए प्रारंभिक अनुमानों की मंजूरी। ऐसे स्थानों पर भवन निर्माण कार्य सौंपा जहां प्रारंभिक अनुमानों को पिछली तिमाही में मंजूरी दी गई थी। Q3- बाकी स्थानों के लिए भवन निर्माण कार्य सौंपना। ऐसे स्थानों पर भवन निर्माण कार्य पूरा करना जहां कार्य दूसरी तिमाही में सौंपा गया था। Q4- बाकी स्थानों पर भवन निर्माण कार्य पूरा करना उपकरण की प्राप्ति शुरू। ऐसे स्थानों पर विभागीय कार्य की प्रगति जहां भवन निर्माण कार्य तीसरी तिमाही में पूरी हो चुकी है।	नौ 200 KW- के लिए निविदाओं का तकनीकी मूल्यांकित किया जा रहा है।
	*300 KW -6 संख्या [डिब्रूगढ (असम), राजकोट (गुजरात), जम्मू (जम्मू-कश्मीर), जालंधर (पंजाब), सूरतगढ़ (राजस्थान), लखनऊ (उ.प्र.)]			1. लोक निर्माण का काम पूरा, उपकरण की खरीद, उपकरण का संस्थापन	Q1- कुछ स्थानों पर लोक निर्माण कार्य के लिए प्रारंभिक अनुमान की प्राप्ति और मंजूरी। उपकरण की लिए आर्डर देना। Q2- बाकी स्थानों के लिए प्रारंभिक अनुमानों मंजूरी। ऐसे स्थानों पर भवन निर्माण कार्य सौंपा जहां प्रारंभिक अनुमानों को पिछली तिमाही में मंजूरी दी गई थी। Q3- बाकी स्थानों के लिए भवन निर्माण कार्य सौंपना। ऐसे स्थानों पर भवन निर्माण कार्य पूरा	नौ 300 KW- के लिए निविदाओं का तकनीकी मूल्यांकित किया जा रहा है।

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2011-12	मात्रात्मक लाभ/वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	टिप्पणी
1	2	3	4		5	6
					करना जहां कार्य दूसरी तिमाही में सौंपा गया था। Q4- बाकी स्थानों पर भवन निर्माण कार्य पूरा करना उपकरण की प्राप्ति शुरू। ऐसे स्थानों पर विभागीय कार्य की प्रगति जहां भवन निर्माण कार्य तीसरी तिमाही में पूरी हो चुकी है।	
2	अरूणाचल-चीन सीमा पर कैप्टिव पावर प्लांट के साथ 3 MW DRM Tr. का उन्नयन					
	पासीघाट -100 KW (10 KW का विस्थापन)			1. लोक निर्माण का काम पूरा 2. उपकरण की खरीद 3. उपकरण का संस्थापन	Q1- लोक निर्माण शुरू करना Q2- लोक निर्माण पूरा करना तथा विभागीय कार्य शुरू करना Q3- उपकरण प्राप्ति और संस्थापन शुरू करना Q4- संस्थापन पूरा करना	उपकरण के लिए निविदाओं का तकनीकी मूल्यांकन किया जा रहा है। पासीघाट में लोक निर्माण कार्य के लिए अनुमान को मंजूरी दे दी गई है।
	ईटानगर 200 KW (100 KW का विस्थापन)			1. लोक निर्माण का काम पूरा 2. उपकरण की खरीद 3. उपकरण का संस्थापन	Q1-लोक निर्माण कार्य सौंपना। उपकरण के लिए ऑर्डर देना। Q2-लोक निर्माण कार्य जारी Q3-भवन निर्माण को पूरा करना और विभागीय कार्य को पूरा करना। उपकरण की प्राप्ति Q4-संस्थापन और विभागीय कार्य की प्रगति	उपकरण के लिए निविदाओं का तकनीकी मूल्यांकन किया जा रहा है। पासीघाट में लोक निर्माण कार्य के लिए अनुमान को मंजूरी दे दी गई है।
	त्वांग-20 KW (10 KW का विस्थापन)			1. लोक निर्माण का काम पूरा 2 उपकरण की खरीद 3. उपकरण का संस्थापन	Q1-लोक निर्माण कार्य सौंपा गया। उपकरण के लिए ऑर्डर दिया गया। Q2-लोक निर्माण कार्य पूरा करना Q3-उपकरण की प्राप्ति Q4- उपकरण का संस्थापन	उपकरण के लिए निविदाओं का तकनीकी मूल्यांकन किया जा रहा है। त्वांग में लोक निर्माण कार्य के अनुमान को मंजूरी दे दी गई है।
3	MW DRM ट्रांसमीटर द्वारा छह 10 KW MW मोबाइल को बदलना			मामूली लंबित काम पूरा		ट्रांसमीटर को भेजने से पहले का निरीक्षण पूरा हो चुका है तथा 10 दिसंबर तक प्राप्त होने की सम्भावना।
4	36 मौजूदा DRM कम्पेटीबल MW Tr. का DRM में रूपांतरण			1. DRM उपकरण की प्राप्ति और संस्थापन का काम पूरा	Q1- प्रमुख DRM उपकरण की प्राप्ति शुरू Q2- संस्थापन की शुरुआत 5 Q3- उपकरण का संस्थापन पूरा करना Q4- परीक्षण और मापन	PAC (प्रोप्राइटरी स्वीकृति प्रमाणपत्र) प्रस्ताव अनुमोदन के लिए मंत्रालय को भेजा गया। मंत्रालय द्वारा मांगे गए प्रमाणन का जवाब दिया जा रहा है।

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2011-12	मात्रात्मक लाभ/वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	टिप्पणी
1	2	3	4		5	6
4	36 मौजूदा DRM कम्पेटीबल MW Tr. का DRM में रूपांतरण			1. DRM उपकरण की प्राप्ति और संस्थापन का काम पूरा	Q1- प्रमुख DRM उपकरण की प्राप्ति शुरू Q2- संस्थापन की शुरुआत 5 Q3- उपकरण का संस्थापन पूरा करना Q4- परीक्षण और मापन	PAC (प्रोप्राइटरी स्वीकृति प्रमाणपत्र) प्रस्ताव अनुमोदन के लिए मंत्रालय को भेजा गया। मंत्रालय द्वारा मांगे गए प्रमाणन का जवाब दिया जा रहा है।
	FM डिजिटल कम्पेटीबल ट्रांसमीटर					
5	मौजूदा 24 AIR/TV साइट पर FM विस्तार			1. लोक निर्माण का काम पूरा 2. उपकरण की खरीद 3. उपकरण का संस्थापन का काम पूरा : 1 KW (12) & 5 KW (12)	Q1- कुछ स्थानों पर लोक निर्माण कार्य को पूरा करना Q2- बाकी स्थानों पर लोक निर्माण कार्य पूरा करना। उपकरण की प्राप्ति शुरू और संस्थापन Q3- उपकरण की प्राप्ति को पूरा करना और कुछ स्थानों पर संस्थापन पूरा करना Q4- बाकी स्थानों पर संस्थापन पूरा करना	उपकरण के लिए निविदाओं के तकनीकी मूल्यांकन पूरा तथा वाणिज्यिक बोली खोली गई। जोनल कायाल्य कार्यक्रम इनपुट रैंक, ऑडियो प्रोसेसर और आडियो एनलाइजर जैसे संबंधित उपकरण खरीद रहा है।
	DD/AIR के मौजूदा 100 LPTs पर 100 Watt FM Trs.			1. उपकरण की खरीद 2. उपकरण (100) का संस्थापन का काम पूरा	Q1- सिविल माडिफिकेशन कार्य पूरा करना Q2- जोनल कार्यालय में उपकरण की प्राप्ति शुरू और करीब 35 स्थानों पर संस्थापन को पूरा करना Q3- उपकरण की प्राप्ति को पूरा करना, 35 स्थानों पर संस्थापन को पूरा करना Q4- बाकी स्थानों पर संस्थापन पूरा करना	ट्रांसमीटर के लिए खरीद प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है
6	40 मौजूदा स्टेशनों पर ज्यादा पावर द्वारा FM/MW ट्रांसमीटर का विस्थापन			1. निर्माण कार्य पूरा 2. 6 KW FM (27) Trs और 10 KW FM Trs. (13) की खरीद 3. संस्थापन का काम पूरा	Q1- सिविल माडिफिकेशन कार्य सौंपना और शुरू Q2- सिविल माडिफिकेशन कार्य पूरा करना और विभागीय कार्य शुरू करना। उपकरण की डिलीवरी शुरू। Q3- विभागीय कार्य और संस्थापन कार्य जारी। Q4- संस्थापन कार्य पूरा करना	सिविल जरूरतों के उपकरण के लिए निविदाओं का तकनीकी मूल्यांकन पूरा होने वाला है। जोनल कार्यालय कार्यक्रम इनपुट रैंक, ऑडियो प्रोसेसर और ऑडियो एनलाइजर जैसे संबंधित उपकरण खरीद रहा है।
7	5 SW ट्रांसमीटर (दिल्ली-2 स., अलीगढ़-2 संख्या, बंगलुरू-1 संख्या) का SW DRM Trs से विस्थापन			1. दिल्ली (किंग्जवे) में 100 KW SW (2 संख्या) Trs. की खरीद 2. अलीगढ़ (उ.प्र.) में 250 KW SW Trs. (2) Trs. की खरीद 3. बंगलुरू (WB) (कर्नाटक)-500 KW SW और खरीद	Q1- दिल्ली (किंग्सवे) और अलीगढ़ में सिविल कार्य के लिए अनुमानों की संस्तुति। 100 KW और 250 KW SW Trs. के लिए ऑर्डर प्लेसमेंट। 500 KW SW Trs. के लिए खरीद प्रस्ताव की प्रोसेसिंग Q2- दिल्ली (किंग्जवे) और अलीगढ़ में सिविल कार्य को सौंपना तथा बंगलुरू में सिविल	100 KW और 250 KW SW Trs. के लिए निविदाओं का तकनीकी मूल्यांकन पूरा हो चुका है तथा 500 KW SW Trs. के लिए प्रगति पर है।

क्र.सं. 1	योजना/कार्यक्रम का नाम 2	उद्देश्य/परिणाम 3	परिव्यय 2011-12 4	मात्रात्मक लाभ/वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य) 5	टिप्पणी 6
					कार्य के लिए अनुमानों की मंजूरी। 500 KW SW Trs. के लिए ऑर्डर का प्लेसमेंट Q3- सिविल कार्यों की प्रगति Q4- अलीगढ़ और दिल्ली (किंग्जवे) में सिविल कार्य पर तथा उपकरण की डिलीवरी पूरी।	
	स्टूडियो					
8	98 स्टूडियो का डिजिटलीकरण और स्टूडियो की नेटवर्किंग			1. ग्यारह स्टूडियो का जीर्णोद्धार 2. AC प्लांट, DG सेट इत्यादि विविध उपकरणों की खरीद और संस्थापन 3. 48 स्टूडियो केंद्रों का डिजिटलीकरण पूरा	Q1- कोन इन कनसोल, पोर्टेबल डिजिटल रिकार्डर, डिजिटल वर्क स्टेशनों और डिजिटल कनसोल जैसे प्रमुख उपकरणों की डिलीवरी शुरू। विभागीय कार्य शुरू Q2- उपकरण की डिलीवरी जारी, विविध उपकरण का संस्थापन पूरा करना, 11 स्टूडियो का जीर्णोद्धार का संस्थापन कार्य शुरू करना Q3- उपकरण की डिलीवरी पूरी करना। 11 स्टूडियो के जीर्णोद्धार का संस्थापन और चालू करने का कार्य पूरा करना तथा विविध कार्य Q4- डिजिटल केबलिंग और 48 स्टूडियो का डिजिटलीकरण पूरा करना	फोन इन कनसोल, पोर्टेबल डिजिटल रिकार्डर, डिजिटल वर्क स्टेशनों, डिजिटल कनसोल और डिजिटल केबलिंग जैसे स्टूडियो उपकरणों के लिए एनआईटी जारी। फोन इन कनसोल और पोर्टेबल डिजिटल रिकार्डर का तकनीकी मूल्यांकन पूरा। जोनल कार्यालयों ने यूपीएस डीजी सेट एसी प्लांट इत्यादि की खरीद की कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी है।
				स्टूडियो नेटवर्किंग – केंद्रीकृत स्टोरेज और सिस्टम साफ्टवेयर के साथ सर्वर का SITC कार्य	Q1- उपकरण के लिए आर्डर का प्लेसमेंट Q2- उपकरण की प्राप्ति और संस्थापन शुरू Q3- उपकरण की प्राप्ति पूरी और संस्थागत	स्टूडियो नेटवर्किंग के लिए निविदाएं 21.10.2010 को खोली गईं। सर्वर के SITC कार्य के साथ केंद्रीकृत भंडार और सिस्टम साफ्टवेयर की निविदाओं की छंटनी की जा रही है।
9	दिल्ली में अभिलेखीय सुविधा बढ़ाना और चेन्नई, मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद में अभिलेखीय सुविधा का सृजन			उपकरण की खरीद और SITC (आपूर्ति, संस्थागत जांच और चालू) कार्य की प्रगति	Q1- निर्माण कार्य सौंपा गया। आंतरिक फाइनांस द्वारा खरीद प्रस्ताव की मंजूरी Q2- निर्माण कार्य प्रगति में। SITC कार्य के लिए मंजूरी और आर्डर Q3- निर्माण कार्य को पूरा करना और विभागीय और संस्थापन कार्य शुरू करना Q4- उपकरण की प्राप्ति और SITC कार्य शुरू	SITC कार्य के लिए निविदाएं 26.10.2010 को खोली गई तथा छंटनी की जा रही है।

क्र.सं. 1	योजना/कार्यक्रम का नाम 2	उद्देश्य/परिणाम 3	परिव्यय 2011-12 4	मात्रात्मक लाभ/वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य) 5	टिप्पणी 6
10	मौजूदा 44 न्यूज यूनिट का ऑटोमेशन और जोधपुर (राज.) राजकोट (गुजरात), विशाखापट्टनम (मध्यप्रदेश), दरभंगा (बिहार), सबलपुर (ओड़िशा), करगिल (जम्मू-कश्मीर) और पासीघाट (अरूणाचल) में 7 नई क्षेत्रीय न्यूज यूनिट बनाना			1. मौजूदा 44 क्षेत्रीय समाचार इकाइयों का डिजिटलीकरण पूरा	Q1- मौजूदा आरएनयू के लि सर्वर, वर्कस्टेशनों और सिस्ट सॉफ्टवेयर का कार्य शुरू Q2- SITC कार्य जारी करना Q3- SITC कार्य को पूरा करना	निविदाएं 28.10.2010 को खोली गई हैं तथा आरएनयू के लि सर्वर वर्कस्टेशनों और सिस्टम सॉफ्टवेयर के SITC कार्य के लिए निविदाओं का तकनीकी रूप से मूल्यांकन किया गया है। जोनल अधिकारियों ने V-SAT, ISON कनेक्टिविटी, UPS, TV सेट, रेडियो सेट, प्रिंटर, PDWA जैसे अन्य आइटम के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।
				2. सात नई क्षेत्रीय समाचार इकाईयों का डिजिटलीकरण पूरा	Q1- निर्माण कार्य शुरू Q2- निर्माण कार्य को पूरा करना और SITC कार्य शुरू Q3- SITC कार्य जारी Q4- SITC कार्य पूरा करना	
				3. 13 जगहों पर न्यूज ऑन फोन सेवा का उन्नयन तथा 16 नई जगहों (29) से यह सेवा शुरू	Q1- आंतरिक फाइनांस द्वारा खरीद प्रस्ताव की अनुमति Q2- खरीद प्रस्ताव की मंजूरी और उपकरण के लिए आर्डर प्लेसमेंट Q3- उपकरण की डिलीवरी और साइटों पर संस्थापन कार्य शुरू Q4- संस्थापन काम पूरा करना	उपकरण के लिए निर्धारण विचार का मुद्दा
11	SITL कनेक्टिविटी का विस्थापन			जगहों पर मौजूदा SITL का डिजिटाइलजेशन की खरीद और संस्थापन पूरा	Q1- साइटों पर उपकरण की प्राप्ति Q2- SITC (आपूर्ति, संस्थापन, परीक्षण और उपकरण को चालू करना) शुरू Q3- SITC कार्य को पूरा करना	मूल्य निविदाएं अभी तक नहीं खोली गई हैं क्योंकि एक वेंडर से पुन: प्रस्तुति के बारे में निर्णय के लिए पीबी सचिवालय की प्रतीक्षा है।
12	CES और SITL के नए प्रस्ताव			35 जगहों परग नए डिजिटल SITL और तिरूचिरापल्ली, मदुरई और धारवाड़ में कैप्टिव भू केंद्र का संस्थापन पूरा	Q1- साइटों पर उपकरण की प्राप्ति शुरू Q2- SITC कार्य आपूर्ति, संस्थापन, परीक्षण और उपकरण को चालू करना) शुरू Q3-SITC कार्य को पूरा करना	1. नए SITLs के लिए तकनीकी मूल्यांकन के अधीन निविदाएं 2. तिरूचिरापल्ली, मदुरई और धारवाड में नए कैप्टिव भू केंद्रों के लिए तकनीकी मूल्यांकन के अधीन निविदाएं
13.	C-बैंड RNT (44) का प्रावधान			SITC कार्य पूरा	Q1- SITC कार्य (आपूर्ति, संस्थापन परीक्षण और उपकरण को चालू करना) के लिए ऑर्डर प्लेसमेंट Q2- साइटों पर उपकरण की प्राप्ति शुरू	निविदाओं का तकनीकी रूप से मूल्यांकन किया गया और मूल्य बोली खोली गई

क्र.सं. 1	योजना/कार्यक्रम का नाम 2	उद्देश्य/परिणाम 3	परिव्यय 2011-12 4	मात्रात्मक लाभ/वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य) 5	टिप्पणी 6
					Q3-SITC कार्य (आपूर्ति, संस्थापन, परीक्षण और उपकरण को चालू करना) शुरू Q4- SITC कार्य को पूरा करना	
14.	DTH चैनल को बढ़ाना			उपकरण की खरीद DTH (18 जगह) उपलिंक/डाउनलिंक का संस्थापन पूरा	Q1- साइटों पर उपकरण की प्राप्ति शुरू 5 Q2- SITC कार्य (आपूर्ति, संस्थापन, परीक्षण और उपकरण को चालू करना) की शुरूआत Q3- SITC कार्य को पूरा करना	उपकरण के लिए निर्धारण विचारणीय मुद्दा
2.2	बाहरी सेवाओं को मजबूत करना	SW ट्रांसमीटरों का डिजिटलाइजेशन	0.50			
	कम्पेटीबल बाहरी सेवाओं SW Trs. को DRM (दिल्ली- 250 KW SW Trs.-2 और अलीगढ़ - 250 KW SW Trs.-2) में रूपांतरण			250 KW SW Trs के कनवर्जन के लिए उपकरण दिल्ली और अलीगढ़ में दो-दो DRM के लिए खरीदे और लगाए जाएंगे।	Q1- कनवर्जन किट्स के लिए खरीद का आर्डर Q2- उपकरण की प्राप्ति Q3- SITC कार्य पूरा होने की संभावना	PAC (प्रोप्राइटरी स्वीकृति प्रमाणपत्र) प्रस्ताव अनुमति के लिए मंत्रालय को भेजा गया। मंत्रालय द्वारा मांगे गए प्रमाणन का जवाब दिया जा रहा है।
2.3	तटीय क्षेत्र के लिए ई-गवर्नेंस, प्रशिक्षण, संसाधन, सुरक्षा, IOF, D/G, अतिरिक्त आवास, कल्याण गतिविधियां और स्टाफ क्वार्टर इत्यादि बुनियादी ढांचे में सुधार	बुनियादी ढांचे में सुधार	25.50			
1	ई-गवर्नेंस और आईटी सुविधाओं का उन्नयन			231 केंद्रों/कार्यालयों में अतिरिक्त 924 कम्प्यूटरों की खरीद	Q1- EFC अनुमोदन और निविदाओं की प्रोसेसिंग एवं तकनीकी मूल्यांकन Q2- वाणिज्यिक बोलियों को खोलना और खरीद प्रस्ताव की प्रोसेसिंग Q3- ऑर्डर प्लेसमेंट Q4- उपकरण की प्राप्ति और संस्थापन	पेबी सचिवालय द्वारा अनुमति के बाद टिप्पणी के लिए SFC प्रस्ताव प्रचारित
2	क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों सहित STI(T) और STI(T) को बढ़ाना					सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा 31.8.2010 को प्रस्ताव स्वीकृत

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2011–12	मात्रात्मक लाभ/वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	टिप्पणी
1	2	3	4		5	6
	(a) दिल्ली STI(T) ऑडिटोरियम/कानफ्रेंस हाल और स्वागत कक्ष का निर्माण			ऑडिटोरियम/कान्फ्रेंस हाल और स्वागत कक्ष का निर्माण कार्य पूरा	Q1– निर्माण कार्य सौंपना Q2– & 03– निर्माण कार्य जारी करना Q4– भवन पूरा करना	निर्माण कार्य के लिए अनुमान प्रस्तुत करने के अधीन
	STI(P), तिरूवनंतपुरम में होस्टल आवास का निर्माण			होस्टल आवास का निर्माण कार्य पूरा	Q1– निर्माण कार्य सौंपना Q2 & Q3– निर्माण कार्य जारी करना Q4– भवन पूरा करना	निर्माण कार्य के लिए अनुमान प्रस्तुत करनेके अधीन
	STI(P), हैदराबाद में होस्टल आवास का निर्माण				Q1– निर्माण कार्य सौंपना Q2 & Q3– निर्माण कार्य जारी करना Q4– भवन पूरा करना	निर्माण कार्य के लिए अनुमान प्रस्तुत करने के अधीन
	STI(P), लखनऊ में होस्टल आवास का निर्माण				Q1– निर्माण कार्य सौंपना Q2 & Q3– निर्माण कार्य जारी करना Q4– भवन पूरा करना	निर्माण कार्य के लिए अनुमान प्रस्तुत करनेके अधीन
	STI(P),अहमदाबाद में होस्टल आवास का निर्माण				Q1– निर्माण कार्य सौंपना Q2 & Q3– निर्माण कार्य जारी करना Q4– भवन पूरा करना	निर्माण कार्य के लिए अनुमान प्रस्तुत करने के अधीन

क्र.सं. 1	योजना/कार्यक्रम का नाम 2	उद्देश्य/परिणाम 3	परिव्यय 2011-12 4	मात्रात्मक लाभ/वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य) 5	टिप्पणी 6
	RTI(T) मलाड, मुंबई में होस्टल और प्रशिक्षण सुविधाएं			होस्टल, लेक्चर हाल और कम्प्यूटर लैब कार्यालय कक्ष इत्यादि का निर्माण	Q1- निर्माण कार्य सौंपना Q2 & Q3- निर्माण कार्य जारी करना Q4- भवन पूरा करना	निर्माण कार्य के लिए अनुमान प्रस्तुत करने के अधीन है। उपकरण के लिए खरीद कार्रवाई शुरू
	दिल्ली STI(T)- एनलॉग आडियो स्टूडियो को डिजिटल रूप में बदलना			उपकरण की खरीद और संस्थापन	Q1- वाणिज्यिक बोलियां खोलना और खरीद प्रस्ताव की प्रोसेसिंग Q2- आर्डर प्लेसमेंट Q3- उपकरण की प्राप्ति और संस्थापन Q4- संस्थापन को पूरा करना	उपकरण की खरीद के लिए खरीद की कार्रवाई शुरू की गई। डिजिटल वर्क स्टेशनों, डिजिटल कनसोल जैसे उपकरण की खरीदकी प्रक्रिया समग्र प्रस्ताव के भाग के रूप में पहले ही प्रक्रियाधीन है।
3	मौजूदा केंद्रों में I.O.F.					मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार पीबी बोर्ड के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव भेजे गए
	आपातकालीन हालात के लिए 5 जोनल कार्यालयों में 5 मोबाइल FM Trs.			उपकरण की खरीद	Q1- EFC अनुमोदन और उपकरण के लिए निविदा मंगाना। Q2- निविदा की प्रोसेसिंग और तकनीकी मूल्यांकन, Q3- वाणिज्यिक बोलियों को खोलना और खरीद प्रस्ताव की प्रोसेसिंग, Q4- आर्डर प्लेसमेंट	
	स्टूडियो के लिए मापन उपकरण का प्रावधान			उपकरण की खरीद	वही	
	23 स्थानों पर रिमोट कंट्रोल के लिए MW Trs. पर टेलीमीटरों का प्रावधान				वही	
	80 स्थानों पर मौजूदा एफएम केंद्रों पर यूपीएस का प्रावधान				वही	
	ग्वालियर, रत्नागिरी और सांगली में स्टूडियो को नया रूप देना				वही	
	श्रीनगर में होस्टल, आवास, सहित, गुवाहाटी में कार्यालय आवास और स्टाफ क्वार्टर			गुवाहाटी में पूर्वोत्तर जोन के लिए कार्यालय, आवास/स्टाफ क्वार्टर और श्रीनगर में होस्टल सुविधाओं का निर्माण	Q1- अनुमानों की मंजूरी ओर पूर्वोत्तर जोन कार्यालय के लिए निविदाएं आमंत्रित करना। गुवाहाटी में स्टाफ क्वार्टर और श्रीनगर में होस्टल के लिए निर्माण कार्य सौंपना Q2- पूर्वोत्तर जोन कार्यालय के लिए निविदाओं की प्रोसेसिंग और निर्माण कार्य सौंपना। स्टाफ	

क्र.सं. 1	योजना/कार्यक्रम का नाम 2	उद्देश्य/परिणाम 3	परिव्यय 2011-12 4	मात्रात्मक लाभ/वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य) 5	टिप्पणी 6
					क्वार्टर के लिए प्रक्रिया जारी Q3- निर्माण कार्य जारी Q4- स्टाफ क्वार्टर का निर्माण कार्य पूरा करना। कार्यालय आवास का निर्माण का कार्य जारी होने की उम्मीद	
2.4	नई प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी (अनुसंधान एवं विकास)	सेटेलाइट और टेरोट्रीयल मोड में मल्टी मीडिया प्रसारण, वेब कास्टिंग/ब्राडकास्टिंग	1.00			
	नई प्रौद्योगिकी					
1	वेबकास्टिंग	ब्राडकास्टिंग		संस्थापन का काम पूरा और कार्यक्रम की विषय सामग्री विकसित की जा रही है।	कार्यक्रम की विषय सामग्री का विकास	
2	अनुसंधान एवं विकास			स्कीमों को पूरा करना	Q1- 26 MHz AM DRM Tr. क्रास फील्ड एंटीना और 1 KW MW DRM Tr., जैसे उपकरणों के लिए निविदाओं का तकनीकी मूल्यांकन को पूरा करना Q2- वाणिज्यिक बोलियों को खोलना, खरीद प्रस्ताव को प्रोसेस करना Q3- आर्डर देना Q4- उपकरण की प्राप्ति	Issued for 26 MHz AM DRM Tr., क्रास फील्ड एंटीना और 1 KW MW DRM Trs. के लिए NIT जारी की गई, निविदा खोली गई और छंटनी की जा रही है।
2.5	साफ्टवेयर	(i) सामान्य श्रेणी, जम्मू-कश्मीर विशेष पैकेज और पूर्वोत्तर विशेष पैकेज के संबंध में इन हाउस और कमीशन्ड कार्यक्रमों का निर्माण, (ii) किसान वाणी, (iii) CD की खरीद, (iv) विविध कनसर्ट/रेडियो कार्यशालाएं/आकाशवाणी, संगीत सम्मेलन इत्यादि (v) महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय आयोजनों का निर्माण और कवरेज (vi) आकाशवाणी अभिलेखागार नेटवर्क का डिजिटाइलेजेशन (vii) समाचार गतिविधियां	15.00	1. नई और ताजगी भरी विषय सामग्री बनाना 2. रेडियो कार्यशालाएं, संगीत सम्मेलन, कनसर्ट आदि 3. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का कवरेज 4. फ्लैगशिप कार्यक्रम निर्माण 5. आकाशवाणी अभिलेखागार का डिजिटलीकरण 6. सूचना और प्रसारण मंत्रालय EFC प्रस्ताव के लिए पहले ही स्वीकृति दे चुका है लेकिन वर्ष 2011-12 के लिए बजट आगे प्राप्त होना है।	साफ्टवेयर प्रोडक्शन/अधिग्रहण और विषय सामग्रह निर्माण के लिए फ्लैगशिप कार्यक्रमों अभिलेखागार का डिजिटलीकरण इत्यादि के लिए कोष का उपयोग करना। अनुमति की तिथि से निर्धारित समय के भीतर काम पूरा करने के प्रयास किए जाएंगे।	

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2011-12	मात्रात्मक लाभ/वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	टिप्पणी
1	2	3	4		5	6
2.6	जम्मू-कश्मीर फेज-III	जम्मू-कश्मीर में सीमा क्षेत्र के एफएम कवरेज के और सुधार के लिए	10.00	एफएम और टीवी एचपीटी की स्थापना करने के लिए 3 नई साइट का अधिग्रहण, निर्माण कार्य पूरा करना, उपकरण की खरीद और 100 W FM के चार ट्रांसमीटर नौशेरा में 10 KW FM ट्रांसमीटरों और राजौरी में 5 KW TV के 2 ट्रांसमीटरों की संस्थापन गतिविधियां को पूरा करना	Q1- तीन नई साइट की पहचान और अनुमान की स्वीकृति तथा लोक निर्माण कार्य सौंपा गया। वाणिज्यिक बोलियां खोलना तथा उपकरण के लिए खरीद प्रस्ताव को प्रोसेस करना Q2- आर्डर देना और निर्माण कार्य को पूरा करना Q3- उपकरण की प्राप्ति Q4- संस्थापन को पूरा करना	1. सरकार की अनुमति 18.08.2010 को प्राप्त हुई। 2. नाथाटोप (जम्मू क्षेत्र) तीन रिज (श्रीनगर क्षेत्र), और हिम्बोटिगला (लद्दाख क्षेत्र) में 3 नई साइट की पहचान और अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू
	आकाशवाणी का योग		260.37			
		राजस्व	17.00			
		पूंजी	243.37			

दूरदर्शन

परिव्यय तथा परिणाम/लक्ष्यों का वक्तव्य (2011-12)

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	स्वीकृत परिव्यय (2011-12)	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)		टिप्पणी/ जोखिम घटक
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.
	चालू स्कीम						
1.	जम्मू-कश्मीर विशेष योजना चरण-I तथा II (पूंजी)	जम्मू-कश्मीर में दूरदर्शन कवरेज प्रसारण में सुधार। अमृतसर में टावर निर्माण के अतिरिक्त जम्मू-कश्मीर विशेष पैकेज का पहला चरण कार्यान्वित हो गया है, टावर निर्माण का कार्य प्रगति पर है। इसके परिणामस्वरूप जम्मू-कश्मीर में दूरदर्शन प्रसारण की गुणवत्ता तथा कवरेज एरिया में सुधार होगा। योजना के द्वितीय चरण में कंटेंट के सुधार पर जोर दिया गया है।	2.20	अमृतसर में 300 एमटीआर टावर अमृतसर में 300 मीटर ऊंचे टावर पर लगे एंटिना से डीडी-1 तथा डीडी-न्यूज एचपीटी का आरंभ	सीमापारीय क्षेत्रों में टीवी कवरेज में वृद्धि सीमापारीय क्षेत्रों में डीडी-1 तथा डीडी-न्यूज चैनल उपलब्ध कराना	नई साइट पर डीडी-1 और डीडी (न्यूज) ट्रांसमीटर का संस्थापन और उन्हें चालू करना-तीसरी तिमाही	- शून्य -
	राजस्व	डीडी कशीर चैनल के लिए कार्यक्रमों का निर्माण/अधिग्रहण/कमीशनिंग और डीडीके श्रीनगर, जम्मू व लेह के लिए क्षेत्रीय सेवा	53.89	8000 एपीसोड का कार्यक्रम	डीडीके श्रीनगर, जम्मू और लेह की डीडी कशीर/क्षेत्रीय सेवा के लिए नए और बेहतर सॉफ्टवेयर	वार्षिक आवंटन के अनुसार	वर्तमान वित वर्ष का 70 रुपये का दायितव आगे ले जाया गया
2.	निर्माण सुविधाओं (स्टूडियो/ओबी) का आधुनिकीकरण तथा डिजिटलीकरण	कार्यक्रमों की तकनीकी गुणवता बढ़ाना	3.00	स्टूडियो केंद्र, केंद्रीकृत रिकार्डिंग, संपादन तथा प्लेबैक का सभी 17 मुख्य दूरदर्शन केंद्रों में आधुनिकीकरण। ओ बी सुविधाओं का विस्तार तथा तीव्र न्यूज डिलीवरी प्रणाली	स्टूडियो का डिजिटलीकरण	कार्य चालू है	

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2011-12	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी
3.	पूर्वोत्तर विशेष पैकेज चरण-II (पूंजी)	पूर्वोत्तर तथा अंडमान-निकोबार क्षेत्र में दूरदर्शन कवरेज का सुदृढ़िकरण। पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप के द्वीपीय इलाकों में दूरदर्शन सेवाओं के विस्तार तथा सुधार के लिए सरकार ने एक विशेष पैकेज (द्वितीय चरण) को मंजूरी दी।	1.91	पूर्वोतर के लिए डीएसएनजी की चार यूनिट और अंडमान निकोबार के लिए एक यूनिट	पूर्वोतर और अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में समाचार एकत्र करने की सुविधा बढाना	डीएसएनजी की एक यूनिट की आपूर्ति	डीजीएनजी की तीन यूनिट की आपूर्ति की गई
	राजस्व	डीडी नार्थ ईस्ट के सैटेलाइट चैनल के लिए प्रोडकशन और सॉफटवेयर को चालू करना और उत्तर पूर्व के 11 क्षेत्रीय केन्द्रों के लिए कार्यक्रमों का निर्माण अधिग्रहण कमीशनिंग	20.00	6880 एपीसोड के इनहाउस और कमिशनड कार्यक्रम	उत्तर पूर्व में डीडी चैनलों और 11 क्षेत्रीय केन्द्रों के लिए नए और गुणवत्तावान कार्यक्रम		
4.	डीटीएच	इस योजना का उद्देश्य शेष बचे क्षेत्रों में टीवी कवरेज उपलब्ध कराना है।	0.00				डीटीएच सेवा शुरू हो चुकी है
5.	एचडीटीवी	यह वह तकनीक है जो उत्कृष्ट पिक्चर तथा वाइड स्क्रीन इमेज के कार्यों में अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराती है। इस तकनीक से 35 मी.मी. फिल्म जैसी पिक्चर क्वालिटी मिलती है। यह तकनीक डिजिटल सराउंडिंग साउंड भी उपलब्ध कराती है। एचडीटीवी फिल्ड प्रोडक्शन के लिए प्रायोगिक परियोजना का कार्य चालू है।	0.40	एचडीटीवी प्रोडक्शन के लिए पायलट परियोजना चालू करना ।	प्रायोगिक योजना एचडीटीवी फार्मेट में निर्माण के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराएगी।		फील्ड निर्माण वैन खरीद ली गई है
6.	**दसवीं योजना की अन्य अनुमोदित योजना**		25.00				

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2011-12	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6		7
क	स्टाफ के लिए आवास, बुनियादी ढांचे तथा सुरक्षा में वृद्धि।	स्टाफ के लिए आवास सुविधा का प्रावधान। बुनियादी ढांचे में वृद्धि/ विभिन्न स्टेशनों पर सुरक्षा को मजबूत करना।		4 मेट्रो शहरों में स्टाफ के लिए आवासों का निर्माण। 11 गैर मेट्रो शहरों में स्टाफ के लिए आवासों का निर्माण।		कार्य प्रगति पर है। पटना और संबलपुर में स्टॉफ कवार्टर का निर्माण पूरा- पहली तिमाही	पटना में स्टॉफ कवार्टर की संशोधित योजना अनुमान की स्वीकृति ली जानी है
ख	**अन्य योजनाएं** i) ट्रांस्सीटर से संबंधित योजनाएं	स्थलीय कवरेज में सुधार		आटोमोड एलपीटी 50	स्थलीय प्रसारण तथा कवरेज क्षेत्र की गुणवत्ता में सुधार।	पहली तिमाही में ट्रांस्मीटर उपकरण के लिए आड्रर दिया। चौथी तिमाही में पचास स्थानों पर आटोमोड एलपीटी 50 का संस्थापन और चालू करना	महबूबनगर के लिए ट्रांसमीटर उपकरण की खरीद के लिए आमंलित निविदांए प्राप्त हो गई है और प्रक्रियाधीन है। टॉवर खड़ा करने के लिए आड्रर दे दिया गया है।
				एचपीटी-2	स्थलीय प्रसारण तथा कवरेज क्षेत्र की गुणवत्ता में सुधार।	तीसरी तिमाही में महबूबनगर में एचपीटी के लिए उपकरण की आपूर्ति और चालू करना चौथी तिमाही में टावर का निर्माण तथा एंटिना लगाना और फीडर केबल चढ़ाना चौथी तिमाही में एचपीटी का परीक्षण और चालू करना।	
	कुल स्कीमें शामिल		**106.40**				

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2011-12	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)		टिप्पणी/
1	2	3	4	5	6		7
	नई योजना						
1	ट्रांसमीटर का डिजीटलीकरण, आधुनिकीकरण, ट्रांसमीटर उपकरणों की वृद्धि तथा नये उपकरण लगाना।		20.00				
	(क) ट्रांसमीटर का डिजिटलीकरण	स्थलीय ट्रांसमिशन का डिजिटलीकरण	-	डिजिटल एचपीटी-19	स्थलीय ट्रांसमिशन के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया शुरू।	पहली तिमाही में 19 डिजिटल एचपीटी के लिए आर्डर दिया गया। तीसरी तिमाही में 19 डिजिटल एचपीटी की आपूर्ति। चौथी तिमाही में 19 डिजिटल एचपीटी का चरणों में संस्थापन। चौथी तिमाही में टॉवरों को मजबूत बनाने सहित एंटिना प्रणाली की आपूर्ति और संस्थापन। चौथी तिमाही मे 19 डिजिटल एचपीटी का परीक्षण और चालू करना	अप्रैल 2010 में योजना को स्वीकृति

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2011-12	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)		टिप्पणी/
1	2	3	4	5	6		7
	(ख) ट्रांसमीटर उपकरणों का आधुनिकीकरण, वृद्धि तथा दूसरे उपकरण लगाना।	ट्रांसमीटर उपकरणों का आधुनिकीकरण, वृद्धि तथा तकनीक पुरानी हो जाने और उपकरण के पुराने पड़ जाने के कारण नये उपकरण लगाना।	-	15 एचपीटी तथा 60 एलपीटी के स्थान पर आटोमोड एलपीटी लगाना।	स्थलीय ट्रांसमिशन की गुणवत्ता तथा कवरेज में सुधार।	कार्य प्रगति पर है।	योजना को अभी स्वीकृति मिलनी है।
2.	**स्टूडियो डिजीटलीकरण : आधुनिकीकरण, वृद्धि, स्टूडियो/ ओबी उपकरणों का प्रतिस्थापन**		80.00				
	(क) स्टूडियो का डिजीटलीकरण	निर्माण, पोस्ट प्रोडक्शन, संपादन तथा अभिलेख सुविधाओं का पूर्ण डिजीटलीकरण।	-	छोटे केंद्रों के 31 स्टूडियो तथा आठ एनॉलाग स्टूडियो का पूर्ण डिजिटलीकरण।	उत्पादन सुविधाओं का पूर्ण डिजिटलीकरण।	तीसरी तिमाही में- 31 आंशिक डिजिटल स्टूडियो का पूर्ण डिजिटलीकरण, आठ एनॉलाग स्टूडियों के लिए आर्डर दिया गया। चौथी तिमाही में- आठ एनॉलाग स्टूडियों के डिजिटलीकरण के लिए उपकरण की आपूर्ति, आठ एनॉलाग स्टूडियो का पूर्ण डिजिटलीकरण	योजना को अप्रैल 2010 में स्वीकृति दी गई।

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2011-12	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ (तिमाही लक्ष्य)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6		7
	(ख) डिजिटलीकरण, वृद्धि तथा स्टूडियो उपकरणों का प्रतिस्थापन	निर्माण संबंधी उपकरणों का आधुनिकीकरण, वृद्धि तथा प्रतिस्थापन और इसके साथ डिजिटल काउंटर पार्ट को भी तकनीकी रूप से उपयुक्त पाया गया है।	–	सभी छोटे तथा 66 बड़े केंद्रों पर निर्माण, पोस्ट प्रोडेक्शन, आडियो, लाइटिंग तथा विद्युत आपूर्ति में वृद्धि।	तकनीकी गुणवत्ता में वृद्धि।	कार्य प्रगति पर है।	योजना को अनुमति मिलनी है।
	डीटीएच : आधुनिकीकरण, वृद्धि, उपग्रह प्रसारण उपकरणों का प्रतिस्थापन		**20.00**				
	(क) डीटीएच	हाइब्रिड मॉडल के साथ डीटीएच पर चैनलों की संख्या 50 से बढ़ाकर 198 करना (फ्री-टू-एयर चैनल तथा पेड चैनल)		डीटीएच प्लेटफॉर्म का उन्नयन		तीसरी तिमाही में आर्डर दिया गया। चौथी तिमाही में वर्तमान 59 चैनल से बढ़ाकर 97 चैनल करने के लिए डीटीएच पलेटफार्म के उन्नयन के लिए उपकरण की आपूर्ति।	योजना को अगस्त 2010 में मंजूरी मिली।

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2010-11	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6		7
	(ख) उपग्रह प्रसारण उपकरणों का डिजिटलीकरण, वृद्धि तथा प्रतिस्थापन	पुराने हो चुके उपग्रह उपकरणों का आधुनिकीकरण, वृद्धि तथा नये डिजिटल उपकरणों द्वारा प्रतिस्थापन, समाचार जुटाने की सुविधा में वृद्धि।		10 अर्थ स्टेशन का उन्नयन	चरणबद्ध ढंग से काम किया जाएगा।	तीसरी तिमाही में 5 अर्थस्टेशन के लिए आर्ड दिया गया चौथी तिमाही में 5 अर्थ स्टेशनों का उन्नयन। दूसरी तिमाही में आर्डर दिया गया चौथी तिमाही में 5 स्थानों पर अर्थ स्टेशन कंप्रेशन उपकरण का प्रतिस्थापन।	6 डीएसएनजी के टेंडर मंगाए गए पीडीए के टेंडर मिले और उनकी जांच जारी।
				5 स्थानों पर अर्थ स्टेशन कंप्रेशन उपकरण का प्रतिस्थापन।			
				6 स्थानों पर डीएसएनजी यूनिट का प्रतिस्थापन।		पहली तिमाही में डीएसएनजी (6) की आपूर्ति।	
				मौजूदा आईआरडी के स्थान पर डीवीबी-एस 2 आधारित आईआरडी लगाना		आईआरडी की खरीद के लिए आर्डर दिया गया। (तीसरी तिमाही) चौथी तिमाही में उपकरण की आपूर्ति	
				सीपीसी और डीडीके ओीनगर में अंपलिंक पीडीए और एसेसरीज का रिप्लेसमेंट।		सीपीसी और डीडीके ओीनगर में पीडीए रिप्लेसमेंट का काम पूरा। (दूसरी तिमाही)	

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2011-12	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6		7
				नए डीएसएनजी (9) नए अर्थ स्टेशन (5)		तीसरी तिमाही में 9 डीएसएनजी के लिए आर्डर दिया गया। चौथी तिमाही में 9 डीएसएनजी की आपूर्ति। दूसरी तिमाही में चार अर्थ स्टेशन का आर्डर दिया गया। चौथी तिमाही में चार स्थानों पर अर्थ स्टेशन की आपूर्ति, संस्थापन और चालू करना	
4.	**एचडीटीवी**	एचडीटीवी प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन तथा प्रसारण सुविधा	**29.00**	दिल्ली, मुंबई में एचडीटीवी प्रोडक्शन सुविधा	एचडी फारमेट में प्रोडक्शन अपलिंकिंग और क्षेत्रीय प्रसारण	दूसरी तिमाही में एचडीटीवी के एसआईटीसी के लिए आर्डर दिया गया, तीसरी तिमाही में उपकरण की आपूर्ति और चौथी तिमाही में संस्थापन और चालू करना।	

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2011-12	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6		7
				दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के लिए पोस्ट प्रोडक्शन सुविधा		तीसरी त्रिमाही में उपकरण की आपूर्ति और संस्थापन। चौथी तिमाही में चार स्थानों पर पोस्ट प्रोडकशन सुविधाएं चालू करना।	
				दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता और चेन्नई के लिए फील्ड प्रोडक्शन सुविधा		तीसरी त्रिमाही में उपकरण की आपूर्ति और संस्थापन। चौथी तिमाही में चार स्थानों पर पोस्ट प्रोडकशन सुविधाएं चालू करना।	
				दिल्ली, मुम्बई में आउटडोर प्रोडक्शन सुविधा के लिए मल्टी कैमरा मोबाइल उपकरण		चौथी तिमाही में एचडीटीवी वैन की आपूर्ति	
				दिल्ली में फ्लाई अवे प्रोडक्शन सेट अप		चौथी तिमाही में उपकरणों के लिए ऑर्डर दिया	

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2010-11	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6		7
				दिल्ली, मुम्बई कोलकाता, चेन्नई के लिए प्रिव्यू सुविधा		पहली तिमाही में उपकरणों की आपूर्ति और संस्थापन। दूसरी तिमाही में चार स्थानों पर पोस्ट प्रोडकशन सुविधाएं चालू करना	निविदाएं आमंत्रित की गई।
				दिल्ली, मुम्बई कोलकाता, चेन्नई में एचडीटीवी ट्रांसमीटर दिल्ली में एचडीटीवी अपलिंक सुविधा और उसे डीटीएच प्लेटफार्म पर डालना		तीसरी तिमाही में ट्रांसमीटर की आपूर्ति। तीसरी तिमाही में एंटिना सिस्टम की आपूर्ति और संस्थापन। चौथी तिमाही में ट्रांसमीटरों का स्थापन , परीक्षण और चालू करना।	चार एचडीटीवी ट्रांसमीटरों और एंटिना सिस्टम की एसआईटीसी की खरीद तथा टॉवर को मजबूत बनाने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई।
5.	**स्टॉफ के लिए आवास और अन्य विविध योजना**	स्टाफ के लिए आवास सुविधा का प्रावधान विभिन्न स्टेशनों पर बुनियादी ढांचे में वृद्धि और सुरक्षा व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण	**15.00**	7 स्थानों पर स्टाफ क्वार्टर 22 स्थानों पर गेस्टहाउस 10 स्थानों पर कम्यूनिटी सेंटर, 17 स्थानों पर डीएमसी भवन 10 स्थानों पर एलपीटी भवन डीडी भवन, काम्प्लैक्स में टावर सी।	स्टाफ क्वार्टर, गेस्टहाउस, कम्यूनिटी सेंटर, डीएमसी भवन, एलपीटी भवन, जोनल ऑफिस के भवन, टावर सी भवन का निर्माण	9 एलपीटी भवन और 7 डीएमसी भवन, 10 गेस्टहाउस, चार स्टॉफ कवार्टर का काम पूरा।	

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2011-12	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम घटक
1	2	3	4	5	6		7
6	**सॉफटवेयर अधिग्रहण और प्रोडकशन (राजस्व)**	दूरदर्शन के विभिन्न चैनलों और केंद्रों के लिए सॉफटवेयर कार्यक्रमों का निर्माण।	1.00	4000 एपीसोड 50 हजार प्रति कार्यक्रम के हिसाब से तथा 1700 कार्यक्रम 3 लाख रु. प्रति कार्यक्रम के हिसाब से कुल 71 करोड़ रु.	विभिन्न डीडी चैनलों पर नए व गुणवत्तावान कार्यक्रम		
		कुल नई योजना	165.00				
		दूरदर्शन का योग	271.40	531.77			
		राजस्व	74.89				
		पूंजी	196.51				

अध्याय-3

सुधार, उपाय तथा नीतिगत पहल

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

जहां तक पारदर्शिता का संबंध है, सांगठनिक ढांचा, फिल्म प्रमाणन दिशा-निर्देश, प्रवर्तन विवरण, प्रमाणन प्रक्रिया संबंधी सभी सूचनाएं वेबसाइट पर डाली गई हैं। आरटीआई एक्ट-2005 के अंतर्गत पीआईओ/एपीआईओ और सभी कर्मचारियों की सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई हैं। नागरिक घोषणा पत्र, पूछताछ, शिकायतें तथा जन विचारों को वेबसाइट पर डाला गया है ताकि सीबीएफसी की फिल्म प्रमाणन प्रक्रिया संबंधी अथवा किसी भी व्यक्तिगत शिकायतों पर आम जनता प्रश्न पूछ सके।

बाल फिल्म समिति, भारत

सीएफएसआई के पूर्व अध्यक्ष ने फिल्म सिटी में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से भूमि आवंटित करने के लिए अनुरोध किया। महाराष्ट्र फिल्म, स्टेज तथा सांस्कृतिक विकास निगम लिमिटेड ने फिल्म सिटी, गोरेगांव में 1600 व.मी. जगह का प्रस्ताव दिया है। सीएफएसआई अब वित्तीय जरुरतों के साथ महाराष्ट्र सरकार के अनुमोदन का इंतजार कर रही है।

सीएफएसआई का उद्देश्य यहां एक राष्ट्रीय महत्व के आधुनिक बाल फिल्म परिसर का निर्माण करना है, जिसमें फिल्म निर्माण के सभी पहलुओं सहित एक एनीमेशन तथा कठपुतली स्टूडियो का निर्माण शामिल है। इसका उद्देश्य अच्छी फिल्मों का निर्माण करना है। इस परिसर में बाल फिल्म अभिलेखागार स्थापित करने की भी योजना है।

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय

निदेशालय अपने कार्मिकों की संख्या को उचित स्तर पर लाकर स्वयं को नया स्वरूप दे रहा है ताकि इसकी कार्यक्षमता में सुधार हो। निदेशालय का मुख्य जोर जनजातीय, सीमावर्ती क्षेत्र, दूरदराज तथा पिछड़े क्षेत्रों में गतिविधियां बढ़ाने पर है जो अन्य मीडिया की पहुंच से बाहर है। पारदर्शिता के मद्दे नजर निदेशालय अपने बेवसाइट को समय-समय पर अद्यतन करते रहता है।

विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय

सुधार उपाय तथा नीतिगत पहलें

पारदर्शिता, सशक्तिकरण, विकंद्रीकरण तथा सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ाने के लिए डीएवीपी के सुधार तथा नीतिगत पहलें इस प्रकार हैं :

मीडिया-लिस्ट सॉफ्टवेयर का सृजन : विज्ञापनों को क्रमबद्ध तरीके से जारी करने के लिए डीएवीपी ने स्वंय एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया है जो विज्ञापनों को प्रसार, कीमत, शामिल विज्ञापनों की संख्या जैसे विविध आधारों पर विज्ञापन आवंटित करेगा।

इलेक्ट्रानिक तरीके से भुगतान जारी करना : डीएवीपी ने नेशनल इलेक्ट्रानिक फाइल ट्रांसफर सिस्टम के जरिये भुगतान जारी करना शुरु किया है। डीएवीपी की वेबसाइट www.davp.nic.in पर बिलों की स्थिति देखी जा सकती है।

समाचार पत्रों नया पैनल तथा दर समीक्षा : प्रसार के साथ ही समाचार पत्रों को बेहतर पारिश्रमिक देने के लिए दरों की समीक्षा की गई और चालू वित्तीय वर्ष में नया पैनल तैयार किया जाएगा।

दृश्य-श्रव्य विंग के लिए एंपैनलमेंट एडवायजरी समिति का गठन : एक समान फार्मूला पर आधारित टीवी और रेडियो चैनलों के लिए नई दरें सुधारने के लिए एक समिति बनाई गई है।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी : एक और क्षेत्र जिसमें एक प्रमुख पहल की गई वह है सृजनात्मकता, चाहे मुद्रित या दृश्य-श्रव्य माध्यम में हो। डीएवीपी ने अपने ग्राहक मंत्रालयों के लिए सृजनात्मक डिजाइन करने के लिए रिकार्ड संख्या में निजी विज्ञापन एजेंसियों का पैनल बनाया है। मल्टीमीडिया अभियानों के लिए क वर्ग में 5 एजेंसियां, ख वर्ग में 1 तथा ग वर्ग में 22 एजेंसियों का पैनल तैयार किया है। प्रोग्रामरों, डाटा एंट्री आपरेटरों की आउट सोर्सिंग की गई।

रिकार्ड वितरण वाला कैलेंडर : जैव विविधता परीक्षण थीम वाले डीएवीपी के कैलेंडर 2011 को दिसंबर में जारी किया गया। पहली बार 12 लाख प्रतियां छापी गई। जि९हें पंचायतों, शैक्षिक संस्थाओं तथा सार्वजनिक क्षेत्रों को बांटा गया।

प्रधानमंत्री के भाषण की पुस्तिका की नई डिजाइन : विभिन्न विषयों को अलग-अलग रंग देने है साथ ही प्रधानमंत्री के भाषणों के लिए एक नया टेम्पलेट अपनाया गया।

फिल्म समारोह निदेशालय

भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, 2011 का आयोजन तथा 2010 के लिए 58वें राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करना।

डीएफएफ वर्ष भर भारत में भारतीय पेनोरमा फिल्मों के प्रदर्शन तथा विश्व भर में फिल्म महोत्सवों में भागीदारी जैसी अपनी नियमित गतिविधियां चलाता रहेगा।

फिल्म प्रभाग

सुधार, उपाय तथा नीतिगत पहल

बाहरी निर्माताओं/एनजीओ से डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनवाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि फिल्म सामाजिक मुद्दों पर हों तथा उनमें समाधान भी हो ताकि राष्ट्र निर्माण में ऐसी फिल्मों की महती भूमिका हो। सरकार का ऐसा प्रयास होता है।

फिल्म प्रभाग, मुंबई में नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया सिनेमा स्थापित करने का भी फैसला किया गया है जो भारतीय सिनेमा के इतिहास को दर्शाएगा। ऑडियो-विजुअल प्रस्तुति तथा अन्य तौर-तरीके अपना कर फिल्मों को संग्रहीत किया जाएगा। इससे फिल्म निर्माताओं, निर्देशकों, संस्थाओं, फिल्म छात्रों तथा अन्य लोगों में फिल्मों के प्रति उत्साह बढ़ेगा। नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया सिनेमा फिल्मों का संग्रह भर नहीं होगा बल्कि यह फिल्म निर्माताओं, फिल्म छात्रों को फिल्म विकास के विविध आयामों की जानकारी देगा। विश्व भर के लोगों के लिए यह जानकारी का यह अच्छा केंद्र होगा।

भारत और विदेशों में फिल्म बाजारों में भागीदारी

फिल्म क्षेत्र हालांकि ज्यादातर निजी क्षेत्र के अंतर्गत आता है परंतु यह भारत में एक सशक्त सांस्कृतिक उद्योग है। भारत संख्या की दृष्टि से विश्व में सबसे अधिक फिल्में बनाने वाले देशों में पहला स्थान रखता है किंतु राजस्व हासिल करने की दृष्टि से विश्व बाजार में भारतीय फिल्मों की भागीदारी नगण्य है। फिल्म उद्योग के अंर्तगत फिल्म निर्माण के सभी क्षेत्रों – यानी फिल्म निर्माण, वितरण, प्रदर्शन और विपणन में प्रौद्योगिकी की प्रगति की अहम भूमिका रही है।

विश्व बाजार में भारतीय फिल्मों की मौजूदगी को प्रोत्साहित करने और उसे बढ़ा देने के उद्देश्य से भारत प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों/बाजारों में हिस्सा लेता रहा है। भारतीय सिनेमा को विभिन्न बाजारों में बढ़ावा देने के उद्देश्य से वार्षिक योजना तैयार करेक इसका कार्यान्वयव सुनिश्चित करने की दृष्टि से वित्त वर्ष 2011-12 से एनएफडी सी को भारत तथा विदेशों में अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म बाजारों में हिस्सेदारी के कार्य की जिम्मेदारी सौंपने का निश्चय किया गया है। भारत में अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह की तर्ज पर फिल्म बाजार अन्य जैसे फिल्म समारोहों की जिम्मेदारी एनएफडीसी अथवा अनय उद्योग निकायों को दी गई है।

भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे

फिल्म निर्माण की कला और तकनीक में प्रशिक्षण प्रदान करने वाला प्रमुख संस्थान होने के नाते भारत सरकार की नीति इसके अस्तित्व, प्रशिक्षण सुविधाओं और प्रशिक्षण माहौल के उन्नयन के लिए अनुदान सहायता के जरिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। तदनुसार, भारत सरकार द्वारा योजना और गैर-योजना स्कीमों के तहत अनुदान सहायता जारी की जा रही है। पुराने उपकरणों को बदलने तथा प्रशिक्षण सुविधाओं के उन्नयन के एकमात्र उद्देश्य के लिए खर्च किया जा रहा है।

मशीनरी और उपकरणों की खरीद अत्यधिक पारदर्शी ढंग से खुली निविदाओं के आमंत्रण तथा वेबसाइट एवं मुद्रित मीडिया पर व्यापक प्रचार के जरिए की जाती है। निर्माण और इलैक्ट्रिकल कार्य मंत्रालय के निर्माण एवं इलैक्ट्रिकल निर्माण विभागों के जरिए निष्पादित किए जाते हैं।

संस्थान के बुनियादी ढांचे का वैश्विक स्तर के अनुरूप उन्नयन करने के लिए वैश्विक फिल्म स्कूल नामक नई स्कीम विचाराधीन है।

संस्थान के विद्यार्थियों द्वारा बताई गई फिल्मों को नियमित रूप से विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सवों में प्रविष्टि दी जाती है ताकि विद्यार्थियों के काम को भारत और विदेशों में पहचान प्रदान की जा सके।

वर्ष के दौरान संस्थान ने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सवों/आयोजनों में भाग लिया।

सत्यजित रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता

सुधार, उपाय और योजनाओं की पहल

लाभकारी सोसाइटी की उपाय वित्तीय समूह द्वारा किया जाता है। योजना परिव्यय भी वार्षिक अनुमान के अनुसार होता और सरकार लागत पिछले कई वर्षों से पैसा लगा रही है।

दो नए अकादमी विभागों के निर्माण के अतिरिक्त संस्थान की इमारत में एक अतिआधुनिक फिल्म स्टूडियो के निर्माण का प्रस्ताव है। (एनिमेशन एंड डिजिटल ईमेज और उत्पादन प्रबंधन फिल्म और टेलीविजन)

बड़ी पारदर्शिकता का परिचय देने के लिए संस्थान में एक शिकायत प्रकोष्ठ है और नागरिक घोषणा पत्र का प्रकाशन भी किया जाता है। यह संस्थान के बेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

भारतीय जन संचार संस्थान

संस्थान विभिन्न मीडिया संस्थानों के साथ जुड़ने को इ१५८छुक युवकों एवं युवतियों को उन बुनियादी कौशल/आवश्यक तकनीकी ज्ञान से सुसज्जित करता है तथा क्षेत्र के विभिन्न आयामों के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। संस्थान की ओर से यह प्रयास किया जाता है कि वह अपने छात्रों को समाज के लिए उपयोगी सदस्य बनाये। ये विशिष्टताएं ही संस्थान एवं पूर्व छात्रों को एक विशिष्ट पहचान और चरित्र प्रदान करती है।

भारत का राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय

फिल्मों तथा अनुषंगी सामग्री का डिजिटाइजेशन

सभी तरह की फिल्में रसायनों का मिश्रण होती हैं जिन्हें यदि आदर्श स्थितियों में न रखा जाए तो नष्ट हो सकती हैं। निम्न स्तरीय भंडारण से और नुकसान होता है जिसके चलते गंदगी और कवक के कारण क्षरण का शिकार हो जाती हैं और गंदी, धब्बेदार तथा फट जाती हैं। फिल्म क्षरण से निपटने का व्यावहारिक तरीका फिल्म और मेग्नेटिक मीडिया को डिजिटल फॉर्मेट में बदलना है जोकि टिकाऊ है, भंडारण में आसान है, बारंबार इस्तेमाल के चलते कटने–फटने का डर नहीं और दीर्घकालीन प्रौद्योगिकीय मियाद है। पोस्टर, फिल्मों और अनुषंगी सामग्री को खोजने और उसे प्राप्त करने के अपने प्राथमिक उद्देश्य को हासिल करते हुए, एनएफएआई का अपना लगभग 6000 फिल्मों तथा 5,00,000 से अधिक गीत पुस्तिकाओं, वाल पोस्टरों, तस्वीरों, पत्र कतरनों, लगभग 40,000 पटकथाओं, दुर्लभ पुस्तकों और पत्रिकाओं जो 30 के दशक तक पुराने हैं,

राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन

भारतीय फिल्म विरासत को शैक्षिक, अकादमिक, शोध उद्देश्यों, के लिए भावी पीढ़ियों तक पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीकृत केटालोगिंग, स्वांगीकरण, संरक्षण और बहाली के लिए तत्काल कार्रवाई करना समय की मांग है। एनएफएआई ने एक प्रमुख पहल की परिकल्पना की है। राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन (एनएफएचएम) नामक इस पहल का उद्देश्य फिल्म सामग्री की पहचान/पता लगाना, संचय करना और केन्द्रीकृत करना है। यह फिल्म सामग्री की कैटालोगिंग, डिजिटाइजेशन, डिजिटल बहाली, संरक्षण, प्रसार और मुद्रीकरण के लिए व्यापक मंच और समाधान भी उपलब्ध कराएगा। यह मिशन व्यापक स्तर पर समाज के लाभ के लिए महत्वपूर्ण है। इसका लक्ष्य रणनीतिक निर्देश, नेतृत्व, भागीदारी तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत एनएफएआई, फिल्म प्रभाग, एनएफडीसी, सीएफएसआई, एफटीआईआई, डीएफएफ जैसे फिल्म क्षेत्र के विभागों और राज्य सरकार के संस्थानों एवं अन्य निजी पुस्तकालयों के बीच सहयोग के जरिए संग्रहालय और संरक्षण नीति तैयार करना है। संग्रहालय और संरक्षण के क्षेत्र में 45 से अधिक वर्षों के अनुभव वाली नोडल एजेंसी होने के नाते एनएफएआई ने डीपीआर तैयार की है तथा यह सुनिश्चित करने के लिए एनएफएचएम को कार्यान्वित करेगी कि निर्धारित समय सीमा में इच्छित परिणाम हासिल करने के लिए प्रयासों और संसाधनों का इष्तम उपयोग किया जाए।

वर्ष 2010-11 से 'राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन' नामक नई योजना स्कीम शुरू की गई

इस नई स्कीम का मुख्य उद्देश्य सभी फिल्मों और फिल्मी सामग्री को सहेजना और संरक्षित करना है। एनएफएचएम फिल्म और फिल्मी सामग्री के रूप में प्रतिष्ठापित हमारी सामाजिक सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और उपयोग की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य करेगा। यह मिशन अपनी समृद्ध सेलुलाइट संपदा को संरक्षित करने के हमारे प्रयासों की दिशा में पहला कदम होगा। भारत 2013 में भारतीय सिनेमा के 100 वर्ष पूरे होने का जश्न मानाने जा रहा है ऐसे में यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।

वर्ष 2010-11 के दौरान नई स्कीम का कार्य निष्पादन इस प्रकार है :

(करोड रुपये में)

वित्तीय परिव्यय	कोष का उपयोग करने के लिए चलाई गई भौतिक गतिविधियां
1.00	नई स्कीम शुरू करने के लिए टोकन प्रावधान किया गया। तथापि इस स्कीम को अभी अंतिम रूप दिया जाना है तथा स्कीम का एसएफसी/ईएफसी अनुमोदन लिया जाना है। इसलिए मौजूदा बजटीय प्रावधान का उपयोग नहीं किया जा सका।

वर्ष 2011-12 के दौरान चलाई जाने वाली भौतिक गतिविधियां इस प्रकार हैं :

(करोड़ रुपये में)

परिव्यय	परिकल्पित भौतिक गतिविधियां
5.00	100 फिल्मों को डिजिटाइज किया जाना है तथा 50 फिल्मों को डिजिटली बहाल करना है।

का संग्रह है। बदलती प्रौद्योगिकी के साथ, एनएफएआई ने फिल्मों और अनुषंगी सामग्री के डिजिटाइजेशन और जीर्णोद्वार का कार्य हाथ में लिया है। रिपोर्ट अवधि के दौरान लगभग 137 महत्वपूर्ण फिल्मों का डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है। जहां तक अनुषंगी सामग्री का संबंध है, सभी वाल पोस्टरों, गीत पुस्तिकाओं, स्टिल्स तथा पत्र कतरनों का डिजिटाइजेशन किया जा चुका है। 1930 और 1940 के दशकों की दुर्लभ पत्रिकाएं और फिल्मफेयर, स्टार एवं स्टाइल, माधुरी और स्क्रीन जैसी नियमित पत्रिकाओं को रिपोर्ट अवधि के दौरान डिजिटाइजड किया गया है।

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड

1. ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्म निर्माण के लिए एनएफडीसी को सरकारी मदद देने का निर्णय लिया गया है।

2. यह प्रस्ताव है कि एनएफडीसी सहनिर्माण के क्षेत्र में भी काम करेगा और संभावनाशील अंतर्राष्ट्रीय एवं स्वदेशी सहनिर्माताओं को बुनियादी पूंजी मुहैया करायेगा। इसके लिए जरूरी पूंजी की पूर्ति कंपनी के आईईबीआर से की जाएगी।

3. एनएफडीसी ने निम्नलिखित उद्देश्यों से विदेशी फिल्म और टेलीविजन बाजार में भागीदारी करने की निर्यात रणनीति बनायी है :

i. प्रदर्शन के विभिन्न माध्यमों के जरिये विदेश वितरण के लिए भारतीय फिल्मों का निर्यात

ii. अंतर्राष्ट्रीय सहनिर्माण के लिए साझेदारों की पहचान

iii. लाइन प्रोड्यूसर के रूप में एनएफडीसी की सेवाओं का विकास

iv. भारत को फिल्मों की शूटिंग के स्थल के रूप में प्रचारित करना

v. भारतीय बाजारों के लिए विदेशी फिल्मों का आयात

vi. फिल्म निर्माण एवं एनिमेशन में विदेशी ग्राहकों के लिये अधिकृत निर्माण के कार्य को हाथ में लेना।

4. भारतीय फिल्म परियोजनाओं की गुणवत्ता, उसके दायरे तथा उसकी आकांक्षाओं में विस्तार करने के उद्देश्य से एनएफडीसी फिल्म उद्योग को विभिन्न तरह की पटकथा की उपलब्धता को व्यापक बनाने के अपने प्रयास के तहत उसने पटकथा विकसित करने के लिये हर साल खास संख्या में भारतीय लेखकों को सहायता देने का लक्ष्य बनाया है ताकि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार को उच्च गुणवत्ता वाली तथा बाजार में बिक सकने वाली सामग्रियां विकसित हो सके।

5. चूंकि एनएफडीसी पिछले कुछ वर्षों से घाटे में है, इसलिये इससे पुनर्जीवन के लिये इसके मामले को बोर्ड फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज (बीआरपीएसई) के पास सौंपने का फैसला किया गया था। तदानुसार एसबीआई केपिटल मार्केट्स लिमिटेड की सहायता से एनएफडीसी द्वारा तैयार एक पुनर्जीवन प्रस्ताव बीआरपीएसई को भेजा गया है।

6. सरकार ने एनएफडीसी को छोटा किंतु दक्ष निकाय बनाने के लिये इसके मानव संसाधनों को सुसंगत बनाने के लिये 2008-09 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को लागू करने के एनएफडीसी के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। इस कड़ी में, 2008-09 की अवधि में वीआरएस के अंतर्गत 69 कर्मचारी मुक्त किए जा चुके है और 2009-10 में निगम की मानव शक्ति को 209 से 140 तक लाना है। 5.91 करोड़ रुपये के योजना परिव्यय के साथ संगठन को हल्का और प्रभावी बनाने के लिए 40 अधिशेष मानव शक्ति छंटनी के लिए निगम वीआरएस का एक और चक्र शुरु करने का प्रस्ताव ला रहा है।

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों तथा गतिविधियों के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए पत्र सूचना कार्यालय सरकार की नोडल एजेंसी है। ब्यूरो मीडिया प्रतिनिधियों को मीडिया सुविधाएं प्रदान करता है। सरकार के आम आदमी तक पहुंचने के प्रयासों के एक हिस्से के रुप में आई बी राष्ट्रीय स्तर पर जनसूचना अभियान (पी आई बी) आयोजित कर रहा है। पी आई बी का मुख्य उद्देश्य सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों जैसे राष्ट्रीय रोजगार गांरटी अधिनियम (नरेगा), राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, सर्व शिक्षा अभियान जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, सूचना का अधिकार अधिनियम, अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतू प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम, एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई सी डी एस) स्कीम, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पारंपरिक बनवासी कल्याण इत्यादि के बारे में जागरुकता पैदा करने तथा सूचना पहुंचाना है।

ब्यूरो एक ही स्थान पर राष्ट्रीय तथा अंतराष्ट्रीय पत्रकारों को मीडिया सुविधाएं प्रदान करने के लिए नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय प्रेस केन्द्र स्थापित कर रहा है। ईएफसी ने पहले ही परियोजना को मंजूरी दे दी है और एनबीसीसी को क्रियान्वयन एजेंसी नियुक्त किया गया है। परियोजना लागत 60 करोड़ रुपये तक पहुंचने के कारण ईएफसी का नया अनुमोदन 15 सिंतबंर 2009 को प्राप्त किया गया। निर्माण कार्य भूतल पर आरसीसी स्लैब तक पहुंच गया है, जो 31 दिसंबर 2012 तक पूर्ण होना है।

इसके अतिरिक्त, 11वीं योजना के दौरान योजना स्कीम में भारत का अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह तथा प्रवासी भारतीय दिवस हिस्सा बन गया है। ये भारत सरकार के प्रतिष्ठित कार्यक्रम हैं जो मिली जुली संस्कृति की झलक प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार, पीआईबी इन दोनों कार्यक्रमों के लिए मीडिया सुविधाएं प्रदान कर रहा है।

सूचना और मास मीडिया के क्षेत्र में मीडियाकारों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम और संयुक्त कमीशन/समझौते के जरिए बेहतर समझ को बढ़ावा देने की महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा करता है।

भारतीय प्रेस परिषद

प्रेस परिषद ने अर्द्ध न्यायिक संस्था होने और प्रेस के आचरण संबंधी मानदंडों के नियमन का उत्तरदायित्व संभालते हुए निम्नलिखित सुधार के उपाय और नीतिगत पहलें की हैं :

1. सुधारात्मक उपाय

प्रेस परिषद अधिनियम में संशोधन के लिए सूचना एवं प्रसारण मंलाालय से विचार विमर्श

2. नीतिगत उपाय :

(क) एचआईवी/एड्स पर गाइडलाइन।

(ख) पेड न्यूज।

(ग) विज्ञापन संबंधी गाइड लाइन।

(घ) मीडिया ट्रायल पर गाइडलाइन।

3. पारदर्शिता

1. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू करना

2 भारतीय प्रेस परिषद का नागरिक चार्टर्ड इसकी वेबसाइट पर उपलब्ध है।

3. प्रेस परिषद की पूरी जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है।

4. फैसलों और परिषद की अन्य संदर्भित रिपोर्टों को वेबसाइट पर डालना।

5. पलाकारिता के मानदंड संबंधी मानक वेबसाइट पर उपलब्ध है।

6 पत्रकारों के लिए आचरण संहिता वेबसाइट पर।

7. परिषद की वार्षिक रिपोर्ट वेबसाइट पर है।

8. पीआरएबी के आदेशों की सूची वेबसाइट पर उपलब्ध है।

फोटो प्रभाग

फोटो प्रभाग का प्रमुख कार्य विभिन्न सरकारी संगठनों के लिए प्रगति और विकास के लिए फोटोग्राफ्स और दृश्य प्रलेखन तैयार करना तथा राजनीतिक और आर्थिक सामाजिक परिवर्तनों से संबंधित दृश्यों को उपलब्ध कराना है। संदर्भों की जांच-पड़ताल करने के लिए पृष्ठभूमि तैयार करने, तस्वीरों को एक स्लाइड में रखने ताकि चित्रों तक पहुंचने की सुविधा मिल सके। पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास संबंधित कार्यकलापों तथा जम्मू और कश्मीर जैसे स्थानों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप जैसे योजना कार्यक्रमों से संबंधित स्थानों के दृश्य प्रलेखों को प्राप्त किया जा सके। डिजिटल लाइब्रेरी सिस्टम (अंकीय पुस्तकालय प्रणाली) को और प्रभावी बनाने की जरूरत है ताकि ज्यादा से ज्यादा समय तक अंकीय तस्वीरों को सुरक्षित रखकर प्रभावी प्रणाली बनाए रख सके और ऐतिहासिक महत्व की गुणवत्ता सम्पन्न तस्वीरों को प्राप्त किया जा सके और ऐसे क्षेत्रों जिन्होंने विकास किए हैं, लेकिन उनके दृश्य अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं, उनके भी फोटो अभिलेख व्यापक रूप से प्राप्त किए जा सकें।

प्रकाशन विभाग

सुधार के उपाय व नीतिगत पहल

प्रशासन : एम्पलॉयमेंट नयूज द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी अलग से दी गई है जबकि विभाग के संपादकीय, प्रशासनिक कारोबार, उत्पादन और योजना शाखाओं में की गईं नीतिगत पहलें निम्नलिखित हैं :-

इस विभाग के लिए जरुरी वस्तुओं और सेवाओं की मंजूरी और खरीदने की प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाया और इनको जीएफआर के नियमों के अनुरुप बनाया गया।

प्रशासनिक मुद्दों पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए और अगर कोई समस्या है तो इसके समाधान के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ नियमित टेलीफोन संपर्क शुरु किया गया।

उत्पादन : - मुद्रण गुणवत्ता सुधारने और लागत घटाने के लिए प्रिंटो का नया पैनल तैयार किया गया है।

- किताबों के लिए प्रयुक्त होने वाले कागज की गुणवत्ता के संबंध में विनिर्देशों में कड़ाई करने के बाद इसमें काफी सुधार हुआ।

– तात्कालिक को छोड़कर टेंडर निकालने और खोलने के लिए निर्धारित 21 दिनों के समय को लागू किया गया।

संपादकीय : किताबों के चयन में पारदर्शिता लाने के लिए एक पुस्तक समिति गठित की गई जिसने किताबों के प्रस्तावों की जांच की और सहमति के आधार पर उनको मंजूरी दी।

कलाकारों को इंटरनेट से विचार लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया और किताबों के आवरणों के डिजायन को बिल्कुल नया रूप दिया गया।

व्यापार : विशिष्ट पुस्तकों के प्रकाशन, विज्ञापन, पुस्तक समीक्षाओं, महत्वपूर्ण प्रदर्शनियों और पुस्तक मेलों में भागीदारी द्वारा विभाग इसकी पुस्तकों और पत्रिकाओं के स्वरुप में सुधार लाने के लिए जोर-शोर से प्रयास किए गए।

आम आदमी को आकर्षित करने के उद्देश्य से पुस्तकों के लिए एक मूल्य नीति को अंतिम रूप देकर मंत्रालय भेजा गया। योजना, कुरुक्षेत्र, आजकल, बालभारती तथा अन्य पत्रिकाओं की विज्ञापन दरों को बाजार के अनुरूप संशोधित किया गया। इंडिया और भारत 2009 की विज्ञापन दरों को भी संशोधित किया गया।

योजना : मानवीय पहलुओं पर केंद्रित कर योजना और कुरुक्षेत्र दोनों के आवरण पृष्ठों को सुधारा गया।

एम्प्लाइमेंट न्यूज/रोजगार समाचार

गैर-योजना

i) कुल राजस्व एवं शुद्ध अधिशेष

रोजगार समाचार ने 2009-10 में 7157.01 लाख रुपये का कुल राजस्व कमाया। खर्च निकालने के बाद शुद्ध अधिशेष 2008-09 के दौरान 3342.60 लाख रुपये की तुलना में 2009-10 में बढ़कर 4887.33 लाख रुपये हो गया। दिसंबर 2010 तक राजस्व 4025.99 लाख रुपये तथा शुद्ध अधिशेष 2443.99 लाख रुपये है।

ii) राजस्व

रोज़गार समाचार ने नौकरी बाजार में अपनी सर्वोच्च स्थिति को बरकरार रखा हुआ है तथा वर्ष के दौरान अधिक विज्ञापन लेने में सफल रहा है। विज्ञापन राजस्व 2009-10 में बढ़कर 5308.54 लाख रुपये हो गया है जबकि प्रसार से 1848.47 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। इस साप्ताहिक पत्र ने चालू वित्त वर्ष (दिसंबर 2010 तक) में 2697.34 लाख रुपये विज्ञापन से तथा प्रसार से 961.80 लाख रुपये प्राप्त किए(विविध प्राप्तियां 1.12 लाख रुपये)। साप्ताहिक ने चालू वित्तीय वर्ष (दिसंबर 2010-11 तक) के दौरान 2443.99 लाख रुपये का अधिशेष प्राप्त किया।

iii) पेजों की औसत संख्या

रोज़गार समाचार में छापे जाने वाले पृष्ठों की औसत संख्या 2000-01 में 39.55 पृष्ठों से बढ़कर 2009-10 में 57.23 पृष्ठों तक पहुंच गई। दिसंबर 2010 तक इन पृष्ठों की औसत संख्या प्रति अंक 64 है।

iv) नेटवर्क में विस्तार

रोजगार समाचार अपने पाठकों तक पहुंचने के लिए ज्यादातर अपने नेटवर्क पर निर्भर करता है। दूर-दराज के क्षेत्रों में कवरेज सुनिश्चित करने के लिए पाठकों के पास सीधे ग्राहक बनने की भी सुविधा है। रोजगार समाचार ने खुले विज्ञापन के जरिए आवेदन-पत्र आमंत्रित करके वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान डीलरों के अपने आधार को विस्तारित किया है। 2011-12 में विभाग की देशभर में अपने नेटवर्क विस्तार की योजना है।

v) इंटरएक्टिव वेबसाइट

रोजगार समाचार की सबसे बड़ी सफलता इसकी वेबसाइट- www.employmentnews.gov.in को शुरू करना है जिसे प्रतिदिन 3 लाख से अधिक लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। यह वेबसाइट सरकारी क्षेत्र में सबसे अधिक प्रयोग हो रही है। वेबसाइट के जरिए पेश की जा रही ऑन लाइन सेवाओं में कैरियर परामर्श, सरकारी क्षेत्र में रिक्तियों के बारे में अग्रिम जानकारी तथा यह जानकारी सीधे पाठकों के ई-मेल पर उपलब्ध कराना शामिल है।

भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक

पिछले कुछ वर्षों में प्रिंट मीडिया का जिस तरह से विस्तार हुआ है उससे वह प्रेस और पुस्तक पंजीयन अधिनियम 1867 के दायरे के भी बाहर निकल गया है। पी.आर.बी. अधिनियम 1867 के अनुसार और इस अधिनियम के प्रावधानों की समीक्षा की गई है ताकि उन्हें प्रिंट मीडिया के वर्तमान परिदृश्य के अनुसार प्रासंगिक बनाया जा सके। समाचार पत्रों के त्वरित, कुशल और पारदर्शी सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पी आर बी अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना और समाचार पत्रों की प्रसार संख्या की कड़ी जांच करने जैसे कार्य किए जा रहे हैं और 2007-12 तक की 11वीं योजना के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में गुवाहाटी और मध्य क्षेत्र भोपाल में दो नये क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना की जा रही है। आर एन आई में व्यक्तिगत स्तर पर की गई प्रार्थना और विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा निर्दिष्ट समाचार पत्रों के लिए 1.6.2006 से प्रभावी नई विज्ञापन नीति के लागू हाने के बाद 75000 या इससे अधिक की प्रसार संख्या वाले बड़े समाचार पत्रों की प्रसार संख्या की कड़ी जांच करना। आर एन आई में पैनलबद्ध किए गए चार्टड एकाउंटेंटों द्वारा समाचार पत्रों की प्रसार संख्या की जांच की जाती है।

गवेषणा, संदर्भ एवं प्रशिक्षण प्रभाग

गवेषणा, संदर्भ एवं प्रशिक्षण प्रभाग ने 11 वीं पंचवर्षीय योजना में समाविष्ट करने के लिए अपने महतवपूर्ण कार्य क्षेत्र में नई नीतिगत पहल शुरु की हैं। इन पहल का उद्देश्य जन कल्याण में मीडिया की ताकत का इस्तेमाल करना तथा पत्रकारिता में उच्च आदर्शों को बढ़ावा देना है।

राष्ट्रीय मीडिया पुरस्कार नामक योजनाएं आम जनता की भलाई के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी का एक उदाहरण हैं।

वर्चुअल पुस्तकालय में पुस्तकालय का उन्नयन ऐतिहासिक संस्थान के निर्माण की पह है जो शोधकर्ताओं और नीति नियामकों के लिए स्रोत साम्रगी एवं सूचना के भंडार का कार्य करेगी।

मास मीडिया में अनुसंधान मीडिया-संबंधी विशिष्ट मुद्दों पर शोध करने, फीडबैक लेने और जनता की राय हासिल करने की स्कीम है जिससे सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तरों पर इसकी मीडिया इकाइयों द्वारा नीति निर्धारण और कार्यान्वयन में मदद मिलेगी।

गीत एवं नाटक प्रभाग

प्रभाग को स्थापना संचार उद्देश्यों के लिए प्रचुर लोक कला और पारंपरिक रूपों का दोहन करने के लिए लघु प्रायोगिक इकाई के रूप में 1954 में की गई थी। लाइव इंडिया जिसे अब इस नाम से व्यापक प्रसिद्धि हासिल है, बहुत प्रभावी सिद्ध हुआ है क्योंकि जनता से तत्काल संपर्क करने का लाभ इसमें निहित है तथा इसमें समकालिक मुद्दों, विचारों और समझाने की विधियों का लचीलापन है। इसलिए प्रभाग का कार्यक्षेत्र और आकार बढ़ाया गया ताकि इसे व्यापक पहुंच और सुगमता प्रदान की जा सके तथा दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, रेगिस्तानी और सीमा क्षेत्रों सहित वास्तविक धरातल पर संचार करने के इसके प्रयासों के प्रभाव को बढ़ाया जा सके।

प्रभाग का मुख्य कार्य (जैसा कि इसकी आधिकारिक वेबसाइट में बताया गया है) आम जनता में सामाजिक, आर्थिक और लोकतांत्रिक आदर्शों (जो राष्ट्र की प्रगति के लिए अनुकूल हों), के बारे में जागरूकता और भावनात्मक आत्मीयता पैदा करना, सीमा क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में रक्षा तैयारियों और शेष देश के साथ सांस्कृतिक एकता की भावना पैदा करना तथा सुदूर क्षेत्रों में तैनात सेना के जवानों का नैतिक बल लाइव मनोरंजन मीडिया (जिसमें शहरी थियेटर के रूप और देश केसभी क्षेत्रों की लोक कला शामिल है) के जरिए ऊंचा बनाए रखना है।

अपने उद्देश्यों को हासिल करने के लिए प्रभाग लोक तथा पारंपरिक नाटकों, नृत्य रूपकों, ओपेरा, नृत्य नाटकों, लोक एवं पारंपरिक काव्य, कठपुतली और सदियों पुरानी परंपरा के जादूगरों के सैंकड़ों कौशल जैसे व्यापक लोक एवं पारंपरिक रूपों का उपयोग करता है। इसके अतिरिक्त प्रभाग साम्प्रदायिक सामंजस्य, राष्ट्रीय एकता, धर्मनिरपेक्षता, सांस्कृतिक विरासत के संवर्द्धन, स्वास्थ्य, पर्यावरण, शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए आधुनिक तकनीकों और सैंकड़ों कलाकारों के साथ ध्वनि एवं प्रकाश साधनों का भी उपयोग करता है।

देश के विभिन्न भागों में उपलब्ध असंख्य लोक और पारंपरिक रूपों के इस्तेमाल के जरिए गीत एवं नाटक प्रभाग एक तरफ तो इन रूपों के जीर्णोद्धार और टिकाऊपन का महत्वपूर्ण स्रोत बन चुका है तथा दूसरी तरफ हजारों कलाकारों की अपनी भाषा, मुहावरों तथा सोद्देश्यपूर्ण और सार्थक संवाद के लिए उनकी बोलियों में उनके कौशल का उपयोग करके उनको आजीविका उपलब्ध कराने में सक्षम हुआ है।

ज्यादा पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आधुनिकीकरण के शीर्ष के तहत कम्प्यूटरीकरण का प्रस्ताव है।

कार्यक्रमों की गुणवत्ता सुधारने के मद्देनजर शोध एवं विकास तथा प्रभाव आकलन कराया जाएगा।

एफ. एम. रेडियो

निजी एफ एम रेडियो का कार्य एफ एम चरण I नीति के माध्यम से 1999 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। प्रथम चरण में बड़े पैमाने पर हुई खामियों को ध्यान में रखते हुए और ट्राई की सिफारिशों और अन्य सार्थक कारकों को ध्यान में रखते हुए निजी एजेंसियों (चरण II) के माध्यम से एफ एम रेडियो प्रसारण सेवा का विस्तार करने की नीति को 30 जून 2005 में स्वीकृति दी गई और 13 जुलाई 2005 को इसकी अधिसूचना जारी की गई। एफएम रेडियो प्रसारण के चरण के कार्यान्वयन का कार्य पूरे जोरों पर चल रहा है। कुल 337 चैनलों को निजी एफएम रेडियो के दूसरे चरण में लगाने का कार्यक्रम शुरू किया गया और उनमें से 280 चैनलों के लिए बोलियां सफल रहीं। जांच पड़ताल के बाद 245 एफएम चैनलों के संचालन के लिए विभिन्न कंपनियों को आशय-पत्र भेजे गए। इस समय 254 चैनल चालू हैं जिनमें 21 चैनल चरण के अंतर्गत संचालन कर रहे हैं।

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानिटरिंग केंद्र (ईएमएमसी)

वर्ष 2007–08 के दौरान 19.65 करोड़ रुपये की कुल लागत से ईएमएमसी की स्थापना हेतु एसएफसी (आरसी) की योजना अनुमोदित की गई थी। 11वीं योजना के तहत ईएमएमसी परियोजना के कार्यान्वयन संवर्धन हेतु 16.75 करोड़ का अनुमान था। वार्षिक योजना 2010–11 के अन्तर्गत 2.18 करोड़ रु. का आवंटन किया गया है। परियोजना का निष्पादन मंत्रालय के अधीन एक पीएसयू ब्रोडकास्ट इंजीनियरिंग कन्सल्टैंट्स इंडिया, लिमिटेड (बीईसीआईएल) द्वारा किया जा रहाहै। यह परियोजना दिनांक– 9 जून, 2008 से अस्तित्व में आई थी और इसकी मानीटरिंग क्षमता बढ़ाकर 300 टीवी चैनल कर दी गई है। केबल टेलीविजन वर्क (विनियम) अधिनियम 1995 तथा उसके अंतर्गत बने नियमों से निहित कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं के अन्तर्गत की निगरानी के अलावा यह संदर्भ में मानीटरिंग विषयवस्तु के अलावा विभिन्न एजेंसियों जिनमें मंत्रिमंडल सचिवालय, पीएमओ, एमएचए आदि सम्मिलित है के लिए आवश्यक विषयपरक विशेष रिपोर्टें तैयार करतीहै। ईएमएमसी मंत्रालय का अधीनस्त कार्यालय है और इसकी स्थापना के लिए परियोजना पूर्ण रूप से सरकार द्वारा वित्तपोषित है।

अंतर्राष्ट्रीय चैनल

सुधारात्मक उपाय तथा नीतिगत पहलें

प्रारंभिक अनुमान के रूप में इसमें 100.00 करोड़ रुपये का व्यय है। इस उद्देश्य के लिए प्रसार भारती को एक स्कीम तैयार करने का निदेश दिया गया है।

सामुदायिक रेडियो के लिए आईईसी गतिविधियां

दिसंबर, 2002 में, भारत सरकार ने आईआईटी/आईआईएम जैसे स्थापित शैक्षिक संस्थानों को सामुदायिक रेडियो स्टेशन (सीआरएम) स्थापित करने के लिये लाइसेंस प्रदान करने की नीति को स्वीकृति प्रदान की। इसके अंतर्गत 104 संस्थानों से आवेदन प्राप्त किए गए। इनमें से 63 योग्य संस्थानों को जवाबी पत्र भेजे गये और 45 संस्थानों ने लाइसेंस समझौतों पर हस्ताक्षर किये। वर्तमान में 103 सामुदायिक रेडियो केंद्र देश के विभिन्न हिस्सों में चलाये जा रहे हैं।

मई 2004 में आयोजित कार्यशाला की सिफारिशों के साथ–साथ सांसदों की परामर्श समिति यदि आदि बारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद सरकार द्वारा इस मुद्दे पर पुन: विचार–विमर्श किया गया और दिसंबर, 2006 में विकास और सामाजिक परिवर्तन से जुड़े मुद्दों पर आम नागरिकों तथा अलाभकारी स्वयंसेवी संस्थानं जैसे संगठनों को इस नीति के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया गया।

सूचना भवन का निर्माण चरण-V

वर्ष 2006 के दौरान, सूचना भवन के चरण-V के निर्माण का एक प्रस्ताव मंत्रालय के नीति योजना एकांश को इस आशय के साथ भेजा गया कि इसे ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) में शामिल किया जाए। योजना आयोग से स्वीकृति प्राप्त करने के बाद सूचना भवन के पांचवें चरण के निर्माण के लिए 12 मार्च, 2008 को व्यय वित्त समिति की बैठक आयोजित की गयी थी। व्यय वित्त समिति (ईएफसी) ने 74.60 करोड़ रुपये लागत की सीमा निर्धारित करते हुए इस परियोजना को इस शर्त पर मंजूरी दे दी कि लागत सीमा को पार नहीं किया जाएगा।

वार्षिक योजना वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 तथा वर्ष 2011-12 के लिए अनुमानित बजट में मंत्रालय द्वारा सीसीडब्ल्यू : आकाशवाणी को उपलब्ध कराई गई निधि का ब्यौरा निम्नानुसार है :

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	आबंटित बजट	उपयोग की गई निधि	वार्षिक योजना
1	सूचना भवन के (नई दिल्ली, लोधी रोड सीजीओ काम्पलेक्स) पांचवें चरण का निर्माण	1.00 करोड़ रुपये	1.00 करोड़	2007-08
2	- वही -	3.53 करोड़ रुपये	1.76 करोड़ रुपये	2008-09
3	- वही -	10.00 करोड़ रुपये	10.00 करोड़ रुपये	2009-10
4.	- वही -	18.00 करोड़ रुपये	18.00 करोड़ रुपये	2010-11
5	- वही -	36.22 करोड़ रुपये (बजट अनुमान स्तर पर)	जुलाई, 10 के दौरान 10.00 करोड़ रुपये जारी किए गए है तथा 8.00 करोड़ रुपये जारी किए जा रहे हैं।	2011-12

विकास संबंधी पहलों का आर्थिक विश्लेषण (नई योजना)

इस स्कीम में मीडिया क्षेत्र में नीति संबंधी अध्ययनों का प्रावधान किया गया है। यह अध्ययन उपयुक्त नीतिगत सुधारों को शुरू करने में इस क्षेत्र के विकास के विभिन्न पहलुओं को समझने में बहुत मददगार होंगे।

मानव संसाधन विकास के लिये प्रशिक्षण

प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा अधिकारियों को शामिल करने के उद्देश्य से विदेशों में स्थित संस्थानों से प्रशिक्षकों को बुलाने का भी प्रस्ताव है ताकि मंत्रालय के अधीन विभिन्न मीडिया इकाइयों की प्रासंगिकता के अनुसार इनमें कार्यरत अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा सके। इन इकाइयों में कार्यरत प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारियों के अनुभवों से मीडिया इकाइयों के कामकाज को बेहतर बनाने में मदद मिलती है।

प्रसार भारती

प्रसार भारती के पास प्रसारण और टेलीकास्टिंग के क्षेत्र में ढांचागत, श्रमशक्ति और तकनीकी विशेषज्ञता के संदर्भ में संसाधनों का व्यापक भंडार है। ढांचागत भंडार में, विशेष रूप से भूमि, इमारत, टावर, ट्रांसमीटर, स्टूडियो, सेटेलाइट अर्थ स्टेशनत, अभिलेखकरण की सुविधा, कर्मचारियों का प्रशिक्षण (तकनीकी)संस्थान, अनुसंधान और विकास आदि शामिल है। 500 डब्ल्यू मीडियम वेव ट्रांसमीटर से शुरुआत करते हुए आकाशवाणी आज प्रमुख प्रसारक संगठन बन गया है। 275 रेडियो ट्रांसमीटर के सात यह 91.82 प्रतिशत क्षेत्र और 99.16 प्रतिशत आबादी के दायरे में फैला हुआ है। इसके अतिरिक्त डीडी डायरेक्ट प्लस के फ्री टू एयर डीटीएच प्लेटफॉर्म पर 21 रेडियो लगभग पूरे देश में सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। दूरदर्शन 31 चैनलों से बढ़कर 39 सेटेलाइट अर्थ स्टेशनों तक फैल गया है और विभिन्न क्षमताओं वाले इसके 1416 ट्रांसमीटर देश की 92 प्रतिशत आबादी को अपने दायरे में लिए हुए हैं।

अपनी क्षमता के सदुपयोग के लिए आकाशवाणी ने मई 2001 में अपने संसाधनों को स्वतंत्र केंद्र के रूप में स्थापित किया जिससे व्यापक ढांचे से राजस्व अर्जित किया जा सके। निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत, अगले 10 से 15 वर्षों में आकाशवाणी के संसाधनों द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से राजस्व उत्सर्जित किए जा सकते हैं :

- निजी प्रसारकों, मोबाइल सर्विस प्रदाताओं/इग्नू के साथ लाइसेंस फीस आधार पर प्रसार भारती (पीबी)के ढांचागत संसाधन, जैसे टावर (एसटीएल टावर, स्व सहायक एस डब्ल्यू टावर, एकीकृत टीवी/एफएम टावर)निर्माण और भूमि को बांटना। अभी पीबी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की निजी एफएम चरण 1 और चरण 2 योजना के तहत निजी एफएम प्रसारकों के साथ अपने ढांचागत संसाधनों को बांट रहा है। इस योजना के तहत वे अपने एंटीना को माउंट कर सकते हैं और अपने ट्रांसमीटर और दूसरे सहायक उपकरणों के इंस्टॉलेशन के लिए स्पेस खोल और बंद कर सकते हैं। भविष्य में, अगर पीपीपी के माध्यम से अपेक्षित हो, तो हम अपने ढांचागत संसाधन की व्यापक हिस्सेदारी कर सकते हैं।
- इसके अतिरिक्त प्रसार भारती परिसर में लगे अपने उपकरण इंस्टॉल करने वाले निजी एफएम प्रसारकों को संचालन और रखरखाव सेवाएं भी प्रदान की जा सकती हैं। इस उद्देश्य के लिए एआईआर/डीडी स्टेशनों को श्रमशक्ति आउटसोर्स करने की अनुमति देने की जरूरत होगी क्योंकि श्रमशक्ति की पहले ही कमी है। पीबी निजी प्रसारकों के स्टूडियो और ट्रांसमीटरों को इंस्टॉल और कमीशन करने का काम भी कर सकता है।
- प्रसार भारती पहले से अपने ज्ञानवाणी के लिए इग्नू के एफएम ट्रांसमीटर के इन्सटॉलेशन और कमिशनिंग का काम कर रहा है।
- आकाशवाणी/डीडी सेटअप के साथ कोसाइट करने वाले चैनल/इग्नू ट्रांसमीटरों के संचालन और रखरखाव का काम भी आकाशवाणी/डीडी स्टेशन कर रहे हैं। प्रसार भारती की योजना है कि भविष्य में इग्नू के ट्रांसमीटरों के लिए भी यह कार्य किया जाएगा।

- मौजूदा समय में आकाशवाणी स्टूडियो और ट्रांसमीटरों का खाली समय इग्नू को किराए पर दिया गया है। जब भी कभी ऐसी आवश्यकता होगी और अगर भविष्य में ऐसा समय देना संभव होगा तो प्रसार भारती दूसरे शैक्षणिक संस्थानों/विश्वविद्यालयों और आउटस्टेशन एजेंसियों को प्रतिस्पर्धात्मक दर पर, मौजूदा ट्रांसमिशन घंटों के लिए किराए पर ये सुविधाएं प्रदान करेगा।
- प्रसार भारती श्रोताओं को आईवीआरएस और एसएमएस आधारित सेवा जैसी मूल्य संवर्धित सेवाएं प्रदान करने के लिए टेलीकॉम सेवाओं के साथ एक समझौता कर रहा है। इस प्रकार की लोकप्रिय सेवाएं प्रदान करके, टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं को मिलने वाले राजस्व में से आकाशवाणी को भी राजस्व प्राप्त हो सकता है। दूरदर्शन पहले से दिल्ली से मूल्य संवर्धित सेवाएं प्रदान कर रहा है और जल्द इसे दूसरे शहरों में भी विस्तार देना चाहता है।
- आकाशवाणी के नेटवर्क में एमडब्ल्यू/एफएम/एसडब्ल्यू प्रसारक ट्रांसमीटर का एयर टाइम शैक्षणिक/कृषि संस्थानों को किराए पर दिया जा सकता है।
- विश्वविद्यालयों/कॉलेजों/आवासीय स्कूलों में 50/100 वॉट के एफएम सामुदायिक रेडियो स्टेशन को स्थापित करने में भी प्रसार भारती मदद प्रदान कर सकता है।
- प्रसार भारती विभिन्न आकाशवाण/दूरदर्शन केंद्रों पर ब्रॉडकास्टिंग के विभिन्न क्षेत्रों में ऑन साइट और संस्थात्मक प्रशिक्षण भी प्रदान कर सकता है। कुछ केंद्रों में यह प्रशिक्षण पहले से दिया जा रहा है जिसका आगे चलकर विस्तार किया जा सकता है।
- डेटा ऑडियो चैनल (डीएआरसी) सेवा के माध्यम से प्रसार भारती राजस्व अर्जित कर सकता है।

लैंगिक बजट

वर्तमान वित्तीय वर्ष में, क्षेत्रीय केंद्रों/चैनलों पर लैंगिक बजट को प्रस्तावित किया गया है और अगले वित्तीय वर्ष में सभी केंद्रों/चैनलों में लैंगिक मुद्दों पर कार्यक्रम बनाने के लिए 20 प्रतिशत बजट आवंटित करना तय किया गया है। अगले वित्तीय वर्ष में दूरदर्शन केंद्रों पर कार्य करने वाली महिलाओं को अधिक सुविधाएं देने के प्रावधान किए जाएंगे, जैसे मनोरंजक क्लब, क्रेश, अलग शौचालय, रेस्ट रूम आदि।

डिजिटलीकरण

आकाशवाणी नेटवर्क के डिजिटलीकरण और सीमांत क्षेत्रों में आकाशवाणी/डीडी के दायरे को बढ़ाना मौजूदा वित्तीय वर्ष की प्रमुख गतिविधियों में से एक था। इस वर्ष आकाशवाणी और दूरदर्शन में सॉफ्टवेयर प्रॉडक्शन/अधिग्रहण की एक नई योजना भी चलाई गई जिसका उद्देश्य गुणात्मक कन्टेंट प्रदान करना था।

एनालॉग ट्रांसमिशन से स्विच ऑफ डेट से लेकर डिजिटल ट्रांसमिशन और विभिन्न योजनाओं, जिसमें डीटीएच योजना शामिल है, के लिए पीपीपी (सार्वजनिक निजी भागीदारी) मॉडल को तलाशना व्यापक नीतिगत संरचना का अंग है।

इस समय लोगों के पास ऐसे टीवी सेट हैं जिनके लिए एनालॉग ट्रांसमिशन देकने के लिए सिर्फ एक यागी एंटीना की जरूरत पड़ती है। पर डिजिटल ट्रांसमिशन देखने के लिए लोगों को डिजिटल सेट टॉप बॉक्स (डीएसटीबी)और एक यागी एंटीना की जरूरत पड़ेगी। दर्शक को डीएसटीबी की कीमत प्रति टीवी चार से पांच हजार रुपए चुकानी होगी।

एचडीटीवी

इसे एशियाई खेलों के बाद ब्रॉडकास्टिंग के इतिहास का मील का पत्थर कहा जा सकता है। एचडीटीवी के प्रारंभ के साथ, राष्ट्रमंडल खेलों का प्रोडक्शन और ट्रांसमिशन करके, दूरदर्शन बहुत जल्द दूसरे बड़े परिवर्तन का अग्रदूत बनेगा। यह भी योजना है कि डीडी इंडिया को एचडीटीवी चैनल में परिवर्तित कर दिया जाएगा और डीडी इंडिया के कन्टेंट को वॉयस ऑफ इंडिया में बदल दिया जाएगा। डीडी-डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, एचडीटीवी मोड में एक मूल्य संवर्धित चैनल की भी योजना है।

दूरदर्शन की डीटीएच सेवा 'डीडी डायरेक्ट प्लस'

दूरदर्शन ने दिसंबर 2004 में 33 टीवी चैनलों (दूरदर्शन और निजी चैनल)के साथ निशुल्क डीटीएच सेवा डीडी डायरेक्ट प्लस की शुरुआत की थी जिसका उद्देश्य स्थानीय प्रसारण से छूट गए क्षेत्रों को कवरेज उपलब्ध कराना था। डीटीएच प्लेटफॉर्म की क्षमता को बढ़ाकर 58 टीवी चैनल कर दिया गया है। टोडापुर, नई दिल्ली स्थित डीटीएच सेंटर से डीटीएच सिग्नल इनसेट 4 बी उपग्रह को अपलिंक किए जाते हैं। अंडमान निकोबार द्वीपसमूह को छोड़कर डीटीएच सिग्नल (कू बैंड) द्वारा हर स्थान पर एक छोटे डिश द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। इस समय दूरदर्शन के डीटीएच प्लेटफॉर्म पर 58 टीवी चैनल हैं। पहले चरण में इस प्लेटफॉर्म की क्षमता बढ़ाकर 100 चैनल और दूसरे चरण में 200 चैनल कर दी जाएगी। 10 डीडी चैनल के साथ सी बैंड की डीटीएच सेवा, विशेष रूप से एंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए, सितंबर 2009 में शुरू की गई है।

ऐनीमेशन, गेमिंग और विशेष प्रभावों के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना

फिल्म क्षेत्र हालांकि अधिकतर निजी क्षेत्रके अंतर्गत आता है परंतु यह भारत में एक सशक्त सांस्कृतिक उद्योग है। भारत का संख्या की दृष्टि से विश्व में सबसे अधिक फिल्में बनाने वाले देशों में पहला स्थान है। किंतु राजस्व हासिल करने की दृष्टि से विश्व बाजार में भारतीय फिल्मों की भागीदारी नगण्य है। फिल्म उद्योग के विकास के सभी क्षेत्र – अर्थात फिल्म निर्माण, वितरण, प्रदर्शन और विपणन में प्रौद्योगिकी में प्रगति की महत्वपूर्ण भूमिका है।

मैसर्स पी डब्ल्यु सी द्वारा आयोजित मानव संसाधन संबंधी अध्ययन के आधार पर सरकार (पी पी पी पद्धति) सरकारी निजी भागीदारी में एनीमेशन, गेमिंग तथा दृश्य प्रबावों के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने पर विचार कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने योजना आयोग से संपूर्ण स्कीम के लिए 'सैद्धांतिक स्वीकृति' प्रदान करने का अनुरोध किया है। योजना आयोग ने मंत्रालय से विस्तृत रिपोर्ट/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (पीडीआर) तैयार करने का निर्देश दिया है। परामर्शदाता द्वारा पी डी आर प्रस्तुत कर दी गई है। मंत्रालय द्वारा योजना आयोग से स्कीम पर स्वीकृति प्राप्त करने की प्रक्रिया कर रही है।

अध्याय 4
पिछले कार्य प्रदर्शन की समीक्षा

केन्द्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड
सूचना और प्रसारण मंत्रालय

(लाख रुपये में)

क्रं.सं.	स्कीम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2010-11 तक	मात्रात्मक प्रतिफल
1.	कंप्यूटरीकृत प्रबंधन तथा सीबीएफसी में बुनियादी सुविधाओं का उन्नयन	सीबीएफसी में प्रमाणन प्रक्रिया का कंप्यूटरीकरण तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए उपकरण खरीद तथा ढांचा उन्नयन	90.00	कंप्यूटर से नौ क्षेत्रीय कार्यालयों को जोड़ा जाना है तथा टीवी, वीसीडी, डीवीडी और अन्य तकनीकी उपकरणों की क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए खरीद और सीबीएफसी का ढांचा उन्नयन
2.	नई दिल्ली, कटक, तथा गुवाहाटी में क्षेत्रीय कार्यालय खोलना	इस क्षेत्र में निर्मित फिल्मों के प्रमाणन के लिए	80.00	उत्तर पूर्व, उत्तर भारत तथा उड़ीसा के निर्माताओं द्वारा निर्मित फिल्मों (सेल्युलॉइड तथा वीडियो फॉर्मेट दोनों) तथा विज्ञापनों को प्रमाणित करना सिनेमेटोग्राफ एक्ट, 1952 के तहत प्रावधानों के उल्लंघन को रोकना
3.	प्रमाणन प्रक्रिया की निगरानी तथा आधुनिकीकरण	बोर्ड सदस्यों/पैनल सदस्यों के लिए कार्यशालाएं/सेमिनार तथा अध्ययन आयोजित करना	50.00	बोर्ड सदस्यों तथा सलाहकार पैनल सदस्यों के लिए नियमित अंतराल पर कार्यशालाएं/सेमिनार आयोजित करना। प्रमाणन प्रक्रिया संबंधी अध्ययन/सूचना संग्रह करना

बाल फिल्म समिति, भारत

	उपलब्धियां 2009-10	लक्ष्य 2010-11	2010-11 की संभावित उपलब्धियां अप्रैल 2010 से दिसंबर 2011 तक		लक्ष्य
			जनवरी 2011 से मार्च 2011 तक		
योजना : निर्माण					
निर्माण	5 फीचर	3 फीचर फिल्म, 2 लघु फिल्म	3 फी. और 2 लघु. फिल्म प्रगति पर		3 फीचर तथा 2 लघु फिल्में
डबिंग	7 फिल्में	14 फिल्में	12 फिल्में, 20 सं.		14 फिल्में
उपशीर्षक	11 फिल्में	10 फिल्में	2 फिल्में		10 फिल्में
खरीद	2 फिल्में	3 फिल्में	2 अंग्रेजी फिल्में		2 फिल्में
प्रिंट की लागत	नई बनी फिल्मों के 35 मिमी के 17 तैयार कर लिए गए हैं।	आवश्यकतानुसार	99 प्रिंट, 52 फिल्मों के बनें		
योजना : डिजिटल रूपांतरण और वेबकास्टिंग					
डिजिटल रूपांतरण	60 घंटों की 40 फिल्में डिजिटलाइजेशन	डिजटलाजेशन और संरक्षण बाल फिल्म समिति की फिल्म	31.03.10 तक लगभग 30 फिल्मों का डिजिटलीकरण की आशा		सीएफएसआई की फिल्मों का डिजिटलीकरण और संरक्षण
वेबकास्टिंग	वेबसाइट अद्यतन है, अंग्रेजी और हिंदी भाषा में	सीएफएसआई वेबसाइट का लगातार अद्यतन	-		सीएफएसआई के वेबसाइड का रखरखाव
योजना : नगर निगम के स्कूलों में फिल्मों का प्रदर्शन					
नगर निगम के स्कूलों में फिल्मों का प्रदर्शन	23 लाख से ज्यादा बच्चों के के लिए 4741 प्रदर्शन किए गए	25 लाख से ज्यादा बच्चों के लिए 5000 प्रदर्शनों का आयोजन	24 लाख बच्चों के लिए 4256 प्रदर्शनों का आयोजन	4 लाख बच्चों के लिए 1705 प्रदर्शन	5000 शो का आयोजन लाखों बच्चों ने देखा।
योजना : फिल्म महोत्सव					
आईसीएफएफ (16वां) का आयोजन	1	-	-		1 (17 आईसीएफएफ 15)
अंतर्रा. फिल्म महोत्सवों में भागीदारी	7	15	7	मांग के अनुसार	

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय

पिछले कार्य निष्पादन वार्षिक योजना 2009-10 के दौरान की समीक्षा

वास्तविक कार्यक्रम गतिविधियां

	2009-10		2011-12		
कार्यक्रम	**लक्ष्य**	**उपलब्धियां**	**2010-11 लक्ष्य**	**2010-11 उपलब्धियां (दिसम्बर, 10 तक)**	**2011-12 लक्ष्य**
दौरे वाले दिन	23568	24187	23568	15972	23568
फिल्म शो	46500	36656	46500	28401	46500
विशेष कार्यक्रम	4968	10440	4968	7688	4968

वार्षिक योजना 2009-10 में केवल दो योजनाओं को मंजूरी मिली है-(i) दौरों का आयोजन/दक्षता उन्नयन तथा (ii) क्षेत्रीय कार्यालयों एवं क्षेत्रीय प्रचार इकाइयों में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का आधुनिकीकरण तथा उन्नयन। इन योजनाओं की लागत 1.49 करोड़ रुपये है।

दौरों का आयोजन/दक्षता उन्नयन योजना के तहत 13 दौरे किए गए। दूसरी योजना के तहत क्षेत्रीय कार्यालयों तथा मुख्यालय के लिए 89 कम्प्यूटर 34 मल्टी मीडिया प्रोजेक्टर, 15 वायरलैस पी ए प्रणालियां, 34 डीवीडी, 4 डिजिटल वीडियो कैमरे क्षेत्रीय कार्यालयों तथा मुख्यालय को प्राप्त हुए। क्षेत्रीय कार्यालयों के कर्मियों/एफपीयू के लिए 11 कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुए तथा 6.59 रुपये की फिल्में प्राप्त हुईं।

वित्तीय कार्य निष्पादन

(लाख रुपये में)

योजना/गैर-योजना	**2009-10**		**2010-11**		**2011-12**
	लक्ष्य	**उपलब्धियां**	**लक्ष्य**	**उपलब्धियां (दिसंबर, 10 तक)**	**2010-11 लक्ष्य**
योजना	149.00	135.82	555.00	53.35	376.00
गैर-योजना	4127.00	4108.59	3572.00	3127.76	4135.00
कुल	**4276.00**	**4244.41**	**4127.00**	**3181.11**	**4511.00**

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय

11वीं योजना परिव्यय

प्रस्तावित 11वीं योजना स्कीम का विवरण और औचित्य नीचे दिया गया है-

(रुपये लाख में)

क्रम सं.	स्कीम का नाम	अनुमोदित 11वीं योजना परिव्यय	वार्षिक योजना 2011-12 के लिए व्यय
1.	आयोजित दौरे/कौशल उन्नयन	230.00	55.00
2.	क्षेत्रीय कार्यालयों और एफपीयूएस में सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर का आधुनिकीकरण और उन्नयन	1102.67	321.00
	कुल	**1332.67**	**376.00**

संगठन

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय ने 32 क्षेत्रीय प्रचार इकाइयों तथा 4 क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ 1953 में कार्य करना शुरू किया। उल्लेखनीय है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नियंत्रण में इस निदेशालय ने पंचवर्षीय योजना प्रचार संगठन के रूप में अपना कार्य शुरू किया। 1959 में इसे क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय का रूप दिया गया। कुछ समय पश्चात् क्षेत्रीय प्रचार इकाइयां तथा क्षेत्रीय कार्यालय खोले गए। मौजूदा दौर में 22 क्षेत्रीय कार्यालय तथा 207 क्षेत्रीय प्रचार इकाइयों के माध्यम से यह निदेशालय ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्रचार अभियान में लगा है। इस निदेशालय की पहुंच बहुत व्यापक है। दूर-दराजों के क्षेत्रों तथा उन गांवों तक इसकी पहुंच है जहां आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता।

क्षेत्रीय प्रचार इकाइयां प्रचार के कई तकनीकों का प्रयोग करती हैं, जैसे-फिल्म शो, गीत तथा नाटक, फोटो प्रदर्शनी, ग्रुप डिसकशन, सेमिनार, संगोष्ठी, रैली तथा विविध प्रतिस्पर्धात्मक तरीके जैसे-वाद-विवाद, ड्राइंग, ग्रामीण खेल आदि। इन गतिविधियों के आयोजन का मुख्य उद्देश्य होता है ग्रामीण तथा जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें शिक्षित तथा जागरूक करना। डीएफपी (क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय) विकास गतिविधियों में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि निम्न स्तर के लोगों को भी जागरूक बनाया जाए तथा विकास गतिविधियों से उन्हें जोड़ा जाए। डीएफपी एक ऐसा मंच प्रदान करता है ताकि लोग सरकार द्वारा जारी विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों तथा योजनाओं के बारे में अपनी प्रतिक्रिया (विचार) व्यक्त कर सकें।

वार्षिक योजना 2010-11

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने वर्ष 2010-11 के लिए 5.55 करोड़ रुपये का कोष उपलब्ध कराया है। इनमें से 55.00 लाख रुपये की राशि आयोजित दौरों/कौशल उन्नयन तथा 5.00 करोड़ रुपये की राशि क्षेत्रीय प्रचार कार्यालयों/इकाइयों के सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर के उन्नयन तथा आधुनिकीकरण स्कीम के लिए है। इसके तहत 11 आयोजित दौरों, मल्टी मीडिया प्रोजेक्टर की 15 इकाइयों, डीवीडी प्लेयर की 16 इकाइयों, 20 वायरलेस पी.ए. सिस्टम, डिजिटल वीडियो कैमरा की 6 इकाइयों का प्रावधान है। इसके अलावा फिल्म प्रभाग आदि से अधिक से अधिक वीएचएस कैसेट/सीडी/डीवीडी प्राप्त करने, एक प्रोग्रामर,दो सहायक प्रोग्रामर तथा 25 डेटा एंट्री आपरेटर, 8 डिजिटल ब्लैक तथा ह्वाइट फोटोकॉपियर्स, एक कलर डिजिटल फोटोकॉपियर,100 डिजिटल कैमरा किराये पर लेने तथा 90 वाहनों को प्राप्त करने का प्रावधान है।

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय

वित्तीय समीक्षा

योजना स्कीम 2010-11

(हजार रुपये में)

क्रम सं.	योजना का नाम	2010 के लिए परिव्यय	लक्ष्य 2010-11	दिस. 10 तक खर्च	उपलब्धि	खाते का नाम
1.	आयोजित दौरे/कौशल उन्नयन	55.00	आयोजित दौरे		दिसंबर 10 तक दौरे आयोजित हुए	मांग सं. 60, ''2220'' सूचना और प्रचार, 60.106 तंत्रीय प्रचार 01-क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय, 01,00.21-वर्ष 2010-11 के लिए आपूर्ति और सामग्री (योजना)
2.	क्षेत्रीय कार्यालयों/इकाइयों के सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर आधुनिकीकरण तथा उन्नयन	500.00	15 मल्टी मीडिया प्रोजेक्टर, 16 डीवीडी प्लेयर, 20 डब्ल्यूपीए सिस्टम, 6 डिटिजटल वीडिये कैपरा प्राप्त करना, 1 प्रोग्रामर, एक सहायक प्रोग्रामर,25 डीईओ, 8 डिजिटल ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपियर, 90 वाहन, 100 डिजिटल कैमराकिराए पर लेना तथा एफडी, सीएफएसआई आदि से यथा संभव अधिक से अधिक फिल्में लेना।		15 एमएमपी, 1 प्रोग्रामर, 1 सहायक प्रोग्रामर, 20 डब्ल्यू पी एएस के लिए आदेश, 6 डिजिटल हैंडी कैमरा के लिए आदेश, एफडी तथा सीएफएसआई से फिल्मों के लिए आदेश	माँग सं. 60, ''4220'' सूचना और प्रचार (मुख्य शीर्ष) पर पूँजी परिव्यय, 60-अन्य (उप मुख्य शीर्ष), 60.052 मशीनरी और सामग्री (लघु शीर्ष), 02 डीईएफ के लिए सामग्री की प्राप्ति, 02.00.52 मशीनरी और सामग्री वर्ष 2010-11 के लिए (योजना)।
	कुल	555.00				

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय

वित्तीय समीक्षा

(हजार रुपये में)

क्रम सं.	स्कीम का नाम	2011-12 के लिए भौतिक लक्ष्य	2011-12 के लिए परिव्यय (लाख रु. में)
1.	आयोजित दौरे/कौशल उन्नयन	11 आयोजित दौरे	55.00
2.	क्षेत्रीय प्रचार इकाइयों तथा क्षेत्रीय कार्यलयों के हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का उन्नयन और आधुनिकीकरण	31 मल्टी मीडिया प्रोजेक्टर (42.16 लाख रु.),10 डीवीडी प्ले पर (0.43 लाख रु.), 15 वायरलेस पी.ए. सिस्टम (2.10 लाख रु.), 08 डिजिटल कैमरा हैंडीकैम्स (2.40 लाख रु.), एफडी, एनएफडीसी, सीएफएसआई आदि से फिल्में लेना (15.00 लाख रु.)। प्रोग्रामर, 1 सहायक प्रोग्रामर तथा 100 डीईओ को किराए पर लेना (120.00 लाख रु.),25 डिटिजटल कैमरा (12.50 लाख रु.), 26 वाहनों की खरीद (136.50 लाख रु.)।	321.00
	कुल :		376.00

विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय

वर्ष 2009-10 के लक्ष्य और उपलब्धियां : वित्तीय और वास्तविक लक्ष्य इस प्रकार हैं :

वित्तीय प्रदर्शन

(लाख रुपये में)

(बजट अनुमान 2009-2010)			वास्तविक व्यय 2009-10		
योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
3688.00	6757.50	10445.50	3688.00	6736.95	10424.95

** वार्षिक योजना 2009-10 के दौरान आरई/एफजी स्तर पर स्वीकृत परिव्यय 2688.00 लाख रुपये से बढ़ाकर 3688.00 लाख रुपये कर दिया गया।*

वास्तविक प्रदर्शन

वार्षिक योजना 2008-2009

वर्ष 2009-10 की वार्षिक योजना को एक जारी कार्यक्रम *विकासात्मक प्रचार कार्यक्रम : अवधारणा एवं प्रसार* के लिए बनाया गया है। इसके अंतर्गत 2688.00 लाख रुपये के परिव्यय की मंजूरी दी गई है। हालांकि संशोधित अनुमान/अंतिम अनुदान के चरण में 3688.00 लाख रुपये का अतिरिक्त कोष दिया गया है। मार्च 2010 तक 3688.00 लाख रुपये की धन राशि व्यय हुई है तथा वित्तीय लक्ष्य के संदर्भ में शत-प्रतिशत उपलब्धि हासिल हुई है। यह योजना बाह्य प्रचार माध्यम, मुद्रित प्रचार माध्यम, प्रदर्शनी, डिसप्ले और वर्गीकृत विज्ञापन तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा सूचना के प्रसार द्वारा लागू किया गया है।

वास्तविक उपलब्धियां :

वित्तीय लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए थे, वास्तविक उपलब्धियां भी उत्कृष्ट थीं जो इस प्रकार रहीं :

प्रदर्शनी : वर्ष 2009-10 की वार्षिक योजना के तहत देश भर में निम्न महत्वपूर्ण प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया जैसे कि स्वस्थ भारत, पुनरुत्थानशील भारत, भारत निर्माण, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनएचआरएम), आजादी एक्सप्रेस, 1857 क्रांति यात्रा, एड्स जागरूकता एवं स्वस्थ मां स्वस्थ बच्चा इत्यादि।

मुद्रित विज्ञापन : 'भारत निर्माण' और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवसों पर विज्ञापन जारी किए गए कुल विज्ञापन 13829 जिनमें से 714 डिसप्ले तथा अन्य क्लासीफाइड इनमें 148 यूपीएससी के लिए।

दृश्य-श्रव्य : डीएवीपी के बजट से राष्ट्रीय एकता (भारत मेरी पहचान), भारतीय संविधान के 60 वर्ष,गांधी जयंती, शहीद दिवस, सद्भावना दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर अभियान।

मुद्रित प्रचार माध्यम : योजना प्रचार के लिए 13, गैर-योजना-67, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए 4 तथा अन्य मंत्रालयों के लिए 86 पुस्तिकाएं मुद्रित की गईं।

बाह्य प्रचार : होर्डिंग्स, बस पैनेल,कियोस्क, सार्वजनिक सुविधाओं इत्यादि के जरिए 239 अभियान चलाए गए।

डीएवीपी का आधुनिकीकरण : आधुनिकीकरण की योजना के तहत ऑनलाइन बिलिंग के लिए आवश्यक हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर तथा सॉफ्टवेयर खरीदे कान्फ्रेंस हाल के अद्यतन किया गया है तथा प्रदर्शनी खंड में डिजीटल लाइब्रेरी के लिए सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर प्रदान किया गया है और निदेशालय के कर्मचारियों की कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया गया है।

योजना/गैर योजना/अन्य मंत्रालय/विभाग

वर्ष 2008-2009 के दौरान लक्ष्य और उपलब्धियां निम्न प्रकार से हैं :

क्र.सं.	ब्योरा	लक्ष्य	उपलब्धियां
1	प्रदर्शनी	650	422
2	डिसप्ले/वर्गीकृत विज्ञापन	15560	13829
3	रेडियो/टेलीविजन पर विज्ञापन@	2182	3900
4	मुद्रित प्रचार	178	170
5	बाह्य प्रचार	250	239

@ इसके अंतर्गत 12 भाषाओं में 325 अभियान शामिल हैं।

II) वर्ष 2010-2011 के लिए लक्ष्य और उपलब्धियां

वित्तीय लक्ष्य

(लाख रुपये में)

योजना	गैर-योजना	कुल
4450.00	6228.00	10678.00

वास्तविक प्रदर्शन

वर्ष 2010-11 में दो योजनाएं बनाई गई हैं **: (1) विकासात्मक प्रचार कार्यक्रम : अवधारणा एवं प्रसार** (चालू योजना) के लिए स्वीकृत परिव्यय 4350.00 लाख रुपये कर दिया गया है।

(2) डीएवीपी का आधुनिकीकरण : 'योजना' जो कि नई योजना है, को 11वीं योजना में वर्ष 2010-11 के लिए 100.00 लाख रुपये अनुमोदित किए गए हैं। योजना और गैर योजना मदों के अन्तर्गत 31 दिसम्बर 2010 तक 7178.79 लाख रुपये व्यय हो चुके हैं।

उपलब्धियां

योजना : विकासात्मक प्रचार कार्यक्रम : अवधारणा तथा प्रसार

प्रदर्शनियां : वार्षिक योजना 2010-11 के दौरान निम्न महत्वपूर्ण प्रदर्शनियों का देश भर में आयोजन हुआ जैसे कि 'स्वस्थ भारत', पुनरुत्थानशील भारत, प्रमुख शिप कार्यक्रम, 'भारत निर्माण', एच1 एन1-प्रदर्शनी, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) आदि।

बाह्य प्रचार : बाह्य प्रचार के अंतर्गत होर्डिंग्स, बस पैनल, कियोस्क, सार्वजनिक सुविधाओं के जरिए उपभोक्ता मामले, भारतीय नौसेना की, आईएस, आयकर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, बीईई, डब्लूसीडी, एमएचए (एनडीएमए) भारत निर्माण तथा सार्वजनिक सुविधाएं अभियान किया गया।

रेडियो स्पॉट : सूचना और प्रसारण मंत्रालय के बजट से भारत निर्माण अभियान चलाया गया। अन्य मंत्रालयों के लिए अतुल्य भारतय, उत्तर पूर्व के लिए प्रचार, सेना/नौसेना में भर्ती, उपभोक्ता जागरूकता, जनसंख्या नियंत्रण पर अभियान चलाए गए।

डिसप्ले तथा क्लासीफाइड : कुल 12,722 विज्ञापन जारी किए गए। इनमें से 799 डिसप्ले तथा बाकी क्लासीफाइड थे। 118 विज्ञापन यूपीएससी के थे।

मुद्रित प्रचार : विभिन्न भाषाओं में 150 कार्य और 302 मदों की महत्वपूर्ण बुकलेट की छपाई करवाई गई।

योजना : डीएवीपी का आधुनिकीकरण

कार्यालय खर्च : आधुनिकीकरण की योजना तहत वित्तीय वर्ष के दौरान ऑन लाइन विलिंग के लिए कम्प्यूटर तथा जरूरी हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर खरीदे गए। साथ ही डीएवीपी मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए आफिस-फर्नीचर खरीदा गया।

योजना/गैर-योजना/अन्य मंत्रालय/विभाग (2010-11)

वास्तविक उपलब्धि (2010-11)

क्र.स.	विवरण	लक्ष्य	31.12.2010 तक उपलब्धियां	31.3.2011 तक अनुमानित उपलब्धियां
1	प्रदर्शनी	500	376	526
2	डिसप्ले/वगीकृत विज्ञापन	15600	12722	15600
3	रेडियो/टीवी के लिए विज्ञापन@	5300	3600	5300
4	मुद्रित प्रचार	160	160	179
5	बाह्य प्रचार	250	289	320

@ इन लक्ष्यों में विभिन्न भाषाओं में कार्यक्रम शामिल हैं।

वर्ष 2011-2012 के लक्ष्य

बजट अनुमान

(लाख रुपये में)

वित्तीय

योजना	गैर योजना	कुल
5600.00	6733.00	12333.00

वित्तीय लक्ष्य

योजना/गैर योजना/अन्य मंत्रालय/विभाग (2011-2012)

क्र.सं.	विवरण	लक्ष्य
1.	प्रदर्शनी	500
2.	डिस्प्ले/वर्गीकृत विज्ञापन	15000
3.	रेडियो/टीवी विज्ञापन	4800
4.	मुद्रित प्रचार	189
5.	बाह्यय प्रचार	250

2011-2012 की वार्षिक योजना

वर्ष 2011-2012 की वार्षिक योजना में : (1) *विकासात्मक प्रचार कार्यक्रम : अवधारणा एवं प्रसार* के लिए 5500.00 लाख रुपये की योजना तथा (2) *डीएवीपी का आधुनिकीकरण* के लिए 100.00 लाख रुपए की मंजूरी वाली दो योजनाओं को शामिल किया गया है।

चल रही योजना अर्थात *विकासात्मक प्रचार कार्यक्रम : अवधारणा एवं प्रसार* के तहत राष्ट्र के महत्वपूर्ण फ्लैगशिप अभियान तथा मल्टीमीडिया प्रचार जैसे कि प्रदर्शनी, बाह्यप्रचार, इलेक्ट्रानिक मीडिया सूचना प्रदान करना, डिसप्ले एवं वर्गीकृत विज्ञापन की सहायता से सरकार की नीतियों के प्रसार का कार्य है।

लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ऊपर्युक्त योजनाओं में अर्थात *विकासात्मक प्रचार कार्यक्रम : अवधारणा एवं प्रसार, डीएवीपी का आधुनिकीकरण* को योजना आयोग ने कम्प्यूटरीकरण और डिजीटलीकरण, आफिस का बुनियादी ढांचा और मानव संसाधन के विकास को शामिल किया है।

फिल्म समारोह निदेशालय

योजना शीर्ष के तहत 2009-10 तथा 2011-12 (31.12.2010 तक) के वास्तविक प्रदर्शन की समीक्षा

क्र. सं.	स्कीम का नाम	2009-10 के लिए लक्ष्य	उपलब्धियां 2009-10	कमी के कारण	2010-11 के लिए लक्ष्य	उपलब्धियां 2010-11 (31.12.10 तक)	वास्तविक प्रदर्शन की समीक्षा	2011-12 के लिए लक्ष्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	विदेशी यात्रा खर्च	-	-	-	-	-	प्रशासनिक खर्च	
2.	(i) भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह सहित भारत तथा विदेश में फिल्म समारोहों के जरिए निर्यात संवर्धन	01	01	शून्य	01	01	शून्य	(01)
3.	(i) विदेशी फिल्म समारोहों में भागीदारी	45	45	शून्य	45	48	-	50
	(ii) भारतीय पैनोरमा	01	01	शून्य	01	01	शून्य	01
4.	फिल्म समारोह परिसर— फेरबदल और संयोजन	आने वाले राष्ट्रमंडल खेल 2010 को देखते हुए सुविधाओं में सुधार	कार्य प्रगति पर	शून्य	राष्ट्रमंडल खेल 2010 को ध्यान में रखकर सिरीफोर्ट ऑडिटोरियम में सुविधांए	कार्य प्रगति पर	शून्य	सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करना ताकि कला, संस्कृकि तथा सिनेमा के क्षेत्र में ऑडिटोरिया को किराए पर देकर उच्च राजस्व अर्जित करना।
5.	प्रिंट यूनिट का उन्नयन	फिल्मों का डिजिटलीकरण	शून्य	योजना आयोग से सैद्धांतिक मंजूरी मिलने की प्रतीक्षा	डीवीडी प्लेयर, रिकार्डर इत्यादि उपकरणों की खरीद	उपकरण खरीदने के लिए अनमिति प्रदान।	2009-10 के लक्ष्य पूरे किए जाएंगे।	भारतीय पैनोरमा फिल्मों का डिजिटलीकरण तथा एलटी-04 प्लेयर आदि की खरीद

फिल्म समारोह निदेशालय

वार्षिक प्रदर्शन की समीक्षा 2009-10 और 2010-11 (31.12.2010 तक) गैर योजना शीर्षक के तहत

गैर योजना

क्र. सं.	स्कीम का नाम	2009-10 के लिए लक्ष्य	उपलब्धियां 2009-10	कमी के कारण	2010-11 के लिए लक्ष्य	उपलब्धियां 2010-11 (31.12.10 तक)	भौतिक निष्पादन की समीक्षा	2011-12 के लिए समीक्षा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	वेतन	-	-	-	-	-	#	#
2.	समयोपरि भत्ता	-	-	-	-	-	#	#
3.	घरेलू यात्रा	-	-	-	-	-	#	#
4.	कार्यालय व्यय	-	-	-	-	-	#	#
5.	किराया, दर और कर	-	-	-	-	-	#	#
6.	लघु कार्य	-	-	-	-	-	#	#
7.	भत्ते	-	-	-	-	-	#	#
8.	अन्य प्रभार	-	-	-	-	-	#	#
9.	सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत फिल्म समारोह	12	12	शून्य	12	11	-	12
10.	राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार	1	1	शून्य	1	1	-	1
11.	बैंकिंग नकदी लेन-देन कर	-	-	-	-	-	-	-
12.	चिकित्सा व्यय	-	-	-	-	-	-	-

प्रशासनिक खर्चे होने के कारण कोई लक्ष्य नहीं

फिल्म प्रभाग

निर्माण गतिविधियां

(रुपये लाख में)

वास्तविक 2009-2010			बजट अनुदान 2010-2011			प्रस्तावित संशोधित अनुमान 2010-2011			बजट अनुदान 2011-2012		
योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
0.00	1276.26	**1276.26**	0.00	1368.00	**1368.00**	0.00	1349.86	**1349.86**	0.00	1387.86	**1387.86**

डॉक्यूमेंट्री (न्यूज मैगजीन सहित)

	उपलब्धि 2009–10	लक्ष्य 2010–11	प्रत्याशित उपलब्धि 2010–11		लक्ष्य 2011–12
			अप्रैल, 2010 से दिसं., 2010 तक	जन., 2011 से मार्च, 2011 तक	
(1) इन हाउस निर्माण (ए) गैर योजना (i) थिएटर/गैर थिएटर के लिए न्यूज मैगजीन	13	*	13	10	*
(ii) डॉक्यूमेंट्री जारी–थिएटर	33	26	12	15	26
(iii) डॉक्यूमेंट्री जारी–गैर थिएटर	14	10	1	–	10
(iv) संस्थागत शिक्षण और प्रशिक्षण फिल्म	–	–	–	3	–
(2) बाहरी निर्माताओं से निर्माण	12	20	5	4	–
कुल					
अन्य मंत्रालयों द्वारा अनुदानित फिल्मों का निर्माण	–	–	–	–	–
बाहरी निर्माताओं द्वारा प्रत्यक्ष	4	–	1	4	–
भुगतान के आधार पर फिल्म निर्माण					
योजना	–	–	12 (टीआर) 51 (एनटीआर)	–	–
कुल	**76**	**56**	**95**	**36**	**36**

(*) फिल्म प्रभाग वीवीआईपी के विदेश जाने तथा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनाओं पर ही न्यूज मैगजीन का निर्माण करता है। इसलिए न्यूज मैगजीन के निर्माण का कोई विशेष लक्ष्य नहीं है।

वितरण

फिल्म प्रभाग डॉक्यूमेंट्री तथा न्यूज मैगजीन का वितरण थिएटर तथा गैर-थिएटर वर्ग के लिए करता है। थिएटर के लिए वितरण देश के सिनेमा हाउस के जरिए होता है जो मान्य फिल्मों (609 मीटर से अधिक नहीं) को प्रदर्शित करते हैं।

वित्तीय

(रुपये लाख में)

वास्तविक 2009-2010			बजट अनुदान 2010-2011			प्रस्तावित संशोधित अनुमान 2010-2011			बजट अनुदान 2011-2012		
योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
0.00	1808.04	**1808.04**	0.00	1938.00	**1938.00**	0.00	1912.30	**1912.30**	0.00	1966.14	**1966.14**

(भौतिक)

प्रिंट्स और कैसेट की संख्या	उपलब्धियां 2009-10	लक्ष्य 2010-11	उपलब्धियां दिसं., 2010 तक	उपलब्धियां मार्च, 2011 तक	लक्ष्य 2011-12
थिएटर के लिए जारी	11562	13000	10229	2700	13000
गैर थिएटर जारी	86	-	88	-	निर्धारित नहीं
डीईवी को वीएचएस कैसेट तथा वीसीडी की आपूर्ति	888	-	-	2507	निर्धारित नहीं
डीईपी को प्रिंट्स की आपर्ति	-	-	-	-	निर्धारित नहीं
प्रिंट की बिक्री					
35एमएम/16 एमएम (कलर)	3	5	3	-	निर्धारित नहीं
35एमएम/16 एमएम (बी एंड डब्ल्यू)					
बेटा (कलर)					
डीवीडी (कलर)	739	निर्धारित नहीं	809	125	1000
वीसीडी (कलर)	1696	5500	1301	500	2500

फिल्म प्रभाग द्वारा प्रति सप्ताह सिनेमा हाउसों को अनुमोदित फिल्मों की आपूर्ति का ब्योरा इस प्रकार है।

2008-09	8007
2009-10	8219
2010-11	6967

गैर थिएटर वितरण के तहत फिल्म प्रभाग प्रति सप्ताह एक डॉक्यूमेंट्री या एक न्यूज मैगजीन (बारी-बारी से) जारी करता है। इसके लिए पूरे देश को एक सर्किट माना जाता है। थिएटर वितरण के तहत प्रति सप्ताह 225 प्रिंट्स तैयार किए जाते हैं।

फिल्म प्रभाग एनएफडीसी तथा अन्य एजेंसियों के माध्यम से विदेशों में फिल्मों के व्यावसायिक वितरण की कोशिश करता है। इसके अलावा फिल्म प्रभाग स्टॉक शॉट्स, व्यावसायिक तथा गैर व्यावसायिक फिल्मों की बिक्री सरकार द्वारा तय दर पर करता है।

फिल्म प्रभाग की डॉक्यूमेंट्री तथा न्यूज मैगजीन की आपूर्ति विदेश मंत्रालय के विदेश स्थित मिशनों की आपूर्ति की जाती है जो सरकारी, अर्ध सरकारी तथा शैक्षिक संस्थाों को प्रदर्शन के लिए नि:शुल्क देते हैं। विदेश में गैर व्यावसायिक प्रयोग के लिए भी फिल्म प्रिंट्स की बिक्री होती है। कुछ डॉक्यूमेंट्री तथा न्यूज रील का विदेशों में रॉयल्टी आधार पर टीवी पर व्यावसायिक उपयोग फिल्म प्रभाग तथा नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कार्पोरेशन द्वारा किया गया।

लघु शीर्ष	**वास्तविक**	**प्रत्याशित प्रस्तावित आरई-2010-11**	**अनुमानित 2011-12 (प्रस्तावित)**
1. किराया	489.62	550.00	606.00
2. प्रिंट्स की बिक्री तथा स्टॉक शॉट्स	32.43.	24.25	27.00
3. अन्य प्राप्ति	33.86	14.00	15.00
कुल	**555.91**	**588.25**	**648.00**

* 1. सम्बद्ध राज्यों के हाई कोर्ट में दायर डब्ल्यू पीएस/डब्ल्यू एएस मामले के मद्देनजर वर्ष 1995-1999 के लिए बकाया क्लीचर नहीं किया गया है।

2. उ.प्र.,नई दिल्ली, पंजाब तथा मं.प्र. के 500 से अधिक सिनेमा हाउसों ने फिल्म प्रभाग से अनुमोदित फिल्में लेना बंद कर दिया है।

प्रशासनिक व्यय

(रुपये लाख में)

वास्तविक 2009-10			बजट अनुदान 2010-2011			प्रस्तावित संशोधित अनुमान 2010-2011			बजट अनुदान 2011-2012		
योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
0.00	460.87	**460.87**	0.00	494.00	**494.00**	0.00	487.45	**487.45**	0.00	501.17	**501.17**

विभिन्न राष्ट्रीय तथा अन्तराष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भागीदारी

	समारोहों की संख्या	**शामिल फिल्मों की संख्या**
राज्य फिल्म समारोह तथा राष्ट्रीय फिल्म समारोह	- 11	- 44
अन्तराष्ट्रीय फिल्म समारोह	01	02
कुल	**12**	**46**

भारत और विदेशों में आयोजित फिल्म बाजारों में भागीदारी

फिल्म स्कन्ध में दो मुख्य सचिवालय योजना कार्यक्रम हैं, यानी (i) विदेशी समारोह/बाजारों में भागीदारी और (ii) एनीमेशन गेमिंग और विशेष प्रभावों के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना। वर्ष 2008-09 के दौरान उपर्युक्त दोनों योजनाओं का कार्य निष्पादन इस प्रकार रहा :-

(i) **विदेशी समारोह/बाजारों में भागीदारी :** यह योजना एसएफसी द्वारा 2007 में मंजूर की गयी थी। इसका उद्देश्य फिल्म उद्योग द्वारा स्वंय निर्यात संवर्द्धन के उपाय करने में समर्थ होने अथवा इस निर्णय को देखते हुए कि कुछ बाजारों का लाभकारी दोहन नहीं किया जा सकता, उसकी सहायता करना है। वास्तव में फिल्म बाजारों में फिल्म उद्योग की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने पर खर्च करने की आवश्यकता है।

फिल्म बाजारों में भागीदार का प्रयोजन भारतीय फिल्म उद्योग को उजागर करना है, और साथ ही फिल्मों से संबद्ध सूचना प्रौद्योगिकी हासिल करना है ताकि वास्तविक व्यापार में संलग्न होने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सके। विश्व में केंस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह और बाजार, बर्लिन फिल्म समारोह और अमरीकी फिल्म समारोह आदि प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म बाजार हैं। सरकार का प्रयास है कि भारत में फिल्म बाजार के आयोजन सहित भारतीय फिल्म उद्योग को प्रोत्साहन का प्रत्येक अवसर प्रदान किया जाए।

हालांकि जो वास्तविक लक्ष्य किए गए उन्हें प्राप्त कर लिया गया है। किन्तु प्रोद्भूत लाभों की मात्रा निश्चित नहीं की जा सकती। फिर भी, उद्योग की संगत और बढ़ती हुई वृद्धि तथा विदेशी बाजारों में भारतीय फिल्म निर्माताओं की बढ़ती हुई भागीदारी इसके लाभों को दर्शाती है। वर्ष 2009-10 और वर्ष 2010-11 के दौरान उपर्युक्त स्कीमों के लिए जारी की गई राशि इस प्रकार है :

(लाख रुपये में)

बजट अनुमान 2009-10	संशोधित बजट/अंतिम अनुदान 2009-10	जारी की गई राशि
220.00	220.00	205.00

बजट अनुमान 2010-11	संशोधित बजट/अंतिम अनुदान 2010-11	जारी की गई राशि (दिसम्बर 2010 तक)

भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे

वर्ष 2010-11 के दौरान संस्थान में विभिन्न पाठ्क्रमों के लिए 158 छात्रों ने पंजीकरण कराया जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :

क्रम संख्या	पाठ्यक्रम का नाम	छात्रों की संख्या
1.	फिल्म एवं टी.वी. में तीन वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम	55
2.	टी.वी. में एक वर्षीय स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	44
3.	अभिनय में दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा	21
4.	फीचर फिल्मों में पटकथा लेखन में एक वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	13
5.	कला निर्देशन एवं प्रोडक्शन डिजाइन में दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम	09
6.	एनीमेशन तथा कम्प्यूटर ग्राफिक्स में डेढ़ वर्षीय प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	14
	कुल	**156+2** **आईसीसीआर उम्मीदवार**

वर्ष 2009-10 के दौरान चलाए गए/प्रस्तावित अल्पकालीन पाठ्यक्रमों का ब्योरा इस प्रकार है :

(1) पहली अप्रैल, 2010 से 31 दिसंबर, 2010 के दौरान चलाए गए अल्पकालीन पाठ्यक्रम-

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	प्रतिभागियों की संख्या	अवधि
1.	दूरदर्शन के लिए 53वां टीवी प्रोडक्शन और तकनीकी आप्रेशन	24	05-07-2010 28-08-2010
2.	परमाणु उर्जा शिक्षा सोसायटी, मुंबई के लिए इटीवी निर्माण में प्रारंभिक पाठ्यक्रम	12	20-12-2010 31-12-2010

(2) पहली जनवरी, 2011 से 31 मार्च, 2011 तक प्रस्तावित अल्पकालीन पाठ्यक्रम–

क्र.सं.	**पाठ्यक्रम का नाम**	**प्रतिभागियों की संख्या**	**अवधि**
1.	53वां निर्माता और तकनीकी सहायता दूरदर्शन हेतु	24	05.07.2010–28.08.2010
2.	बुनियादी कोर्स इटीवी प्रोडक्शन, एटोमिक एनर्जी शिक्षण संस्थान, मुंबई	12	20.12.2010–31.12.2010

एचआरडी स्कीम के तहत 11वीं योजना के लिए निम्नलिखित गतिविधियां चलाई गईं:

1. विभिन्न कार्य क्षेत्रों में स्टाफ तथा संकाय के लिए प्रशिक्षण।
2. संस्थान की पत्रिका लेनसाइड का प्रकाशन तथा अन्य अनुसंधान संबंधी वित्त पोषित प्रकाशनों, आवधिकों आदि का प्रकाशन।
3. सेमिनारों, व्याख्यानों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा संबंधित पहलुओं पर खर्च हुआ।
4. संस्थान की पुस्तकालय के लिए मानव संसाधन संबंधी पुस्तकों की खरीद।
5. संस्थान के विभिन्न पाठ्यक्रमों संबंधी कार्यशालाओं के लिए विजिटिंग स्कॉलरों पर खर्च हुआ।
6. मेजिक फाउंटेन जैसी एजेंसियों से लाइब्रेरी के लिए डीवीडी विशेषकर वृत्तचित्र प्राप्त करना।
7. एफटीआईआई के स्वर्णजयंती वर्ष समारोह के 21 मार्च 2009 को हुए आयोजन के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करना (यह एजेंडा 14 नवंबर, 2008 को एफटीआई, पुणे की शासकीय परिषद की 11वीं बैठक में रखा गया और विधिवत संस्तुति ली गई)।

सभी विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। अतीत की तरह, हमारे विद्यार्थी तकनीकी क्षेत्रों और सौन्दर्यपरक अपील दोनो ही तरह से सिनेमा और मानक को बुलंदी पर पहुंचा रहे हैं।

भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे

योजना

(करोड़ रुपये में)

परिव्ययों और परिणामों/लक्ष्यों का विवरण (2011-12) (परिणाम बजट 2011-12 के अनुसार) तथा वास्तविक उपलब्धि

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2010-11 (अंतिम)	निर्धारणीय/वितरणीय	प्रक्रिया/ समयबद्धता	उपलब्धियां 31.03.2010 को डब्ल्यू.आर.एल कॉल (5)
1	2	3	4	5	6	7
(अ)	चालू योजनाएँ					
(i)	**संस्थान को अनुदान राशि**					
(i)	मशीनरी एवं उपकरण	(i) फिल्म तथा टीवी उद्योग दोनों में आधुनिक एवं तकनीकी प्रगति के अनुरूप पुराने एवं अप्रचलित उपकरणों के स्थान पर नये उपकरणों की खरीद और संसाधनों में वृद्धि। उच्च व्यवसायिक शिक्षा फिल्म निर्माण और टी निर्माण (ii) ओबीसी के लिए आरक्षण और छात्रों की संख्या बढ़ाई जाए। शिक्षा के लिए अधिक गतिविधि करना।	7.00	सामान प्राप्त हो गया है और मंत्रालय के एसएफसी के अनुमोदन के मुताबिक कार्य संपन्न कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष शुरू होने से पहले ही त्रैमासिक भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य तय कर दिए गए हैं और उपलब्धि की नजदीकी से विभागीय बैठकों, मासिक व्यय रिपोर्टों और मंत्रालय के अर्द्धवार्षिक निष्पादन के माध्यम से निगरानी की जाती है।	(1) उपयोगकर्ता विभाग से इंडेंट प्राप्ति (2) जब भी आवश्यक हो समाचार पत्रों में टेंडर प्रकाशन के लिए कोटेशन मंगाना (3) विशिष्ट अवधि के बाद कोटेशनों/टेंडरों को खोलना तथा जांचना (5) आपूर्ति/खरीद/ निष्पादन आदेश देना (6) उपयोगकर्ता विभाग द्वारा सामग्री/ सामान का निरीक्षण (7) मात्रा/ गुणवत्ता इत्यादि के लिए सामानों की जांच रिपोर्ट/खरीद आदेश में उपरकण का प्रदर्शन और अन्य शर्तों की जांच। विभागीय बैठकों में समयबद्धता पर विचार किया जाता है और त्रैमासिक भौतिक और वित्तीय लक्ष्य सुनिश्चित करने के लिए संबंधित कार्य योजना की तिथि बताई जाती है।	6.90

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2010-11	निर्धारणीय/वितरणीय भौतिक परिव्यय	प्रक्रिया/ समयबद्धता	उपलब्धियां 31.03.2010 को डब्ल्यू.आर.एल कॉल (5)
1	2	3	4	5	6	7
		(iii) नई तकनीकों जैसे हाई डेफिनेशन टी.वी., विकसित कंप्यूटर एनिमेशन, डिजिटल फिल्म रिकार्डिंग आदि का समावेश।			प्रक्रिया (i) विभाग द्वारा इंडेंट की रसीद (ii), आवश्यकता-नुसार समाचारपत्रों में निविदाओं के प्रकाशन हेतु कोटेशन मंगवाना, (iii) निश्चित अवधि के पश्चात कोटेशन/ निविदाओं को खोलना तथा उनकी जांच, (iv) वित्तीय संस्तुति लेना, (v) आपूर्ति/ खरीद/ प्रदर्शन आदेश देना, (vi) प्रयोक्ता विभाग द्वारा सामग्री का निरीक्षण, (vii) मात्रा/ गुणवत्ता के आधार पर सामग्री के निरीक्षण की रिपोर्ट, उपकरण का प्रदर्शन तथा अन्य शर्तों को खरीद आर्डर में निर्दिष्ट करना। विभागीय बैठकों में समयबद्धता पर विचार किया जाता है तथा अर्द्धवार्षिक भौतिक तथा वित्तीय लक्ष्य सुनिश्चित करने के लिए संबंधित कार्ययोजना की तिथि बताई जाती है।	

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2010-11	निर्धारणीय/वितरणीय भौतिक परिव्यय	प्रक्रिया/ समयबद्धता	उपलब्धियां 31.03.2010 को डब्ल्यू.आर.एल कॉल (5)
(ii)	भवन निर्माण	छात्रों के रहने तथा कार्यक्रमों के लिए वर्तमान में स्थान की कमी है। वर्तमान योजना 100 कमरों के छात्रावास निर्माण की है। एक आधुनिक संसाधन तथा ज्ञान केंद्र की याजेना भी है। एफटीआईआई के स्वर्ण जयंती वर्ष समारोह के आयोजन तथा ढांचागत विकास के लिए अतिरिक्त आवश्यकता है।	0.95			1.13
(iii)	कम्प्यूटरीकरण तथा आधुनिकीकरण		0.25			0.25
(iv)	सामुदायिक रेडियो की स्थापना	विद्यार्थियों को रेडियो प्रोग्रामिंग के क्षेत्र में शोध तथा प्रशिक्षण उपलब्ध कराना	0.05			0.05
(v)	कैप्टिव टीवी चैनल की स्थापना		0.10			0.10

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2010-11	निर्धारणीय/वितरणीय भौतिक परिव्यय	प्रक्षिप्त परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम घटक
(vi)	एच.आर.डी पक्ष जिसमें छात्रों के लिए छात्रवृति तथा विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ कार्यक्रमों का आदान-प्रदान शामिल है।		1.00	आदान-प्रदान कार्यक्रम की गतिविधि से छात्र अपने क्षेत्र से बाहर निकलकर, फिल्म स्कूलों से मिलकर फिल्म निर्माण के नये विचार प्राप्त करेंगे ताकि अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में आधुनिक तकनीक से परिचित हों। एफटीआईआई की योजना है कि भारत के विश्वविद्यालयों एवं फिल्म स्कूलों के साथ-साथ देश में अपनी गतिविधि बढ़ाएं। संकाय/स्टाफ का प्रशिक्षण, प्रशिक्षण से संबंधित पत्रिका जैसे लेनसाईट का प्रकाशन खरीद, सेमिनार, लेक्चर, सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि का आयोजन, एचआरडी संबंधी पुस्तकों की खरीद तथा लाइब्रेरी के लिए डीवीडी की खरीद। संस्थान के स्वर्ण जयंती महोत्सव के लिए विभिन्न फिल्म महोत्सव सेमिनार का आयोजन		0.92	
		कुल : (क)	**9.35**			**9.35**	
(ए)	नई स्कीम ग्लोबल फिल्म स्कूल		**9.35**			**9.35**	

सत्यजित रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता

गैर योजना

वर्ष 2008 के दौरान शैक्षिक सत्र, 2008–11 के लिए त्रिवर्षीय पी जी डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए 40 छात्रों ने पंजीकरण करवाया। वर्तमान में अध्यनरत (प्रत्येक विशेषज्ञता क्षेत्र में 10) बैच सहित 112 छात्र हैं।

वर्तमान छात्रों का ब्यौरा बैच के अनुसार नीचे है :-

क्रमांक	विषय	2007–10		2008–11		2009–13		कुल	
		पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री
1.	निर्देशन	7	2	9	1	5	4	21	7
2.	सिनेमोटोग्राफी	10	0	8	2	9	1	27	3
3.	संपादन	7	3	7	3	6	4	20	10
4.	ऑडियोग्राफी	7	1	7	2	6	1	20	4
	कुल	31	6	31	8	26	10	88	24

योजना स्कीम

क्र. सं.	योजना स्कीम का नाम	2010–11 के दौरान वास्तविक प्रदर्शन (31.12.2010 तक)
1.	नए शैक्षिक विभाग का सृजन : फिल्म और टेलीविजन में निर्माण प्रबंधन	1. निर्माण के लिए बुनियादी योजना तैयार; कोलकाता नगर निगम से अनुमति मिलने के बाद तुरन्त सिविल निर्माण कार्य शुरू करेगा। 2. मंत्रालय द्वारा अनुमोदित भर्ती प्रक्रिया में पहल।
2.	नए शैक्षिक विभाग का सृजन : एनिमेशन और इलेक्ट्रॉनिक इमेजिंग	1. निर्माण के लिए बुनियादी योजना तैयार; कोलकाता नगर निगम से अनुमति मिलने के बाद तुरंत सिविल निर्माण कार्य शुरू करेगा। 2. मंत्रालय द्वारा अनुमोदित भर्ती प्रक्रिया शुरू।
3.	कंप्यूटरीकरण तथा आधुनिकीकरण	1. कुछ अति आधुनिक उपकरण खरीदकर लगाए गए। 2. ई–बिजनेस स्यूट का इस्तेमाल करते हुए ईआरपी के क्रियान्वयन के लिए सॉल्युशन डिजाइन पूर्ण, दूसरे चरण का क्रियान्वयन शुरू। 3. मंत्रालय द्वारा अनुमोदित 17 कर्मियों की भर्ती। 4. नए फिल्म स्टूडियो तथा फिल्म अभिलेखागार की डिजाइन तथा योजना तैयार करने के लिए जादवपुर विश्वविद्यालय के वास्तु विभाग द्वारा सौंपी गई स्थानीय निकाय से अनुमति के बाद निर्माण कार्य शुरू होगा।

क्र. सं.	योजना स्कीम का नाम	2008-09 के दौरान वास्तविक प्रदर्शन
4.	एचआरडी पहलू/छात्रवृत्ति/छात्र आदान प्रदान कार्यक्रम/इंटर्नशिप	1. 17 छात्रों को एसआरएफटीआई की मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान की गई। 2. एसआरएफटीआई के छात्र और शिक्षक ईडन वर्ग नैपियर यूनिवर्सिसिटी के साथ छात्रों के आदान-प्रदान कार्यक्रम के भग लिया। 3. एफटीआई फिल्म महोत्सव आयोजित 4. वार्ता विनियम जॉन जोश, सुप्रसिद्ध फिल्म निर्माता के साथ आयोजित किया गया।
5.	प्रशिक्षण और कौशल विभाग	1. कई छात्र फिल्मों के कार्य आरंभ और पूर्ण जैसे गायन, ड्रामा, शूट। 2. विभिन्न संगठनों द्वारा फिल्म और टेलीविजन संबंधी सेमिनार/कार्यशालाओं में संस्थान के कुछ संकाय सदस्यों ने हिस्सा लिया।
6.	एसआरएफटीआई में सामुदायिक रेडियो (सीआरएस) की स्थापना	1. सीआरएस का सफलतापूर्वक उदघाट्न तथा 90.4 मेगा हटर्ज फ्रीक्वेंसी पर प्रसारण 2. मई 2008 से नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं।
7.	एसआरएफटीआई में केप्टिव टीवी चैनल (सीटीवीसी) की स्थापना	1. बेसिल से उपकरण हासिल 2. एक सुविधा नामित अधिकारी द्वारा कार्यक्रम बनाने हेतु दी जाती है।

स्कीम वार भौतिक लक्ष्य और उपलब्धियां

(2009-10 और 2010-11)

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	वास्तविक लक्ष्य 2008-09	वास्तविक उपलब्धियां 2009-10	वास्तविक लक्ष्य 2010-11	31-12-2010 तक वास्तविक उपलब्धियां	कमी के कारण यदि कोई है
1.	**चालू योजना** अभिलेख फिल्मों की प्राप्ति एवं प्रदर्शन	1.76	6.99	5.00	8.90	5.08
	कुल	1.76	6.99	5.00	8.90	5.08
1.	**चालू योजना** अभिलेख फिल्मों की प्राप्ति एवं प्रदर्शन	600 फिल्में/डीवीडी, वीएचएस प्राप्त करना 151 फिल्मों का डिजिटाइजेशन, 50 फिल्मों और अनुषंगी फिल्म सामग्री का जीणोद्वार करना	939 फिल्में/डीवीडी प्राप्त की, 148 फिल्में डिजिटाइज की, 48 फिल्मों का जीर्णोद्वार किया तथा 208539 अनुषंगी फिल्म सामग्री का जीर्णोद्वार किया	600 फिल्में/डीवीडी, वीएचएस प्राप्त करना, 300 फिल्मों का डिजिटाइज करना तथा 100 फिल्मों और अनुषंगी फिल्म सामग्री का जीर्णोद्वार करना	209 फिल्में/डीवीडी प्राप्त की, 127 फिल्में डिजिटाइज की तथा 137 फिल्में एवं 12,032 अनुषंगी सामग्री का जीर्णोद्वार किया	कोष की कमी के कारग

राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय का गैर प्लॉन व्यय में विद्युत डाक दूरभाष, कर्मचारी का वेतन और स्टोर और स्टेशनरी है गैर योजना के तहत बजट में हेड के अनुसार ब्यौरा

क्रं. सं	सह-हेड ब्यौरा	वास्तविक खर्च 2009-10	एस.बी.जी. 2010-11	आर.ई. 2010-11	वास्तविक व्यय दिसम्बर 2010 तक	बी.ई. 2011-12
1.	वेतन	146.11	140.00	160.00	115.38	180.00
2.	ओवरटाइम ब्लावन्स	0.10	0.10	0.10	0.10	0.15
3.	चिकित्सिय व्यय	2.37	5.00	3.50	1.32	5.00
4.	देशीय यात्रा भत्ता	3.42	3.00	3.00	1.95	4.00
5.	विदेशी यात्रा भत्ता	0.0	4.00	4.00	1.59	4.00
6.	दफ्तरीय व्यय	104.24	10000	110.00	76.41	172.00
7.	किराया, मूल्य और कर	0.08	2.50	5.00	4.46	3.00
8.	लघु कार्य	38.40	60.40	99.40	46.86	99.85
	कुल	**294.72**	**31500**	**38500**	**248.07**	**468.0**

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड

पूर्व निष्पादन समीक्षा

योजना स्कीमें

2010-11 के दौरान योजना स्कीम के संबंध में निष्पादन नीचे दिया गया है :

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	स्कीम का नाम	स्वीकृत परिव्यय 2010-11 के लिए		2010-11 के लिए उपलब्धियां	
		वित्तीय		वास्तविक	वित्तीय वास्तविक
			बीई		
1.	विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्म निर्माण	500.00	4 फिल्में	500.00	4 फिल्मों के प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं तथा कानूनी कार्यवाही चालू है जिसके बाद ही निर्माण शुरू होगा।
2.	फिल्मों का जीर्णोद्धार और डिजिटलीकरण	500.00	38 फिल्में	500.00	चालू वित्त वर्ष के दौरान 38 फिल्मों का जीर्णोद्धार किया जाना है
3.	पूंजी भागीदारी	300.00		300.00	निगम की इक्विटी पूंजी में 3 करोड़ रुपये पहले ही शामिल कर लिए गए हैं
	कुल	1300.00		1300.00	

पत्र सूचना कार्यालय

1. वर्ष 2010-11 के दौरान पहले 9 महीनों में योजना और गैर योजना प्रदर्शन

2. वर्ष 2009-10 के दौरान योजना एवं गैर-योजना प्रदर्शन

वार्षिक योजना 2009-2010

मार्च 2010 तक योजना व्यय विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	स्कीम परिव्यय		ऋण जारी एफ जी	वास्तविक व्यय 31.3.10 तक	उत्तर-पूर्व के क्षेत्र में परिव्यय 2009-10	31.3.2010 तक व्यय	कमी के कारण (यदि कोई हो)
		एसबीजी	आर.ई.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रेस केंद्र की स्थापना	5.00	4.00	4.00	4.00	जैसा कि नई दिल्ली में निर्माणाधीन भवन पूरे देश के लाभार्थ है, अतः उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए पृथक राशि नहीं रखी गई है		परियोजना स्कोप और लागत बढ़ने के चलते 60 करोड़ रुपये हो गई। तदनुसार, एक संशोधित ईएफसी मेमो नई स्वीकृति के लिए सू. और प्र. मंत्रालय भेजा गया था। सित.-अक्तू. 2009 में नया अनुमोदन प्राप्त किया गया. पिछले के स्थान पर एक नयी संविदा पर 22-03-10 को पीआईबी और एनबीसीसी के बीच हस्ताक्षर हुए। अग्रिम जमा के रूप में एनबीसीसी को मार्च 2010 में 4 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।
2.	मीडिया आउटरीच कार्यक्रम	9.50	9.50	8.30	7.75	0.95	0.93	15 वीं लोकसभा के चुनावों के कारण आचार संहिता लागू होने के चलते मई 2009 तक कोई पीआईसी नहीं हुआ। इसलिए मार्च 2010 तक 93 पीआईसी, 93 सफलता की कहानियां और 7 प्रेस दौरे आयोजित किए गए। यद्यपि व्यय की स्थिति संतोषजनक रही।

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	स्कीम परिव्यय		ऋण जारी एफ जी	वास्तविक व्यय 31.3.09 तक	उत्तर-पूर्व के क्षेत्र में परिव्यय (08/09	31.3.2009 तक व्यय	कमी के कारण (यदि कोई हो)
		एसबीजी	आर.ई.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	**विशेष कार्यक्रमों का प्रचार** इस योजना में तीन उप-स्कीमें शामिल हैं:							राज्य में शोक की स्थिति के चलते कुछ प्रमुख कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सके, इसलिए केवल 1.30 लाख रुपए व्यय किए गए।
क.	भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह	0.075	0.075	0.05	0.0677	शून्य	शून्य	
ख.	प्रवासी भारतीय दिवस समारोह	0.018	0.018	--	-- --	शून्य	शून्य	चूंकि पीबीडी, नई दिल्ली में आयोजित हुआ अतः किसी फंड की आवश्यकता नहीं हुई और अंतिम अनुदान स्थिति में फंड लौटाया दिया गया।
ग.	मीडिया आदान-प्रदान कार्यक्रम	0.4369	0.4369	0.044	--	0.044	शून्य	इस मद को लागू करना अन्य देशों पर निर्भर करता है। अन्य देशों से कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर कोई सीईपी आयोजित नहीं हुआ।
4.	राष्ट्रमंडल खेल 2010 हेतु मीडिया प्रबंधन और सुविधाओं हेतु प्रस्ताव	10.00	10.00	10.00	9.77	चूंकि खेल पुणे और दिल्ली में आयोजित हुए, अतः उत्तर-पूर्व के लिए प्रथक राशि वहीं रखी गई है।		लघु कारण
	कुल	**25.03**	**24.03**	**22.39**	**21.59**	**0.95**	**0.93**	

दिसम्बर 2010 तक योजना व्यय विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	स्कीम परिव्यय				उत्तर पूर्व परिव्यय 2010-11	31-12-2010 तक व्यय	कमी के कारण (यदि कोई हो)
		एसबीजी	संशोधित परिव्यय	अंतिम अनुदान	वास्तविक व्यय 31.12.10 तक			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रेस केंद्र की स्थापना	10.00	10.00		शून्य	चूंकि नई दिल्ली की इमारत पूरे देश के लाभ के लिए है एनई क्षेत्र के लिए कोई फंड निर्दिष्ट नहीं किया गया है		वर्षा के कारण 6 माह पिछड़ गया। अगस्त 2010 में कार्य शुरु हुआ और 31-12-2010 तक खुदाई, पीसीसी, आरसीसी आदि कार्य 31-12-2010 तक पूर्ण हुआ।
2.	मीडिया आउटरीच कार्यक्रम	14.50	14.00		6.14	2.00	0.90	विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा पीआईसी के लिए अग्रिम भुगतान हासिल किया। 31-12-2010 तक 79 पीआईसी आयोजित किए जा चुके थे।
3.	**विशेष कार्यक्रमों का प्रचार** इस स्कीम के निम्नलिखित तीन हिस्से हैं :							राज्य में शोक अवधि के कारण कुछ प्रमुख कार्यक्रम आयोजित नहीं हो सके और इसलिए केवल 1.30 लाख रुपये खर्च किए गए।
	1. भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह	0.08	0.08		0.060	शून्य	—	6.09 लाख रुपये इफ्फी पर व्यय किए गए
	2. प्रवासी भारतीय दिवस समारोह	0.0125	0.0125		—	शून्य	—	चूंकि इसका आयोजन जनवरी में किया जाएगा अत: उसी दौरान फंड का इस्तेमाल किया जाएगा।
	3. मीडिया आदान-प्रदान कार्यक्रम	0.1575	0.1575		—	शून्य	—	इस हिस्से का क्रियान्वयन अन्य देशों पर निर्भर करता है।
4.	पुणे के राष्ट्रमंडल युवा खेल 2008, तथा दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल 2010 के लिए मुख्य मीडिया केंद्र तथा अन्य मीडिया केंद्र	21.75	21.75		19.87	पुणे और दिल्ली में खेल आयोजित होने के कारण एनई क्षेत्र के लिए कोई फंड निर्दिष्ट नहीं किया गया।		—
	कुल	**46.50**	**46.00**	-	**26.07**	**2.00**	**0.90**	

भारतीय प्रेस परिषद

निष्पादित कार्यों की समीक्षा

भारतीय प्रेस परिषद एक अर्धन्यायिक संस्था है। प्रेस के लिए यह नियमक संस्था है। यह प्रेसके लिए मानकों को तय करती है। कहने का तात्पर्य है कि प्रेस परिषद के परामर्शदायी तथा नियामक उत्तरदायित्व भी हैं। परिषद को प्रेस के खिलाफ जो भी शिकायतें मिलीं, उनका निपटारा इसने किया। निपटारे के पहले परिषद शिकायतों कीविधिवत जांच करती है, उसके बाद ही कोई फैसला देती है।

परिषद ने पूरे वर्ष देश के विभिन्न हिस्सों में वाद-विवाद आयोजित किए। इनमें विविध विषयों पर स्वस्थ चर्चा हुई तथा प्रेस की स्वतंत्रता तथा प्रेस की कार्यप्रणाली को लेकर कई तथ्य सामने आए। मौजूदा दौर में प्रेस की भूमिका बढ़ती जा रही है। प्रेस का नैतिक दायित्व महत्वपूर्ण तो है ही, साथ ही प्रेस युवाओं को शिक्षित करने का भी दायित्व निभा रहा है। इसके लिए पत्रकारिता मानदण्डों का ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि देश के युवाओं को जैसी सीख मीडिया से मिलेगी, वैसा ही देश, समाज तथा मानवताका विकास होगा। प्रेस परिषद मीडिया के इन कार्यों पर निगरानी रखती है।

इस वर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस मीडिया कार्पोरेट की दुनिया : चुनौतियां तथा अवसर के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर एक स्मारिका का भी विमोचन किया गया जिसमें पत्रकारिता के मूल्यों से संम्बद्ध आलेख संग्रहीत हैं। स्मारिका हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित हुई।

परामर्शदायी नियामक के रूप में संस्था ने सरकार तथा अन्य प्राधिकारों को अपने विचारों से अवगत कराया।

परिषद ने जिन मुद्दों पर अपने विचारों से अन्य संस्थाओं को अवगत कराया, वे हैं -

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई से 23.2.2009 को यूरोपीयन लॉटरी गिल्ड के प्रकाशित एक विज्ञापन के संबंध में प्राप्त परिपत्र।

2. अतिरिक्त आर्थिक सलाहकार, एम आई बी (पी एम एस) से 16.4.2010 को प्राप्त परिपत्र। यह डिलीवरी लाभ से सम्बद्ध था।

3. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा अग्रसहति 27.4.2010 का परिपत्र जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय से सम्बद्ध था। यह परिपत्र अंतरराष्ट्रीय दशक सांस्कृतिक शांति तथा बच्चों के खिलाफ अहिंसा से संबद्ध था।

4. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का 8.7.2010 का प्राप्त परिपत्र जो पूर्वोत्तर राज्यों में प्रेस परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रमों तथा आलेखों से संबद्ध था।

5. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा अग्रसारित 13.7.2010 का परिपत्र। इसके साथ एक याचिका (सं. 5367 एमआईबीपीआईएच वर्ष 2010) की भी कॉपी थी जो भारतीय जन कल्याण पार्टी बनाम भारत संघ तथा अन्य से संबद्ध मानवीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में दायर की गई थी।

6. सूचना एवंप्रसारण मंत्रालय द्वारा अग्रसारित दिनांक 26.2.10) जो श्रीमती किरण माहेश्वरीविधायक द्वारा भेजागया। इसमें प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित प्रसारित विज्ञापनों पर रोक की बात कही गई थी।

7. सूना एवं प्रसारण मंत्रालय से 12.5.2010 का प्राप्त जो यूनेस्को के ड्राफ्ट कार्यक्रम और बजट 2012-2013 की तैयारी की प्रश्नावली से सम्बद्ध था।

8. केंद्रीय ट्रिब्यूनल प्रभाग के गठन को लेकर कानून एवंन्याय मंत्रालय (न्याय विभाग) का कैबिनेट नोट।

9. भारत के कानून आयोग से प्राप्त परिपत्र जिसमें भारतीय प्रेस परिषद से स्टिंग आपरेशन पर उसके विचार मांगे गए थे।

पेड न्यूज

पेड न्यूज पर रिपोर्ट

मीडिया में पेड न्यूज एक गंभीर चुनौती बनती जा रही है। आम चुनाव, 2009 में पेड न्यूज की प्रवृत्ति देखने को मिली। यह प्रवृत्ति कोई तंत्र के लिए घातक है।प्रेस परिषद ने इसे संज्ञान में लिया है ताकि इस पर रोक लगाई जा सके। पेड न्यूज की समीक्षा के लिएएक कमेटी ने रिपोर्ट भी तैयार की गई जो 30 जुलाई 2010 को प्राप्त हुई। उस रिपोर्ट में पेड न्यूज के बारे में बताया गया कि कोई भी न्यूज जो प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रानिक मीडिया में छपे, पैसा या कुछ अन्य लेकर छपी हो, वह पेड न्यूज है।

परिषद ने इन विषयों को भी संज्ञान में लिया –

1. जम्मू और कश्मीर में मीडिया से जुड़े लोगों के कार्यों में भी सशस्त्र सेनाओं द्वारा बाधा डालने पर तत्काल कार्रवाई। जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि समाचार पत्रों के खिलाफ उनके कार्य में बाधा डालने वाली कोई कार्रवाई नहीं होगी।

2. द हिंदू के प्रमुख न्यूज फोटोग्राफर तथा मंगलम के रिपोर्टर के खिलाफ पुलिस कार्यवाही। इस मामले पर भी परिषद ने तत्काल कार्रवाई की तथा यह मामला विचाराधीन है।

अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रियता

भारतीय प्रेस परिषद विश्वके कई देशों की प्रेस परिषद से संवाद बनाए रखती है ताकि विश्व स्तर पर मीडिया की स्वतंत्रता तथा मीडिया के मानकों को व्यापक तौर पर मीडिया से जोड़ा जा सके। काठमांडू में 23–27 अक्तूबर, 2010 तक वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ प्रेस कौसिल्स की एक बैठक हुई जिसमें भारतीय प्रेस परिषद ने भी हिस्सा लिया। इसकी मेजवानी नेपाल प्रेस कौंसिल ने की। इस बैठक में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की आजादी तथा उसके दायित्व आदि विषयं पर विचार–विमर्श हुआ।

25.1.2010 को भारतीय प्रेस परिषद तथात इंडोनेशियाई प्रेस परिषद के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। दोनों परिषदों ने सूचना, अनुभव तथा ज्ञान के आदान–प्रदान पर सहमति जदाई है। इसके साथ ही, अहिंसा, शांतिपूर्ण न्यूज व खोज, पत्रकारिता के मूल्यों को सुदृढ़ बनाने तथा समाज व अन्तर्राष्ट्रीय हितों के प्रति प्रतिबद्धता जताई है।

एक दिसम्बर को विश्व एड्स दिवस के पर भारतीय प्रेस परिषद ने सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च के सहयोग से एक कार्यशाला का आयोजन किया। यह कार्यशाला 2 दिसम्बर को आयोजित की गई जिसका विषय भारतीय प्रेस परिषद द्वारा रिपोर्टिंग के लिए एचआईवी एड्स गाइड से सम्बद्ध था।

मामलों का विवरण

क्र.सं	विवरण	2009-010	2010-11 अप्रैल से जनवरी 2011 तक	अप्रैल से मार्च 2012 (अनुमानित)
1.	लम्बित मामले	904	1173	
2.	दर्ज मामले	950	683	900
3.	परिषद द्वारा मामलों पर निर्णय	200	225	
4.	अध्यक्ष द्वारा निर्णय लिए जाने वाले मामले	481	801	
5.	31.03.2011 को लंबित मामले	1173	830*	

फोटो प्रभाग

लक्ष्य एवं कार्य निष्पादन 2009-10

वित्तीय *(लाख रुपये में)*

स्वीकृत बजट अनुदान			वास्तविक परिव्यय		
योजना	**गैर-योजना**	**कुल**	**योजना**	**गैर-योजना**	**कुल**
210.00	381.78	591.78	209.47	368.98	578.45

2010-11

(लाख रुपये में)

	योजना	गैर-योजना	कुल
स्वीकृत बजट अनुदान	253.00	335.00	609.00
संशोधित अनुदान	178.00	356.00	534.00
12/2010 तक वास्तविक परिव्यय	24.04	203.72	227.76

बजट अनुमान 2011-12 *(लाख रुपये में)*

योजना	गैर-योजना	योग
210.00	396.00	606.00

		20010-11		2011-12
क्र.सं.		**लक्ष्य**	**उपलब्धि**	**लक्ष्य**
1.	निर्धारित कार्य	5000	2300	3500
2.	श्वेत-श्याम प्रिंट एवं रंगीन प्रिंट	1,50,000	60,000	1,00,000
3.	वीआईपी प्रजेन्टेशन फोटो एलबम	150	227	200
4.	अंकीय तस्वीरों का इन-हाउस संग्रह	80,000	1,90,980	1,00,000

प्रकाशन विभाग

वित्तीय

(लाख रुपये में)

बजट आकलन 2009-10			वास्तविक व्यय 2010-11 (31.12.2010 तक)			बजट आकलन 2011-12		
योजना	गैर	कुल	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
28.62	2339.72	2368.34	शून्य	1708.06	1708.06	20.00	-	-

वास्तविक

	2009-10		2010-11		2011-12 (लक्ष्य)	
	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
पत्रिकाएं	20	20	20	20	20	–
पुस्तक	120	86	90	51 (फरवरी 2010 तक) (40 प्रकाशनाधीन)	90	–

4.2 नेट पर इंडिया 2011 और भारत 2011

प्रकाशन विभाग की वेबसाइट पर इंडिया 2011 और भारत 2011 के 2600 से भी अधिक पृष्ठों को ई-पीडीएफ फॉर्मेट में डिजीटलीकृत किया गया है। यह वेबसाइट है www.publicationsdivision.nic.in

4.3 अन्य सरकारी विभागों के साथ गठजोड़

विभाग डाक विभाग के साथ गठजोड़ की संभावना तलाश कर रहा है ताकि अपने नेटवर्क को बढ़ाकर विभाग की पुस्तकें/पत्रिकाएं जनता को बेची जा सकें।

4.4 सार्वजनिक निजी भागीदारी

प्रकाशन विभाग की किताबों को बेचने के लिए शीर्ष पुस्तक विक्रेताओं/प्रकाशकों को शामिल करके सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। विभाग

में मानव श्रम कम होने के कारण पांडुलिपि, प्रूफ रीडिंग, अनुवाद इत्यादि से संबंधित कार्य बाहर से करवाए जा रहे हैं। स्वचलन से संपूर्ण प्रक्रिया में ज्यादा पारदर्शिता आएगी और माऊस को क्लिक करके सारी सूचना प्राप्त की जा सकेगी। प्रकाशन विभाग की वेबसाइट www.publicationsdivision.nic.in के माध्यम से निविदा संबंधी सभी पूछताछ को इंटरनेट पर डाला जा रहा है।

4.4 प्रकाशन विभाग ने वर्ष 2011-12 में योजना के तहत निम्नलिखित गतिविधियों के लिए प्रस्ताव दिया है।

(लाख रुपये में)

घटक का नाम	प्रस्तावित राशि
स्टॉक, सूची और बिक्री प्रबंधन प्रणाली का आधुनिकीकरण	1190.10
कुल	**119.10**

वितरण और बिक्री को बढ़ावा :

प्रकाशन विभाग की पुस्तकें बिक्री केन्द्रों/आउटलेटों, पुस्तक प्रदर्शनियों और 470 से भी अधिक एजेंटों के नेटवर्क के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचती हैं। ये बिक्री केन्द्र नई दिल्ली, मुम्बई, हैदराबाद, कोलकता, लखनऊ, चेन्नई, पटना और तिरुवनंतपुरम में स्थित हैं। बंगलुरु और गुवाहाटी में योजना कार्यालय में भी बिक्री के आउटलेट हैं।

प्रकाशन विभाग ने अप्रैल 2010 से दिसंबर 2010 तक पुस्तक प्रदर्शनियों/मेलों में जो आयोजन किया या भागीदारी की उसका विवरण नीचे दिया गया है:-

क्रम संख्या	अवसर	आयोजन स्थल	आयोजित करने वाली इकाई	अवधि
1.	महात्मा सांस्कृतिक महोत्सव के अवसर पर पुस्तक प्रदर्शनी	तिरुवनंतपुरम	एसई, टीवीएम	21.5.2010 से 23.5.2010 तक
2.	राष्ट्रीय पुस्तक मेला	कोटा (राजस्थान)	मुख्यालय	4.9.2010 से 12.9.2010 तक
3.	8वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला-2010	लखनऊ	एसई, लखनऊ	1.10.2010 से 10.10.2010 तक
4.	फैजाबाद पुस्तक मेला	फैजाबाद (उप्र)	एसई, लखनऊ	20.10.2010 से 24.10.2010 तक
5.	7वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला-2010	कानपुर	एसई, लखनऊ	23.10.2010 से 24.10.2010 तक
6.	बनारस पुस्तक मेला-2010	वाराणसी	एसई लखनऊ	14.11.2010 से 21.11.2010 तक

क्रम संख्या	अवसर	आयोजन स्थल	आयोजित करने वाली इकाई	अवधि
7.	खम्मम पुस्तक मेला-2010	खम्मम	एसई हैदराबाद	14.11.2010 से 21.11.2010 तक
8.	14वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला	कोचि	एसई त्रिवेंद्रम	27.11.2010 से 6.12.2010 तक
9.	25वां हैदराबाद पुस्तक मेला	हैदराबाद	एसई हैदराबाद	16.12.2010 से 26.12.2010 तक
10.	दिल्ली पुस्तक मेला	प्रगति मैदान (नई दिल्ली)	मुख्यालय	25.12.2010 से 2.1.2011 तक
11.	पटना पुस्तक मेला	पटना	एसई पटना	10.12.2010 से 21.12.2010 तक
12.	राष्ट्रीय पुस्तक मेला	जयपुर	मुख्यालय	11.12.2010 से 19.12.2010 तक
13.	दिल्ली पुस्तक मेला	प्रगति मैदान (नई दिल्ली)	नई दिल्ली मुख्यालय	25.12.2010 से 2.1.2011 तक

प्रकाशन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान निम्नलिखित पुस्तक प्रदर्शनियों/मेलों को आयोजित करने या इसमें भाग लेने की योजना बनाई है :

1.	22वां विजयवाड़ा पुस्तक मेला-2011	विजयवाड़ा (आंप्र)	एसई, हैदराबाद	1.1.2011 से 11.1.2011 तक
2.	चेन्नई पुस्तक मेला-2011	चेन्नई	एसई, चेन्नई	4.1.2011 से 17.1.2011 तक
3.	तीसरा राष्ट्रीय पुस्तक मेला-2011	इलाहाबाद	एसई. लखनऊ	14.1.2011 से 23.1.2011 तक
4.	राष्ट्रीय पुस्तक मेला	ग्वालियर	मुख्यालय	15.1.2011 से 23.1.2011 तक
5.	कोलकाता पुस्तक मेला-2011	कोलकाता	एसई, कोलकाता	26.1.2011 से 6.1.2011 तक

इसके अतिरिक्त प्रकाशन विभाग ने अप्रैल 2010 से नवंबर 2011 तक जन सूचना अभियानों के अवसर व पुस्तक प्रदर्शनियों को भी आयोजित किया था:

1.	जन सूचना अभियान के अवसर पर पुस्तक प्रदर्शनी	गुडालुर, नीलगिरी डि. (तमिलनाडु)	एस ई, चेन्नई	16.6.2010 से 20.6.2010 तक
2.	जन सूचना अभियान के अवसर पर पुस्तक प्रदर्शनी	मनमादुरई (तामिलनाडु)	एस ई, मुम्बई	29.7.2010 से 31.7.2010
3.	जन सूचना अभियान के अवसर पर पुस्तक प्रदर्शनी	परामकुड़ी, रमनाड	एस ई, चेन्नई	7.8.2010 से 9.8.2010

क्रम संख्या	अवसर	आयोजन स्थल	आयोजित करने वाली इकाई	अवधि
4.	जन सूचना अभियान के अवसर पर पुस्तक प्रदर्शनी	टिहरी–उन–सौन, जिला रोहतास (बिहार)	एस ई, पटना	19.8.2010 से 21.8.2010
5.	जन सूचना अभियान के अवसर पर पुस्तक प्रदर्शनी	तेनीटाउन (तामिलनाडु)	एस ई, चेन्नई	21.8.2010 से 23.8.2010
6.	जन सूचना अभियान के अवसर पर पुस्तक प्रदर्शनी	पलानी, जि. डिंडीगुल (तामिलनाडु)	एस ई, चेन्नई	2.9.2010 से 4.9.2010
7.	जन सूचना अभियान के अवसर पर पुस्तक प्रदर्शनी	तिरुपुर (तामिलनाडु)	एस ई, चेन्नई	3.12.2010 से 5.12.2010
8.	जन सूचना अभियान के अवसर पर पुस्तक प्रदर्शनी	बाराबंकी (उत्तर प्रदेश)	एस ई, लखनऊ	11.12.2010 से 13.12.2010
9.	जन सूचना अभियान के अवसर पर पुस्तक प्रदर्शनी	तिरुपतुर (तमिलनाडु)	एस ई, चेन्नई	21.12.2010 से 23.12.2010

प्रकाशन विभाग ने जनवरी 2010 तक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनाओं पर अपने कुछ बिक्री आउटलेटों पर पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया जिनका उल्लेख नीचे किया गया है:–

1.	विश्व पुस्तक दिवस पुस्तक प्रदर्शनी	19.4.2010 से 30.4.2010	इसके 10 ब्रिक्री आउटलेट में
2.	ग्रीष्म पुस्तक प्रदर्शनी	14.6.2010 से 25.6.2010	इसके 10 ब्रिक्री आउटलेट में
3.	स्वतंत्रता दिवस पुस्तक प्रदर्शनी	9.8.2010 से 20.8.2010	इसके 10 ब्रिक्री आउटलेट में
4.	शिक्षक दिवस पुस्तक प्रदर्शनी	30.8.2010 से 9.9.2010	इसके 10 ब्रिक्री आउटलेट में
5.	हिन्दी पखवाड़ा पुस्तक प्रदर्शनी	13.9.2010 से 24.9.2010	इसके 10 ब्रिक्री आउटलेट में
6.	गांधी जयंती पुस्त्क प्रदर्शनी	1.10.2010 से 12.10.2010	इसके 10 ब्रिक्री आउटलेट में
7.	राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह पर पुस्तक प्रदर्शनी	8.11.2010 से 190.11.2010	इसके 10 ब्रिक्री आउटलेट में
8.	क्रिसमस तथा नव वर्ष पुस्तक प्रदर्शनी	22.12.2010 से 07.01.2011	इसके 10 ब्रिक्री आउटलेट में

प्रकाशन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनाओं पर अपने बिक्री केन्द्रों काउंटरों पर स्वस्थानीय पुस्तक प्रदर्शनियों को आयोजित करने की भी योजना बनाई है :

1.	गणतंत्र दिवस पुस्तक प्रदर्शनी	22.01.2011 से 04.02.2011	इसके 10 ब्रिक्री आउटलेट में
2.	उपभोक्ता अधिकार दिवस पुस्तक प्रदर्शनी	12.03.2011 से 23.03.2011	इसके 10 ब्रिक्री आउटलेट में

राजस्थान, तामिलनाडु राज्य सरकारों से प्राप्त आर्डरों को भी पूरा किया है। आर्डर प्राप्त करने के लिए राजा राममोहनराय लाइब्रेरी फाउंडेशन स्कीम, कोलकता के तहत राजस्थान तथा उ. प्र. ने बड़ी मात्रा में खरीद के लिए प्रकाशन विभाग ने आवेदन किया है।

प्रकाशन विभाग को अप्रैल 2010 से दिसंबर 2010 तक पुस्तकों, पत्रिकाओं की बिक्री और विज्ञापनों के माध्यम से (रोजगार समाचार को छोड़कर) 332.15 लाख रुपये की कुल आमदनी हुई।

अपने प्रकाशनों और पत्रिकाओं के अलावा प्रकाशन विभाग अन्य सरकारी विभागों, राज्य सरकारों और नेशनल बुक ट्रस्ट, साहित्य अकादमी, सी एस आई आर, आई सी ए आर, आई सी सी आर, लोकसभा सचिवालय और राज्यसभा सचिवालय जैसे स्वायत्त संगठनों द्वारा निकाले गए प्रकाशनों का विपणन भी संभालता है।

एम्प्लाइमेंट न्यूज/रोज़गार समाचार

2009–10 के दौरान उपलब्धियां अत्यंत संतोषजनक रहीं क्योंकि एम्प्लाइमेंट न्यूज को पूर्व वर्ष की तुलना में विज्ञापन से अधिक राजस्व तथा अधिक लाभ अर्जित हुआ। यह प्रवृत्ति मौजूदा वित्त वर्ष 2010–11 के दौरान भी बनी रही और 4700.00 लाख रुपये के राजस्व के लक्ष्य की तुलना में कुल 7157.01 लाख रुपये का राजस्व अर्जित हुआ। यह 4887.33 अरब रुपये का अधिशेष है। 2010–11 के दौरान एम्पलाइमेंट न्यूज/रोजगार समाचार ने 4025.99 लाख रुपये अर्जित किए हैं और लक्ष्य प्राप्ति के करीब है। यह लक्ष्य 4887.33 अरब रुपये की डीएवीपी तथा अन्य सरकारी विभागों से वसूली से प्राप्त हुआ है।

भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक

वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 (30.11.2010 तक) तथा 2011-12 के दौरान लक्ष्य और निष्पादन

वित्तीय

(लाख रुपये में)

गतिविधि का नाम	वर्ष	योजना	गैर-योजना	कुल
अनुमानित बजट	2009-10	17.00	384.00	401.00
वास्तविक बजट	2009-10	16.17	360.71	376.88
अनुमानित बजट	2010-11	17.00	359.00	376.00
संशोधित अनुमान	2010-11	17.00	377.00	394.00
अनुमानित बजट	2011-12	17.00	435.00	452.00

आरएनआई के सुदृढ़ीकरण के लिए 88.06 लाख रु. के व्यय के लिए योजना आयोग के तहत मंत्रालय द्वारा एक योजना स्कीम मंजूर की गई। वर्ष 2010-11 के लिए 17.00 लाख रु. की राशि निर्धारित की गई है।

भौतिक

क्र. सं.		2009-10		2010-11		2011-12
	कार्यक्रम/गतिविधियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां नवंबर 2010 तक	लक्ष्य
अ.	**गतिविधियां**					
1.	शीर्षक देने का कार्य (आवेदन)	***	22417	***	16085	***
2.	शीर्षकों को मुक्त करना	***	16054	***	5769	***
3.	पंजीकरण	***	5045 (4164-नये 881-संशोधित)	***	3028 (2583-नये 445-संशोधित)	***
4.	प्रसार के दावों की जांच	***	07	***	05	***
5.	प्रिंटिंग मशीनों के आयात के लिए आवश्यक प्रमाणपत्र जारी किए	***	02	***	0	***
6.	एफसीआरए,1976 के अंतर्गत समाचार पत्रों को जारी प्रमाणपत्रों की संख्या	***	07	***	02	***
7.	अखबारी कागज के आयात के लिए प्रकाशकों को जारी किये गये योग्यता प्रमाणपत्रों की संख्या	***	994	***	920	***
8.	सूचना के अधिकार के अन्तर्गत किये गये आवेदनों की संख्या	***	568	***	624	
ख.	**कार्यक्रम**					
9.	आरएनआई की वार्षिक रिपोर्ट (भारत के समाचार पत्र)	2008-09 रिपोर्ट	2008-09 रिपोर्ट	2009-10 रिपोर्ट	2009-10 रिपोर्ट	2010-11 रिपोर्ट

नोट : प्रकाशकों द्वारा प्राप्त किये गये आवेदनों पत्रों/आवेदनों पर आधारित इस श्रेणी में इस तरह का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा सकता।

भारत के समाचारपत्र पंजीयक का कार्यालय

वर्ष 2009–10 के संशोधित अनुमान के लिए योजनागत परिव्यय	:	17.00 लाख रुपये
वर्ष 2009–10 के लिए योजनागत कार्य/उपलब्धियां	:	16.17 लाख रुपये

2010–11 के लिए योजनागत परिव्यय

2010–11 के लिए स्वीकृत बजट सहायता	:	17.00 लाख रुपये
2010–11 के लिए संशोधित अनुमान	:	17.00 लाख रुपये
2011–12 के लिए बजट अनुमान	:	17.00 लाख रुपये
11वीं योजना के कार्यक्रमों का नाम		
कुल योजना परिव्यय	:	**88.06 लाख**

11वीं योजना स्कीम : आर एन आई का सुदृढ़ीकरण

वर्ष 2007–08 के दौरान 88.06 लाख रुपये के कुल परिव्यय के साथ स्वीकृत 11वीं योजना में आर एन आई में सुदृढ़ीकरण को शामिल किया गया। इसके अन्तर्गत आर एन आई के दो क्षेत्रिय कार्यालय एक गुवाहाटी में और एक भोपाल खोलने का प्रावधान रखा गया। वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के दौरान कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए 2007–08 की वार्षिक योजना में 5.88 लाख रुपये का प्रावधान किया गया। वर्ष 2008–09 के लिए स्वीकृत बजट सहायता में 20.00 लाख रुपये की मंजूरी दी गई और संशोधित अनुमान और अंतिम सहायता के लिए 15.00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया। 31.3.2009 तक व्यय में 14.69 लाख रुपये का प्रावधान किया गया। 2009–10 के स्वीकृत बजट सहायता में 17.00 लाख रुपये निर्धारित किये गये। वर्ष 2009–10 के वित्त वर्ष के दौरान 16.17 लाख रुपये निधार्रित किये गये।

पूर्वोत्तर क्षेत्र और मध्य क्षेत्र में समाचार पत्रों के प्रकाशकों की सुविधा के लिए गुवाहाटी और भोपाल में दो नये कार्यालय स्थापित करने की आवश्यकता महसूस की गई। योजना के पूरी तरह कार्यान्वित हो जाने के बाद से पंजीयन, शीर्षक के लिए प्रकाशकों द्वारा किये गये आवेदनों की संख्या, अखबारी कागज और प्रिंटिंग मशीनरी के आयात आदि के लिए कार्य सुविधाजनक हो जाएगा। नये क्षेत्रिय कार्यालय खोलने से इन क्षेत्रों के प्रकाशकों को पूछताछ के लिए मुख्यालय पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। संबंधित जानकारी वह इन क्षेत्रीय कार्यालयों से ही प्राप्त कर सकते हैं। इन क्षेत्रों के प्रकाशकों के आवेदन इन क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से ही मुख्यालय पहुंचेंगे।

वर्ष 2010–11 के लिए एसबीजी तथा पुनरीक्षित अनुभाग के तहत 17.00 लाख रु. निर्धारित है। वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए (31.12.2010 तक) व्यय के लिए 12.92 लाख रुपये प्राप्त हुए। भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय के लिए कार्यालय का स्थान का निर्धारण कर लिया गया है। आरएनआई भोपाल ने भवन को अपने अधीन ले लिया है।

गवेषणा, संदर्भ एवं प्रशिक्षण प्रभाग

(क) गतिविधि के आधार पर वर्गीकरण

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	गतिविधि वर्गीकरण	2009-10 के लिए वास्तविक			2010-11 के बजट अनुमान			संशोधित अनुमान 2010-11			बजट अनुमान 2011-12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
1.	गवेषणा, संदर्भ और प्रलेखन तथा प्रशिक्षण	11.93	182.31	194.24	25.00	197.00	222.00	10.00	189.00	199.00	25.00	217.00	242.00
		11.93	182.31	194.24	25.00	197.00	222.00	10.00	189.00	199.00	25.00	217.00	242.00

(ख) उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	गतिविधि वर्गीकरण	2009-10 के लिए वास्तविक			2010-11 के बजट अनुमान			संशोधित अनुमान 2010-11 प्रस्तावित			2011-12 के बजट अनुमान		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
1.	वेतन	-	155.00	155.00	-	160.60	160.60	-	150.35	150.35	-	175.00	175.00
2.	चिकित्सा	-	0.95	0.95	-	3.00	3.00	-	5.50	5.50	-	4.50	4.50
3.	ओवरटाइम भत्ता	-	-	-	-	0.40	0.40	-	0.25	0.25	-	0.40	0.40
4.	घरेलू यात्रा व्यय	-	0.55	0.55	-	1.50	01.50	-	1.50	1.50	-	1.50	1.50
5.	कार्यालय व्यय (ओ ई-आई आईएस प्रशिक्षण	11.93	25.15	37.08	25.00	28.00/	53.00	10.00	28.20	38.20	-	28.00	28.00
6.	अन्य प्रशासनिक व्यय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.00	-	25.00
7.	बैंकिंग कैश ट्रांजेक्शन टेक्स	-	0.00	0.00	-	0.10	0.10	-	0.00	0.00	-	-	-
8.	प्रशिक्षण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	सूचना प्रौद्योगिकी	-	0.66	0.66	-	3.40	3.40	-	3.40	3.40	-	7.60	7.60
	कुल जोड़	**11.93**	**182.31**	**194.24**	**25.00**	**197.00**	**222.00**	**10.00**	**189.00**	**199.00**	**25.00**	**217.00**	**242.00**

भौतिक निष्पादन के लिए परिणाम बजट (योजना) 2011-12

योजना का नाम	2009-10		2010-11		असमानता के कारण	2011-12
	लक्ष्य	**उपलब्धि**	**लक्ष्य**	**जनवरी 2011 तक उपलब्धि**		**लक्ष्य**
1. गवेषणा इकाई मास मीडिया में शोध।	अनुसंधान पत्र जारी करना	1	1		- लागू नहीं -	1
2. अ) संदर्भ इकाई लाइब्रेरी का आधुनिकीकरण करना।	50 बुक रैक, 1000 किताबें ई-बुक और आवधिक पत्रिकाएं खरीदना। पिछले वर्ष खरीदे गए आई टी उपकरण के लिए वार्षिक रखरखाव समझौता करना।	योजना स्कीम के तहत कोई पुस्तक नहीं खरीदी जा सकी	500 किताबें/ई-बुक, आवधिक पत्रिकाएं और पिछले वर्ष खरीदे गए आईटी उपकरण के लिए एएमसी खरीदना।	योजना स्कीम के तहत कोई पुस्तक नहीं खरीदी जा सकी	पुस्तकालय के लिए जगह की कमी।	500 पुस्तकें /ई-पुस्तकें, आवधिक पत्रिकाएं और पिछले वर्ष खरीदे गए आई टी उपकरण के लिए एएमसी खरीदना
2. ब संदर्भ इकाई राष्ट्रीय मीडिया पुरस्कार।	राष्ट्रीय मीडिया पुरस्कार चयन समिति का गठन करना, पुरस्कारों के लिए चयन करना, स्मृति चिह्न का डिजाइन कास्टिंग और गढ़ायी करना, पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित करना।	शून्य	राष्ट्रीय मीडिया पुरस्कार और चयन समिति का गठन करना, पुरस्कारों के लिए चयन करना, स्मृति चिह्न का डिजाइन कास्टिंग और गढ़ायी करना, पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित करना।	शून्य	योजना को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका।	इस स्कीम के तहत प्रभाग का दस विभिन्न शेणियों में अंग्रेजी और संविधान की 8 वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में 30 पुरस्कार तक देने का प्रस्ताव है।

**अध्ययन के लिए प्रतिबद्ध विधियां अर्थात 2009-10 के दौरान विश्वविद्यालय को प्रदान किया गया था, इसलिए पहले नौ महीनों के दौरान अधयनन को अंतिम रूप नहीं दिया गया। अध्ययन का दायरा सीमित करने के लिए निर्णय लिया गया है जिसके लिए वर्तमान में निधियां उपलबध हैं तथा इस निधि को अन्य अध्ययन के लिए उपयोग करने का निर्णय लिया गया है। अध्ययन का विषय शोध परामर्श समिति (आरएसी) द्वारा संस्तुत हो गया है। अध्ययन शीघ्र ही शुरु किया जाएगा।*

भौतिक निष्पादन के लिए परिणाम बजट (गैर योजना) 2011-12

वास्तविक उपलब्धि (गैर-योजना)

योजना का नाम	2009-10		2010-11		असमानता के कारण	2011-12
	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति जनवरी 2011 तक		लक्ष्य
1. एनडीसीएमसी आवर्ती सेवाओं द्वारा मास मीडिया की प्रवृत्तियों और घटनाओं की जानकारी एकत्रित करना, विश्लेषण करना और उनका प्रसार करना।	59	56	56	47	स्टाफ की कमी	56
मास मीडिया इन इंडिया वार्षिक प्रकाशन का संकलन एवं संपादन करना।	1	1	1	0	- लागू नहीं -	1
2- संदर्भ एकांश 'इंडिया-वार्षिक संदर्भ' ग्रंथ का संकलन एवं संपादन	1	1	1	1	- लागू नहीं -	1
'डायरी ऑफ इवेन्ट्स' पाक्षिक का प्रकाशन	24	24	24	20	- लागू नहीं -	24

गीत एवं नाटक प्रभाग

प्रभाग को स्थापना संचार उद्देश्यों के लिए प्रचुर लोक कला और पारंपरिक रूपों का दोहन करने के लिए लघु प्रायोगिक इकाई के रूप में 1954 में की गई थी। लाइव इंडिया जिसे अब इस नाम से व्यापक प्रसिद्धि हासिल है, बहुत प्रभावी सिद्ध हुआ है क्योंकि जनता से तत्काल संपर्क करने का लाभ इसमें निहित है तथा इसमें समकालिक मुद्दों, विचारों और समझाने की विधियों का लचीलापन है। इसलिए प्रभाग का कार्यक्षेत्र और आकार बढ़ाया गया ताकि इसे व्यापक पहुंच और सुगमता प्रदान की जा सके तथा दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, रेगिस्तानी और सीमा क्षेत्रों सहित वास्तविक धरातल पर संचार करने के इसके प्रयासों के प्रभाव को बढ़ाया जा सके।

प्रभाग का मुख्य कार्य (जैसा कि इसकी अधिकारिक वेबसाइट में बताया गया है) आम जनता में सामाजिक, आर्थिक और लोकतांत्रिक आदर्शों (जो राष्ट्र की प्रगति के लिए अनुकूल हों), के बारे में जागरूकता और भावनात्मक आत्मीयता पैदा करना, सीमा क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में रक्षा तैयारियों और शेष देश के साथ सांस्कृतिक एकता की भावना पैदा करना तथा सुदूर क्षेत्रों में तैनात सेना के जवानों का नैतिक बल लाइव मनोरंजन मीडिया (जिसमें शहरी थियेटर के रूप और देश के सभी क्षेत्रों की लोक कला शामिल है) के जरिए ऊंचा बनाए रखना है।

अपने उद्देश्यों को हासिल करने के लिए प्रभाग लोक तथा पारंपरिक नाटकों, नृत्य रूपकों, ओपेरा, नृत्य नाटकों, लोक एवं पारंपरिक काव्य, कठपुतली और सदियों पुरानी परंपरा के जादूगरों के सैंकड़ों कौशल जैसे व्यापक लोक एवं पारंपरिक रूपों का उपयोग करता है। इसके अतिरिक्त प्रभाग साम्प्रदायिक सामंजस्य, राष्ट्रीय एकता, धर्मनिरपेक्षता, सांस्कृतिक विरासत के संवर्द्धन, स्वास्थ्य, पर्यावरण, शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए आधुनिक तकनीकों और सैंकड़ों कलाकारों के साथ ध्वनि एवं प्रकाश साधनों का भी उपयोग करता है।

देश के विभिन्न भागों में उपलब्ध असंख्य लोक और पारंपरिक रूपों के इस्तेमाल के जरिए गीत एवं नाटक प्रभाग एक तरफ तो इन रूपों के जीर्णोद्धार और टिकाऊपन का महत्वपूर्ण स्रोत बन चुका है तथा दूसरी तरफ हजारों कलाकारों की अपनी भाषा, मुहावरों तथा सोद्देश्यपूर्ण और सार्थक संवाद के लिए उनकी बोलियों में उनके कौशल का उपयोग करके उनको आजीविका उपलब्ध कराने में सक्षम हुआ है।

ज्यादा पारदर्शित सुनिश्चित करने के लिए आधुनिकीकरण के शीर्ष के तहत कम्प्यूटरीकरण का प्रस्ताव है।

कार्यक्रमों की गुणवत्ता सुधारने के मद्देनजर शोध एवं विकास तथा प्रभाव आकलन कराया जाएगा।

प्रभाग को स्थापना संचार उद्देश्यों के लिए प्रचुर लोक कला और पारंपरिक रूपों का दोहन करने के लिए लघु प्रायोगिक इकाई के रूप में 1954 में की गई थी। लाइव इंडिया जिसे अब इस नाम से व्यापक प्रसिद्धि हासिल है, बहुत प्रभावी सिद्ध हुआ है क्योंकि जनता से तत्काल संपर्क करने का लाभ इसमें निहित है तथा इसमें समकालिक मुद्दों, विचारों और समझाने की विधियों का लचीलापन है। इसलिए प्रभाग का कार्यक्षेत्र और आकार बढ़ाया गया ताकि इसे व्यापक पहुंच और सुगमता प्रदान की जा सके तथा दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, रेगिस्तानी और सीमा क्षेत्रों सहित वास्तविक धरातल पर संचार करने के इसके प्रयासों के प्रभाव को बढ़ाया जा सके।

प्रभाग का मुख्य कार्य (जैसा कि इसकी अधिकारिक वेबसाइट में बताया गया है) आम जनता में सामाजिक, आर्थिक और लोकतांत्रिक आदर्शों (जो राष्ट्र को प्रगति के लिए अनुकूल हों), के बारे में जागरूकता और भावनात्मक आत्मीयता पैदा करना, सीमा क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में रक्षा तैयारियों और शेष देश के साथ सांस्कृतिक एकता की भावना पैदा करना तथा सुदूर क्षेत्रों में तैनात सेना के जवानों का नैतिक बल तथा सुदूर क्षेत्रों में तैनात सेना के जवानों का नैतिक बना लाइव मनोरंजन मीडिया (जिसमें शहरी थियेटर केरूप और देश के सभी क्षेत्रों की लोक कला शामिल है) के जरिए ऊंचा बनाए रखना है।

लोक कला और पारंपरिक मीडिया या ज्यादा प्रसिद्ध नाम से ज्ञात लाइव इंडिया का न सिर्फ भाषाई, भौगोलिक और सांस्कृतिक संबद्धता एवं पहचान के कारण बल्कि ग्रामीण भारत में वर्तमान सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में अत्यधिक प्रभावी हैं। यह बहुत फायदेमंद स्थिति भी है कि हमारे देश में लोककला और पारंपरिक रूपों का विशाल भंडार है

जिसके जरिए संदेशों, सूचना या जागरूकता इस ढंग से पैदा की जा सकती है कि जनता उसे तत्काल मान्यता प्रदान करे, प्राप्त करे और उसके अनुरूप क्रिया करे। यह राष्ट्रीय एकीकरण और सांप्रदायिक सामंजस्य, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में ग्रामीण जनता के सामान्य कल्याण और गरीबी उन्मूलन के लिए लक्षित विकास योजनाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

इसलिए लोककला और पारंपरिक मीडिया को विशेषरूप से ग्रामीण एवं अविद्युतीकृत तथा दुर्गम क्षेत्रों में आम आदमी के हित में विशेष रूप से गरीबों के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे विविध कार्यक्रमों के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए सभी मीडिया रणनीति का प्रभावी और एकीकृत घटक के रूप में उपयोग जारी रहेगा।

विभागीय दलों, पैनल में शामिल कलाकारों और प्रभाग के साथ स्पष्ट रूप से नियमित आधार पर काम करने वाली प्राइवेट पंजीकृत मंडलियों सहित लगभग 10,000 लोक और पारंपरिक कलाकार हैं।

संभवत: गीत एवं नाटक प्रभाग मॉडल सरकारी संगठनों में से एक है जिसमें अपने परिचालन के क्षेत्रों के साथ-साथ अपनी गतिविधि को भी गैर योजना व्यय बढ़ाए बिना स्थायी दीर्घावधि दायित्व निभाने के लिए विस्तार के लिए जबरदस्त लचीलापन है। प्रभाग की सिर्फ करीब 8 प्रतिशत कार्यकारी शक्ति प्रभाग के नियमित रोल पर है। इसके अतिरिक्त यह निर्विवाद तथ्य है कि पारंपरिक मीडिया या लाइव मीडिया इसकी पहुंच, प्रभाव और लचीलेपन के मद्देनजर आईईसी गतिविधियों के लिए सर्वाधिक किफायती माध्यम है।

निदेशक की अध्यक्षता में प्रभाग तीन स्तरों पर कार्य करता है अर्थात (i) दिल्ली में मुख्यालय, (ii) बंगलुरू, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, कोलकाता, लखनऊ, पुणे और रांची में दस क्षेत्रीय केन्द्र, (iii) सहायक निदेशकों की अध्यक्षता में सात सीमा केन्द्र दरंभगा, गुवाहाटी, जम्मू, जेबापुर, इंफाल, नैनीताल और शिमला में, (iv) प्रबंधकों की अध्यक्षता में छह विभागीय नाटक मंडली भुवनेश्वर, दिल्ली, हैदराबाद, पटना, पुणे और श्रीनगर (जम्मू) में स्थित है।

एफएम रेडियो (निजी)

परियोजना अप्रैल 2006 में शुरू हुई। अप्रैल 2009 तक परियोजना की स्थिति निम्नलिखित है :

क्र. सं.	साइट का नाम	स्थिति		टावर तैयार होने के लिए निर्धारित लक्ष्य	पूर्ण होने का संभावित समय
		नींव	टावर		
1.	जयपुर	पूर्ण	पूर्ण	मार्च, 2007	पूर्ण
2.	हैदराबाद	पूर्ण	पूर्ण	मार्च, 2007	पूर्ण
3.	नई दिल्ली	पूर्ण	पूर्ण	मार्च, 2007	पूर्ण
4.	चेन्नई	पूर्ण	पूर्ण	मार्च, 2007	पूर्ण
5.	कोलकाता	नींव का काम शुरू	ढांचे का कार्य प्रगति पर	मार्च, 2007	...
6.	देहरादून	पूर्ण	पूर्ण	मार्च, 2009	पूर्ण

* कोलकाता में आकाशवाणी द्वारा स्थल की अनापत्ति निलंबित

छह शहरों में इस परियोजना पर हुए व्यय का ब्योरा निम्नलिखित है :

क्र.सं.	शहर का नाम	स्वीकृत लागत	अब तक खर्च राशि
1.	जयपुर	166.12 लाख रुपये	1084.79 लाख रुपये
2.	हैदराबाद	166.12 लाख रुपये	
3.	चेन्नई	220.83 लाख रुपये	
4.	नई दिल्ली	439.05 लाख रुपये	
5.	कोलकाता	220.83 लाख रुपये	
6.	देहारादून	98.29 लाख रुपये	
	कुल	**1311.24 लाख रुपये**	**1084.79 लाख रुपये**

परियोजना की प्रगति की समीक्षा मंत्रालय द्वारा मासिक एवं त्रैमासिक छमाही और वार्षिक आधार पर की जाती है।

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानीटरिंग केंद्र (ईएमएमसी)

यह परियोजना कुछ अपरिहार्य कारणों से 10वीं योजना अवधि में क्रियान्वित नहीं की जा सकी। इसमें सीपीडब्ल्यूडी द्वारा स्थान पर पुष्पा भवन की छत पर आवंटित एंटीना और अन्य उपकरण लगाने की मंजूरी न मिलने का कारण भी शामिल है। यह परियोजना वैकल्पित भवन अर्थात आर एण्ड डी भवन, 14-बी, रिंग रोड, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली पर शुरू की गई और दिनांक 9.6.2008 से प्रचालित की गई। ईएमएमसी, 300 टीवी चैनलों (24X7) की विषयवस्तु मानीटरिंग कर रहा है। निजी एफ एम चैनलों की विषयवस्तु की मानीटरिंग करने के लिए भी योजना बना रही है।

अंतर्राष्ट्रीय चैनल

लागू नहीं है क्योंकि योजना अभी प्राथमिक चरण में है।

सामुदायिक रेडियो के लिए आई ई सी गतिविधियां

सामुदायिक रेडियो के लिये आईईसी गतिविधियों के रूप में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय नई दिल्ली के एशियाई राष्ट्रमंडल शैक्षिक मीडिया केंद्र के साथ मिल देश भर में कई केन्द्रों पर कार्यशालाएं/गोष्ठियां और परामर्श बैठकें आयोजित की गई। इस तरह की पहली परामर्श बैठक का आयोजन लखनऊ में 28-30 नवंबर 2007 और दूसरी परामर्श बैठक 24 और 25 मार्च 2008 में कोलकाता में आयोजित की गई। इस समय काम कर रहे सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के प्रबंधकों के लिये क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन नई दिल्ली में 13 फरवरी 2008 किया गया।

वर्ष 2008-09 और 2009-10 के दौरान निम्न विवरण के अनुसार परामर्श/कार्याशालाएं आयोजित की गईं :-

परामर्श	**राज्य**	**स्थान**	**माह और वर्ष**
तीसरा क्षेत्रीय परामर्श	दक्षिण ज़ोन	श्री मानाकुला इंजीनियरिंग कालेज, पुडुचेरी	1-2 जुलाई, 2008
चौथा क्षेत्रीय परामर्श	पश्चिम ज़ोन	विद्या प्रतिष्ठान प्रौद्योगिकी संस्थान बारामती, महाराष्ट्र	8-9 सितम्बर, 2008
पाचवां क्षेत्रीय परामर्श	गुजरात, राजस्थान	सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अहमदाबाद, गुजरात	24-25 नवम्बर, 2008
छठा क्षेत्रीय परामर्श	सभी पूर्वोत्तर राज्य	कृष्णकांत हांडिक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, गुवाहाटी	28-29 जनवरी, 2009
सातवां क्षेत्रीय परामर्श	हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चण्डीगढ़ (यू.टी.)	एम.एस. पंवार इंस्टीट्यूट ऑफ कम्यूनिकेशन सोलन, हिमाचल प्रदेश	13-14 मार्च, 2009
आठवां क्षेत्रीय परामर्श	छत्तीसगढ़, ओडीशा, मध्य प्रदेश	इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़	24-25 मार्च, 2009
दूसरी क्षमता निमार्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम	सभी राज्य	अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई	10-11 फरवरी, 2009

प्रथम राज्य परामर्श	राजस्थान	तिलोनिया-बेयरफुट कालेज	9-10 नवम्बर 2009
द्वितीय राज्य परामर्श	मेघालय	शिलांग-शिलांग क्लब	13-14 नवम्बर 2009
तृतीय राज्य परामर्श	हरियाणा	मानव रचना विश्वविद्यालय,फरीदाबाद	24-25 नवम्बर 2009
चतुर्थ राज्य परामर्श	मध्य प्रदेश	चंदेरी-चंदेरी-बुनकर विकास संस्था	18-19 दिसंबर 2009
पंचम राज्य परामर्श	तमिलनाडु	तिरुचेन्दुर-आदितनार कालेज आफ आर्ट्स एवं साइंस	22-23 दिसंबर 2009
छठा राज्य परामर्श	केरल	वयानंद-वयानंद सोषल सर्विस सोसायटी	11-12 जनवरी 2010
सातवां राज्य परामर्श	कर्नाटक	बुद्धिकोट-मर्यादा	28-29 जनवरी 2010
आठवां राज्य परामर्श	महाराष्ट्र	पुणे-एफटीआईआई	4-5 फरवरी 2010
नौवां राज्य परामर्श	उत्तराखंड	मुक्तेश्वर-टेरी	10-11 मार्च 2010
दसवां राज्य परामर्श	उत्तर प्रदेश	कानपुर-आईआईटी	12-13 मार्च 2010

सूचना भवन का निर्माण

वार्षिक योजना वर्ष 2007–08, 2008–09 एवं 2009–10 के लिए क्रमशः 1.00 करोड़ रुपये, 1,76,20,000/– रुपये तथा 10.00 करोड़ रुपये सूचना भवन फेज के निर्माण के लिए सिविल कंस्ट्रक्शन विंग, आकाशवाणी को जारी किये गये। चालू वित्त वर्ष (2010–11) में सूचना भवन फेज के निर्माण के लिए 18.00 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है, जिसमें से 10.00 करोड़ रुपये जारी किये जा चुके हैं तथा 8.00 करोड़ रुपये चालू वित्त वर्ष के दौरान जारी किये जा रहे हैं। शेष निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए आगामी वित्त वर्ष 2011–12 के दौरान 43.84 करोड़ रुपये की राशि की आवश्यकता होगी। हालांकि बजट अनुमान स्तर पर आगामी वित्त वर्ष के लिए 36.22 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है।

विकास संबंधी पहलों का आर्थिक विश्लेषण (नई योजना)

निम्नलिखित अध्ययन कार्य किए गए हैं :

1. **वार्षिक योजना 2007-08**
   ''उत्तर पूर्व तथा जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में जनसंचार मीडिया का प्रभाव और पहुंच'' : रिपोर्ट भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी) द्वारा सौंपी गई।

2. **वार्षिक योजना 2008-09**
   ''भारत में अंत:मीडिया स्वामित्व'': प्रारूप रिपोर्ट भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कालेज, हैदराबाद (एएससीआई) द्वारा सौंपी गई।

3. फिल्म खंड की दो चालू स्कीमों का मूल्यांकन, तथा; (i) फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा ''फिल्म समारोहों के जरिए निर्यात संवर्द्धन'' और (ii) मुख्य सचिवालय द्वारा ''देश और विदेश में फिल्म बाजारों में भागीदारी'' प्रारूप रिपोर्ट भारतीय जन प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) द्वारा 2009-10 में जमा की जानी है।

4. 2009-10 के दौरान निम्नलिखित दो अध्ययनों को पूरा किया जाना है :-

   I. ''एफएम पर संगीत के लिए मॉडल आईपीआर व्यवस्था''। यह अध्ययन 2008-09 में मंजूर किया गया था। लेकिन इसके बाद एजेंसी ने इसे पूरा करने में असमर्थता जता दी। इसलिए यही अध्ययन 2009-10 में पूरा किया जा रहा है।

   II. ''प्रसारण उद्योग के कॉपीराइट तथा संबंधित अधिकार''।

प्रसार भारती
आकाशवाणी – वार्षिक योजना (2010–11)
परिव्यय परिणाम/लक्ष्य

(करोड़ रुपये में)

क्रमांक	योजना/कार्यक्रम	उद्देश्य/परिणाम	लागत 2010–11 योजना बजट	व्यय (दिसंबर 10 तक)	मात्रात्मक लाभ/ भौतिक परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	उपलब्धियां (31.12.10 तक) कालम 5 के अनुसार	टिप्पणियां
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
क	**चालू योजनाएं** पूंजी राजस्व		**80.50**	26.32				
1	जम्मू एवं कश्मीर के लिए विशेष पैकेज फेज़–I और फेज़–II पूंजी	जम्मू एवं कश्मीर में रेडियो कवरेज का विस्तार	3.50 1.50	4.43 2.63	जम्मू कश्मीर में पैकेज चरण 1 की योजना पूरी हो गई हैं। जम्मू कश्मीर पैकेज चरण 2 एसआईटीसी (आपूर्ति, संस्थापन ,परीक्षण और कमीशनिंग) का कार्य पूरा। 1 MVA (3) डीजीसेट का कार्य पूरा–2 सेट के लिए कार्य सौंपा गया। तीसरे के लिए करीब 1.78 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि की जरूरत है जो फेज–II के तहत आकाशवाणी को उपलबध कराए गए 5.70 करोड़ के अलावा है।	डीजी सेट 1 एमवीए (3) क्यू 2 संस्थापन का काम पूरा। क्यू–3 परीक्षण और कमिशनिंग का काम पूरा 2 डीजी सेट 500 केवीए– कार्य सौंपा गया।	जम्मू में प्राप्त दो सेट संस्थापित और चालू। नारबल, श्रीनगर में तीसरे सेट के लिए आर्डर प्रसार भारती से अतिरिक्त राशि के आश्वासन के बाद दिए गए हैं तथा वर्ष के अंत तक काम पूरा होने की संभावना है। नारबल, श्रीनगर में डीजी सेट 500 केवीए (2) का कार्य पूरा	

(करोड़ रुपये में)

क्रमांक	योजना/कार्यक्रम	उद्देश्य/परिणाम	लागत 2010-11 योजना बजट	व्यय (दिसंबर 10 तक)	विवरण योग्य परिणाम/भौतिक परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	उपलब्धियां (31.12.10 तक) कालम 5 के अनुसार	टिप्पणियां
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2	**राजस्व**		**2.00**	**1.80**				
	पूर्वोत्तर के लिए विशेष पैकेज	पूर्वोतर में रेडियो कवरेज बढ़ाना	40.00	4.91	**19 नए एफएम स्टेशन** (i) साइट-15 साइट का अंतिम रूप से (14 साइट अ्धिग्रहीत और एक शीघ्र ही ली जा रही है)। मणिपुर में तमेंग लोंग और उखरूल जुनेहबोतो (नगालैंड) और अनिनी (अरुणाचल) में शेष 4 साइट का शीघ्र अधिग्रहण किया जाना है।	**19 नए एफएम स्टेशन** (i) साइटस-क्यू 1 शेष 4 साइट का शीघ्र अधिग्रहण होने की संभावना है।	15 साइटों का अधिग्रहण कर लिया गया है और 1 साइट जुनेहबोतो (नगालैंड) का अधिग्रहण होने की संभावना है। अरूणाचल में अनिनी, मणिपुर में उखरूल और तमेंगलोंग को राजय सरकारों द्वारा आवंटित किया जाना है।	संबंधित राज्य सरकारों को चेम्फई, फेक, गोलपाड़ा और कोलासिब में आकाशवाणी साइट्स तक सड़क मार्ग बनाना होगा। चामंलाग, खोनसा और दापोरिजो का मामला आगे बढ़ाया जा रहा है।
	पूंजी		37.00	4.91	(ii) लोकनिर्माण कार्य- (क) सुरक्षा बाड़ उदयपुर और नूतन बाजार में पूरी हो चुकी है। बोमडिला, गोलपाड़ा, बमडिंग, टोपोरिजो, योनसा, तुईपांग, चेम्फई, और कोलासिन में 9 स्थानों पर कार्य प्रगति पर है।	(ii) लोक निर्माण कार्य- (क) सुरक्षा बाड़ क्यू-1 9 स्थानों पर कार्य पूरा होने की संभावना है। क्यू-2 4 स्थानों पर कार्य पूरा होने की संभावना है।	मणिपुर में कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब है। लमडिंग, तुईपांग, उदयपुर, नूतनबाजार, दापोरिजो, कोलासिब, बोमडिला , खोनसा, चेम्फाई और गोलपाड़ में निर्माण पूरा हो चुका है। चेरापूंजी , फेक, लोखा और चांगलांग में 4 स्थानों पर कार्य प्रगति पर है। भूमि का मसला हल होने के बाद चांगलांग में बुनियाद का कार्य अभी शुरू हुआ है। करीमगंज में बाड़ कार्य के लिए अनुमान प्रक्रियाधीन है।	करीमगंज में भूमि के मुआवजे का मुद्दे पर यह पता चलता है कि मसला अभी सुलझा नहीं है कयोकि पूर्ववर्ती भू-स्वामी ने निर्माण कार्य की अनुमति नहीं दी है। डीसी करीमगंज द्वारा भेजा गया भूमि का प्रस्ताव असम सरकार के राजस्व विभाग के सचिव की अनुमति के लिए लंबित है। आकाशवाणी के डीजी ने भी असम सरकार के मुख्य सचिव को शीघ्र मसला हल करने के लिए लिखा है। मामला आगे बढ़ाया जा रहा है।

(करोड़ रुपये में)

			लागत 2010-11 योजना बजट	व्यय (दिसंबर 10 तक)	विवरण योग्य परिणाम/भौतिक परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	उपलब्धियां (31.12.10 तक) कालम 5 के अनुसार	टिप्पणियां
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	राजस्व		3.00	0.00	लक्ष्य जून, 2010 चेरापूंजी, करीमगंज, वोखा और फेक में कार्य मार्च 10 तक शुरू होने की संभावना है। शेष 4 साइट के लिए प्रावधान किया गया है जो अधिग्रहीत की जानी है। ख. ट्रांसमीटर भवन और उपकरण संस्थापन - गोलपाड़ा, तुइपांग, कोलासिब, दापोरिजो, नूतन बाजार, उदयपुर और चेम्फई में 8 स्थानों के लिए अनुमानों को मंजूरी दी जा चुकी है तथा खोनसा के लिए प्रक्रियाधीन है। भवन निर्माण कार्य शुरू करने के लिए निविदा कार्य प्रगति पर है। लक्ष्य - अक्तूबर 10। सात स्थानों के लिए अनुमान तैयार हैं तथा फरवरी, 2010 में प्राप्त होने की संभावना है। इन स्थानों पर कार्य वर्ष 2010-11 के दौरान	ख. ट्रांसमीटर भवन क्यू-1 भवन का निर्माण कार्य में पहले से पास 15 साइट पर प्रगति होने की संभावना है तथा टॉवर्स के लिए आर्डर देने की संभावना है। क्यू-2 टॉवर्स को खड़ा करना शुरू होने की संभावना है। क्यू-3 भवन को पूरा करना तथा 8 स्थानों पर संस्थापन की शुरुआत जिनके लिए कार्य पहले ही सौंप दिया गया है या सौंपा जा रहा है। टॉवर का कार्य पूरा होने की संभावना है। क्यू-4 पहले से पास हो चुकी 8 साइटों पर संस्थापन पूरा होने की संभावना है। ट्रांसमीटर भवन पहले से पास हो चुके शेष 7 स्थानं पर पूरे होने की संभावना है। लोक निर्माण कार्य शेष 4 अधिग्रहीत किए जाने वाले स्थानों पर शुरू होने की संभावना है।	ट्रांसमीटर भवन का तकनीकी क्षेत्र तुईपांग, नूतन बाजार, उदयपुर, गोलपाड़ा, दापोरिजो और कोलासिब में 6 स्थानों पर तैयार है तथा फिनिशिंग कार्य प्रगति पर है। इन 6 स्थानों पर ट्रांसमीटर भवन के तकनीकी क्षेत्र का निरीक्षण सीसीडब्ल्यू को समन्वय से पूरा किया जा रहा है। इन स्थानों पर संस्थापन मार्च, 2011 तक तैयार करने का लक्ष्य है। 4 स्थानों पर कार्य प्रगति पर है। चेम्फई और लन्डिंग में भवन छत के स्तर तक पहुंच गया है तथा योनसा में कार्य प्लिंच लेवल से ऊपर है। चांगलांग बुनियाद कार्य प्रगति में है। चेरापूंजी, बोमडिला, फेक और वोखा में भवन के लिए अनुमान प्रक्रियाधीन है। 6 स्थानों पर टॉवर के लिए फर्म के लिए आशय पत्र जारी किए गए हैं जहां संस्थापन मार्च, 2011 तक पूरा करने का लक्ष्य है।	समुचित पहुंच मार्ग उपलब्ध न होने के कारण कार्य की प्रगति धीमी है जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है तता कई क्षेत्रों खास तौर पर मणिपुर, नगालैंड और असम में कानून और व्यवस्था की समस्या है।

(करोड़ रुपये में)

			लागत 2010-11 योजना बजट	व्यय (दिसंबर 10 तक)	विवरण योग्य परिणाम/भौतिक परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	उपलब्धियां (31.12.10 तक) कालम 5 के अनुसार	टिप्पणियां
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
					प्रगति में होगा। शेष चार साइट के लिए अनुमान साइट के अधिग्रहणछ`क बाद तैयार किए जाएंगे तथा वर्ष के दौरान कार्य शुरू होने की संभावना है। उपकरण-ट्रांसफर खरीद लिए गए हैं। 50 एम टावर खरीदने की प्रक्रिया जारी, निविदा बुलाई गई।			
					2 सिल्चर-5 के डब्ल्यू एफ एम ट्रांसमीटर - ट्रांसमीटर और पैनल एंटीना की खरीद औरग संस्थापन। ट्रांसमीटर के लिए खरीद प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। पैनल एंटीना के लिए निविदाओं का तकनीकी मूल्यांकन किया जा रहा है।	2 सिल्चर-5 के डब्ल्यू एफ एम ट्रांसमीटर- क्यू-2 ट्रांसमीटर उपकरण की प्राप्ति और संस्थापन शुरू। क्यू-3 एंटीना की प्राप्ति और संस्थापन तथा ट्रांसमीटर संस्थापन का काम पूरा। क्यू-4 परीक्षण और मापन का काम पूरा।	ट्रांसमीटर के लिए खरीद आर्डर दे दिए गए हैं तथा वर्ष के आखिर तक ये प्राप्त होने की संभावना है। पैनल एंटीना की निविदा फिर जारी की गई है।	
					3. गैंगटॉक-10 केवी के एफएम ट्रांसमीटर की खरीद और इंस्टॉलेशन का काम करना। याचिका के कारण देरी। दिल्ली	3. गैंगटॉक-10 केडब्ल्यू एफएम ट्रांसमीटर - क्यू-1 ट्रांसमीटर का आर्डर जारी होने की संभावना। होस्टल निर्माण शुरू। क्यू-3 ट्रांसमीटर की प्राप्ति और संस्थापन शुरू क्यू-4 काम पूरा	3. फर्म के समुचित पीबीजी जमा करने के बाद ट्रांसमीटर के लिए औपचारिक एटी 9.3.10 को की गई। ट्रांसमीटर 2010-11 में प्राप्त होने की संभावना है।	

(करोड़ रुपये में)

			लागत 2010-11 योजना बजट	व्यय (दिसंबर 10 तक)	विवरण योग्य परिणाम/भौतिक परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	उपलब्धियां (31.12.10 तक) कालम 5 के अनुसार	टिप्पणियां
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
					उच्च न्यायालय ने याचिका रद्द कर दी है (21.5.09) लेकिन एल-1 फर्म बैंक गारंटी नहीं दे सकी।			
					4. चिन्सुरा- 1000 केवी एमडब्ल्यू ट्रांसमीटर का लोक निर्माण पूर्ण, ट्रांसमीटर की खरीद और इंस्टॉलेशन	4. चिन्सुरा 1000 केडब्ल्यू एमडब्ल्यू ट्रांसमीटर-क्यू-1 लोक निर्माण कार्य पूरा और विभागीय काम चालू। क्यू-3 ट्रांसमीटर प्राप्त और इंस्टॉलेशन का काम शुरू। क्यू-4 ट्रांसमीटर के इंस्टॉलेशन का काम पूरा।	4. निर्माण कार्य पूरा, ट्रांसमीटर के प्रेषण से पूर्व निरीक्षण में काल प्राप्त और मंजूरी के लिए प्रस्ताव मंत्रालय को सौंपा जा रहा है।	
					5. 100 स्थानों पर 100 वॉट एफएम ट्रांसमीटर। शेष 20 स्थानों (80 स्थानों पर संस्थापन पिछले वर्ष पूरा हो गया था) पर संस्थापन का काम पूरा।	5. क्यू-1 मार्च, 2010 के बाद बचे स्थानों पर संस्थापन।	5. 9 स्थानों पर संस्थापित (कुल 89 स्थानों पर काम पूरा) तथा 3 स्थानों पर कार्य जारी। 8 स्थानों पर राज्य सरकार (2 अरुणाचल में) की मंजूरी तथा कानून-व्यवस्था में सुधार (मणिपुर में 4 और त्रिपुरा में 2) के बाद कार्य शुरू होगा।	
					6. डीएसएलजी/एमएसएस (3) टर्मनल की खरीद के लिए निविदा दोबारा मंगाई गई।	6. डीएसएनजी एमएसएस सिस्टम्स-(3) निविदा प्रक्रिया की उम्मीद तथा तकनीकी मूल्यांकन की संभावना।	6. डीएसएनजी- एमएसएस टर्मिनल-(1) डीएसएनजी निविदा स्वीकृत नहीं हुई और 31.8.10 को दोबारा मंगाई गई। (2) निविदा 27-10-10 को खोली गई और छंटनी की जा रही है।	

(करोड़ रुपये में)

			लागत 2010-11 योजना बजट	व्यय (दिसंबर 10 तक)	विवरण योग्य परिणाम/भौतिक परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	उपलब्धियां (31.12.10 तक) कालम 5 के अनुसार	टिप्पणियां
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3.	एमडब्ल्यू सेवाओं का विस्तार	प्राथमिक कवरेज क्षेत्र को मजबूत करने के लिए ट्रांसमीटर का आधुनिकीकरण करना।	0.00	0.01	कार्य पूरा	कार्य पूरा		
4.	एफएम सेवाओं का विस्तार	बेहतरीन गुणवत्ता के कारण लोकप्रिय हुए एमएम कवरेज का विस्तार	30.00	15.52	तीन 1 केवी एफएम ट्रांसमीटर का इंस्टॉलेशन श्रीकाकुलम में पूरा नई टिहरी में भवन पूरा और संस्थापन शुरू गैरषेण में भवन पूरा और संस्थान शुरू	1 केवी एफएम ट्रांसमीटर (3) श्रीकाकुलम-ट्रांसमीटर की खरीद लेकिन विजयवाड़ा में संस्थापित वहां नया ट्रांसमीटर आगे के बाद इसे वापस लाया जाएगा।		श्रीकाकुलम में ट्रांसफारमर वापस लाया जाएगा। नई टिहरी में वन विभाग की मंजूरी न मिलने के कारण देरी।
5	निर्माण सेवाओं का डिजिटलीकरण	सामग्री की तकनीकी गुणवत्ता बढ़ाना	1.00	0.05	डिजिटल कंसोल (27) खरीद प्रस्ताव की प्रक्रिया चालू है। डिजिटल रिकार्डिंग कंसोल (16) खरीद प्रस्ताव की प्रक्रिया चालू है।	डिजिटल कंसोल-क्यू 1 खरीद होने की संभावना। कंसोल का संस्थापन पूरा होने की संभावना		
6	स्टूडियो सुविधाओं और अन्य योजनाओं का स्वचलन		6.00	1.40	सिल्चर और देहरादून में कैप्टिव अर्थ स्टेशन की स्थापना उपकरणों की खरीद एवं इंस्टॉलेशन। नई एनआईटी जारी की गई।	सिल्चर और देहरादून में कैप्टिव अर्थ स्टेशन-क्यू 1 आर्डर दिए जाएंगे। क्यू 3 उपकरण प्राप्त हो जाएंगे और इंस्टॉलेशन शुरू होगा। 48 स्थानों पर हार्ड डिस्क आधारित प्रणाली (हाई एंड सर्वर वाले एसआईटीसी) की खरीद	48 स्थानों पर हार्ड डिस्क आधारित प्रणाली (हाई एंड सर्वर वाले एसओटीसी) की खरीद। क्यू-1 एसआईटीसी कार्य सौंपा जाएगा। क्यू-2 एसआईटीसी कार्य शुरू होने की संभावना।	डिजिटल अपलिंक स्टेशन और कंपयूटरीकृत वर्क स्टेशन कार्यक्रमों की गुणवत्ता बढ़ाते हैं।

(करोड़ रुपये में)

			लागत 2010-11 योजना बजट	व्यय (दिसंबर 10 तक)	विवरण योग्य परिणाम/भौतिक परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	उपलब्धियां (31.12.10 तक) कालम 5 के अनुसार	टिप्पणियां
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
					राजकोट-1000 केडब्ल्यू एमडब्ल्यू ट्रांसमीटर टावर-लोक निर्माण कार्य पूरा करना।	राजकोट-1000 केडब्ल्यू एमडब्ल्यू ट्रांसमीटर-क्यू1 लोक निर्माण कार्य पूरा और विभागीय काम जारी। क्यू-3 ट्रांसमीटर प्राप्त और इंस्टॉलेशन का काम शुरू। क्यू-4 इंस्टॉलेशन का काम पूरा और परीक्षण शुरू।		पुराने ट्रांसमीटर को नए डिजिटल ट्रांसमीटर द्वारा बदला जाएगा, जिसकी क्षमताअधिक है।
					तवांग में स्थायी स्टूडियो- (कार्य का सीमित मौसम) का कार्य प्रगति पर	तवांग में स्थायी स्टूडियो-(कार्य का सीमित मौसम) क्यू-1 इंस्टॉलेशन काकाम पूरा।		डिजिटल कंसोल, डिजिटल अपलिंकिंग, डाउनलिंकिंग उपकरण कार्यक्रमों की गुणवत्ता बढ़ाते हैं।
					जयपुर में स्थायी स्टूडियो- उपकरणों को इंस्टॉल करने का कार्य पूरा होने की संभावना	जयपुर में स्थायी स्टूडियो- क्यू-1 लंबित काम पूरा। संयुक्त निरीक्षण और कमीशनिंग		
7.	मेट्रो शहरों में स्टाफ क्वार्टर बनाना	प्रसार भारती के स्टाफ के लिए मेट्रो शहरों में स्टाफ क्वार्टर बनाना	फंडिंग दूरदर्शन द्वारा की जा रही है		दिल्ली चरण 1 (323) निर्माण कार्य पूरा होने के करीब और चरण 2 - (203) ठेका दिया गया मुंबई - 48 क्वार्टरों का निर्माण। दो प्रखंडों के लिए स्थानीय निकाय से मंजूरी मिली।	दिल्ली - निर्माण कार्य पूरा होने की संभावना मुंबई- क्यू-1 निर्माण का ठेका दिए जाने की उम्मीद। क्यू-4 काम जारी रहने की उम्मीद।		कल्याण गतिविधियों की फंडिंग दूरदर्शन द्वारा की जा रही है

(करोड़ रुपये में)

			लागत 2010-11 योजना बजट	व्यय (दिसंबर 10 तक)	विवरण योग्य परिणाम/भौतिक परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	उपलब्धियां (31.12.10 तक) कालम 5 के अनुसार	टिप्पणियां
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
					चेन्नई- स्थानीय निकाय से भवन निर्माण योजना को मंजूरी की प्रतीक्षा	चेन्नई - सीएमडीए को भवन निर्माण योजना को मंजूरी देनी बाकी है। सीएमडीए ने अतिरिक्त ढांचे और सुविधा शुल्क की मांग की है जिसे पूरा करना संभव नहीं है, क्योंकि जमीन सरकार की है। मामले पर काम जारी है।		
					कोलकाता- केएमसी द्वारा उत्परिवर्तन की कमी से भवन योजना को स्थानीय निकाय की मंजूरी मिलना बाकी।	कोलकाता- केएमसी द्वारा उत्परिवर्तन की कमी से भवन योजना को स्थानीय निकाय की मंजूरी मिलना बाकी और केएमडीए द्वारा एकपक्षीय विदड्रॉअल। कोलकाता उच्च न्यायालय में याचिका दायर।		
2	**नई योजनाएं**		**102.98**	**1.96**				
2.1	ट्रांसमीटर स्टूडियो, कनेक्टिविटी और डीटीएच चैनल को डिजिटल बनाना	एसडब्ल्यू, डीआरएम ट्रांसमीटर के राष्ट्रीय स्तर के कवरेज को डिजिटल मोड में करना, एफएम विस्तार, स्टूडियो को डिजिटल बनाना और कनेक्टिविटी बढ़ाना	30.80	0.46				

(करोड़ रुपये में)

			लागत 2010-11 योजना बजट	व्यय (दिसंबर 10 तक)	विवरण योग्य परिणाम/भौतिक परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	उपलब्धियां (31.12.10 तक) कालम 5 के अनुसार	टिप्पणियां
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.1.1	एम डब्ल्यू डीआरएम ट्रांसमीटर							
2.1.1 क	पुराने एम डब्ल्यू ट्रांसमीटरों (31) की जगह मौजूदा स्टेशनों पर नए डीआरएम एम डब्ल्यू ट्रांसमीटर लगाना				ईएफसी प्रस्ताव मंत्रालय में विचाराधीन	क्यू-1 ईएफसी स्वीकृति और उपकरण के लिए निविदा मंगाई गई। क्यू-2 निविदा की प्रोसेसिंग और तकनीकी मूल्यांकन क्यू-3 वाणिज्यिक बोली खोली गई और खरीद प्रस्ताव की प्रोसेसिंग क्यू-4 ठेका दिया गया		ईएफसी प्रस्ताव मंत्रालय में विचाराधीन
2.1.1. ख	(i) 3 एम डब्ल्यू डीआरएम ट्रांसमीटर का अरूमाचल-चीन सीमा पर कैप्टिव पावर प्लांट के साथ उन्नयन				ईएफसी प्रस्ताव मंत्रालय में विचाराधीन	क्यू-1 ईएफसी स्वीकृति और उपकरण के लिए निविदा मंगाई गई। क्यू-2 निविदा की प्रोसेसिंग और तकनीकी मूल्यांकन क्यू-3 वाणिज्यिक बोली खोली गई और खरीद प्रस्ताव की प्रोसेसिंग क्यू-4 ठेका दिया गया		ईएफसी प्रस्ताव मंत्रालय में विचाराधीन
2.1.1. ग	एम डब्ल्यू डीआरएम ट्रांसमीटरों द्वारा 10 केडब्ल्यू एम डब्ल्यू (6) मोबाइल का प्रतिस्थापन				19.00 करोड़ रुपए की राशि की एसएफसी के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की मंजूरी। ट्रांसमीटर के लिए अग्रिम एटी दिसंबर 2010 को दी गई	क्यू-3 ट्रांसमीटर प्राप्त होने की संभावना		

(करोड़ रुपये में)

			लागत 2010-11 योजना बजट	व्यय (दिसंबर 10 तक)	विवरण योग्य परिणाम/भौतिक परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	उपलब्धियां (31.12.10 तक) कालम 5 के अनुसार	टिप्पणियां
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.1.1. घ	36 मौजूदा डीआरएम कंपेटीबल एमडब्ल्यू ट्रांसमीटर का डीआरएम में रूपांतरण				36 मौजूदा डीआरएम कंपेटीबल एमडब्ल्यू ट्रांसमीटर का डीआरएम में रूपांतरण अनुमति के लिए इएफसी प्रस्ताव मंत्रालय में विचाराधीन उपकरण खरीद और संस्थापन मार्च 2011 तक करने का लक्ष्य	क्यू-1 ईएफसी अनुमति और उपकरण के लिए निविदा मंगाई गई क्यू-4 संस्थापन पूरा		
2.1.2.	एफएम डीआरएम कंपेटीबल ट्रांसमीटर							
2.1.2 क	मौजूदा 24 आकाशवाणी/टीवी साइटों पर एफएम विस्तार तथा डीडी के मौजूदा 100 एलपीटी पर 100 वाट एफएम ट्रांसमीटर				ईएफसी प्रस्ताव मंत्रालय की अनुमति के अधीन। उपकरण की खरीद मार्च 2011 तक होने की उम्मीद	क्यू-1 ईएफसी अनुमति और उपकरण के लिए निविदा मंगाई गई क्यू-4 ठेका दिया गया		
2.1.2. ख	मौजूदा 40 स्टेशनों पर हायर पावर द्वारा एफएम/एमडब्ल्यू ट्रांसमीटर का स्थापन				ईएफसी प्रस्ताव अनुमति के लिए मंत्रालय के विचाराधीन। उपकरण की खरीद मार्च 2011 तक होने की संभावना	क्यू-1 ईएफसी अनुमति और उपकरण के लिए निविदा मंगाई गई क्यू-4 ठेका दिया गया		
2.1.3.	5 एस डब्ल्यू ट्रांसमीटरों (दिल्ली-2, छ अलीगढ़ -2, बंगलुरू-1) का एस डब्ल्यू डीआरएम ट्रांसमीटर प्रतिस्थापन				ईएफसी प्रस्ताव अनुमति के लिए मंत्रालय के विचाराधीन	क्यू-1 ईएफसी अनुमति और उपकरण के लिए निविदा मंगाई गई क्यू-4 ठेका दिया गया		

(करोड़ रुपये में)

			लागत 2010-11 योजना बजट	व्यय (दिसंबर 10 तक)	विवरण योग्य परिणाम/भौतिक परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	उपलब्धियां (31.12.10 तक) कालम 5 के अनुसार	टिप्पणियां
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.1.4क	98 स्टूडियो का डिजिटलीकरण तथा नेटवर्किंग				वर्ष के दौरान 36 स्टूडियो में उपकरण प्राप्त होने की आशा	क्यू-1 ईएफसी अनुमति और उपकरण के लिए निविदा मंगाई गई क्यू-4 ठेका दिया गया		
2.1.4 ख	दिल्ली में अभिलेखीय सुविधा तथा चेन्नई, मुंबई, कोलकाता तथा हैदराबाद में भी ये सुविधाएं देना					क्यू-1 ईएफसी अनुमोदन। क्यू-2 उपकरणों के लिए विशिष्टताएं तय कर निविदा मंगाना। क्यू-3 तकनीकी मूल्यांकन। क्यू-4 निविदा खोलना और खरीद प्रस्ताव की प्रक्रिया आगे बढ़ाना।		
2.1.4 ग	44 मौजूदा इकाइयों का आॅटोमेशन तथा नई क्षेत्रीय इकाइयों का सृजन					-वही-		
2.1.5 क	एसटीएल कनेक्टिविटी को बदलना				मंत्रालय ने इस उप-स्कीम के लिए 31.50 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। लक्ष्य - मार्च 2011	क्यू-1 तकनीकी मूल्यांकन के बाद वाणिज्यिक बिड खोलने की आशा। क्यू-2 खरीद प्रस्ताव प्रक्रिया आगे बढ़ने की आशा। क्यू-4 उपकरण आपूर्ति की संभावना।		
2.1.5 ख,ग	सीईएस, एसटीएल, डीएसएनजी के नए प्रस्ताव					-वही-		
2.1.5 ज	सीबैंड आरएनटी (44) का प्रावधान				इस उप स्कीम के लिए मंत्रालय ने 4.28 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। खरीद प्रस्ताव प्रक्रियाधीन लक्ष्य - दिसंबर-10	-वही-		

(करोड़ रुपये में)

			लागत 2010-11 योजना बजट	व्यय (दिसंबर 10 तक)	विवरण योग्य परिणाम/भौतिक परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	उपलब्धियां (31.12.10 तक) कालम 5 के अनुसार	टिप्पणियां
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.1.5 ङ	डीटीएच चैनलों का आग्मेंटेशन					क्यू-1 ईएफसी अनुमोदन उपकरण विशेषताएं निर्धारित करना। क्यू-2 टेंडर मंगाना। क्यू-3 टेंडर प्रक्रिया तथा तकनीकी मूल्यांकन। क्यू-4 वाणिज्यिक बिड खोलना तथा खरीद प्रस्ताव की प्रक्रिया।		
2.2	विदेश सेवा को मजबूत करना	एसडब्ल्यू का डिजिटलीकरण	0.10	–	मंत्रालय ने 10.00 करोड़ रुपये की उपयोजना को अनुमति दे दी है			
2.3	ई गर्वनेंस, प्रशिक्षण, सुरक्षा अतिरिक्त कार्यालय परिसर, स्टाफ क्वार्टर बनाना	ढांचागत संरचना में सुधार	21.38		एसएफसी/ईएफसी/ प्रस्ताव विचाराधीन है। हार्डवेयर की खरीद पूरी हो जाएगी	ईएफसी अनुमति और उपकरण के लिए निविदा मंगाई गई। ठेका दिया गया।		
2.4	नई तकनीक और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	सेटेलाइट और क्षेत्रीय मोड में मल्टीमीडिया प्रसारण, ब्राडकास्टिंग और पाड कास्टिंग	1.50	0.03	परियोजना चालू। अन्य योजनाओं के लिए एसएफसी/ ईएफसी अनुमति के लिए भेजी गई।	क्यू-4 वेबकास्टिंग और पाडकास्टिंग का काम पूरा होने की उम्मीद। वेबकास्टिंग/पाड कास्टिंग के लिए प्रसार भारती के सीइओ ने 3.70 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दी।		
2.4 क	अनुसंधान और विकास				अनुमोदन प्राप्त उपकरण विशिष्टताएं प्रक्रियाधीन।	क्यू-1 ईएफसी स्वीकृत क्यू-3 टेंडर खोला जाना। क्यू-4 आर्डर दिया गया।		

2.5	साफ्टवेयर	उच्च क्वालिटी का साफ्टवेयर	10.00	1.86	100 करोड़ रुपये के लिए संशोधित ईएफसी

(करोड़ रुपये में)

			लागत 2010-11 योजना बजट	व्यय (दिसंबर 10 तक)	विवरण योग्य परिणाम/भौतिक परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	उपलब्धियां (31.12.10 तक) कालम 5 के अनुसार	टिप्पणियां
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.5	साफ्टवेयर	उच्च क्वालिटी का साफ्टवेयर बनाने के लिए ताकि प्रतिस्पर्द्धी मीडिया माहौल में आकाशवाणी के श्रोताओं को आकर्षित और बनाया रखा जा सके।	10.00	1.86	100 करोड़ रुपये के लिए संशोधित ईएफसी प्रस्ताव सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को आनवर्ड ट्रांसमीशन के लिए प्रसार भारती को सौंपा जा रहा है।			
2.6	जम्मू-कश्मीर फेज-III	जम्मू-कश्मीर सीमा क्षेत्रों में एफएम कवरेज में और सुधार के लिए	40.00		ईएफसी अनुमति के अधीन है। 2010-11 के दौरान ट्रांसमीटर और संबंधित उपकरण खरीदे जाएंगे और लोकनिर्माण कार्य पूरे हो जाएंगे। उपकरण एकल स्रोत के जरिए खरीदने का प्रस्ताव है।	क्यू-1 ईएफसी अनुमोदन और उपकरण के लिए निविदा आमंत्रण तथा लोक निर्माण कार्य के लिए प्रारंभिक अनुमान के प्रोसेसिंग क्यू-2 निविदाओं औरतकनीकी मूल्यांकन की प्रोसेसिंग तथा अनुमानों को मंजूरी तथा लोक निर्माण कार्य सौंपा गया। क्यू-3 वाणिज्यिक बोली बोलना और खरीद प्रस्ताव की प्रोसेसिंग तथा लोक निर्माण कार्य प्रगति की संभावना क्यू-4 आर्डर प्लेसमेंट तथा लोक निर्माण कार्य पूरा करना		उच्च पावर वाले तीन एफएम ट्रांसमीटर पहाड़ों के चोटियों पर लगाए जाएंगे और एक एफएम ट्रांसमीटर मौजूदा डीडी सेंटर में लगाएजाने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त कम पावर वाला ट्रांसमीटर अनकवर्ड क्षेत्रों में लगाए जाने का प्रस्ताव है।
	कुल आकाशवाणी		**183.48**	**28.67**				
		राजस्व	**15.00**	**3.66**				
		पूंजी	**168.48**	**25.01**				

प्रसार भारती
आकाशवाणी - वार्षिक योजना (2009-10)
परिव्यय परिणाम/लक्ष्य

(लाख रुपये में)

क्रमांक	योजना/कार्यक्रम	उद्देश्य/परिणाम	लागत 2010-11 योजना बजट	वर्ष 2009-10 के दौरान व्यय	विवरण योग्य परिणाम/भौतिक परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	उपलब्धिया कालम 6 के अनुसार	टिप्पणियां/जोखिम
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
क	**चालू योजनाएं** पूंजी राजस्व		**113.60** 110.60 3.00	- 32.81 **0.00**				
1	जम्मू एवं कश्मीर के लिए विशेष पैकेज पूंजी राजस्व	जम्मू एवं कश्मीर में रेडियो कवरेज	4.00 4.00	3.59 3.59 0.00	जम्मू कश्मीर में पैकेज चरण 1 की योजना पूरी हो गई हैं। जम्मू कश्मीर पैकेज चरण 2 में 62.5 केवीए (6) एवं 15 केवीए (9) की खरीद की गई है। यूपीएस (7) के लिए निविदाओं का तकनीकी मूल्यांकन किया जा रहा है। डीजी सेट 1 एमवीए (3) एवं डीजी सेट 500 केवीए (2) के लिए आपूर्ति, इंस्टॉलेशन, जांच और कमीशनिंग के आधार पर एनाईटी जारी किए गए हैं।	क्यू 1- 62.5 केवीए (6) और 15 केवीए (8) डीजी सेट- खरीद और इंस्टॉलेशन का काम पूरा। यूपीएस (7) - खरीद और इंस्टॉलेशन का काम पूरा। क्यू 2 डीजी सेट 1 एमवीए (3) ऑर्डर दे दिए गए। क्यू 3- डीजी सेट 500 केवीए (2)- एसआईटीसी ऑर्डर देने की उम्मीद।	1- 62.5 केवीए (6) और 15 केवीए (8) डीजी सेट- खरीद और इंस्टॉलेशन। (2) 40 केवी यूपीएस खरीदे गए एवं इंस्टाल किए गए। डीजी सेट 1 एमवीए (3)- एसआईटीसी के आधार पर दो सेट्स जम्मू को मिलेष तीसरा श्रीनगर को मिला। मूल्य के लिए बोली लगाने का कार्य प्रगति पर है। 1078 करोड़ रु. की आवश्यकता है इसमें से 570 करोड़ रुपये आकाशवाणी ने दिए है लेकिन चरण II का इंतजार है। बकाया प्रसार भारती से उपलब्ध होगें। (2) 500 केवीए डीजीसेट (2 नंबर) एसएलटीसी के आधार पर जनवरी 2010 को खरीदने का आदेश दिया गया। डीजी सेट इंस्टालेशन और कमीशनिंग होगा।	जम्मू और कश्मीर में मौजूदा रेडियो स्टेशनों पर अतिरिक्त डीजी सेटों और यूपीएस उपलब्ध कराने से कैप्टिव बिजली आपूर्ति मजबूत होगी और बिजली चले जाने पर और आपातकाल या प्राकृतिक आपदा के दौरान सतत प्रसारण सुनिश्चित हो सकेगा।

(लाख रुपये में)

क्रमांक	योजना/कार्यक्रम	उद्देश्य/परिणाम	लागत 2010-11 योजना बजट	वर्ष 2009-10 के दौरान व्यय (दिसंबर 09 तक)	विवरण योग्य परिणाम/भौतिक परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	उपलब्धियां (31.12.09 तक) कालम 6 के अनुसार	टिप्पणियां/जोखिम
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2	पूर्वोत्तर के लिए विशेष पैकेज	पूर्वोतर में रेडियो कवरेज बढ़ाना	43.00	10.65	1 19 नए एफएम स्टेशन स्थान का अधिग्रहण और एमएम ट्रांसमीटरों की खरीद के प्रस्ताव की उम्मीद है।	1. 19 नए एफएम स्टेशन-10 साइटों का अधिग्रहण कर लिया गया। 4 साइट्स को राज्य सरकारों को प्रदान करना है। एक स्थान के लिए लागत की प्रतीक्षा है। चार स्थानों की पहचान की जानी है। क्यू 1- स्थान पर बाड़ा लगाने का काम शुरू। भवन निर्माण के लिए अनुमान मंजूर। एफएम ट्रांसमीशन प्राप्त होने की संभावना। क्यू 2- अधिग्रहित स्थानों के लिए भवन निर्माण का ठेका दिए जाने की उम्मीद।	1. 19 नए एफएम स्टेशन-15 साइटों, जिसमें वर्तमान वर्ष की 5 साइट्स भी शामिल हैं, का अधिग्रहण कर लिया गया और 4 साइट का अधिग्रहण किया जाना है। मणिपुर के तेमांगलांग और उखरुल, नगालैंड के जुनेहबोटो और अरुणाचल प्रदेश के अनिनी (अरुणाचलप्रदेश) स्थित चार साइट्स को अंतिम रूप देना है।	इससे सीमांत सहित पूर्वोत्तर क्षेत्रों में कवरेज में सुधार होगा।
	पूंजी		40.00	10.65			तीन स्थानों पर सुरक्षा फेंसिंग का काम पूरा और 38 स्थानों पर काम चल रहा है।	संबंधित राज्य सरकारों को चेम्फई, फेंक, गोलपाड़ा और कोलासिब में आकाशवाणी साइट्स तक सड़क मार्ग बनाना होगा। तुइपंग और कोलासिब तक स्थानीय लोक निर्माण विभाग द्वारा अभी एचटी लाइन शिफ्ट करना बाकी है जो हमारी जमीन पर है। इससे कार्य में बाधा आ रही है। इस विषय पर काम बाकी है।

(लाख रुपये में)

क्रमांक	योजना/कार्यक्रम	उद्देश्य/परिणाम	लागत 2010-11 योजना बजट	वर्ष 2009-10 के दौरान व्यय)	विवरण योग्य परिणाम/भौतिक परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	उपलब्धियां कालम 6 के अनुसार	टिप्पणियां/जोखिम
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	राजस्व		3.00	0.00			गोलपारा, कोलासिब और तुइपंग के लिए ठेके दे दिए गए हैं और दापोरिजो, उदयपुर और नूतन बाजार के लिए निविदा पर काम चल रहा है। चंगलंग के लिए अनुमानों को मंजूरी मिल गई है। खोंसा के लिए प्रक्रियाधीन है। चंगलंग में विवाद के कारण काम शुरू नहीं हो पाया। अन्य स्थानों के लिए अनुमानों का इंतजार है। 1 केवी के एफएम ट्रांसमीटर को कोलकाता में प्राप्त कर लिया गया है और राज्य राजधानियों में जांच के लिए भेज दिया गया है।	
					2. सिलचर- 5 केवी के एफएम ट्रांसमीटर की खरीद और इंस्टॉलेशन के लिए निविदाओं का तकनीकी मूल्यांकन किया जा रहा है।	2. सिल्चर 5 केडब्ल्यू एफएम ट्रांसमीटर- क्यू 1- ऑर्डर जारी होने की उम्मीद। क्यू 3- ट्रांसमीटर इंस्टॉलेशन का काम शुरू। क्यू 4- इंस्टॉलेशन का काम पूरा ।	2. सिलचर- 5 केवी के एफएम ट्रांसमीटर- ट्रांसमीटर का ऑर्डर मंजूरी के लिए प्रक्रियाधीन है। पैनल एंटीना की निविदा टीई के अंतर्गत है।	सिल्चर में ट्रांसमीटर के लिए ऑर्डर रद्द होने के कारण खरीद लंबित हो गई चूंकि कंपनी निरीक्षण के लिए ट्रांसमीटर प्रदान करने में विफल रही। अब 5 केवी एफएम ट्रांसमीटर के साथ इसकी खरीद की गई जो 2010-11 तक मिल जाएगी।

(लाख रुपये में)

क्रमांक	योजना/कार्यक्रम	उद्देश्य/परिणाम	लागत 2010–11 योजना बजट	वर्ष 2009–10 के दौरान व्यय	विवरण योग्य परिणाम/भौतिक परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	उपलब्धियां कालम 6 के अनुसार	टिप्पणियां/जोखिम
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
					3. गैंगटॉक– 10 केवी के एफएम ट्रांसमीटर की खरीद और इंस्टॉलेशन का काम करना। डिलिवरी जुलाई 09 तक।	3. गैंगटॉक 10 केडब्ल्यू एफएम ट्रांसमीटर– क्यू 2– ट्रांसमीटर की प्राप्ति इंस्टॉलेशन का काम शुरू। क्यू 3– इंस्टॉलेशन का काम पूरा।	3. गैंगटॉक– 10 केवी के एफएम ट्रांसमीटर– कानूनी प्रक्रिया के कारण ट्रांसमीटर की खरीद में विलंब हो गया।	
					4. चिन्सुरा– 1000 केवी एमडब्ल्यू ट्रांसमीटर का लोक निर्माण पूर्ण, ट्रांसमीटर की खरीद और इंस्टॉलेशन	4. चिन्सुरा 1000 केडब्ल्यू एमडब्ल्यू ट्रांसमीटर– क्यू 1– लोक निर्माण कार्य पूरा और विभागीय काम चालू। क्यू 3– ट्रांसमीटर प्राप्त और इंस्टॉलेशन का काम शुरू। क्यू 4– ट्रांसमीटर के इंस्टॉलेशन का काम पूरा।	4. चिन्सुरा– 1000 केवी के मीडियम वेव ट्रांसमीटर– निर्माण कार्य पूरा, भवन के भीतर को छोड़कर, जो औपचारिक एटी देने के बाद शुरू होगी। एडवांस एडी के खिलाफ मामला उच्चतम न्यायालय मे दिया गया था। ट्रांसमीटर की खरीद के लिए औपचारिक आदेश दिसंबर 2009 को देने के साथ उसकी तक उसकी डिलिवरी देनी है।	
					5. डीएसएलजी/ एमएसएस टर्मिनल की खरीद व्यावसायिक नीलामी खोली	5. डीएसएनजी/ एमएसएस सिस्टम्स– क्यू 1– डीएसएनजी सिस्टम्स के लिए ऑर्डर और एमएसएस की प्राप्ति। क्यू	5. डीएसएनजी– एमएसएस टर्मिनल– (1) डीएसएनजी निविदा स्वीकृत नहीं हुई और दोबारा मंगाई गई। (2) एमएसएस	

(लाख रुपये में)

क्रमांक	योजना/कार्यक्रम	उद्देश्य/परिणाम	लागत 2010-11 योजना बजट	वर्ष 2009-10 के दौरान व्यय	विवरण योग्य परिणाम/भौतिक परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	उपलब्धियां कालम 6 के अनुसार	टिप्पणियां/जोखिम
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
					गई। फर्म के प्रस्ताव की वैधता बढ़ाने से इनकार किया और निविदा दोबारा मंगाई गई। एमएसएस टर्मिनल ऑर्डर रिप्लेस किया।	4- उपकरणों की प्राप्ति और स्थापना।	टर्मिनल के लिए ऑर्डर दिए जा चुके हैं लेकिन फर्म द्वारा कोटेशन में दर्ज उपकरणों की मॉडल संख्या में फेरबदल किया गया जो स्वीकार्य नहीं था। ऑर्डर रद्द करने का प्रस्ताव दिया गया।	
					7. 100 दूरदराज के क्षेत्रों में वॉट एफएम स्थापना का कार्य समाप्त। 16 स्थानों पर इंस्टॉलेशन का काम पूरा और 17 स्थानों पर कार्य प्रगति पर है। 24 स्थानों के लिए निविदाएं मंजूर।	7. 100 वॉट एफएम रिले सेंटर्स- क्यू 1- ट्रांसमीटर के इंस्टॉलेशन का काम पूरा होने की उम्मीद।	6. 100 वॉट एफएम रिले सेंटर - 80 सेंटर पर इंस्टॉलेशन पूरा और 10 स्थानों पर प्रक्रियाधीन। बचे हुए 10 स्थानों पर (मिजोरम में 6 और मणिपुर में 4) ट्रांसमीटर लगाने के लिए राज्य सरकारों के साथ निरंतर सहयोग किया जा रहा है।	मणिपुर में कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब है। मिजोरम को स्थान आवंटित करने हैं।
3	एमडब्ल्यू सेवाओं का विस्तार	प्राथमिक कवरेज क्षेत्र को मजबूत करने के लिए ट्रांसमीटर का आधुनिकीकरण करना	**0.05**	**0.14**	डूंगरपुर के लिए 1 केवी का एमडब्ल्यू ट्रांसमीटर स्थापित। स्टेशन की कमीशनिंग के लिए ओएंडएम स्टाफ मंजूरी का इंतजार	स्टेशन का परिचालन शुरू होने की संभावना	स्टाफ की मंजूरी की प्रतीक्षा है।	

(लाख रुपये में)

क्रमांक	योजना/कार्यक्रम	उद्देश्य/परिणाम	लागत 2010-11 योजना बजट	वर्ष 2009-10 के दौरान व्यय	विवरण योग्य परिणाम/भौतिक परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	उपलब्धियां कालम 6 के अनुसार	टिप्पणियां/जोखिम
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
4	एफएम सेवाओं का विस्तार	बेहरतीन गुणवत्ता के कारण लोकप्रिय हुए एमएम कवरेज का विस्तार	42.00	12.81	10 केवी एफएम ट्रांसमीटर प्राप्ति और इंस्टॉलेशन करना, 41 उन्नत एटी के ऑर्डर जारी। जुलाई 09 तक डिलिवरी की उम्मीद।	10 केवी एफएम ट्रांसमीटर (41) क्यू 2- प्राप्ति और इंस्टॉलेशन की शुरुआत। क्यू 4- इंस्टॉलेशन पूरा।	कानूनी प्रक्रिया के कारण ट्रांसमीटर की खरीद में विलंब हो गया। 19.3.2010 को ट्रांस्मीटर खरीदने का आदेश दे दिया गया। इसका 2010-11 के अंत तक प्राप्त करने की उम्मीद है। क्यू-4 तकनीकी रूप से पूर्ण क्यू-4 तकनीकी रूप से पूर्ण क्यू-1 खरीदने का प्रस्ताव क्यू-2 आंतरिक वित्तीय सहायता से मंजूरी	चालू योजनाओं के लागू होने के बाद एफएम कवरेज बढ़ने की उम्मीद है।
5	निर्माण सेवाओं का डिजिटलीकरण	सामग्री की तकनीकी गुणवत्ता	2.75	1.32	डिजिटल कंसोल खरीद प्रस्ताव की प्रक्रिया चालू है।	डिजिटल कंसोल- क्यू1 - ऑर्डर जारी होने की संभावना। क्यू 3- कुछ कंसोल मिलने की उम्मीद। क्यू 4- बाकी बचे कंसोल के प्राप्त होने की उम्मीद।	डिजिटल डबिंग कंसोल और डिजिटल स्विचिंग कंसोल की खरीद।	डिजिटल कंसोल, डिजिटल अपलिंकिंग, डाउनलिंकिंग उपकरणों से कार्यक्रमों की गुणवत्ता बढ़ेगी।
6	स्टूडियो सुविधाओं और अन्य योजनाओं का स्वचलन		21.80	4.30	सिल्चर में कैप्टिव अर्थ स्टेशन की स्थापना उपकरणों की खरीद एवं इंस्टॉलेशन	सिल्चर में कैप्टिव अर्थ में उपकरण स्टेशन- क्यू 1- ऑर्डर दिए जाएंगे। क्यू 3 उपकरण प्राप्त हो जाएंगे और इंस्टॉलेशन शुरू होगा।	सिल्चर में कैप्टिव अर्थ स्टेशन (अपलिंक)- कोई निविदा तकनीकी रूप से स्वीकृत नहीं की गई। नई निविदा मांगी जाएंगी।	डिजिटल अपलिंक स्टेशन और कंप्यूटरीकृत वर्क स्टेशन कार्यक्रमों की गुणवत्ता बढ़ाते हैं।

(लाख रुपये में)

क्रमांक	योजना/कार्यक्रम	उद्देश्य/परिणाम	लागत 2010-11 योजना बजट	वर्ष 2009-10 के दौरान व्यय	विवरण योग्य परिणाम/भौतिक परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	उपलब्धियां कालम 6 के अनुसार	टिप्पणियां/जोखिम
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
					48 स्थानों पर हार्ड डिस्क आधारित प्रणाली (हाई एंड सर्वर वाले एसआईटीसी)की खरीद	48 स्थानों पर हार्ड डिस्क आधारित प्रणाली (हाई एंड सर्वर वाले एसआईटीसी)की खरीद- क्यू 1- ऑर्डर दिए जाएंगे। क्यू 3- कुछ ऑर्डर मिलने की उम्मीद। क्यू 4- बाकी बचे ऑर्डर के प्राप्त होने की उम्मीद।	48 स्थानों पर हार्ड डिस्क आधारित प्रणाली (हाई एंड सर्वर वाले एसआईटीसी)- कोई निविदा तकनीकी रूप से स्वीकृत नहीं की गई। संशोधित विनिर्देशों के साथ दोबारा मंगाई जा रही हैं।	
					राजकोट- 1000 केडब्ल्यू एमडब्ल्यू ट्रांसमीटर टावर- लोक निर्माण कार्य पूरा करना। ट्रांसमीटर और वायुरोधी की खरीद करना, नए मास्ट की खरीद के ऑर्डर जारी। डिलिवरी अवधि अक्टूबर 2009 तक।	राजकोट- 1000 केडब्ल्यू एमडब्ल्यू ट्रांसमीटर- क्यू 1- लोक निर्माण कार्य पूरा और विभागीय काम शुरू। क्यू 3- ट्रांसमीटर प्राप्त और इंस्टॉलेशन का काम शुरू। क्यू 4- इंस्टॉलेशन का काम पूरा।	राजकोट- 1000 केडब्ल्यू एमडब्ल्यू ट्रांसमीटर- ट्रांसमीटर की खरीद और इंस्टॉलेशन का काम पूरा। ट्रांसमीटर के लिए एडवांस एटी दे दी गई। एडवांस एटी के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट में। ट्रांसमीटर की खरीद के लिए औपचारिक एटी दे दी गई है जिसकी डिलिवरी दिसंबर 2010 तक की जानी है। 156 एम एमडब्ल्यू के मास्ट को लगाने और उसकी मरम्मत का काम पूरा और तीन दूसरे मास्ट को पेंट करने का काम पूरा।	पुराने ट्रांसमीटर को नए डिजिटल ट्रांसमीटर द्वारा बदला जाएगा, जिसकी क्षमता अधिक है

(लाख रुपये में)

क्रमांक	योजना/कार्यक्रम	उद्देश्य/परिणाम	लागत 2010-11 योजना बजट	वर्ष 2009-10 के दौरान व्यय	विवरण योग्य परिणाम/भौतिक परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	उपलब्धियां कालम 6 के अनुसार	टिप्पणियां/जोखिम
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
					लेह और तवांग में स्थायी स्टूडियो- (कार्य का सीमित मौसम)का का कार्य प्रगति पर और अगले कार्य सत्र अप्रैल 09 में समाप्त होने की उम्मीद।	लेह और तवांग में स्थायी स्टूडियो-(कार्य का सीमित मौसम) क्यू 1- इंस्टॉलेशन का काम पूरा।	लेह और तवांग में स्थायी स्टूडियो- (कार्य का सीमित मौसम)- लेह में इंस्टॉलेशन का काम पूरा और निरीक्षण। तवांग में इंस्टॉलेशन का काम पूरा, सिर्फ हीटिंग प्लांट्स का काम बाकी है जो प्रक्रियाधीन है।	डिजिटल कंसोल, डिजिटल अपलिंकिंग, डाउनलिंकिंग उपकरण कार्यक्रमों की गुणवत्ता बढ़ाते हैं।
					जयपुर में स्थायी स्टूडियो- उपकरणों को इंस्टॉल करने का कार्य पूरा। भवन कार्य संपन्न	जयपुर में स्थायी स्टूडियो - क्यू 1- इंस्टॉलेशन का काम शुरू। क्यू 4- इंस्टॉलेशन का काम पूरा।	जयपुर में स्थायी स्टूडियो - इंस्टॉलेशन का काम प्रक्रियाधीन।	
7	मेट्रो शहरों में स्टाफ क्वार्टर बनाना	प्रसार भारती के स्टाफ के लिए मेट्रो शहरों में स्टाफ क्वार्टर बनाना			दिल्ली चरण 1 निर्माण कार्य पूरा होने के करीब और चरण 2- ठेका दिया गया।	दिल्ली- निर्माण कार्य पूरा होने की संभावना।	दिल्ली- चरण 1 (323 क्वार्टर) - काम पूरा, सिवाय म्यूनिसिपल सीवरेज और जल आपूर्ति के काम के। चरण 2- (203 क्वार्टर) 128 क्वार्टर के लिए काम प्रक्रियाधीन। 75 (डी टाइप) क्वार्टर के लिए एमसीडी की मंजूरी मिलनी बाकी।	कल्याण गतिविधियां

(लाख रुपये में)

क्रमांक	योजना/कार्यक्रम	उद्देश्य/परिणाम	लागत 2010–11 योजना बजट	वर्ष 2009–10 के दौरान व्यय	विवरण योग्य परिणाम/भौतिक परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	उपलब्धियां कालम 6 के अनुसार	टिप्पणियां/जोखिम
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
					मुंबई– क्वार्टरों का निर्माण। दो प्रखंडों के लिए स्थानीय निकाय से मंजूरी मिली।	मुंबई– क्यू 1– निर्माण का ठेका दिए जाने की उम्मीद। क्यू 4– काम जारी रहने की उम्मीद।	मुंबई– बीएमसी द्वारा चार प्रखंडों के लिए लागत योजना मंजूर। पाइल फाउंडेशन का काम चालू है।	
					चेन्नई– स्थानीय निकाय से भवन निर्माण योजना को मंजूरी मिलनी बाकी।	चेन्नई–क्यू 1– निर्माण का ठेका दिए जाने की उम्मीद। क्यू 4– काम जारी रहने की उम्मीद।	चेन्नई– सीएमडीए को भवन निर्माण योजना को मंजूरी देनी बाकी है। सीएमडीए ने अतिरिक्त ढांचे और सुविधा शुल्क की मांग की है जिसे पूरा करना संभव नहीं है, क्योंकि जमीन सरकार की है। मामले पर काम जारी है।	
					कोलकाता– केएमसी द्वारा उत्परिवर्तन की कमी से भवन योजना को स्थानीय निकाय की मंजूरी मिलना बाकी।	कोलकाता– क्यू 1 स्थानीय निकाय द्वारा मंजूरी मिलने की संभावना। क्यू 2– निर्माण का ठेका दिए जाने की उम्मीद।	कोलकाता– केएमसी द्वारा उत्परिवर्तन की कमी से भवन योजना को स्थानीय निकाय की मंजूरी मिलना बाकी और केएमडीए द्वारा एकपक्षीय विदड्रॉअल। कोलकाता उच्च न्यायालय में याचिका दायर।	

(लाख रुपये में)

क्रमांक	योजना/कार्यक्रम	उद्देश्य/परिणाम	लागत 2010-11 योजना बजट	वर्ष 2009-10 के दौरान व्यय (दिसंबर 09 तक)	विवरण योग्य परिणाम/भौतिक परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	उपलब्धियां (31.12.09 तक) कालम 6 के अनुसार	टिप्पणियां/जोखिम
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	नई योजनाएं		**147.00**	**0.85**				
1	ट्रांसमीटर स्टूडियो, कनेक्टिविटी और डीटीएच चैनल को डिजिटल बनाना	एसडब्ल्यू, डीआरएम ट्रांसमीटर के राष्ट्रीय स्तर के कवरेज को डिजिटल मोड में करना, एफएम विस्तार, स्टूडियो को डिजिटल बनाना और कनेक्टिविटी बढ़ाना	28.00	0.00	पुराने एमडब्ल्यू मोबाइल ट्रांसमीटरों की जगह 10 केवी एमडब्ल्यू डीआरएम टर्मिनल (6) बदले जाएंगे। खरीद की जानी है। एनआईटी जारी।	क्यू 1- निविदा खोले और तकनीकी मूल्यांकन के लिए खोले जाने की उम्मीद। क्यू 3- ऑर्डर जारी किए जाने की उम्मीद।	ट्रांसमीटर के लिए आदेश दिया गया और दिसंबर 10 तक डिलीवरी मिली।	
					सी बैंड टर्मिनल (44) निविदाओं का तकनीकी मूल्यांकन प्रक्रियाधीन है। स्टूडियो के लिए डिजिटल स्टूडियो ट्रांसमीटर कनेक्टिविटी लिंक्स की खरीद- निविदा खोली जाएगी और तकनीकी मूल्यांकन किया जाएगा।	सी बैंड टर्मिनल- क्यू 1- ऑर्डर जारी करने की उम्मीद। क्यू 4- उपकरण मिलने की उम्मीद। क्यू 1- निविदा का तकनीकी मूल्यांकन पूरा होगा। क्यू 2- व्यावसायिक नीलामी खोली जाएगी और खरीद प्रस्ताव आगे बढ़ेगा। क्यू 4- उपकरण पहुंचने की उम्मीद।	नीलामी खोली गई है और खरीद प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। खरीद प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।	

(लाख रुपये में)

क्रमांक	योजना/कार्यक्रम	उद्देश्य/परिणाम	लागत 2010–11 योजना बजट	वर्ष 2009–10 के दौरान व्यय	विवरण योग्य परिणाम/भौतिक परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	उपलब्धियां कालम 6 के अनुसार	टिप्पणियां/जोखिम
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2	विदेश सेवा को मजबूत करने के लिए उसे डिजिटल बनाना	एसडब्ल्यू का डिजिटलीकरण	3.00	0.00	दिल्ली और अलीगढ़ में 250 केवी एसडब्ल्यू टर्मिनल को डीआरएम मोड में बदलने के लिए उपकरणों की खरीद– मैसेर्स फैलकन को निविदा जारी और कंपनी से कोटेशन प्राप्त।	क्यू 1– उपकरणों के आदेश दिए जाएंगे। क्यू 3– कार्य पूरा होने की उम्मीद।	खरीद प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। पीएसी सर्टिफिकेट के लिए एफएसी ने जांच बैठाई है। मंत्रालय से पीएसी सर्टिफिकेट हासिल करना है। अनुमति के लिए प्रस्ताव आंतरिक वित्त विभाग के पास है।	विदेशी सेवा ट्रांसमीटर पर डीआरएम सेवा चुनींदा श्रोताओं को ही उपलब्ध होंगी।
3	ई गवर्नेस, प्रशिक्षण, सुरक्षा अतिरिक्त कार्यालय परिसर, स्टाफ क्वार्टर बनाना	संरचना में सुधार	1.00	0.00	एसएफसी/ईएफसी प्रस्ताव विचाराधीन हैं।	क्यू 4– श्रीनगर होस्टल आवास का निर्माण कार्य पूरा होने की उम्मीद।	एसएफसी प्रस्ताव मंजूरी के लिए भेजा गया है।	
4	नई तकनीक और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	सेटेलाइट और क्षेत्रीय मोड में मल्टीमीडिया प्रसारण, ब्रॉडकास्टिंग और पॉड–कास्टिंग	1.40	0.00	परियोजना चालू। अन्य योजनाओं के लिए एसएफसी/ईएफसी में 3.70 करोड़ रुपये की परियोजना अनुमति के लिए भेजी गई।	क्यू 4– वेबकास्टिंग और पॉडकास्टिंग का काम पूरा होने की उम्मीद।	वेबकास्टिंग और पॉडकास्टिंग– एनआईसी द्वारा एसआईटीसी कार्य प्रक्रियाधीन है। एसएंडटी के अंतर्गत अन्य योजनाओं के लिए मंत्रालय की मंजूरी हासिल करनी है। उपकरणों संबंधी विनिर्देश अंतिम रूप में हैं। ए/ए और ई/एस जारी किए गए हैं।	

(लाख रुपये में)

क्रमांक	योजना/कार्यक्रम	उद्देश्य/परिणाम	लागत 2010–11 योजना बजट	वर्ष 2009–10 के दौरान व्यय (दिसंबर 09 तक)	विवरण योग्य परिणाम/भौतिक परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	उपलब्धियां (31.12.09 तक) कालम 6 के अनुसार	टिप्पणियां/जोखिम
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
5	जम्मू कश्मीर चरण 3	योजना से जम्मू एवं कश्मीर के सीमांत क्षेत्रों में एफएम और टीवी कवरेज में सुधार	100.00	0.00	पीएमओ के निर्देशानुसार 100 करोड़ के चुनाव आयोग के प्रस्ताव को मंत्रालय को भेजा गया है।		ईएफसी प्रस्ताव अनुमति के लिए मंत्रालय के पास भेजे गए हैं। स्थानों की पहचान कर ली गई है और क्षेत्रीय कार्यालयों को राज्य सरकारों के सहयोग से स्थान चुनने को कहा गया है। उपकरणों संबंधी विनिर्देश अंतिम रूप में हैं।	उच्च पावर वाले तीनों एफएम ट्रांसमीटर पहाड़ों की चोटियों पर लगाए जाएंगे और एक एफएम ट्रांसमीटर मौजूदा डीडी सेंटर में लगाए जाने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त निम्न पावर वाला ट्रांसमीटर बैकवर्ड क्षेत्रों में लगाए जाने का प्रस्ताव है।
6	सॉफ्टवेयर अधिग्रहण		14.00	0.00	पीएमओ के निर्देशानुसार 100 करोड़ के प्रस्ताव आई एंड बी प्रसार भारती को दिया गया।			
ग	कुल आकाशवाणी		**261.00**	**33.66**				

प्रसार भारती

दूरदर्शन - वार्षिक योजना (2010-11)

परिणाम बजट के परिणाम/लक्ष्य (2010-11)

(रुपये करोड़ में)

क्रम	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	लागत 2010-11	व्यय दिसंबर, 2010 तक	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	उपलब्धियां	टिप्पणी/ जोखिम घटक
	चालू योजना								
1.	जम्मू-कश्मीर विशेष योजना प्रथम तथा द्वितीय चरण (पूंजी)	जम्मू-कश्मीर में दूरदर्शन कवरेज प्रसारण में सुधार। अमृतसर में टावर निर्माण के अतिरिक्त जम्मू-कश्मीर विशेष पैकेज का पहला चरण कार्यान्वित हो गया है। अमृतसर में टावर, निर्माण का कार्य प्रगति पर है। इसके परिणामस्वरूप जम्मू-कश्मीर में दूरदर्शन प्रसारण की गुणवत्ता तथा कवरेज एरिया में सुधार होगा। योजना के द्वितीय चरण में कंटेट सुधार पर जोर दिया गया है। दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर, लेह तथा जम्मू की क्षेत्रीय सेवाओं तथा कशीर चैनल पर 24 घंटे के लिए कार्यक्रमों का निर्माण	4.00	5.03	अमृतसर में 300 मीटर का टावर पूरा	सीमापार क्षेत्रों में टीवी कवरेज में वृद्धि। डीडी-1 और डीडी न्यूज के सिगनल सुदूर सीमाक्षेत्रों में उपलब्ध कराना	दूसरी तिमाही में टावर का काम पूरा और एंटिना लगाने का कार्य पूरा।	टॉवर खड़ा करने का काम प्रगति पर, अब तक 240 मीटर की उंचाई हासिल कर ली गई है	एजेंसी द्वारा धीमा कार्य
					300 मीटर टावर पर अमृतसर में डीडी 1 तथा डीडी (न्यूज) की कमीशनिंग		नई साइट पर डीडी-1 और डीडी नयूज का संस्थापन	भवन निर्माण पूरा, एंटिने का आदेश और फीटर केबल साइट पर पहुंचा।	300 मीटर की पूरी उंचाई तक टॉवर खड़ा करने के बाद संस्थापन किया जाएगा।
	(राजस्व)		31.00	26.71					

2.	निर्माण सुविधाओं का आधुनिकीकरण तथा डिजिटलीकरण	कार्यक्रमों की तकनीकी गुणवता बढ़ाना	10.00	3.25	स्टूडियो केंद्र, केंद्रीकृत रिकार्डिंग, संपादन तथा प्लेबैक का सभी 17 मुख्य दूरदर्शन केन्द्रों के लिए	स्टूडियो का डिजिटलीकरण करने के लिए	कार्य जारी करने के लिए	कार्य जारी करने के लिए	मल्टी कैमरा ओबी वैन की आपूर्ति में देरी
3.	पूर्वोत्तर विशेष पैकेज चरण-II (पूंजी)	पूर्वोत्तर तथा अंडमान-निकोबार क्षेत्र में दूरदर्शन कवरेज का सुदृढ़िकरण। पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप के द्वीपीय इलाकों में दूरदर्शन सेवाओं के विस्तार तथा सुधार के लिए सरकार ने एक विशेष पैकेज मई 2006 में 256.85 करोड़ रुपये (द्वितीय चरण) को मंजूरी दी।	4.00	2.96	कोकराझार एचपीटी के लिए ट्रांसमीटर उपकरण की आपूर्ति, 10 कि.वा. एचपीटी कोकराझार चालू करना	गुवाहाटी से अंपलिकिंग सुविधा बढ़ाना, अंडमान निकोबार में डीटीएच उपलबध कराया जाएगा स्थलीय प्रसारण के क्षेत्र और तकनीकी गुणवत्ता में सुधार	पहली तिमाही में ट्रांसमीटर उपकरण की आपूर्ति दूसरी तिमाही में ट्रांसमीटर की स्थापना	ट्रांसमीटर उपकरण की आपूर्ति की गई 4 डीएसएनजी की आपूर्ति। बाकी के टेंडर मंगाए गए	
	पूर्वोत्तर विशेष		21.00	4.56					
4.	डीटीएच	इस योजना का उद्देश्य शेष बचे क्षेत्रों में टीवी कवरेज उपलब्ध कराना है।	0.00	0.00					डीटीएच सेवा शुरू हो चुकी है
5.	एचडीटीवी	यह वह तकनीक है जो उत्कृष्ट पिक्चर तथा वाइड स्क्रीन इमेज के कार्यों में अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराती है। इस तकनीक से 35 मी.मी. फिल्म जैसी पिक्चर क्वालिटी मिलती है। यह तकनीक डिजिटल सराउंडिंग साउंड भी उपलब्ध कराती है। एचडीटीवी फिल्ड प्रोडक्शन के लिए प्रायोगिक परियोजना का कार्य चालू है।	2.00	3.55	एडीटीवी प्रोडक्शन के लिए पायलट परियोजना चालू करना ।	प्रायोगिक योजना एडीटीवी फार्मेट में निर्माण के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराएगी।	एचडीटीवी कैमकार्डर और वीसीआर की खरीद	एचडीटीवी कैमकार्डर और वीसीआर की आपूर्ति की गई	फील्ड प्रोडकशन वैन पहले ही खरीदी जा चुकी है

6.	दसवीं योजना की अन्य अनुमोदित योजना	कार्यक्रमों की तकनीकी गुणवता बढ़ाना	10.00	17.80					
	स्टाफ के लिए आवास, बुनियादी ढांचे तथा सुरक्षा में वृद्धि।	टाफ के लिए आवास सुविधा का प्रावधान। बुनियादी ढांचे में वृद्धि/विभिन्न स्टेशनों पर सुरक्षा को मजबूत करना।			4 मेट्रो शहरों में स्टाफ के लिए आवासों का निर्माण।	चार स्थानों पर मैट्रों शहरों में स्टॉफ कवार्टरों का निर्माण और गैर मैट्रों में प्रगति		दिल्ली और मुम्बई में प्रगति	
					11 गैर मेट्रो शहरों में स्टाफ के लिए आवासों का निर्माण।		बंगलुरु, पटना और संबलपुर में स्टॉफ कवार्टरों का निर्माण पूरा- तीसरी तिमाही	नौ स्थानों पर स्टॉफ कवार्टर बना लिए गए है। पटना और संबलपुर में प्रगति	लखनऊ, जयपुर, वारानसी, भवानीपट्नम, हिसार, इलाहाबाद, त्रिचूर, इटानगर और बंगलुरु में स्टॉफ कवार्टर का निर्माण पूरा
	अन्य योजनाएं								
क.	स्टूडियो संबंधी योजनाएं	स्टूडियो केंद्र उपलबध कराने के जरिए स्थानीय प्रतिभा को अवसर उपलबध कराना और प्रोडकशन सुविधा बढ़ाना			तीन स्टूडियो का सैटअप	नैटवर्क स्टूडियो के प्रोडकशन में सुधार	चंडीगढ़, जम्मू एवं लेह में दूसरी तिमाही में स्टूडियो परियोजना पूरी	चंडीगढ़, जम्मू एवं लेह में भवन निर्माण पूरा तथा संस्थापन प्रगति पर	उपकरण की खरीद और विभागीय कार्य में देरी

	i) ट्रांस्मीटर से संबंधित योजनाएं	स्थलीय कवरेज में सुधार			आटोमोड एलपीटी 50	स्थलीय प्रसारण तथा कवरेज क्षेत्र की गुणवत्ता में सुधार।	पहली तिमाही में एलपीटी की आपूर्ति। दूसरी और तीसरी तिमाही में एलपीटी का संस्थापन	आठ ऑटो मोड एलपीटी चालू, 22 अतिरिक्त ऑटोमोड एलपीटी का संस्थापन पूरा। 50 अतिरिक्त ऑटोमोड एलपीटीकी खरीद के लिए निविदाएं खोली गई, तकनीकी मूल्यांकन पूरा।	
	नई योजनाएं								
1.	ट्रांसमीटर का डिजीटलीकरण, आधुनिकीकरण, ट्रांसमीटर उपकरणों की वृद्धि तथा नये उपकरण लगाना।		20.00	0.30					
क.	ट्रांसमीटर का डिजिटलीकरण	स्थलीय ट्रांसमिशन का डिजिटलीकरण	15.00		40 डीडीटी ट्रांसमीटर के लिए उपकरण की खरीद	स्थलीय ट्रांसमिशन का डिजिटलीकरण की प्रक्रिया शुरु	चरणबद्ध ढंग से पूरा होने की संभावना	19 डिजिटल ट्रांसमीटरों की खरीद के लिए निविदाएं आमंतित की गई, 15 स्थानों पर टॉवर की मजबूती का कार्य	योजना अप्रैल 2010 में मंजूर

ख.	ट्रांसमीटर उपकरणों का आधुनिकीकरण, वृद्धि तथा दूसरे उपकरण लगाना।	ट्रांसमीटर उपकरणों का आधुनिकीकरण, वृद्धि तथा तकनीक पुरानी हो जाने और उपकरण के पुराने पड़ जाने के कारण नये उपकरण लगाना।	5.00		15 एचपीटी तथा 60 एलपीटी के स्थान पर आटोमोड एलपीटी लगाना। **आंशिक परिणाम**	स्थलीय ट्रांसमिशन की गुणवत्ता तथा कवरेज में सुधार। **आंशिक परिणाम**	चरणबद्ध ढंग से पूरा होने की संभावना		ईएफसी का मूल्यकंन पूरा
2.	**स्टूडियो डिजीटलीकरण : आधुनिकीकरण, वृद्धि, स्टूडियो/ ओबी उपकरणों का प्रतिस्थापन**		**25.00**	**0.52**					
क.	स्टूडियो का डिजीटलीकरण	निर्माण, पोस्ट प्रोडक्शन, संपादन तथा अभिलेख सुविधाओं का पूर्ण डिजीटलीकरण।	20.00		छोटे केंद्रों पर 31 स्टूडियो का आंशिक से लेकर पूर्ण डिजिटलीकरण तथा आठ केंद्रों का पूर्ण डिजिटलीकरण।	उत्पादन सुविधाओं का पूर्ण डिजिटलीकरण।	चरणबद्ध ढंग से काम करना है	180 उपकरणों के लिए निविदा आमंतण प्रक्रियाधीन है। एक उपकरण की आपूर्ति	योजना अप्रैल 2010 में मंजूर
ख.	डिजिटलीकरण, वृद्धि तथा स्टूडियो उपकरणों का प्रतिस्थापन	निर्माण संबंधी उपकरणों का आधुनिकीकरण, वृद्धि तथा प्रतिस्थापन और इसके साथ डिजिटल काउंटर पार्ट को भी तकनीकी रूप से उपयुक्त पाया गया है।	5.00		सभी छोटे तथा 66 बड़े केंद्रों पर निर्माण, पोस्ट प्रोडेक्शन, आडियो, लाइटिंग तथा विद्युत आपूर्ति में वृद्धि। **आंशिक परिणाम**	तकनीकी गुणवत्ता में वृद्धि। **आंशिक परिणाम**	चरणबद्ध ढंग से काम करना है		ंएफसी का मूल्यकंन पूरा
3.	**डीटीएच : आधुनिकीकरण, वृद्धि, उपग्रह प्रसारण उपकरणों का प्रतिस्थापन**		**5.00**	**3.00**					

क.	डीटीएच	हाइब्रिड मॉडल के साथ डीटीएच पर चैनलों की संख्या 50 से बढ़ाकर 198 करना (फ्री-टू-एयर चैनल तथा पेड चैनल)			डीटीएच प्लेटफॉर्म का उन्नयन (59 से 97 चैनल)		चरणबद्ध ढंग से पूरा होने की संभावना	तैयारी करनी है	योजना अगस्त 2010 में मंजूर
ख.	उपग्रह प्रसारण उपकरणों का डिजिटलीकरण, वृद्धि तथा प्रतिस्थापन	पुराने हो चुके उपग्रह उपकरणों का आधुनिकीकरण, वृद्धि तथा नये डिजिटल उपकरणों द्वारा प्रतिस्थापन, समाचार जुटाने की सुविधा में वृद्धि।			10 अर्थ स्टेशन का उन्नयन	11 वीं योजना में चरणबद्ध ढंग से काम किया जाएगा।	चौथी तिमाही में 10 अर्थस्टेशन के लिए आर्डर दिया गया 3अर्थ स्टेशनों का उन्नयन।	6 डीएसएनजी के टेंडर मंगाए गए। 5 पीडीए के लिए टेंडर मिले और 5 अर्थ स्टेशन की निविदा प्राप्त	
4.	**एचडीटीवी**	एचडीटीवी प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन तथा प्रसारण सुविधा	15.00	7.10		एचडी फारमेट में प्रोडक्शन अपलिंकिंग और क्षेत्रीय प्रसारण	दिल्ली में एचडीटीवी अपलिंक सुविधा का काम पूरा		
					दिल्ली, मुंबई में एचडीटीवी प्रोडक्शन सुविधा		पहली तिमाही में कुछ उपकरणों के लिए आर्डर	तैयारी	
					दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के लिए पोस्ट प्रोडक्शन सुविधा		पहली तिमाही में कुछ उपकरण की आपूर्ति। चौथी तिमाही में आंशिक उपकरण की आपूर्ति।		
					दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता और चेन्नई के लिए फील्ड प्रोडक्शन सुविधा		चौथी तिमाही में उपकरण की आंशिक आपूर्ति। पहली तिमाही में आंशिक उपकरण का आदेश	निविदा आमंलित	
					दिल्ली में फ्लाई अवे प्रोडक्शन सेट अप		पहली तिमाही में उपकरणों के लिए ऑर्डर दिया		

5.	**स्टॉफ के लिए आवास और अन्य विविध योजना**	स्टाफ के लिए आवास सुविधा का प्रावधान विभिन्न स्टेशनों पर बुनियादी ढांचे में वृद्धि और सुरक्षा व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण	5.00	1.58	7 स्थानों पर स्टाफ क्वार्टर 22 स्थानों पर गेस्टहाउस 10 स्थानों पर कम्यूनिटी सेंटर, 17 स्थानों पर डीएमसी भवन 10 स्थानों पर एलपीटी भवन डीडी भवन, काम्प्लैक्स में टावर सी।	स्टाफ क्वार्टर, गेस्टहाउस, कम्यूनिटी सेंटर, डीएमसी भवन, एलपीटी भवन, जोनल ऑफिस के भवन, टावर सी भवन का निर्माण	11 वीं योजना में चरणबद्ध ढंग से काम सौंपा गया। एलपीटी भवन का निर्माण पूरा और चार डीएमसी भवन का निर्माण चौथी तिमाही में पूरा	सभी भवनों का डिजाइन तैयार। 42 परियोजनाओं की योजना अनुमान को मंजूरी।	
6.	**सॉफटवेयर अधिग्रहण और निर्माण**		5.00	0.00	एसएफसी अभी मंजूर नहीं				
	कुल		157.00	73.36					
	राजस्व		57.00	31.27					
	पूंजी		100.00	42.09					

प्रसार भारती

दूरदर्शन - वार्षिक योजना (2009-10)

परिणाम तथा परिणाम/लक्ष्य 2009-10

(करोड़ रुपये में)

क्रमांक	योजना/कार्यक्रम	उद्देश्य/परिणाम	लागत 2010-11 योजना बजट	व्यय (दिसंबर 10 तक)	विवरण योग्य परिणाम/भौतिक परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता		उपलब्धियां	टिप्पणियां/जोखिम
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		8.	9.
	चालू योजनाएं								
1	**जम्मू एवं कश्मीर के लिए विशेष पैकेज-चरण 1 और चरण 2 (पूंजी)**	जम्मू कश्मीर में दूरदर्शन कवरेज प्रसारण में सुधार। अमृतसर में टावर निर्माण के अतिरिक्त जम्मू एवं कश्मीर के विशेष पैकेज का पहला चरण कार्यान्वित हो गया है। अमृतसर में टावर निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके परिणामस्वरूप जम्मू एवं कश्मीर में दूरदर्शन प्रसारण की गुणवत्ता और कवरेज क्षेत्र में सुधार होगा। योजना के दूसरे चरण में कन्टेंट के सुधार पर जोर दिया जाएगा।	5.09	4.81	अमृतसर में 300 मीटर का टावर बनाया गया	सीमापारीय क्षेत्रों में डीडी 1 और डीडी न्यूज चैनल उपलब्ध कराना	अमृतसर में टावर का निर्माण कार्य पूर्ण	टावर की लंबाई 130 मीटर तक हो गई है। 282 मीटर तक बनाने के लिए टावर सामग्री साइट पर पहुंच चुकी है।	संस्था द्वारा धीमा काम
					अमृतसर में 300 मीटर ऊंचे टावर पर लगे एंटीना से डीडी 1 और डीडी न्यूज एचटीपी का आरंभ		अमृतसर में एचपीटी कार्य पूरा	भवन निर्माण हो चुका है। एंटीना का ऑर्डर दे दिया गया है। फीडर केबल साइट पर पहुंच चुकी है।	टावर 300 मीटर बनने और एंटीना व फीडर केबल ढोकर ले जाने के बाद इंस्टॉलेशन किया जाएगा, चूंकि मौजूदा ट्रांसमीटर (जो मौजूदा स्टेशन में लगा है) का भी उपयोग करना है।
	राजस्व		**30.00**	**27.87**					

(करोड़ रुपये में)

क्रमांक	योजना/कार्यक्रम	उद्देश्य/परिणाम	लागत 2010-11 योजना बजट	व्यय (दिसंबर 10 तक)	विवरण योग्य परिणाम/भौतिक परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता		उपलब्धियां	टिप्पणियां/जोखिम
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		8.	9.
2	निर्माण सुविधाओं (स्टूडियो-ओबी) का आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण	कार्यक्रमों की तकनीकी गुणवत्ता बढ़ाना	20.00	11.94	स्टूडियो केंद्र, केंद्रीकृत रिकॉर्डिंग, संपादन और प्लेबैक का सभी 17 मुख्य दूरदर्शन केंद्रों में आधुनिकीकरण। ओबी सुविधाओं का विस्तार और तेज न्यूज डिलिवरी प्रणाली	स्टूडियो का डिजिटलीकरण	वर्ष 2009-10 में चरणबद्ध तरीके से पूर्ण योजनाएं पूरी	मल्टी कैमरा ओवी वैन खरीद का आर्डर दिया गया	
3	पूर्वोत्तर के लिए विशेष पैकेज, चरण 2 (पूंजी)	पूर्वोत्तर और अंडमान और निकोबार क्षेत्र में दूरदर्शन कवरेज को मजबूत बनाना। पूर्वोत्तर क्षेत्र और अंडमान निकोबार एवं लक्षदीप के द्वीपीय इलाकों में दूरदर्शन सेवाओं के विस्तार और सुधार के लिए सरकार ने मई 2006 में 256.85 करोड़ रुपए (हार्डवेयर-134.3, सॉफ्टवेयर 122.55) की लागत से एक विशेष पैकेज (दूसरे चरण) को मंजूरी दी।	10.95	9.31	कोकराझार में 150 मीटर के 10 के डबल्यू एचपीटी टावर का कार्य पूर्ण		परियोजना पुर्ण	150 मीटर तक टावर बन चुका है।	
					कोकराझार में 150 मीटर के टावर पर लगे एंटीना के साथ 10 केवी के एचटीपी का आरंभ	और तकनीकी गुणवत्ता में सुधार। टीवी सिग्नल प्रदान करना		भवन निर्माण हो चुका है। विभागीय काम हो चुका है।	
					गुवाहाटी- 2 चैनल के अर्थ स्टेशन का आधुनिकीकरण।			गुवाहाटी में अतिरिक्त (2 प्लस 1) अपलिंक चेन का इंस्टॉलेशन हो चुका है।	

(करोड़ रुपये में)

क्रमांक	योजना/कार्यक्रम	उद्देश्य/परिणाम	लागत 2010-11 योजना बजट	व्यय (दिसंबर 10 तक)	विवरण योग्य परिणाम/भौतिक परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता	उपलब्धियां	टिप्पणियां/जोखिम
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
					अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के कवरेज के लिए (10 प्लस 1) सी बैंड स्टेशन		अर्थ स्टेशन का इंस्टॉलेशन हो चुका है। अंडमान निकोबार द्वीपसमूह के लिए सी बैंड की डीटीएच सेवा पर 17.09. 09 से काम शुरू हो चुका है।	
							1 डीएसएनजी यूनिट खरीदी जा चुकी है। एक यूनिट के लिए जनवरी में ऑर्डर दे दिया गया था, पर फर्म इसकी आपूर्ति नहीं कर पाई। 2 डीएसएनजी यूनिट्स का ऑर्डर अगस्त 09 में दे दिया गया था।	
							मार्च 08 में डीडी 1 और डीडी न्यूज के एचपीटी कमीशन किए गए थे।	
					तीनों वीएलपीटी कमीशन की जा चुकी हैं।		तीनों वीएलपीटी कमीशन की जा चुकी हैं।	
	राजस्व		**34.00**	**7.50**				

(करोड़ रुपये में)

क्रमांक	योजना/कार्यक्रम	उद्देश्य/परिणाम	लागत 2010-11 योजना बजट	व्यय (दिसंबर 10 तक)	विवरण योग्य परिणाम/भौतिक परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता		उपलब्धियां	टिप्पणियां/जोखिम
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		8.	9.
4	डीटीएच	इस योजना का उद्देश्य शेष बचे क्षेत्रों में टीवी कवरेज उपलब्ध कराना है। डीटीएच की वर्तमान क्षमता 50 टीवी चैनल हैं।	0.00	0.00	कार्य पूर्ण। बचे हुए भुगतान के लिए अनुदान प्रस्तुत।	डीटीएच सुविधा शुरू हो चुकी है	शून्य		कार्यरत है।
5	एडीटीवी	यह वह तकनीक है जो उत्कृष्ट पिक्चर और वाइट स्क्रीन इमेज के कार्यों में अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराती है। इस तकनीक से 35 एमएम फिल्म जैसी पिक्चर क्वालिटी मिलती है। यह तकनीक डिजिटल सराउंडिंग साउंड भी उपलब्ध कराती है। एचडीटीवी फिल्म प्रोडक्शन के लिए प्रायोगिक परियोजना का कार्य चालू है।	12.00	8.67	एचडीटीवी प्रोडक्शन के लिए एक फील्ड वैन	प्रायोगिक योजना एचडीटीवी फॉरमेट में निर्माण के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराएगी।	वर्ष 2009-10 में उपकरणों की आपूर्ति और उन्हें लगाना	ईपीएफ वैन खरीदी जा चुकी हैं। एचडीटीवी कैमकॉर्डर और आमंत्रित वीसीआर की खरीद की	
6	दसवीं योजना की अनुमानित योजना		86.75	54.84					
	स्टाफ के लिए आवास, बुनियादी ढांचे और सुरक्षा में वृद्धि	स्टाफ के लिए आवास सुविधा का प्रावधान। बुनियादी ढांचे में वृद्धि- विभिन्न स्टेशनों पर सुरक्षा को मजबूत करना।			चार मेट्रो शहरों में स्टाफ के लिए क्वार्टर	चार मेट्रो शहरों और 11 गैर मेट्रो शहरों पर स्टाफ के लिए आवास का निर्माण तथा बुनियादी ढांचे व	स्टाफ के लिए आवासों का काम पूरा हो चुका है।		

(करोड़ रुपये में)

क्रमांक	योजना/कार्यक्रम	उद्देश्य/परिणाम	लागत 2010-11 योजना बजट	व्यय (दिसंबर 10 तक)	विवरण योग्य परिणाम/भौतिक परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता		उपलब्धियां	टिप्पणियां/जोखिम
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		8.	9.
					11 मेट्रो शहरों में स्टाफ के लिए क्वार्टर विभिन्न दूरदर्शन केंद्रों पर सुरक्षा और बुनियादी ढांचे में वृद्धि			निविदा निकाली गई है। 8 स्थानो पर स्टाफ क्वार्टर बनाए जा चुके हैं। बैंगलोर, पटना और संभलपुर में क्वार्टर बनाए जा रहे हैं।	लखनऊ, जयपुर, वाराणसी, भवानीपटना, हिसार, इलाहाबाद, त्रिचूर और इटानगर में स्टाफ क्वार्टर बन गए हैं।
	अन्य योजनाएं								
	स्टूडियो संबंधी योजना	स्टूडियो केंद्रों के निर्माण और उत्पादन सुविधाओं की वृद्धि से स्थानीय प्रतिभाओं को अवसर प्रदान करना।			7 स्टूडियो की स्थापना	नेटवर्क में शामिल स्टूडियो में निर्माण की गुणवत्ता में सुधार	चंडीगढ़ (अतिरिक्त), जम्मू (अतिरिक्त) और लेह में स्टूडियो परियोजना पूर्ण	चंडीगढ़, लेह, जम्मू में भवन निर्माण का काम पूरा हो गया है। इन स्थानों पर इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है। देहरादून और तिरुपति में भवन निर्माण का काम चल रहा है।	पणजी और गोरखपुर में स्टूडियो वर्ष 2009-10 से पहले ही बन गए हैं।
	ट्रांसमीटर संबंधी योजना	क्षेत्रीय कवरेज में सुधार			3 ऑटोमोड एलपीटी और एचटीपी	क्षेत्रीय प्रसारण तथा कवरेज क्षेत्र की गुणवत्ता में सुधार	एचपीटी महबूबनगर का कार्य प्रगति पर है। एचपीटी बिलासपुर, कुन्नूर और कुंभकोणम का कार्य प्रगति पर है। एलीपीटी ऑटोमोड की खरीद और इंस्टॉलेशन।	11 एलपीटी के इंस्टॉलेशन का काम पूरा हो गया है। 29 स्थानों पर काम चल रहा है। 50 एलपीटी खरीदने का काम चल रहा है। नए टेंडर मिल चुके हैं। ट्रांसमीटर का ऑर्डर दिया जा चुका है। तीसरे स्थान (महबूबनगर) में भवन निर्माण का काम चल रहा है। टावर और ट्रांसमीटर उपकरण के लिए ऑर्डर देने का काम चल रहा है।	तकनीकी कारणों से 50 एलपीटी के लिए प्राप्त निविदाओं को रद्द कर दिया गया है। नई निविदाओं पर काम चल रहा है। एचपीटी सहरसा शुरू हो चुका है।

(करोड़ रुपये में)

क्रमांक	योजना/कार्यक्रम	उद्देश्य/परिणाम	लागत 2010–11 योजना बजट	व्यय (दिसंबर 10 तक)	विवरण योग्य परिणाम/भौतिक परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता		उपलब्धियाँ	टिप्पणियां/जोखिम
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		8.	9.
	नई योजना								
1.	ट्रांसमीटर का डिजिटलीकरण, आधुनिकीकरण, ट्रांसमीटर उपकरणों का संवर्धन और नए उपकरण लगाना		1.00						अनुमति/ अनुसमर्थन जारी करना है।
	क) ट्रांसमीटर का डिजिटलीकरण	क्षेत्रीय प्रसारण का डिजिटलीकरण			40 डीटीटी ट्रांसमीटर के लिए उपकरणों की खरीद (आंशिक परिणाम)	क्षेत्रीय प्रसारण के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया शुरू (आंशिक परिणाम)	11 वीं योजना में चरणबद्ध तरीके से पूर्ण होने की संभावना		अप्रैल 2010 में स्कीम अनुमोदित
	ख) ट्रांसमीटर उपकरणों का आधुनिकीकरण, संवर्धन और दूसरे उपकरण लगाना	ट्रांसमीटर उपकरणों का आधुनिकीकरण, संवर्धन और तकनीक पुरानी हो जाने और उपकरण के पुराने पड़ जाने के कारण नए उपकरण लगाना।			15 एचटीपी और 60 एलपीटी के स्थान पर ऑटोमोड एलपीटी लगाना (आंशिक परिणाम)	क्षेत्रीय प्रसारण की गुणवत्ता और कवरेज में सुधार (आंशिक परिणाम)	11 वीं योजना में चरणबद्ध तरीके से पूर्ण होने की संभावना		स्कीम स्वीकृत होनी है।

(करोड़ रुपये में)

क्रमांक	योजना/कार्यक्रम	उद्देश्य/परिणाम	लागत 2010-11 योजना बजट	व्यय (दिसंबर 10 तक)	विवरण योग्य परिणाम/भौतिक परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता		उपलब्धियां	टिप्पणियां/जोखिम
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		8.	9.
	ग) आपदा प्रबंधन, आपातकालीन आवश्यकताएं	आपदा प्रबंधन और आपातकालीन जरूरतें।			आपदा प्रबंधन और आपातकालीन उपकरणों की खरीद (आंशिक परिणाम)	आंशिक परिणाम	11 वीं योजना में चरणबद्ध तरीके से पूर्ण की जाएगी।		
2.	स्टूडियो डिजिटलीकरण : आधुनिकीकरण, संवर्धन, स्टूडियो-ओबी उपकरणों का प्रतिस्थापन		1.00	0.00					
	क) स्टूडियो का डिजिटलीकरण	निर्माण, पोस्ट प्रोडक्शन, संपादन और अभिलेख सुविधाओं का पूर्ण डिजिटलीकरण			छोटे केंद्रों के 31 स्टूडियो का आंशिक और पूर्ण डिजिटलीकरण और 8 केंद्रों का पूर्ण डिजिटलीकरण (आंशिक परिणाम)	प्रोडक्शन सुविधा का पूर्ण डिजिटलीकरण (आंशिक परिणाम)	11 वीं योजना में चरणबद्ध तरीके से पूर्ण की जाएगी		स्कीम अप्रैल 2010 में स्वीकृत
	ख) स्टूडियो उपकरणों का डिजिटलीकरण, संवर्धन और प्रतिस्थापन	निर्माण संबंधी उपकरणों का आधुनिकीकरण, संवर्धन और प्रतिस्थापन, क्योंकि बदलती तकनीक के कारण वे उपकरण पुराने पड़ गए हैं।			सभी छोटे और 66 बड़े केंद्रों पर निर्माण, पोस्ट प्रोडक्शन, ऑडियो लाइटिंग और विद्युत आपूर्ति में वृद्धि (आंशिक परिणाम)	तकनीकी गुणवत्ता में वृद्धि (आंशिक परिणाम)	11 वीं योजना में चरणबद्ध तरीके से पूर्ण की जाएगी		स्कीम स्वीकृत होनी है।

(करोड़ रुपये में)

क्रमांक	योजना/कार्यक्रम	उद्देश्य/परिणाम	लागत 2010-11 योजना बजट	व्यय (दिसंबर 10 तक)	विवरण योग्य परिणाम/भौतिक परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता		उपलब्धियां	टिप्पणियां/जोखिम
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		8.	9.
	ग) ई गवर्नेस, सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी योजनाएं	नेटवर्क में ई गवर्नेस का समावेश तथा कार्यान्वयन			ई गवर्नेस, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित कार्य प्रवाह, प्रबंधन प्रणाली और स्टूडियो संचालन (आंशिक परिणाम)	डिलिवरी की प्रभावी प्रणाली (आंशिक परिणाम)	11 वीं योजना में चरणबद्ध तरीके से पूर्ण की जाएगी		
	घ) अनुसंधान और विकास एवं प्रशिक्षण	नेटवर्क में प्रशिक्षण तथा अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं की वृद्धि			प्रशिक्षण और अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं में वृद्धि, एक स्थान पर उच्च स्तरीय तकनीकी संस्थान, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए गुवाहाटी में एसटीआईटी (आंशिक परिणाम)	आंशिक परिणाम	11 वीं योजना में चरणबद्ध तरीके से पूर्ण की जाएगी		
3.	डीटीएच : आधुनिकीकरण, संवर्धन और सेटेलाइट ब्रॉडकास्ट उपकरणों का प्रतिस्थापन		5.00	0.58					
	क) डीटीएच	डीटीएच प्लेटफार्म में चैनलों को बढ़ाना			डीटीएट प्लेटफार्म पर चैनलों में वृद्धि	आंशिक परिणाम	11 वीं योजना में चरणबद्ध तरीके से पूर्ण की जाएगी		योजना को मंजूरी मिलनी बाकी है।

(करोड़ रुपये में)

क्रमांक	योजना/कार्यक्रम	उद्देश्य/परिणाम	लागत 2010-11 योजना बजट	व्यय (दिसंबर 10 तक)	विवरण योग्य परिणाम/भौतिक परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता		उपलब्धियां	टिप्पणियां/जोखिम
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		8.	9.
	ख) सेटेलाइट ब्रॉडकास्ट उपकरणों का डिजिटलीकरण, संवर्धन और प्रतिस्थापन	पुराने हो चुके सेटेलाइट उपकरणों का आधुनिकीकरण, संवर्धन और नए डिजिटल उपकरणों द्वारा प्रतिस्थापन, समाचार जुटाने की सुविधा में वृद्धि			अर्थ स्टेशन का उन्नयन, वी सेट की संख्या 10 करना, 50 वी सेट टर्मिनल, 9 नए डीएसएनजी, 6 पुराने डीएसएनजी और अन्य उपकरणों के प्रतिस्थापन के साथ 5 नए अर्थ स्टेशन (आंशिक परिणाम)	प्रगति पर	11 वीं योजना में चरणबद्ध तरीके से पूर्ण की जाएगी	सीपीसी में 5 चैनल एमसीपीसी के कंप्रेशन उपकरण को बदलने के लिए निविदा मांगी गई हैं। 6 डीएसएनजी वैन के एसआईटीसी के लिए निविदा जारी सीपीसी और डीडीके श्रीनगर में अपलिंक पीडीए के एसआईटीसी के लिए निविदा जारी	अनुमति मिल चुकी है। अनुसमर्थन फरवरी 09 में जारी किया जा चुका है।
	एचडीटीवी	एचडीटीवी प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन और प्रसारण सुविधा	16.00	0.00	दिल्ली और मुंबई में एचडीटीवी प्रोडक्शन सुविधा, दिल्ली में प्लेआउट एक्टिविटी, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में पोस्ट प्रोडक्शन सुविधा, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के लिए फील्ड प्रोडक्शन सुविधा, दिल्ली, मुंबई में आउटडोर प्रोडक्शन सुविधा के लिए मल्टी मीडिया कैमरा	प्रगति पर	11 वीं योजना में चरणबद्ध तरीके से पूर्ण की जाएगी	सीसीईए द्वारा योजना स्वीकृत। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के लिए एचडीटीवी ट्रांसमीटर के लिए एनआईटी जारी	फरवरी, 09 में अनुमति मिल चुकी है।

(करोड़ रुपये में)

क्रमांक	योजना/कार्यक्रम	उद्देश्य/परिणाम	लागत 2010-11 योजना बजट	व्यय (दिसंबर 10 तक)	विवरण योग्य परिणाम/भौतिक परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता		उपलब्धियां	टिप्पणियां/जोखिम
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		8.	9.
					मोबाइल उपकरण, दिल्ली में फ्लाईअवे प्रोडक्शन सेट अप, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के लिए परव्यू सुविधा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में एचडीटीवी ट्रांसमीटर, एचडीटीवी अपलिंक				
5.	स्टाफ के लिए आवास, अन्य कार्य	स्टाफ के लिए आवास सुविधा का प्रावधान। विभिन्न स्टेशनों पर बुनियादी ढांचे में वृद्धि और सुरक्षा व्यवस्था का सुदृढीकरण	5.00	0.01	17 स्थानों पर डीएमसी बिल्डिंग, 10 स्थानों पर एलपीटी, 7 स्थानों पर स्टाफ क्वार्टर, 22 स्थानों पर गेस्ट हाउस, गुवाहाटी में जोनल ऑफिस बिल्डिंग, डीडी भवन में टावर सी तथा अन्य बुनियादी ढांचे और सुरक्षा संबंधित कार्य	प्रगति पर	11 वीं योजना में चरणबद्ध तरीके से पूर्ण की जाएगी	सभी भवनों के लिए स्थान तय। एलपीटी भवनों, डीएमसी बिल्डिंग, गेस्ट हाउस और सामुदायिक केंद्रों के लिए टाइप डिजाइन। भवन योजना और योजना अनुमान तैयार किए जा रहे हैं। टावर सी के लिए योजना अनुमान मंजूरी की प्रक्रिया में हैं।	फरवरी, 09 में अनुमति मिल चुकी है।

(करोड़ रुपये में)

क्रमांक	योजना/कार्यक्रम	उद्देश्य/परिणाम	लागत 2010–11 योजना बजट	व्यय (दिसंबर 10 तक)	विवरण योग्य परिणाम/भौतिक परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता	उपलब्धियां	टिप्पणियां/जोखिम
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
6.	**सॉफ्टवेयर अधिग्रहण**		**24.21**	**0.00**				
	कुल		**251.00**	**125.53**				
		राजस्व	**88.21**	**35.37**				
		पूंजी	**162.79**	**90.16**				

अध्याय-5

वित्तीय समीक्षा
2008-2009

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई का नाम/गतिविधि	बजट अनुमान 2008-2009			संशोधित अनुमान 2008-2009			वास्तविक 2008-2009		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
राजस्व खंड									
प्रमुख शीर्ष '2251' - सचिवालय सामाजिक सेवाएं									
1. मुख्य सचिवालय (पीएओ सहित)	**115700**	**213500**	**329200**	**100800**	**290750**	**391550**	**91514**	**283754**	**375268**
प्रमुख शीर्ष - '2205' - सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों का कला और संस्कृति से संबंधित प्रमाणन									
2. केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड	14200	31200	45400	5500	46600	52100	5977	45344	51321
3. फिल्म प्रमाणन अपीलीय ट्रिब्यूनल	0	1200	1200	0	1500	1500	0	1381	1381
कुल प्रमुख शीर्ष '2205'	**14200**	**32400**	**46600**	**5500**	**48100**	**53600**	**5977**	**46725**	**52702**
प्रमुख शीर्ष - '2220' - सूचना, फिल्म और प्रचार									
4. फिल्म प्रभाग	110000	249700	359700	110000	302150	412150	59488	304765	364253
5. फिल्म समारोह निदेशालय	40000	65765	105765	40000	65445	105445	32119	69929	102048
6. भारत का राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार	30000	16400	46400	30000	22450	52450	17623	24372	41995
7. सत्यजीत रे फिल्म और टेली. संस्थान, कोलकाता का अनुदान सहायता	80000	50735	130735	80000	52580	132580	40000	52100	92100
8. बाल फिल्म समिति को अनुदान सहायता	40000	8400	48400	40000	9700	49700	40000	9700	49700
9. भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे को अनुदान सहायता	80000	77500	157500	56900	93267	150167	54400	93267	147667
10. फिल्म सोसायटी को अनुदान सहायता	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानीटरिंग केंद्र	0	30000	30000	0	30000	30000	0	6240	6240
12. गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग	10000	12800	22800	2300	16256	18556	1483	16498	17981
13. आईआईएमसी को अनुदान सहायता	10000	39500	49500	100	47994	48094	0	46030	46030
14. विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय	217600	526000	743600	481800	533100	1014900	481734	707470	1189204
15. पत्र सूचना कार्यालय	109089	223600	332689	109089	296226	405315	101776	293376	395152
16. भारतीय प्रेस परिषद को अनुदान सहायता	0	26300	26300	0	31604	31604	0	31604	31604
17. पीटीआई के ऋण पर ब्याज के बदले रियायत	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई का नाम/गतिविधि	बजट अनुमान 2008-2009			संशोधित अनुमान 2008-2009			वास्तविक 2008-2009		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
18. विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0	200	200	0	100	100	0	0	0
19. पत्रकार कल्याण कोष में हस्तांतरण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय	4900	262500	267400	4900	331428	336328	4129	323987	328116
21. गीत एवं नाटक प्रभाग	35600	155400	191000	35600	193850	229450	32867	186271	219138
22. प्रकाशन विभाग	4300	140500	144800	4300	198630	202930	4086	192676	196762
23. रोजगार समाचार	600	281900	282500	600	255715	256315	519	242006	242525
24. भारत का समाचारपत्र पंजीयक	2000	23400	25400	1500	28900	30400	1469	29278	30747
25. फोटो प्रभाग	5500	24300	29800	5500	27630	33130	5028	28381	33409
26. संचार के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में योगदान	0	1400	1400	0	1400	1400	0	1550	1550
27. एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान के लिए योगदान	0	2000	2000	0	2000	2000	0	1560	1560
कुल : प्रमुख शीर्ष '2220'	**779589**	**2218300**	**2997889**	**1002589**	**2540425**	**3543014**	**876721**	**2661060**	**3537781**
कुल प्रमुख शीर्ष 2251, 2205 और 2220	**909489**	**2464200**	**3373689**	**1108889**	**2879275**	**3988164**	**974212**	**2991539**	**3965751**

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई का नाम/गतिविधि	बजट अनुमान 2008-2009			संशोधित अनुमान 2008-2009			वास्तविक 2008-2009		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
प्रसारण (प्रमुख शीर्ष-2221)									
ध्वनि प्रसारण (उप प्रमुख शीर्ष)									
निर्देशन और प्रशासन (लघु शीर्ष)									
वेतन	100	100	200	100	100	200	0	0	0
टेलीविजन (उप प्रमुख शीर्ष)									
वेतन	100	100	200	100	100	200	0	0	0
सामान्य (उप प्रमुख शीर्ष)									
प्रसार भारती (लघु शीर्ष)									
सहायता अनुदान	1787371	9636300	11423671	1325471	11371225	12696696	759600	11429800	12189400
कुल-प्रसारण	**1787571**	**9636500**	**11424071**	**1325671**	**11371425**	**12697096**	**759600**	**11429800**	**12189400**
पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के फायदे के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र अन्य व्यय योजना									
एकमुश्त प्रावधान (प्रमुख शीर्ष-2552)	179640	0	179640	336040	0	336040	0	0	0
कुल-राजस्व खंड	**2876700**	**12100700**	**14977400**	**2770600**	**14250700**	**17021300**	**1733812**	**14421339**	**16155151**

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई का नाम/गतिविधि	बजट अनुमान 2008-2009			संशोधित अनुमान 2008-2009			वास्तविक 2008-2009		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
पूंजी खंड									
1. फिल्म प्रभाग हेतु उपकरण का अधिग्रहण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. पत्र सूचना कार्यालय हेतु उपकरण का अधिग्रहण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय हेतु उपकरण का अधिग्रहण	15100	0	15100	15100	0	15100	13948	0	13948
4. गीत एवं नाटक प्रभाग हेतु उपकरण का अधिग्रहण	400	0	400	400	0	400	204	0	204
5. फोटो प्रभाग हेतु उपकरण का अधिग्रहण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. मुख्य सचिवालय हेतु उपकरण का अधिग्रहण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. भारतीय जनसंचार संस्थान हेतु उपकरण का अधिग्रहण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता हेतु उपकरण का अधिग्रहण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे हेतु उपकरण का अधिग्रहण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड हेतु उपकरण का अधिग्रहण	5800	0	5800	4000	0	4000	1610	0	1610
11. फिल्म समारोह निदेशालय में प्रिंट इकाई के स्तर में सुधार	3000	0	3000	100	0	100	0	0	0
12. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग केंद्र	71000	0	71000	71000	0	71000	55000	0	55000
13. प्रकाशन विभाग हेतु उपकरण का अधिग्रहण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.. एम्पलायमेंट न्यूज हेतु उपकरण का अधिग्रहण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
बी- भवन									
15. फिल्म प्रभाग हेतु बहु-मंजिला भवन - प्रमुख कार्य	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. चलचित्र संग्रहालय की स्थापना (फिल्म प्रभाग) - प्रमुख कार्य	50000	0	50000	2000	0	2000	1752	0	1752
17. नाइट्रेट वॉल्ट्स/कर्मचारी आवास (एनएफएआई हेतु) निर्माण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. एनएफएआई परिसर हेतु दूसरे चरण का भवन निर्माण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. फिल्म समारोह परिसर - अतिरिक्त और वैकल्पिक-प्रमुख कार्य	40000	0	40000	40000	0	40000	39805	0	39805
20. कोलकाता में फिल्म और टेलीविजन संस्थान की स्थापना, भूमि अधिग्रहण और भवन निर्माण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. सूचना भवन का निर्माण - प्रमुख कार्य	35300	0	35300	35300	0	35300	17620	0	17620
22. क्षेत्रीय प्रचार हेतु कार्यालय और आवासीय परिसर का निर्माण - प्रमुख कार्य	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. पत्र सूचना कार्यालय हेतु राष्ट्रीय प्रेस केन्द्र और मिनी मीडिया केन्द्र की स्थापना	43700	0	43700	43700	0	43700	0	0	0

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई का नाम/गतिविधि	बजट अनुमान 2008-2009			संशोधित अनुमान 2008-2009			वास्तविक 2008-2009		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
24. भारतीय प्रेस परिषद हेतु भवन का निर्माण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. आईआईएमसी हेतु भवन निर्माण तथा आवास परियोजना	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. निजी एफएम रेडियो स्टेशनों के लिए भवन और टावर	1000	0	1000	1000	0	1000	1000	0	1000
27. मास मीडिया संस्थान की स्थापना	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. इलेक्ट्रोनिक मीडिया मॉनिटरिंग केंद्र	4000	0	4000	4000	0	4000	0	0	0
निवेश									
इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स (इंडिया) लिमिटेड	80000	0	80000	100	0	100	0	0	0
कुल - पूंजी खंड प्रमुख शीर्ष '4220'	**349300**	**0**	**349300**	**216700**	**0**	**216700**	**130939**	**0**	130939
सूचना और प्रचार हेतु ऋण (प्रमुख शीर्ष - 6220) फिल्म (उप प्रमुख शीर्ष) सार्वजनिक क्षेत्र और अधीन उपक्रमों के लिए ऋण **(लघु शीर्ष)** राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ऋण और अग्रिम राशि	0	0	0	0	0	0	0	0	0
प्रसारण के लिए ऋण (प्रमुख शीर्ष - 6221) **सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य अधीन उपक्रमों के लिए ऋण** **प्रसार भारती** ऋण और अग्रिम राशि	3264000	0	3264000	2616600	0	2616600	2383100	0	2383100
पूर्वोत्तर क्षेत्र पर पूंजी व्यय और अन्य लागत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के हित में परियोजना/योजना (प्रमुख शीर्ष - 4552) क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के लिए एकमुश्त प्रावधान	0	0	0	0	0	0	0	0	0
पूर्वोत्तर क्षेत्र पर पूंजी व्यय और अन्य लागत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के हित में परियोजना/योजना (प्रमुख शीर्ष - 6552)									
प्रसार भारती	510000	0	510000	396100	0	396100	0	0	0
कुल - पूंजी खंड	4123300	0	4123300	3229400	0	3229400	2514039	0	2514039
कुल - मांग संख्या - 59	7000000	12100700	19100700	6000000	14250700	20250700	4247851	14421339	18669190

वित्तीय समीक्षा
2009-2010

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई का नाम/गतिविधि	बजट अनुमान 2008-2009			संशोधित अनुमान 2008-2009			वास्तविक 2008-2009		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
राजस्व खंड									
प्रमुख शीर्ष '2251' - सचिवालय सामाजिक सेवाएं									
1. मुख्य सचिवालय (पीएओ सहित)	**135000**	**394900**	**529900**	**130400**	**380100**	**510500**	**117487**	**367730**	**485217**
प्रमुख शीर्ष - '2205' - सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों का कला और संस्कृति से संबंधित प्रमाणन									
2. केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड	13500	56000	69500	7000	55300	62300	6208	50927	57135
3. फिल्म प्रमाणन अपीलीय ट्रिब्यूनल	0	2000	2000	0	2000	2000	0	1875	1875
कुल प्रमुख शीर्ष '2205'	**13500**	**58000**	**71500**	**7000**	**57300**	**64300**	**6208**	**52802**	**59010**
प्रमुख शीर्ष - '2220' - सूचना, फिल्म और प्रचार									
4. फिल्म प्रभाग	63000	378900	441900	68000	360600	428600	70130	354523	424653
5. फिल्म समारोह निदेशालय	42700	75700	118400	42700	97200	139900	40518	96479	136997
6. भारत का राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार	40000	25200	65200	70000	31000	101000	69988	29472	99460
7. सत्यजीत रे फिल्म और टेली. सं., कोलकाता का अनुदान सहायता	70000	60000	130000	70000	60000	130000	42500	60000	102500
8. बाल फिल्म समिति को अनुदान सहायता	40000	11200	51200	40000	17500	57500	40000	17500	57500
9 भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे को अनुदान सहायता	60000	95000	155000	95000	129400	224400	93500	129400	222900
10. फिल्म सोसायटी को अनुदान सहायता	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानीटरिंग केंद	0	48000	48000	0	28700	28700	0	26793	26793
12. गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग	11800	20000	31800	3000	19700	22700	1193	18216	19409
13. आईआईएमसी को अनुदान सहायता	7000	50000	57000	7000	78500	85500	2000	78500	80500
14. विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय	268800	648700	917500	368800	670000	1038800	368130	672138	1040268
15. पत्र सूचना कार्यालय	190300	342200	532500	190300	372600	562900	175558	369207	544765
16. भारतीय प्रेस परिषद को अनुदान सहायता	0	35000	35000	0	45600	45600	0	45600	45600
17. पीटीआई के ऋण पर ब्याज के बदले रियायत	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0	100	100	0	100	100	0	0	0
19. पत्रकार कल्याण कोष में हस्तांतरण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय	4900	412700	417600	4900	406600	411500	4168	411120	415288
21. गीत एवं नाटक प्रभाग	40000	200200	240200	40000	222500	262500	43496	228331	271827
22. प्रकाशन विभाग	1900	241400	243300	1900	246900	248800	1649	233964	235613

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई का नाम/गतिविधि	बजट अनुमान 2008-2009			संशोधित अनुमान 2008-2009			वास्तविक 2008-2009		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
23. रोजगार समाचार	500	285900	286400	500	231900	232400	482	226959	227441
24. भारत का समाचारपत्र पंजीयक	1700	39100	40800	1700	38600	40300	1578	36615	38193
25. फोटो प्रभाग	7000	33500	40500	21000	38000	59000	20947	37939	58886
26. संचार के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में योगदान	0	1400	1400	0	1500	1500	0	1370	1370
27. एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान के लिए योगदान	0	2000	2000	0	2000	2000	0	1780	1780
कुल : प्रमुख शीर्ष '2220'	**849600**	**3006200**	**3855800**	**1024800**	**3098900**	**4123700**	**975837**	**3075906**	**4051743**
कुल : प्रमुख शीर्ष 2251, 2205 और 2220	**998100**	**3459100**	**4457200**	**1162200**	**3536300**	**4698500**	**1099532**	**3496438**	**4595970**

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई का नाम/गतिविधि	बजट अनुमान 2008-2009			संशोधित अनुमान 2008-2009			वास्तविक 2008-2009		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
प्रसारण (प्रमुख शीर्ष-2221)									
ध्वनि प्रसारण (उप प्रमुख शीर्ष)									
निर्देशन और प्रशासन (लघु शीर्ष)									
वेतन	100	100	200	100	100	200	0	0	0
टेलीविजन (उप प्रमुख शीर्ष)									
वेतन	100	100	200	100	100	200	0	0	0
सामान्य (उप प्रमुख शीर्ष)									
प्रसार भारती (लघु शीर्ष)									
अनुदान सहायता	2131900	14221400	16353300	1754600	12464200	14218800	1935000	12472150	14407150
कुल-प्रसारण	**2132100**	**14221600**	**16353700**	**1754800**	**12464400**	**14219200**	**1935000**	**12472150**	**14407150**
पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के फायदे के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र अन्य व्यय योजना									
एकमुश्त प्रावधान (प्रमुख शीर्ष-2552)	389700	0	389700	249700	0	249700	0	0	0
कुल-राजस्व खंड	**3519900**	**17680700**	**21200600**	**3166700**	**16000700**	**19167400**	**3034532**	**15968588**	**19003120**

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई का नाम/गतिविधि	बजट अनुमान 2008-2009			संशोधित अनुमान 2008-2009			वास्तविक 2008-2009		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
पूंजी खंड									
1. फिल्म प्रभाग हेतु उपकरण का अधिग्रहण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. पत्र सूचना कार्यालय हेतु उपकरण का अधिग्रहण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय हेतु उपकरण का अधिग्रहण	8500	0	8500	8500	0	8500	9450	0	9450
4. गीत एवं नाटक प्रभाग हेतु उपकरण का अधिग्रहण	500	0	500	500	0	500	468	0	468
5. फोटो प्रभाग हेतु उपकरण का अधिग्रहण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. मुख्य सचिवालय हेतु उपकरण का अधिग्रहण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. भारतीय जनसंचार संस्थान हेतु उपकरण का अधिग्रहण	10000	0	10000	10000	0	10000	0	0	0
8. सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता का अधिग्रहण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे हेतु उपकरण का अधिग्रहण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड हेतु उपकरण का अधिग्रहण	5000	0	5000	5000	0	5000	3099	0	3099
11. फिल्म समारोह निदेशालय में प्रिंट इकाई के स्तर में सुधार	100	0	100	100	0	100	93	0	93
12. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग केंद्र-मशीनरी तथा उपकरण	18000	0	18000	18000	0	18000	18000	0	18000
13. प्रकाशन विभाग हेतु उपकरण का अधिग्रहण	1000	0	1000	1000	0	1000	976	0	976
14.. रोज़गार समाचार हेतु उपकरण का अधिग्रहण	100	0	100	100	0	100	100	0	100
बी- भवन									
15. फिल्म प्रभाग हेतु बहु-मंजिला भवन - प्रमुख कार्य	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. चलचित्र संग्रहालय की स्थापना (फिल्म प्रभाग)- प्रमुख कार्य	125000	0	125000	125000	0	125000	125000	0	125000
17. नाइट्रेट वॉल्ट्स/कर्मचारी आवास (एनएफएआई हेतु) निर्माण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. एनएफएआई परिसर हेतु दूसरे चरण का भवन निर्माण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. फिल्म समारोह परिसर - अतिरिक्त और वैकल्पिक - प्रमुख कार्य	39000	0	39000	39000	0	39000	39000	0	39000
20. कोलकाता में फिल्म और टेलीविजन संस्थान की स्थापना, - भूमि अधिग्रहण और भवन निर्माण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. सूचना भवन का निर्माण - प्रमुख कार्य	100000	0	100000	100000	0	100000	100000	0	100000
22. क्षेत्रीय प्रचार हेतु कार्यालय और आवासीय परिसर का निर्माण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. पत्र सूचना कार्यालय हेतु राष्ट्रीय प्रेस केन्द्र और मिनी मीडिया केन्द्र की स्थापना	50000	0	50000	40000	0	40000	40000	0	40000
24. भारतीय प्रेस परिषद हेतु भवन का निर्माण	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई का नाम/गतिविधि	बजट अनुमान 2009-2010			संशोधित अनुमान 2009-2010			वास्तविक 2009-2010		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
25. आईआईएमसी हेतु भवन निर्माण तथा आवास परियोजना	20000	0	20000	20000	0	20000	1750	0	1750
26. निजी एफएम रेडियो स्टेशनों के लिए भवन और टावर	32000	0	32000	32000	0	32000	10889	0	10889
27. मास मीडिया संस्थान की स्थापना	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. इलेक्ट्रोनिक मीडिया मॉनिटरिंग केंद्र	2000	0	2000	2000	0	2000	2000	0	2000
निवेश									
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम	100	0	100	100	0	100	0	0	0
कुल - पूंजी खंड प्रमुख शीर्ष '4220'	**411300**	**0**	**411300**	**401300**	**0**	**401300**	**350825**	**0**	350825
सूचना और प्रचार हेतु ऋण (प्रमुख शीर्ष - 6220)									
फिल्म (उप प्रमुख शीर्ष)									
सार्वजनिक क्षेत्र और अधीन उपक्रमों के लिए ऋण									
(लघु शीर्ष)									
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम									
ऋण और अग्रिम राशि	0	0	0	0	0	0	0	0	0
प्रसारण के लिए ऋण (प्रमुख शीर्ष - 6221)									
सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य अधीन उपक्रमों के लिए ऋण									
प्रसार भारती									
ऋण और अग्रिम राशि	3558400	0	3558400	1302100	0	1302100	1348500	0	1348500
पूर्वोत्तर क्षेत्र पर पूंजी व्यय और अन्य लागत									
पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के हित में परियोजना/योजना									
(प्रमुख शीर्ष - 4552)									
क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के लिए उपकरणों का अधिग्रहण	900	0	900	900	0	900	0	0	0
पूर्वोत्तर क्षेत्र पर पूंजी व्यय और अन्य लागत									
पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के हित में परियोजना/योजना									
(प्रमुख शीर्ष - 6552)									
प्रसार भारती	509500	0	509500	199000	0	199000	0	0	0
कुल - पूंजी खंड	**4480100**	**0**	**4480100**	**1903300**	**0**	**1903300**	**1699325**	**0**	**1699325**
कुल - मांग संख्या - 59	**8000000**	**17680700**	**25680700**	**5070000**	**16000700**	**21070700**	**4733857**	**15968588**	**20702445**

वित्तीय समीक्षा
2009-2010

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई का नाम/गतिविधि	बजट अनुमान 2010-2011			संशोधित अनुमान 2010-2011		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
राजस्व खंड						
प्रमुख शीर्ष '2251'–सचिवालय सामाजिक सेवाएं						
1. मुख्य सचिवालय (पीएओ सहित)	**170100**	**380700**	**550800**	**153100**	**369300**	**522400**
प्रमुख शीर्ष – '2205' – सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों का कला और संस्कृति से संबंधित प्रमाणन						
2. केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड	13000	55000	68000	13000	58300	71300
3. फिल्म प्रमाणन अपीलीय ट्रिब्यूनल	0	2000	2000	0	2000	2000
कुल प्रमुख शीर्ष '2205'	13000	57000	70000	13000	60300	73300
प्रमुख शीर्ष – '2220' – सूचना, फिल्म और प्रचार						
4. फिल्म प्रभाग	56000	380000	436000	56000	373400	429400
5. फिल्म समारोह निदेशालय	45000	79200	124200	45000	86400	131400
6. भारत का राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार	50000	31500	81500	89000	38500	127500
7. सत्यजीत रे फिल्म और टेली. संस्थान, कोलकाता को अनुदान सहायता	70000	60000	130000	70000	61800	131800
8. बाल फिल्म समिति को अनुदान सहायता	40000	14300	54300	40000	15300	55300
9. भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे को अनुदान सहायता	80000	125000	205000	72000	144400	216400
10. फिल्म सोसायटी को अनुदान सहायता	0	0	0	0	0	0
11. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानीटरिंग केंद्र	21800	41000	62800	0	43600	43600
12. गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग	2500	19700	22200	1000	18900	19900
13. आईआईएमसी को अनुदान सहायता	7000	67000	74000	7000	71700	78700
14. विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय	445000	622800	1067800	445000	643700	1088700
15. पत्र सूचना कार्यालय	345000	368800	713800	340000	381700	721700
16. भारतीय प्रेस परिषद को अनुदान सहायता	0	42100	42100	0	48900	48900
17. पीटीआई के ऋण पर ब्याज के बदले रियायत	0	0	0	0	0	0
18. विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0	100	100	0	100	100
19. पत्रकार कल्याण कोष में हस्तांतरण	0	0	0	0	0	0
20. क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय	4500	357200	361700	4500	411400	415900

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई का नाम/गतिविधि	बजट अनुमान 2010-2011			संशोधित अनुमान 2010-2011		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
21. गीत एवं नाटक प्रभाग	47200	202400	249600	47200	212400	259600
22. प्रकाशन विभाग	1000	210400	211400	1000	215900	216900
23. रोजगार समाचार	600	284600	285200	600	258100	258700
24. भारत का समाचारपत्र पंजीयक	1700	35900	37600	1700	37700	39400
25. फोटो प्रभाग	25300	35500	60800	17800	35500	53300
26. संचार के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में योगदान	0	1600	1600	0	26600	26600
27. एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान के लिए योगदान	0	2000	2000	0	2000	2000
कुल : प्रमुख शीर्ष '2220'	**1242600**	**2981100**	**4223700**	**1237800**	**3128000**	**4365800**
कुल : प्रमुख शीर्ष 2251, 2205 और 2220	**1425700**	**3418800**	**4844500**	**1403900**	**3557600**	**4961500**

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई का नाम/गतिविधि	बजट अनुमान 2010-2011			संशोधित अनुमान 2010-2011		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
प्रसारण (प्रमुख शीर्ष-2221)						
ध्वनि प्रसारण (उप प्रमुख शीर्ष)						
निर्देशन और प्रशासन (लघु शीर्ष)						
वेतन	100	100	200	100	100	200
टेलीविजन (उप प्रमुख शीर्ष)						
वेतन	100	100	200	100	100	200
सामान्य (उप प्रमुख शीर्ष)						
प्रसार भारती (लघु शीर्ष)						
अनुदान सहायता	3447500	14123500	17571000	1578300	14123500	15701800
कुल प्रसारण	**3447700**	**14123700**	**17571400**	**1578500**	**14123700**	15702200
पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के फायदे के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र अन्य व्यय योजना						
एकमुश्त प्रावधान (प्रमुख शीर्ष-2552)	281200	0	281200	281200	0	281200
कुल-राजस्व खंड	**5154600**	**17542500**	**22697100**	**3263600**	**17681300**	**20944900**

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई का नाम/गतिविधि	बजट अनुमान 2010-2011			संशोधित अनुमान 2010-2011		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
पूंजी खंड						
1. फिल्म प्रभाग हेतु उपकरण का अधिग्रहण	0	0	0	0	0	0
2. पत्र सूचना कार्यालय हेतु उपकरण का अधिग्रहण	0	0	0	0	0	0
3. क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय हेतु उपकरण का अधिग्रहण	45000	0	45000	45000	0	45000
4. गीत एवं नाटक प्रभाग हेतु उपकरण का अधिग्रहण	500	0	500	500	0	500
5. फोटो प्रभाग हेतु उपकरण का अधिग्रहण	0	0	0	0	0	0
6. मुख्य सचिवालय हेतु उपकरण का अधिग्रहण	0	0	0	0	0	0
7. भारतीय जनसंचार संस्थान हेतु उपकरण का अधिग्रहण	10000	0	10000	10000	0	10000
8. सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता हेतु उपकरण का अधिग्रहण	0	0	0	0	0	0
9. फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे हेतु उपकरण का अधिग्रहण	0	0	0	0	0	0
10. केन्द्रीय फिल्म निदेशालय में प्रिंट इकाई के स्तर में सुधार	9000	0	9000	9000	0	9000
11. फिल्म समारोह निदेशालय में प्रिंट इकाई के स्तर में सुधार	10000	0	10000	10000	0	10000
12. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग केंद्र - मशीनरी तथा उपकरण	0	0	0	20000	0	20000
13. प्रकाशन विभाग हेतु उपकरण का अधिग्रहण	1000	0	1000	1600	0	1600
14.. रोजगार समाचार हेतु उपकरण का अधिग्रहण	0	0	0	0	0	0
बी —भवन						
15. फिल्म प्रभाग हेतु बहुमंजिला भवन-प्रमुख कार्य	0	0	0	0	0	0
16. चलचित्र संग्रहालय की स्थापना (फिल्म प्रभाग) - प्रमुख कार्य	290000	0	290000	340000	0	340000
17. नाइट्रेट वॉल्ट्स/कर्मचारी आवास (एनएफएआई) निर्माण	0	0	0	0	0	0
18. एनएफएआई परिसर हेतु दूसरे चरण का भवन निर्माण	0	0	0	0	0	0
19. फिल्म समारोह परिसर-अतिरिक्त और वैकल्पिक-प्रमुख कार्य	40000	0	40000	64200	0	64200
20. कोलकाता में फिल्म और टेलीविजन संस्थान की स्थापना, भूमि अधिग्रहण और भवन निर्माण	0	0	0	0	0	0
21. सूचना भवन का निर्माण - प्रमुख कार्य	100000	0	100000	180000	0	180000
22. क्षेत्रीय प्रचार हेतु कार्यालय और आवासीय परिसर का निर्माण - प्रमुख कार्य	0	0	0	0	0	0
23. पत्र सूचना कार्यालय हेतु राष्ट्रीय प्रेस केन्द्र और मिनी मीडिया केन्द्र की स्थापना	100000	0	100000	100000	0	100000
24. भारतीय प्रेस परिषद हेतु भवन का निर्माण	0	0	0	0	0	0
25. आईआईएमसी हेतु भवन निर्माण तथा आवास परियोजना	20000	0	20000	20000	0	20000

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई का नाम/गतिविधि	बजट अनुमान 2010-2011			संशोधित अनुमान 2010-2011		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
26. निजी एफएम रेडियो स्टेशनों के लिए भवन और टावर	100	0	100	100	0	100
27. मास मीडिया संस्थान की स्थापना	0	0	0	0	0	0
28. इलेक्ट्रोनिक मीडिया मॉनिटरिंग केंद्र	0	0	0	1800	0	1800
निवेश						
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम	30000	0	30000	30000	0	30000
कुल - पूंजी खंड प्रमुख शीर्ष '4220'	**655600**	**0**	655600	**832200**	**0**	832200

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई का नाम/गतिविधि	बजट अनुमान 2010-2011			संशोधित अनुमान 2010-2011		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
सूचना और प्रचार हेतु ऋण (प्रमुख शीर्ष-6220)						
फिल्म (उप प्रमुख शीर्ष)						
सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य अधीन उपक्रमों के लिए ऋण **(लघु शीर्ष)**						
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम						
ऋण और अग्रिम राशि	0	0	0	0	0	0
प्रसारण के लिए ऋण (प्रमुख शीर्ष - 6221)						
सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य अधीन उपक्रमों के लिए ऋण						
प्रसार भारती						
ऋण और अग्रिम राशि	2274800	0	2274800	3896400	0	3896400
पूर्वोत्तर क्षेत्र पर पूंजी व्यय और अन्य लागत						
पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के हित में परियोजना/योजना (प्रमुख शीर्ष - 4552)						
क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के लिए उपकरणों का अधिग्रहण	5000	0	5000	5000	0	5000
पूर्वोत्तर क्षेत्र पर पूंजी व्यय और अन्य लागत						
पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के हित में परियोजना/योजना (प्रमुख शीर्ष - 6552)						
प्रसार भारती	410000	0	410000	502800	0	502800
कुल - पूंजी खंड	**3345400**	**0**	**3345400**	**5236400**	**0**	**5236400**
कुल-मांग संख्या-59	**8500000**	**17542500**	**26042500**	**8500000**	**17681300**	**26181300**

वित्तीय समीक्षा
विषय-शीर्षानुसार वर्गीकरण

(हजार रुपये में)

विवरण	बजट अनुमान 2008-2009		संशोधित अनुमान 2008-2009		वास्तविक 2008-2009		बजट अनुमान 2009-2010		संशोधित अनुमान 2009-2010		वास्तविक 2009-2010		बजट अनुमान 2010-2011		संशोधित अनुमान 2010-2011		बजट अनुमान 2011-2012	
	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना
राजस्व खंड																		
वेतन																		
स्वीकृत	1200	977181	700	1423481	0	1403351	3450	1798750	700	1841720	273	1823747	3200	1681960	3200	1787300	3000	1928800
भारित			0															0
मजदूरी	384	26529	0	26419	0	8168	340	36210	340	20312	259	19536	300	5590	340	4690	350	5230
समयोपरि भत्ता	20	8406	0	7588	0	6770	70	8565	101	7503	47	6035	300	8575	300	8350	110	8290
चिकित्सा व्यय	300	27160	0	25549	0	19664	300	29495	1	28690	0	23081	20	29565	20	34585	20	32415
घरेलू यात्रा व्यय	5699	47238	2699	43411	1688	40863	6500	48980	5300	47150	3885	49174	6300	48550	6300	55905	12900	57355
विदेशी यात्रा व्यय	3950	8000	3950	7200	178	7017	10200	7550	10300	6795	4545	4104	7600	7950	7600	7400	11600	9000
कार्यालय व्यय	59476	172908	42680	170723	38015	171177	59840	192240	60658	190765	62226	200045	52380	197370	50540	215830	62115	217050
किराया, महसूल और कर																		
स्वीकृत	1600	35933	1600	29838	1059	26487	1600	30830	400	35215	1451	30987	0	39740	0	40425	0	41840
भारित	0	300	0	300		0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	300
प्रकाशन	0	34450	0	41105	0	41225	0	36750	0	43835	0	58471	0	39420	0	39250	0	39540
बैंकिंग नकदी लेन-देन कर	0	160	0	20	0	56	0	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0
अन्य प्रशासनिक व्यय	21860	12340	21860	11796	14063	10744	114700	15170	115900	15640	111502	13577	232500	16225	229200	18530	17800	19120
आपूर्ति एवं सामग्री	11900	259060	11900	233214	5497	223749	12600	261400	12600	216400	11632	191074	35100	261400	17100	222400	18500	228700
पी.ओ.एल.	0	17840	0	16060	0	14956	900	18455	1000	16735	988	14128	0	18455	0	20000	1100	20200
विज्ञापन और प्रचार	277300	462800	551500	421515	554674	596583	336450	497520	436600	497065	427721	508851	560000	497570	555000	497060	675400	497475
लघु कार्य	0	52312	0	59927	0	64928	0	74190	0	75440	0	74144	0	81390	0	72340	5	78385
व्यावसायिक सेवाएं	117800	47225	101100	51980	100243	50758	128300	56330	123000	50110	118102	45562	161200	80850	146000	80900	272400	85130
सहायता अनुदान	1997371	9839265	1502471	11606875	894000	11662866	2308900	14473105	1976600	12795680	2128000	12803515	3644500	14432430	1802300	14466125	109000	14406314
पूंजी सृजन के लिए अनुदान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	893900	63111
अंशदान	0	3400	0	3400	0	3110	0	3400	0	3500	0	3150	0	3600	0	28600	0	3700
आर्थिक सहायता	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
एकमुश्त प्रावधान	179640	1200	336040	1500	0	1381	389700	2000	249700	2000	0	1875	281200	2000	281200	2000	250200	2000
अन्य प्रभार	189300	53993	189300	51929	118291	51583	140650	57530	167900	76915	163105	77060	162200	57610	158500	60970	405200	62585
अंत लेखा अंतरण	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
सूचना और प्रौद्योगिकी	8900	13000	4800	16870	6105	16003	5400	31920	5600	28930	796	20472	7800	31940	6000	18340	1000	20560
केंद्रीय अनुश्रवण सेवाएं	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
योग	**2876700**	**12100700**	**2770600**	**14250700**	**1733813**	**14421439**	**3519900**	**17680700**	**3166700**	**16000700**	**3034532**	**15968588**	**5154600**	**17542500**	**3263600**	**17681300**	**2734600**	**17827100**

(हजार रुपये में)

विवरण	बजट अनुमान 2008-2009		संशोधित अनुमान 2008-2009		वास्तविक 2008-2009		बजट अनुमान 2009-2010		संशोधित अनुमान 2009-2010		वास्तविक 2009-2010		बजट अनुमान 2010-2011		संशोधित अनुमान 2010-2011		बजट अनुमान 2011-2012	
	योजना	गैरयोजना	योजना	गैरयोजना	योजना	गैरयोजना	योजना	गैरयोजना	योजना	गैरयोजना	योजना	गैरयोजना	योजना	गैरयोजना	योजना	गैरयोजना	योजना	गैरयोजना
पूंजी भाग																		
मशीन और उपस्कर	95300	0	90600	0	110567	0	43200	0	43200	0	32186	0	75500	0	96100	0	89100	0
मुख्य निर्माण कार्य	174000	0	126000	0	20372	0	368000	0	358000	0	350825	0	550100	0	706100	0	1375500	0
निवेश	80000	0	100	0	0	0	100	0	100	0	o	0	30000	0	30000	0	0	0
ऋण एवं अग्रिम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ऋण प्रसार भारती	3264000	0	2616600	0	2383100	0	3558400	0	1302100	0	1348500	0	2274800	0	3896400	0	3799700	0
उत्तर पूर्वी व सिक्किम के लाभ	510000	0	396100	0	0	0	510400	0	199900	0	1699325	0	415000	0	5236400	0	5875400	0
के लिए							0	0				0	0	0			0	0
योग	**4123300**	**0**	**3229400**	**0**	**2514039**	**0**	**4480100**	**0**	**1903300**	**0**	**3430836**	**0**	**3345400**	**0**	**9965000**	**0**	**11139700**	**0**
कुल योग	7000000	12100700	6000000	14250700	4247852	14421439	8000000	17680700	5070000	16000700	6465368	15968588	8500000	17542500	13228600	17681300	13874300	17827100

वित्तीय समीक्षा
स्वायत्त संस्थानों के आधार पर वर्गीकरण

(हजार रुपये में)

		बजट अनुमान 2008-2009		संशोधित अनुमान 2008-2009		वास्तविक 2008-2009		बजट अनुमान 2009-2010		संशोधित अनुमान 2009-2010		वास्तविक 2009-2010		बजट अनुमान 2010-2011		संशोधित अनुमान 2010-2011		बजट अनुमान 2011-2012	
		योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना
बाल फिल्म समिति		40000	8400	40000	9700	40000	9700	40000	11200	40000	17500	4000	17500	40000	14300	40000	15300	40000	15500
भारतीय फिल्म और	**(R)**	80000	77500	56900	93267	54400	93267	60000	95000	95000	129400	93500	129400	80000	125000	72000	144400	80000	135000
टेलीविजन संस्थान पुणे	**(C)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
सत्यजीत रे फिल्म और	**(R)**	80000	50735	80000	52580	40000	52100	70000	60000	70000	60000	42500	60000	70000	60000	70000	61800	70000	70000
टेलीविजन संस्थान कोलकाता	**(C)**																		
भारतीय जनसंचार संस्थान	**(R)**	10000	39500	100	47994	0	46030	7000	50000	7000	78500	2000	78500	7000	67000	7000	71700	10500	71700
	(C)	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000	0	0		10000	0	10000	0	20000	0
	(C)	0	0	0	0	0	0	20000	0	20000	0	0		20000	0	20000	0	168500	0
भारतीय प्रेस परिषद		0	26300	0	31604	0	31604	0	35000	0	45600	0	45600	0	42100	0	48900	0	53200
प्रसार भारती		1787571	9636500	1325671	11371225	759600	11429800	2131900	14221400	1754600	12464200	1935000	12472150	3447500	14123500	1578300	14123500	716200	14123500

उपभोग शेष के समेत विभिन्न निकायों को जारी अनुदान

(हजार रुपये में)

क्र.सं.	नाम	अवधि में जारी अनुदान				अप्रयुक्त शेष (यदि कोई हो)			
		2008-09		2009-2010		2008-09		2009-2010	
		योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना
1	बाल फिल्म समिति	380.00	97.00	400.00	175.00	14.00	**शून्य**	2.00	**शून्य**
2	भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे	528.28	932.67	935.00	1294.00	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**
3	सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता	400.00	521.00	600.00	700.00	82.07	**शून्य**	1.64	**शून्य**
4	भारतीय जनसंचार संस्थान	**शून्य**	452.45	37.50	7.85	**शून्य**	0.135	0.16	0.14
5	भारतीय प्रेस परिषद	**शून्य**	316.04	**शून्य**	4.56	**शून्य**	0.39	**शून्य**	2.21
6	प्रसार भारती	32013.00	113712.00	32835.00	124721.00	3408.00	**शून्य**	11.00	**शून्य**

अध्याय-6

स्वायत्तशासी निकायों की समीक्षा और प्रदर्शन

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

(गैर-योजना) (लाख रुपये में)

क्र.सं.	उप शीर्षक	एसबीजी 2009-10	दिसंबर 2009 तक व्यय	आरई 2009-10	अंतिम अनुदान	बीई 2010-11
1	**2**	**3**	**4**	**5**		**8**
1.	कंप्युटरीकृत प्रबंधन प्रणाली की स्थापना	50.00	11.80	50.00	--	92.00
2.	नई दिल्ली, कटक और गुवाहाटी में क्षेत्रीय कार्यालय खोलना	85.00	10.57	20.00	--	103.00
3.	प्रमाणन प्रक्रिया की निगरानी और आधुनिकीकरण	50.00	29.52	50.00	--	60.00
4.	कुल	185.00	51.89	120.00	--	255.00

बाल फिल्म समिति, भारत

अध्याय IV और V में सीएफएसआई के व्यापक वास्तविक तथा वित्तीय प्रदर्शन की जानकारी दी गई है। उसके अनुसार संगठन का प्रदर्शन संतोषजनक है और सरकार की सीएफएसआई द्वारा जमा की गई रिपोर्ट से सहमति है।

समीक्षा और उपलब्धि स्वायत्त संस्थान

विगत पांच वर्षों से कई फिल्मों का निर्माण और बाल दर्शकों तक पहुंच निम्नलिखित हैं :

2005-06

निर्माण : 4 फीचर फिल्म पूरी की

विपणन : 7026 शो का आयोजन 27 लाख बच्चे दर्शक

व्यय : 448.68 लाख रुपये का व्यय

2006-07

निर्माण : 7 फीचर फिल्म और 4 लघु फिल्मों का निर्माण

विपणन : 7895 शो का आयोजन 32 लाख बच्चे दर्शक

व्यय : 273.8 लाख रुपये का व्यय

2007-08

निर्माण : पूरे वर्ष किसी फिल्म का निर्माण नहीं जबकि दो फीचर फिल्म और एक लघु एनिमेशन फिल्म लगभग पूरी।

विपणन : 6589 शो का आयोजन 32 लाख बच्चे दर्शक

व्यय : 246.00 लाख रुपये का व्यय

2008-09

निर्माण : 4 फीचर फिल्म और 1 लघु फिल्म पूरी

विपणन : 12957 आयोजित लगभग 35 लाख दर्शक बच्चे

व्यय : 381.00 लाख रुपये का व्यय

2009-10

निर्माण : 5 फीचर फिल्म पूरी कर ली गई

विपणन : 4741 आयोजित लगभग 23 लाख दर्शक बच्चे

व्यय : 419.00 लाख रुपये का व्यय

2010-11 (31.12.2010 तक)

निर्माण : अब तक कोई फिल्म नहीं बनी

विपणन : 4256 आयोजित लगभग 21 लाख दर्शक बच्चे

व्यय : 158.80 लाख रुपये का व्यय

सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता

सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता के कार्यों की समीक्षा

1. फिल्म तथा टेलीविजन कार्यक्रमों की विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षित मानवशक्ति उपलब्ध कराने के मकसद से भारत सरकार ने एक स्वायत्त शैक्षणिक संस्थान के रूप में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन कोलकाता के सत्यजीत राय फिल्म तथा टेलिविजन संस्थान की स्थापना की थी और इसे पश्चिम बंगाल सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1961 के तहत पंजीकृत किया गया था। संस्था विख्यात व्यक्तित्व के साथ मिलकर कार्यक्रम आयोजित करता है जैसे फिल्म, टेलीविजन, संचार, कला,भूतपूर्व संस्थान के विद्यार्थी और भूतपूर्व सरकारी सदस्य। यह संस्था सरकारी कॉसेल द्वारा संचालित किया जाता है जिसके प्रमुख अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में सुप्रसिद्ध फिल्म कलाकार श्री रजत मल्लिक अध्यक्ष हैं।

2. संस्थान तीन वर्ष का स्नातोकोत्तर डिप्लोमा निर्देशन और स्क्रीनप्ले व लेखन, संपादन, सिनेमेटोग्राफी और ऑडियोग्राफी।

3. संस्थान में बुनियादी डिप्लोमा के साथ अन्य लज कोर्स और अन्य संस्थाओं के अनुरोध पर विभिन्न परियोजना पर कार्य और फिल्म उद्योग।

4. वर्ष के दौरान विभिन्न फिल्म महोत्सवों में निम्नलिखित हात्र फिल्में चुनी गई हैं :

क्रमांक	फिल्म के नाम	पुरस्कार जीता	निर्देशक/सिनेमोटोग्राफी
1.	मीरा झा (हिन्दी)	सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार निर्देशक की पहली फिल्म, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार-2001	निर्देशक : अंजालिका शर्मा
2.	भोर (बांग्ला)	श्रेष्ठ लघु फिक्शन फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार-2001	निर्देशक : ऋतुबाला चुडगर
3.	मीरा झा (हिन्दी)	विशेष उल्लेख 48वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार-सिनेमोटोग्राफी	सिनेमोटोग्राफी : अमल निनाद सी. आर
4.	खोज (बंग्ला)	सिने फाउंडेशन की कांस फिल्म महोत्सव 2002 में (कनाडा) दर्शायी गया।	निर्देशक : पोद्दार त्रिदेव
5.	द इगोटिक वर्ल्ड (मलयालम)	ओवाहसन फिल्म महोत्सव 2002 (जर्मनी) मॉनट्रेल फिल्म फेस्टीवल (कनाडा) में दिखाया गया	सिनेमोटोग्राफी : मिलिंद नागमॉली

6.	द इगोटिक वर्ल्ड (मलयालम)	कोटक स्टूडेंट फेस्टीवल 2001 में श्रेष्ठ छात्र फिल्म	निर्देशन : त्रिदेव पोद्दार
7.	खोज (बंग्ला)	बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार बंग्ला फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन (बीएफजेए) पुरस्कार 2003	निर्देशक : त्रिदेव पोद्दार
8.	अभिमन बंद पार्टी (बंग्ला)	श्रेष्ठ लघु फिल्म बंग्ला फिल्म जनलिस्ट (बीएफजेए) 2002	निर्देशक : शैलादित्य सान्यल
9.	सुंदर जीवोन (बंग्ला)	श्रेष्ठ लघु फिक्शन राष्ट्रीय पुरस्कार–2003	निर्देशक : सुदीप चट्टोपाध्याय
10.	खोज (बंग्ला)	ईडपा अवार्ड (प्रथम फिल्म) मिफ्फ 2004	निर्देशक : त्रिदेव पोद्दार
11.	ब्रिट्रील (बंग्ला/अंग्रेजी)	सिने फाउडेशन सेक्शन ऑफ द कैनन फिल्म फेस्टीवल 2006 में दर्शने हेतु चयन	निर्देशक : अर्नीबान दत्ता
12.	कुलाई चऊला (उड़िया)	केरला फिल्म फेस्टीवल 2006 में प्रतियोगिता के लिए चयन	निर्देशक : संजीब बेहरा
13.	बाघेर बाच्चा (बंग्ला)	1. एशियन फिल्म फेस्टिवल, फिल्म, सिंगापुर 2. फिल्म फेस्टीवल फ्रांस सिनेरिल, फ्रांस 3. राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार (एनएफए) 2007 सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार (पुरस्कृत 2009 में)	निर्देशक : विष्णु देब हालदर
14.	एन एक्टर प्रिप्रेयर (बंग्ला/हिन्दी)	सिनेमा डू रिली फ्रांस में चयनित	निदेशक : कानन बेहल
15.	बाघेर बाच्चा (बंग्ला)	जेगराबडॉक्स अंतरराष्ट्रीय, फिल्म फेस्टीवल, करोटीआ में रेटोस्पेटिव में प्रदर्शन हेतु आमंत्रित	निर्देशक : विष्णुदेव हालदार
16.	चाइनिंज विस्पर	सिने फाउडेशन ऑफ द कांस फिल्म फेस्टीवल 2007 में प्रदर्शन हेतु चयन। एसआरएफटीआई के द्वारा सबसे सफलतापूर्वक डिप्लोमा फिल्म का निर्माण	निर्देशक : राका दत्ता

17.	लाल जुटो	बेस्ट क्रिस्टेटिव आयडिया के लिए संधाई में पुरस्कार : बेस्ट नॉन-फिक्शन फिल्म ऑफ ए डायरेक्टर का पुरस्कार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2007, (2009 में पुरस्कृत किया गया)।	निर्देशक : श्वेता मर्चेंट
18.	सोलीडेट्री (अंग्रेजी) माया (हिन्दी)	6वीं कल्पानीनहार अंतर्राष्ट्रीय लघु फिक्शन फिल्म फेस्टीवल 2008 में प्रदर्शन के लिए चयनित एवं भागीदारी के लिए प्रमाणपत्र	निर्देशक : मो० शकील
19.	गरम (हिन्दी)	अंतर्राष्ट्रीय फेस्टीवल ऑफ फिल्म स्कूलस्, मुंच जर्मनी, 2009 में प्रदर्शन के लिए चयनित और सर्वश्रेष्ठ छात्र सिनेमोटोग्राफर पुरस्कार साथ ही टेली-अवीवा अंतराष्ट्रीय फिल्म फेस्टीवल	निदेर्शक : स्नेहल नायर
20.	दयाम् (हिन्दी)	क्रीव फिल्म फेस्टीवल रूस, 2009 के समारोह में प्रदर्शन के लिए चयन	निदेर्शक : मो० शकील
21.	पोचा एप्पल	प्रथम पुरस्कार (संयुक्त विजय) सर्वश्रेष्ठ डिप्लोमा फिल्म, कैंपस फ्रांस फिल्म स्कूल कंपीटीशन ऑफ डिप्लोमा फिल्म एम्बेसी ऑफ फ्रांस, भारत स्थित और कैम्पस फ्रांस ने जनवरी 2010 में पुरस्कृत किया।	
22.	माई अर्मीनिया नेबरहुड (अंग्रेजी)	बेस्ट सिनेमोग्राफर का पुरस्कार, डक्यूमेंटरी फिल्म फेस्टीवल, केरला, 2009	सिनेमोटोग्राफर : के. अपाल्ला स्वामी

वर्ष 2009-10 के दौरान गैर योजना खर्च 652.82 लाख रुपये था। इसमें 600.00 लाख रुपये वास्तविक रूप से प्राप्त हुए हैं। अतिरिक्त व्यय 52.82 लाख रुपये हुए जितना बजट वर्ष के दौरान मिला था।

2009-10 में कुल अनुदान 700.00 लाख रुपये में से वर्ष के दौरान 425.00 लाख रुपये प्राप्त हुए। जिसमें वर्ष 2008-09 के बकाया भी है। 2009-10 के दौरान 423.35 लाख रुपये खर्च किए गए है, 2009-10 में बाकी 1.65 लाख रुपयों का उपयोग नहीं हुआ है।

संस्थान के कार्य की निगरानी सरकार द्वारा समय-समय पर की जाती है। वार्षिक रिपोर्ट और ऑडिट विवरण के प्रकाश में संस्थान का प्रदर्शन संतोषजनक पाया गया है।

भारतीय जन संचार संस्थान

जन संचार के क्षेत्र में प्रशिक्षण, शिक्षण और अनुसंधान के मामले में आईआईएमसी का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा है क्योंकि आईआईएमसी ने अपने पाठ्यक्रम के संचालनके साथ-साथ सरकारी अधिकारियों, सेना और अर्द्ध सैनिक बलों के अधिकारियों को पशिक्षण देने के प्रति पर्याप्त ध्यान दिया है। आईआईएमसी ने मंत्रालयों और सरकारी विभागों की ओर से शुरू की गयी परियोजनाओं के संबंध में भी उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। ओबीसी आरक्षण के तीसरे और अंतिम चरण को 2010-11 के दौरान पूरा किया गया है।

आईआईएमसी ने योजना स्कीम के तहत अपने को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उन्नयन की भी समय पर कार्रवाई की है। इस दिशा में, आईआईएमसी ने, पहले चरण में, मीडिया उद्योग की जरूरत को पूरा करने के लिए पत्रकारिता एवं जनसंचार एक वर्ष के पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को मास्टर डिग्री के समतुल्य बनाने के लिए दो वर्ष के एडवांस पी जी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में बदलने का प्रस्ताव रखा है। उसने जम्मू व कश्मीर, मिजोरम, महाराष्ट्र (विदर्भ) और केरल में चार नई शाखाएं खोलने की योजना बनायी है।

भारतीय प्रेस परिषद

भारतीय प्रेस परिषद विधि द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संस्था है। मंत्रालय में व्यय सुधार समिति की अनुशंसाओं पर विचार करते समय यह महसूस किया गया कि भारतीय प्रेस परिषद की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए जो कि प्रेस की एक स्वनियामक संस्था है, ऐसी समीक्षा न तो उपयुक्त होगी और ना ही उसके कार्यों की समीक्षा करने के लिए कोई अन्य निगरानी संस्था उपलब्ध है। उक्त निर्णय की जानकारी वित्त मंत्रालय को भी दे दी गयी।

तथापि, प्रेस परिषद के कार्य की समीक्षा संसद द्वारा सीधे उसके समक्ष प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट के द्वारा की जाती है।

एफएम रेडियो

परिणाम बजट को प्रस्तुत किए जाने के बाद की कार्रवाई

परियोजना की निगरानी परियोजना के भौतिक एवं वित्तीय प्रदर्शन के संदर्भ में मंत्रालय की ओर से मासिक, चौमाही और अर्द्धवार्षिक बैठकों में होती है।

सामुदायिक रेडियो के लिए आईईसी गतिविधियां

गैर सरकारी संगठनों और केन्द्रीय सामाजिक संगठनों के बीच जागरूकता कायम करने के लिये देश केविभिन्न भागों में अनेक कार्यशालाओं एवं सेमिनारों का आयोजन एशिया के लिये राष्ट्रमंडल शैक्षिक मीडिया सेंटर फार एशिया (सीईएमसीए), नयी दिल्ली तथा भारतीय सामुदायिक रेडियो फोरम के सहयोग से किया गया। आगे की आवश्यक कार्यवाई के लिए मंत्रालय को अनुशंसाएं/सुझाव प्राप्त हुए हैं।

प्रसार भारती

प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) देश में सार्वजनिक सेवा प्रसारणकर्ता है। आकाशवाणी और दूरदर्शन इसके दो घटक हैं। देश के लोगों को जानकारी देने, शिक्षित करने और उनका मनोरंजन करने के साथ ही प्रसारण का एक संतुलित विकास सुनिश्चित करने हेतु सार्वजनिक प्रसारण सेवाएं आयोजित करने और उन्हें संचालित करने के अधिदेश के साथ 23 नवंबर, 1997 को प्रसार भारती की स्थापना की गई।

प्रसार भारती द्वारा वर्ष 2009-10 के दौरान तथा वर्ष 2010-11 तक वास्तविक और वित्तीय कार्य निष्पादन संबंधी उपलब्धियों का वर्णन अध्याय- IV में दिया गया है। इसकी रिपोर्ट के अनुसार संगठन का कार्य निष्पादन कठिनाइयों भरा है फिर भी संतोषजनक निष्पादन से भी ऊंचे स्तर पर निर्धारित उद्देश्यों को हासिल करने की भरसक कोशिश कर रहा है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय की स्कीमों/परियोजनाओं की प्रगति और क्रियान्वयन की निगरानी के दो स्तर है- (द्व) मीडिया इकाई स्तर और (द्व) मंत्रालय स्तर। प्रसार भारती को जारी किए गए योजना व्यय फंड की गति की निगरानी के लिए साप्ताहिक आधार पर मंत्रालय में समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं। प्रगति की निगरानी वित्तीय और भौतिक दोनों मापदंडों पर की जा रही है। योजना परिव्यय के उपयोग स्तर के संबंध में मंत्रालय तीव्र विकास प्रक्रिया की आवश्यकता पर बल देता है और आने वाली अड़चनों को दूर करने पर जोर देता है।